चतुर्थ माला, खंड 14, अंक 21 Tuesday, 19 March, 1968

Fourth Series, Vol. XIV, No. 21

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 14 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XIV contains Nos. 21—30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया Price : One Rupee.

विषय-सूची CONTENTS

अंक 25—मंगलवार, 19 मार्च, 1968/29 फाल्गुन, 1889 (शक)
No. 25—Tuesday, March 19, 1968/Phalguna 29, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
688.	रेलवे अधिकारियों द्वारा डिब्बों का प्रयोग	Use of Carriages by Railway Officers.	551—55
689.	स्कूटरों का निर्माण	Production of Scooters . . .	556—61
691.	संश्लिष्ट (नकली) धागे का आयात	Import of Synthetic Yarn	561—66
	अल्प-सूचना प्रश्न Short Notice Q.		
10.	कुल्टी में इस्पात ढलाई कारखाने का जमीन में धंसना	Sinking of Steel Foundry at Kulti .	566—69

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
690.	अभ्रक की खानों के लिये लाइसेंस	Licences of Mica Mines	569
692.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से कच्चे माल का आयात	Import of Raw Materials through M.M.T.C.	570
693.	भारतीय माल के निर्यात के संबंध में प्रचार	Publicity of India's Exports	570-71
694.	पटसन की वस्तुओं के न्यूनतम निर्यात मूल्य	Minimum Export Prices for Jute Goods	571-72
695.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने	Public Sector Steel Plants	572
696.	महाराष्ट्र में ट्रैक्टर कारखाना	Tractor Factory in Maharashtra . . .	572
697.	हैदराबाद और हरिद्वार में हैवी इलैक्ट्रिकल्स प्लांट	Heavy Electrical Plants at Hyderabad and Hardwar	572-73
698.	मसालों के प्रसिद्ध आयातकर्त्ता	Established Importers of Spices . .	573
699.	रेलवे वाणिज्यिक क्लर्क संस्था का ज्ञापन	Memorandum from Railway Commercial Clerks' Association	573-74

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
700. खनन तथा संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड	Mining and Allied Machinery Corporation Ltd.	574-75
701. पाकिस्तान में भारतीय नागरिकों की नकदी का हस्तान्तरण	Transfer of Cash Balances of Indian Citizens in Pakistan	575
702. इस्पात सौदों के बारे में जाँच समिति	Committee of Enquiry into Steel Transactions	575-76
703. टायरों का पोत-लदान	Shipment of Tyres	576
704. हुबली-शोलापुर सैक्शन के स्टेशनों का अपर कृष्णा परियोजना योजना के जल में डूब जाना	Submerging of Stations on Hubli-Sholapur Section under Upper Krishna Project Scheme	576
705. रेलवे द्वारा खरीदे गये कोयले की चोरी के कारण हानि	Loss due to Pilferage of Coal purchased by Railways	576-77
706. अल्यूमिनियम स्मैल्टर तथा शीट मिल	Aluminium Smelter and Sheet Mill	578
707. रेलवे अफसरों के लिये सैलून	Saloons for Railway Officers	578
708. केरल में मोटरगाड़ी पुर्जा निर्माण कारखाना	Automobile Spare Parts Manufacturing Factory in Kerala	579
709. दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant	579-80
710. रेलवे को कोक और कोयले की सप्लाई	Supply of Coke and Coal to Railways	580
711. रेलवे कर्मचारियों को यात्रा संबंधी सुविधायें	Travelling Concession to Railway Employees	580-81
712. छोटी कार परियोजना	Small Car Project	581
713. मोटरकार किस्म जाँच समिति का प्रतिवेदन	Motor Car Quality Enquiry Committee's Report	581-82
714. मध्य प्रदेश में पन्ना खानें	Panna Mines in M.P.	582
715. जूता उद्योग में मशीनों का प्रयोग	Mechanisation of Footwear Industry	582
716. सूक्ष्म औजार कारखाने को पालघाट से कोटा ले जाया जाना	Shifting of Precision Instruments Project at Palghat to Kota	583
717. रूस को जूतों का निर्यात	Export of Shoes to USSR	584

UNSTARRED QUESTION

4269.	माचेरला और नागार्जुन-सागर के बीच यात्री यातायात	Passenger Traffic between Macherla and Nagarjunasagar	584
4270.	दक्षिण एक्सप्रैस	Dakshin Express	584-85
4271.	हैदराबाद में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries in Hyderabad	585
4272.	ट्रैक्टरों का मूल्य	Price of Tractors	585-86
4273.	चाय बोर्ड	Tea Board	586
4274.	चाय बोर्ड	Tea Board	586
4275.	रेलवे में चोरियाँ	Thefts on Railways	586-87
4276.	तेल तथा तिलहनों के वायदे के सौदे	Forward Trading in Oil and Oil seed	587-88
4278.	भारत में निर्बाध पत्तन	Free Ports in India	588
4279.	तिरूपति रेलवे बुकिंग आफिस से मुद्रा की चोरी	Theft of Currency from Tirupati Railway Booking Office	588-89
4280.	राजस्थान में नये उद्योग	New Industries in Rajasthan	589
4281.	राजस्थान के लिये एक पृथक रेलवे ज़ोन	Separate Railway Zone for Rajasthan	590
4282.	'भारतीय रेलवे 1966-67.' का प्रकाशन	Publication of 'Indian Railways 1966-67'	590
4283.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में सेवा-निवृत्ति के नियम	Retirement Rules in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	590
4284.	खादी कर्मचारी सम्मेलन, पानीपत	Khadi Workers' Conference, Panipat	590
4285.	विशाखापत्तनम में निर्बाध व्यापार क्षेत्र	Free Trade Zone at Visakhapatnam	591
4286.	रेलवे कर्मचारियों की भरती	Recruitment of Railways Staff	591
4287.	टिटेनियम उत्पाद उद्योग समूह के लिये संयुक्त राष्ट्र सहायता	U. N. Assistance for Titanium Products Complex	591-92
4288.	हिन्दुस्तान मोटर्स के जाली शेयर	Bogus shares of Hindustan Motors	592

अता० प्र० संख्या U.N.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ / PAGES
4289.	अमृत वनस्पति कम्पनी लिमिटेड / Amrit Vanaspati Co. Ltd.,	593
4290.	दूसरे संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के मार्गदर्शकों को विदेशी भाषा का ज्ञान / Guides knowledge in foreign Language of U.N.C.T.A.D. II	593
4291.	बोकारो, इस्पात कारखाना / Bokaro Steel Plant	594
4292.	महेश्वर क्षेत्र के बुनकरों को रोजगार दिलाना / Rehabilitation of Weavers of Maheshwar Area	594
4293.	औद्योगिक सहकारी समितियां / Industrial Co-operatives	595
4294.	लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता / Financial Assistance to Small Scale Industries	595
4295.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड / Hindustan Zinc Ltd.	595-96
4296.	रूरकेला इस्पात कारखाना / Rourkela Steel Plant	596-97
4297.	उदयपुर में हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर / Hindustan Zinc Smelter in Udaipur	597
4298.	राजस्थान में खनिज पर आधारित उद्योग / Mineral based industries in Rajasthan	597
4299.	रेलवे लाइनें / Railway Lines	597-58
4300.	उद्योग समूहों के सम्पर्क अधिकारी / Liaison Officers of Industrial Houses	598-99
4301.	सीमेंट के कारखाने / Cement Factories	599
4302.	कच्चे रेशम का आयात / Import of Raw Silk	599
4303.	रेलवे अधिकारियों द्वारा धातु से बने रेलवे पासों का दुरुपयोग / Misuse of Metal Passes by Railway Officers	599
4304.	रेलवे विश्रामालयों के किराये में वृद्धि / Increase in the rent of Railway Retiring Rooms	600
4305.	रेलवे कर्मचारियों के लिए क्वाटरों का आवंटन / Allotment of Accommodation to Railway Employees	600
4306.	अयस्कों का निर्यात / Export of Ores	600-01
4307.	नई रेलवे लाइनें / New Railway Lines	601
4308.	रेलवे सुरक्षा और पुलिस का केन्द्रीय सरकार को हस्तांतरण / Transfer of Railway Security and Police to Central Government	601

तारांकित प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
4309. जर्मनी से उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers from West Germany .	601-02
4310. प्रथम श्रेणी के डिब्बों में परिचरों की नियुक्ति	Posting of attendants in 1st Class Compartments	602
4311. बोकारो इस्पात कारखाना	Bokaro Steel Plant	602
4312. विदेशी सहयोग संबंधी करार	Agreements on Foreign Collaborations	602-03
4313. यात्री डिब्बों और माल-डिब्बों का निर्यात	Export of Passenger Coaches and Wagons	603
4314. कोयला विकास निगम के साथ समझौता	Agreement with Coal Development Corporation	603
4315. रेलवे इंजनों का आयात	Import of Railway Engines	604
4316. खेत्री ताँबा परियोजना	Khetri Copper Projcect	604-05
4317. मेरठ-हापुड़ रेलवे लाइन पर चन्दसारा हाल्ट-स्टेशन	Chandsara halt on Meerut-Hapur Line .	605
4318. विदर्भ में कपड़ा मिलें	Textile Mills in Vidarbha	605-06
4319. रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति	Scholarship to Railway Employees' Children	606
4320. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम जाँच समिति	National Coal Development Corporation Enquiry Committee	606-07
4321. माथुर समिति	Mathur Committee	607
4322. सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने	Public Sector Steel Plants . .	607-08
4323. अलौह धातुओं की कमी	Shortage of Non-Ferrous Metals . .	608-09
4324. रूस को माल डिब्बों का निर्यात	Export of Wagons to U.S.S.R.	609
4325. रेलवे लाइनों के पास पड़े हुए इस्पात तथा लकड़ी के स्लीपर	Steel and Wooden Sleepers lying Along Railway Line	610
4326. उत्तर रेलवे पर सब-ओवरसियर, मिस्त्री और ड्राफ्टस्मैन (नक्शानवीस)	Sub-overseers, Mistris and Draftsmen on Northern Railway	610

तारांकित प्र० सं०

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
4327.	बिहार में खानें	Mines in Bihar	610
4328.	चमड़ा निर्माण कम्पनियां	Leather Manufacturing Companies	611
4229.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant	611-12
4330.	आयात नीति	Import Policy	612
4331.	स्टेनलेस स्टील इस्पात का कोटा	Quotas of Stainless Steel	612
4332.	पश्चिम बंगाल में इंजीनियरी कारखाने	Engineering Units in West Bengal	613
4333.	भिंड-चरिगांव रेलवे लाइन	Bhind-Chirgaon Railway Line	613
4334.	पश्चिम बंगाल में इंजीनियरी कारखाने	Engineering Unit in West Bengal	613
4335.	बोकारो इस्पात कारखाना	Bokaro Steel plant	614
4336.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant	614
4337.	मैसर्स गुजदार काजोरा कोल माइन्स लिमिटेड और मैसर्स कलकत्ता सेफ डिपोजिट कम्पनी लिमिटेड	M/s, Guzdar Kajora Coal Mines and M/s. Calcutta Safe Deposit Co. Ltd.	615
4338.	कपास के मूल्य	Price of Cotton	615
4339.	न्यू विक्टोरिया मिल्स बन्द होना	Closure of New Victoria Mills	615-616
4340.	अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड	Ashoka Paper Mills Ltd.	616
4341.	कोयला खानों का बन्द होना	Closure of Coal Mines	616-617
4342.	काँडला में अबाध व्यापार क्षेत्र	Free Trade Zone at Kandla	617
4343.	रियायती टिकटों का दुरुपयोग	Misuse of Concession Tickets	617-18
4344.	राज्य व्यापार निगम द्वारा ताँबे की छड़ों की सप्लाई	Supply of Copper Bars by the State Trading Corporation	618-19
4345.	वस्तुविनिमय व्यापार करार	Barter Trade Agreements	619
4346.	रूस के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत	Talks with Soviet Prime Minister	619-20
4347.	रायपुर में विद्यार्थियों द्वारा रेलगाड़ी का रोका जाना	Stopping of Trains by Students at Raipur	620

U.S.Q.Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4348. रूस को इंजीनियरी माल का निर्यात	Esxport of Engineering Goods to U.S.S.R. .	620
4349. जूतों का निर्यात	Exports of Shoes . . .	620-21
4350. मध्य प्रदेश में कोयले तथा लोहे की खानें	Coal and Iron Mines in Madhya Pradesh	621
4351. बिहार का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Bihar	621
4352. खनिज तथा धातु व्यापार निगम का स्टाक	Stocks of M.M.T.C. .	621
4353. लघु उद्योगों के लिए आयात लाइसेंस	Import Licences for Small Scale Industries .	622
4354. शक्तिचालित हलों का निर्माण	Manufacture of Power Tillers	622
4355. रूई का आयात	Import of Cotton . . .	623
4356. लौह-मैंगनीज उद्योग	Ferro-Manganese Industry .	623
4357. उद्योगों में ईंधन और भाप का प्रयोग	Use of Fuel and Steam in Industries .	624-25
4358. धातुओं को जंग लगना	Metal Corrosion	625
4359. पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर जिला मुख्यालय का बदला जाना	Shifting of North-Eastern Railway Samastipur Distt. Headquarters	625
4360. हाजीपुर और भैंसालोटन के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Hajipur and Bhainsalotan	625-26
4361. ईराक के साथ व्यापार	Trade with Iraq . . .	626
4362. सूती कपड़ा फैक्टरी जावरा में आग लगने की दुर्घटना	Fire in Cotton Textile Factory, Jawra . .	626
4363. रेलवे अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Railway Officers .	627
4364. इस्पात कारखाने	Steel Plants	627
4365. चाय पर निर्यात शुल्क	Export Duty on Tea . .	628
4366. चीनी संयंत्रों और मशीनों का निर्माण	Manufacture of Sugar Plants and Machinery	628
4367. रोल ग्राइन्डिग मशीनें	Roll Grinding Machines	628-29
4368. कागज उद्योग	Paper Industry .	629
4369. स्कूटरों का निर्माण .	Manufacture of Scooters . . .	629-30
4370. रेल गाड़ी के मासिक टिकट	Railway Monthly Season Tickets .	630

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4371.	छपाई मशीनों का निर्माण	Manufacture of Printing Machines	630-31
4372.	अमरीका को रेडियो सैटों का निर्यात	Export of Radio Sets to U.S.A.	631
4373.	रूरकेला इस्पात कारखाना	Rourkela Steel Plant	631
4374.	मोर पंखों का निर्यात	Export of Peacock Feathers	631-32
4375.	बिड़लाओं को लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of Licences to Birlas	632-33
4376.	माल गाड़ियों तथा माल गोदामों से सामान की चोरी	Theft of Goods from Goods Trains and Goods Sheds	633
4377.	आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग	Industries in Adivasi Areas	633-34
4378.	मध्य प्रदेश में बेल्लाडिल्ला में रेलवे लाइनों का बिछाया जाना	Laying of Railway Lines in Belladilla (M.P.)	634
4380.	मध्य प्रदेश में ग्रामोद्योग सहकारी समितियां	Gramodyog Co-operative Societies in M.P.	634
4381	अखिल भारतीय रेलवे अवर्गीकृत (अनग्रेडिड) एकाउन्ट्स क्लर्क सम्मेलन	All India Railway (Ungraded) Accounts Clerks Convention	635
4382.	दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ की एर्णाकुलम शाखा	Dakshin Railway Employees' Union, Ernakulam Branch	635
4383.	एर्णाकुलम के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Quarters for Workers at Ernakulam	635-36
4384.	एर्णाकुलम में कर्मचारियों की विशेष रेलगाड़ी	Workmen Special Train at Ernakulam	636
4385.	गैर-सरकारी पूंजी निदेश	Private Investment	636
4386.	आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले उद्योग	Industries to be set up in Andhra Pradesh	636-37
4387.	ओंगल-हैदराबाद रेलवे लाइन	Ongole-Hyderabad Railway Line	637
4388.	उद्योगों में लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त करना	Delicensing of Industries	637
4389.	उद्योगों का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Industries]	637-38
4390.	कृषि पर आधारित उद्योग	Agro-Industries	638
4391.	विदेशी कम्पनियाँ	Foreign Companies	639
4392.	रेलवे में स्वचालित मशीनें	Automatic Machines on the Railways	639-40

U. S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4393. कटनी स्थित कारखाने के निकट रेलवे का उपरि पुल	Railways Over-bridge near Ordnance Factory, Katni	640
4394. रेलवे बोर्ड के कार्यालयों में निःसवर्ग पद	Ex-Cadre Posts in the Railway Board's Officce	640-41
4395. रेलवे सेवा आयोग	Railway Service Commissions	641
4396. मध्य प्रदेश में निचले तथा उपरि पुल	Under and Over-bridges in M.P.	641-42
4397. यात्री रेल गाड़ियां	Passenger Trains	642
4398. कटनी और इटारसी यार्डों से माल गुम हो जाना	Goods Lost from Katni and Itarsi Yards	642-43
4399. शिमला-कालका तथा मेत-पालाइप-ऊटाकमंड रेलवे लाइन से घाटा	Loss on Simla-Kalka and Mettupaliyam--Ootacamand Lines	643
4400. रेलवे कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of quarters to Railway Employees	643-44
4401. रेलवे अधिकारियों को तीसरी श्रेणी के क्वाटरों का नियतन	Allotment of Class III quarters to Railway officers	644
4402. रलवे कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of quarters to Railway employees	644
4403. पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों का कम किया जाना	Reduction in posts of Assistant Station Masters and Station Masters in N.F. Railway	645
4404. राज्य व्यापार निगम को आयात लाइसेंस देना	Grant of Import Licences to S.T.C.	645
4405. अमोनियम सल्फेट का आयात	Import of Ammonium Sulphate	645-46
4406. गोमांस और बछड़े के चमड़े का निर्यात	Export of Beef and Calf Leather	646
4407. बोकाजन (आसाम) में सीमेंट कारखाना	Cement Factory at Bokajan (Assam)	646
4408. खादी ग्रामोद्योग भवनों का बन्द होना	Closure of Khadi Gramodyog Bhavans.	646

अता० प्र० सं०

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4409.	राजस्थान और मध्य प्रदेश में घड़ियों के कारखाने	Watch Factories in Madhya Pradesh and Rajasthan	647
4410.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Limited	647
4411.	विदेशी सहयोग	Foreign Collaborations .	647
4412.	निर्यात-प्रधान कताई मिल	Export--Oriented Spinning Mills .	648.
4413.	दानापुर स्थित पूर्व रेलवे बायज हाई स्कूल के अध्यापकों की ओर से ज्ञापनपत्र	Memorandum from Teachers of Eastern Railway Boys High School, Danapur	648
4414.	छोटी कार परियोजना	Small Car Project	648
4415.	बैल्लडिल्ला (मध्य प्रदेश) में इस्पात कारखाना	Steel Plant at Bailadilia (Madhya Pradesh)	648-49
4416.	अप रेल गाड़ी के साथ लगाया जाने वाला शयन डिब्बा	Sleeper Coach Attached to 33 UP Trains	649
4417.	मध्य रेलवे टिकट निरीक्षकों को ऊनी वर्दियाँ	Woollen Liveries to Ticket Examiners of Central Railway	649
4418.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों के मूल्य	Prices of H.M.T. Watches .	649-50
4419.	पूर्वोत्तर रेलवे यात्री सुरक्षा परिषद	North-Eastern Railway Passengers Safety Council	650
4422.	श्रीलंका में औद्योगिक विकास के लिए सहयोग	Collaboration for Industrial Development in Ceylon	650
4423.	सीमेंट आवंटन तथा समन्वय संगठन	Cement Allocation and Co-ordinating Organisation	650-51
4424.	कागज का दाम	Price of Paper . . .	651
4425.	उत्तर प्रदेश में नये उद्योग	New Industries in U.P. . . .	651
4426.	इंग्लैण्ड, रूस और पश्चिम जर्मनी से आयात तथा उनको निर्यात	Imports and Exports to U.K., U.S.S.R. and West Germany	651-52
4427.	बैटरी सैलों का निर्माण	Manufacture of Battery Cells . .	652
4428.	बैटरी सैलों का निर्माण करने वाले कारखानों में कर्मचारी	Employees in the Factories Manufacturing Battery Cells	652
4429.	बैटरी के सैलों का निर्माण करने वाली कम्पनियों द्वारा मुनाफा	Profits by Companies Manufacturing Battery Cells	652-53

4430.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation .	653
4431.	कोयले का न मिलना	Non-availability of Coal .	654
4432.	भेजीपुत में रेलवे स्टेशन	Railway Station at Bhejiput	654
4433.	दिल्ली से भुवनेश्वर को सीधी रेलगाड़ी	Direct Train from Delhi to Bhubaneswar	655
4434.	सिल्चर नगर के निकट रेल का ऊपरी पुल	Railway Over-Bridge near Silchar Town	656
4435.	अखबारी कागज का उत्पादन	Production of News print .	655-56
4436.	अखबारी कागज का उत्पादन	Production of News Print .	656-57
4437.	मशीनी औजार निर्माताओं तथा उपभोक्ताओं की गोष्ठी	Seminar of Machine Tool Manufacturers and Consumers	657
4438.	मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ores	657
4439.	अरब देशों के साथ व्यापार	Trade with Arab Countries .	658
4440.	ग्रैफाइट क्रूसिबल कारखाना	Graphite Crucible Plant	658
4441.	नये सीमेंट कारखानों की स्थापना	Setting up of New Cement Factories .	658-59
4442.	रूस को खेल के सामान का निर्यात	Export of Sports Goods to U.S.S.R. .	659-60
4443.	दिल्ली क्षेत्र में उपनगर सैक्शन पर रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना तथा अधिक गाड़ियाँ चलाना	Improvement of Frequency and Speed of Trains on Suburban Section in Delhi Area	660
4444.	रेलवे में 'कंटेनर सर्विस'	Container Service on Railways.	660-61
4445.	रूस के साथ व्यापार प्रणाली	Mode of Trade with U.S.S.R.	661
4446.	पश्चिमी बंगाल में इंजीनियरिंग उद्योग	Engineering Industry in West Bengal . .	661-62
4447.	डम डम से प्रिन्सेसघाट और डम डम से बालीगंज तक रेलवे लाइनें	Railway Lines from Dum-Dum to Princess Ghat and Dum-Dum to Ballygunj . .	662

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ / PAGES
4448.	रेलवे विद्युतीकरण परियोजना, कलकत्ता के कर्मचारी	Employees of Electrification Railway Project Calcutta	662-63
4449.	दुर्गापुर स्टेशन पर पहले दर्जे के महिला प्रतीक्षालय में काम करने वाली आया	Ayha attached to 1st Class Ladies Waiting Room at Durgapur Station	663
4450.	कपड़ा निगम	Textile Corporation	663
4451.	माडल वूलन मिल्स, बम्बई	Model Woollen Mills, Bombay	664
4452.	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं के आयात के लिये लाइसेंस	Import Licences for Deep Sea Fishing Trawlers	664
4453.	कन्नानूर सहकारी कताई मिल	Cannanore Co-operative Spinning Mill	664-65
4454.	केरल में क्षेत्रीय व्यापार निगम	Regional Trading Corporation in kerala	665
4455.	बड़ौदा के मैसर्स साराभाई मार्क को आयात लाइसेंस	Import Licences to M/s. Sarabhai Marc of Baroda	665-66
4456.	मैसर्स कूपर एलन कम्पनी	M/s. Cooper Allen Co.	666
4457.	खेत्री ताँबा खान में एक मजदूर की मृत्यु	Death of a Worker in Khetri Copper-Mines	666-67
4458.	केरल में सहकारी कताई मिल	Co-operative Spinning Mill in Kerala	667
4459.	कोकिंग कोयला	Coking Coal	667-68
4460.	उड़ीसा में क्रोमाइट के लिये खनन पट्टा	Mining Lease for Chromite in Orissa	668
4461.	अमरीका द्वारा प्रेस बैकों का आयात	Import of Press-breaks by U.S.A.	668
4462.	राजस्थान में जिप्सम के भण्डार	Gypsum Deposits in Rajasthan	668-69
4463.	सिगनल तथा दूर-संचार शाखा के कर्मचारी	Employees of Signal and Tele-communications Branch	669
4464.	रेलवे के सिगनल और दूर-संचार कर्मचारियों के लिए वर्दी	Uniforms for Railway Signal and Telecomunication Staff	669

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4465.	अखिल भारतीय रेलवे मनसचिवीय कर्मचारी एसोसिएशन	All India Railway Ministerial Staff Association	669-70
4466.	मद्रास में बड़ी औद्योगिक परियोजनायें	Major Industrial Projects in Madras	670
4467.	इस्पात का निर्यात	Export of Steel	670
4468.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Ltd.	671
4469.	मैसूर में सरकारी उद्योग	Government-owned Industries in Mysore	671
4470.	रेलवे में रेलगाड़ी परीक्षक	Train Examiners on the Railways	671
4471.	मनीपुर के मंत्रियों को कारों की खरीद के लिए ऋण	Loans given to Ministers of Manipur for Purchase of Cars	672
4472.	शराब का निर्यात और आयात	Export and Import of Liquors	672
4473.	आम के लदान से रेलवे की आय	Earnings to Railways on Mango Consignments	672-73
4474.	रेलवे में भ्रष्टाचार का उन्मूलन	Eradication of Corruption on Railways	673
4475.	पत्थरों के लदान से रेलवे को आय	Earning to Railways on Stone Consignments	673-74
4476.	राज्य व्यापार निगम द्वारा जूतों का समाहार	Procurement of Shoes by S.T.C..	673-74
4477.	राज्य व्यापार निगम द्वारा लिए गए जूतों के मूल्य	Prices of Shoes Charged by S.T.C..	674-75
4478.	बांदा जंकशन पर पूछ-ताछ कार्यालय	Enquiry office at Banda Junction	675
4479.	लखनऊ-बड़ौदा एक्सप्रेस तथा कानपुर-बड़ौदा यात्री गाड़ियां	Lucknow-Banda Express and Kanpur-Banda Passenger Trains	675
4480.	सल्फर के आयात करने के लिए लाइसेंस	Licence for Import of Sulphur	675-76
4481.	हसन-मंगलोर रेलवे लाइन	Hassan Mangalore Railway Line	676
4482.	रेलगाड़ी के मालडिब्बों से कोयले की चोरी	Pilferage of Coal from Railway Wagons	676
4483.	रेलवे सुरक्षा दल का समाप्त किया जाना	Disbanding of Railway Protection Force	677

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4484.	जापानी औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल	Japanese Industrial Delegation	677
4485.	दिल्ली में मनीपुर हस्तशिल्प बिक्री केन्द्र	Handicraft Sales Centre for Manipur in Delhi	677
4486.	मनीपुर में उद्योग	Industries in Manipur	678
4487.	बल्लाडिल्ला में पैलट बनाने का कारखाना	Pollotisation Plant at Balladilla Railway	678
4488.	रेलवे गार्ड	Railway Guards	679-79
4489.	निर्यात गृह	Export Houses	679
4490.	रूस को वैगनों का निर्यात	Export of Wagons to U.S.S.R	579-80
4491.	सागर जिले में कैल्साइट निक्षेप	Calcite Deposits in Saugar District	680
4492.	रूसी रेलवे प्रतिनिधि मण्डल की भारत की यात्रा	Visit of Soviet Railway Delegation to India	680
4493.	जूतों के निर्यात पर राज्य व्यापार निगम द्वारा लिया गया कमीशन	Commission Charged by S.T.C. on Export of Shoes	681
4494.	मैसूर लोहा तथा इस्पात, वर्क्स, भद्रावती	Mysore Iron and Steel Works, Bhadravathi	681
4495.	खादी ग्रामोद्योगभवन, नई दिल्ली में वस्तुओं की बिक्री	Sale of Goods in Khadi Bhavan, New Delhi	681-82
4496.	निमियाघाट स्टेशन के निकट मालगाड़ी का लूटा जाना	Looting of Goods Trains near Nimiaghat Station	682
4497.	मुगलसराय स्टेशन पर बम विस्फोट	Explosion of Bomb on Mughal Sarai Station	682
	अतारांकित प्रश्न संख्या 1295 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to unstarred Q.No. 1295	683
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent public Importance	683-85
	वामपंथी साम्यवादी नागाओं द्वारा सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न नागालैंड की माँग	Demand for Sovereign Nagaland by Left Communist Nagas	683-85
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	686-87
	प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	68 7

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सैंतालीसवां प्रतिवेदन	Forty-seventh Report	
मुंगेर के निकट गंगा नदी में हाल ही में आग लगने के बारे में वक्तव्य	Statement *re.* recent blaze in Ganga near Monghyr	687
श्री रघुरमैया	Shri Raghu Ramaiah	
अनुदानों की मांगें, रेलवे, 1968–69 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), 1967–1968	Demands for Grants (Railway), 1968-69 & Demand for Supplementary Grants (Railways). 1967-68	689
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C. M. Poonacha	689-91
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	691-93
श्रीमती तारा सप्रे	Shrimati Tara Sapre	693-94
श्री द० रा० परमार	Shri D. R. Parmar	694
श्री दशरथ राम रेड्डी	Shri D. R. Reddy	694-95
श्री ओ० प्र० त्यागी	Shri O.P. Tyagi	695-96
श्री अ० सि० सहगल	Shri A.S. Saigal	696
श्री दीवीकन	Shri Deiveekan	696-97
डा० महादेव प्रसाद	Dr. Mahadeva Prasad	697
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	697-98
श्री द्व० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	698
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen	698-99
श्री जी० एस० रेड्डी	Shri G. S. Reddy	699
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinkar Desai	699-701
श्री अरुमुगम	Shri R. S. Arumugam	701
श्री महन्त दिग्विजय नाथ	Shri Mahant Digvijai Nath	701-02
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	702-03
श्री अब्दुल गनी डार	Shri Abdul Ghani Dar	703
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki	744
श्री गुणानन्द ठाकुर	Shri Gunanand Thakur	745-46
श्री मुद्रिका सिंह	Shri Mudrika Sinha	746
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	746-47
सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई	Arrest and Release of Members	702
जम्मु काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) विधेयक	Jammu and Kashmir Represenation of the people (Supplementary) Bill	
खण्ड 2, 3 तथा 1	Clauses 2, 3, & 1	688
संशोधित रूप में पारित किये जाने का प्रस्ताव	Motion to Passed as amended	747
श्री मु० यूनस सलीम	Shri M. Yunus Saleem	748-49
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	750
श्री धीरेन्द्र देव	Shri D. N. Deb	753
श्री प० गोपालन	Shri P. Gopalan	753-54
श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी	Shri Gulam Mohammad Bakshi	754-55

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण

दिनांक 19 मार्च , 1968 । 29 फाल्गुन, 1889 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
553	पंक्ति 1 , सदस्य का नाम `श्री शिवाजीराव रा देशमुख ` के स्थान पर `श्री शिवाजीराव शं.देशमुख `पढ़िये ।
554	पंक्ति 19 , मंत्री महोदय का नाम `श्री के .गु.पुनाचा ` के स्थान पर `श्री वे.गु.पुनाचा `पढ़िये ।
569	'Licences for Mica Mines ' शीर्षक के अन्तर्गत प्रश्न की संख्या `690 `पढ़िये ।
645	पंक्ति 3 , सदस्य का नाम `श्री वे.कृ.दास चौधरी ` के स्थान पर `श्री वे.कृ.दासचौधरी `पढ़िये ।
683	पंक्ति 18 , `प्रभुत्वसंयत्र ` के स्थान पर `प्रभुत्वसम्पन्न ` पढ़िये ।
691	पंक्ति 1 , `1968-69 `के स्थान पर`1967-68 ` पढ़िये । मांग संख्या 4 , 5 , 6, 7, 8 की संशोधित राशि निम्नलिखित पढ़िये : 4 1,10,63,000 रुपए 5 5,94,95,000 रुपए 6 2,25,76,000 रुपए 7 9,06,13,000 रुपए 8 2,06,70,000 रुपए

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 19 मार्च, 1968/29 फाल्गुन, 1889 (शक)

Thursday, March 19, 1968/Phalguna 29, 1889 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये । / MR. SPEAKER *in the chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रेलवे अधिकारियों द्वारा डिब्बों का प्रयोग

*688. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अधिकारियों के पद नाम क्या हैं, जो सरकारी कार्य यात्रा के लिये विशेष रेल-गाड़ियों/डिब्बों का उपयोग करने के अधिकारी हैं ;

(ख) प्रत्येक ज़ोनल रेलवे में अधिकारियों के प्रयोग के लिये ऐसे कितने विशेष डिब्बे/विशेष रेल गाड़ियाँ निश्चित की गई हैं ; और

(ग) गत पाँच वर्षों में, वर्षवार, प्रत्येक ज़ोनल रेलवे में इन डिब्बों/विशेष रेल गाड़ियों के अनुरक्षण पर कितना व्यय किया गया ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) सरकारी यात्रा के सम्बन्ध में किसी भी अधिकारी को विशेष गाड़ी के उपयोग करने का अधिकार नहीं है । राजपत्रित अधिकारी-सरकारी यात्रा के लिये निरीक्षण-यान का उपयोग करने के हकदार है ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 486/68]**

(ग) सवारी डिब्बों के अनुरक्षण का खर्च अलग-अलग टाइप के अनुसार नहीं रखा जाता ।

Shri R. S. Vidyarthi: Is it not a fact that the Officers for whom the Railway runs carriages and special trains travel alongwith their families? Is there any check on this misuse and are those officers entrusted with the task of checking senior or junior to those whom special carriages are given?

श्री परिमल घोष : कोई रेलवे अधिकारी स्पेशल ट्रेन या सैलून के लिये हकदार नहीं है। सैलून सामान्यतः रेलवे बोर्ड के सदस्यों का प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा ही प्रयोग किये जाते हैं। रेलवे अधिकारी सामान्यतः निरीक्षण डिब्बों के हकदार होते हैं जो कि उनके निरीक्षण कार्य के लिये अत्यावश्यक हैं। सैलूनों के प्रयोग पर विशेष निगरानी रखी जाती है। रेलवे बोर्ड या भारत सरकार के किसी रेलवे अधिकारी द्वारा किसी स्पेशल ट्रेन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

श्री वेदव्रत बरुआ : सैलूनों की चलाने की ऊंची लागत को सामने रखते हुये क्या सरकार ऊंचे अधिकारियों के लिये वातानुकूलित यात्रा की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ?

श्री परिमल घोष : ये निरीक्षण डिब्बे उन्हीं रेलवे कर्मचारियों को दिये जाते हैं जिन्हें मौके पर निरीक्षण के लिये इसकी वास्तविक आवश्यकता होती है।

श्री रंगा : साधारण, डाक या ऐक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा करके भी मौके पर निरीक्षण किये जा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि संसद सदस्य कई वर्षों से इस अलाभ प्रद खर्च को हटाने की माँग कर रहे हैं, क्या सरकार सैलूनों के प्रयोग को समाप्त करेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): यह इस प्रकार का काम है जिसे निरन्तर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कोई यह नहीं कह सकता कि किस समय निरीक्षण की आवश्यकता पड़ जाये। फिर सैलून और निरीक्षण डिब्बों के सम्बन्ध में थोड़ी उलझन है। सैलूनों का प्रयोग राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। पर्यटकों द्वारा भी उनका प्रयोग किया जाता है और उनकी संख्या 116 है—ये सैलून सभी गेज, 'ब्राड', 'मीटर', और 'नैरो', गेज पर चल सकते हैं। रेलवे अधिकारी निरीक्षण डिब्बों में यात्रा करते हैं जिनमें निरीक्षण सम्बन्धी उपकरण लगे होते हैं। वे साधारण गाड़ी से यात्रा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें निरीक्षण खिड़की नहीं होती है। ये निरीक्षण डिब्बे गाड़ी के अन्त में जोड़े जाते हैं ताकि उन्हें चाहे जब गाड़ी से अलग किया जा सके और पटरी का निरीक्षण किया जा सके। रेल की पटरी और अन्य प्रतिष्ठानों के उचित संधारण के लिये इन सब बातों का पूरा करना आवश्यक है। उनका दुरुपयोग नहीं किया जाता है। अधिकतम सावधानी बरती जा रही है और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिये हम निश्चय ही कड़े उपाय करेंगे।

श्री बूटा सिंह : क्या यह सच है कि रेल डिब्बों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये रेलवे प्राधिकार द्वारा कुछ विशेष डिब्बों का निर्माण किया गया था, किन्तु उन्हें निर्यात नहीं किया गया और अब रेलवे अधिकारियों द्वारा वे सैलूनों के रूप में प्रयोग में लाये जाते हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जी नहीं। ये विशेष डिब्बे पर्यटकों के लिये तथा सार्वजनिक जनता के लिये विशेष प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाये जाते हैं।

Shri A.B. Vajpayee: Is the hon. Minister aware that in one case the officers sent their saloon with the goods train at night from Jaipur to Delhi and they themselves came to Delhi by a passenger train next day? Has any enquiry been held into it?

श्री चे० मु० पुनाचा : यदि ऐसे किसी मामले की जानकारी मुझे दी जाती है, तो मैं निश्चय ही उसकी जाँच करूंगा।

श्री शिवाजी राव रां० : देशमुख रेलवे के किस श्रेणी के अधिकारियों को सैलूनों के प्रयोग का अधिकार है ? जब कि मंत्रि परिषद के लोकप्रिय सदस्यों और संसद सदस्य को सैलूनों के प्रयोग का अधिकार नहीं, फिर क्या कारण है कि रेलवे के इन उच्च अधिकारियों को यह अधिकार क्यों दिया गया है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सैलूनों में यात्रा करने का अधिकार है ; भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री उप-प्रधान मंत्री, उप-राष्ट्रपति, मंत्रीमण्डल के मंत्री, सेनाध्यक्ष, तथा उप-सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष, सेना पति, योजना आयोग के सदस्य, रेलवे के उप-मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जाँच ब्यूरो के निदेशक, विदेश सचिव, भारत सरकार, वैदेशिक कार्य मंत्रालय जब कि वह अपनी ड्यूटी पर और सचिव के रूप में यात्रा कर रहे हों, तथा रेलवे बोर्ड के सदस्य ।

Shri S. M. Joshi: May I know whether, in view of the fact that the saloons had been introduced during the British regime and that it is not in keeping with our democratic institutions, do Government propose to dispense with it forth with?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करता हूं किन्तु यह प्रथा पहले से चल रही है और इसका दुरुपयोग नहीं किया गया है । उन विशेषाधिकारियों का किसी भी व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग न हो, यह सुनिश्चित करने के लिये हम पूरी सावधानी बरतेंगें ।

Shri Madhu Limaye: Sir, Joshiji's question has not been answered. He is demanding the abolition of saloons as they are inconsistent with our democratic set up.

श्री परिमल घोष: रेलवे संचालन का कार्य इस प्रकार का है कि इस प्रकार के निरीक्षण डिब्बे अत्यावश्यक हैं । केवल भारतीय रेलों में ही नहीं, अपितु संसार भर में इनका प्रयोग किया जा रहा है । यह कोई विशेषाधिकार नहीं हैं, अपितु रेलवे संचालन के लिये अत्यावश्यक मद है ।

श्री हेम बरूआ: क्या मंत्री महोदय को पता है कि जब श्री एस० के० पाटिल रेलवे मंत्री थे, तो वह गोहाटी से लम्डिंग तक मोटर कार में गये, यद्यपि रेल की पटरी सड़क के समानान्तर दौड़ती है? इस प्रकार मोटर कार पर फालतू व्यय किया गया ।

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं । हो सकता है कुछ अन्य परिस्थितियों वश उन्होंने सड़क के रास्ते यात्रा की हो । वे परिस्थितियां मुझे स्पष्ट नहीं हैं ।

Shri Mohammad Ismail: Will it not be more appropriate to use motor trollies for inspection purposes instead of saloons as the Members of the Railway Board go to sleep in the saloons and do not know when the station has come?

श्री चे० मु० पुनाचा : पटरी के निरीक्षण के लिये उपलब्ध आवश्यक सुविधाओं का प्रयोग करने के लिये पूरी सावधानी बरती जाती है चाहे वह सुविधा मोटर ट्रोली की हो या कोई अन्य साधन हो । मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इन सुविधाओं का कोई दुरुपयोग नहीं होगा ।

Shri Suraj Bhan: The hon. Minister just now stated that there was some confusion about inspection carriages and saloons. Are saloons not misused in place of inspection Carriages?

श्री चे० मु० पुनाचा : यदि मुझे कोई विशिष्ट जानकारी दी जाये तो मैं निश्चय ही उसकी जांच करूंगा ।

श्री लोबो प्रभु : क्या सरकार पास रखने वाले रेलवे कर्मचारियों पर आय कर लगायेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि रेलवे कर्मचारियों का आरक्षण आरक्षण रद्द करने के सामान्य शुल्क की अदायगी के बिना रद्द नहीं किया जायेगा ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये समस्त प्रश्नों का उत्तर मैंने रेलवे बजट पर सामान्य बहस के समय दिया था। उस समय वह अनुपस्थित थे।

श्री लोबो प्रभु : न तो ये प्रश्न उठाये गये तथा न ही उनका उत्तर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं वह उनका उत्तर दे चुके हैं।

श्री लोबो प्रभु : पहले मैंने ये उठाये ही नहीं थे। ये तो बड़े साधारण प्रश्न हैं; यदि वह उत्तर दे भी चुके हैं तो फिर से दे दें।

श्री चे० मु० पुनाचा: माननीय सदस्य का सुझाव भविष्य में ध्यान में रखा जायेगा।

श्री हेम बरूआ : क्या आप उनसे पूछेंगे कि उन्होंने माननीय व्यक्तियों को अपनी सूची में लोक सभा के अध्यक्ष का नाम क्यों नहीं रखा ?

अध्यक्ष महोदय: श्री राम अवतार शास्त्री !

Shri Ram Avatar Shastri: The hon. Minister has just now enumerated from the list as to who are entitled to a saloon or a special carriage; but I know that the name of a D.S. in the Eastern Railways is not there in that list, although he also travels in a saloon or a special carriage. Whether the Railway Minister is aware of it? If not, and if this fact is established after an inquiry, will an action be taken against him ?

श्री के० मु० पुनाचा : यदि माननीय सदस्य मुझे कोई ब्यौरा लिख कर दें तो मैं इसकी जांच कर सकता हूं।

श्री सम्बन्धन : इस सत्य की दृष्टि से कि सैलून अथवा विशिष्ट डब्बों में यात्रा करने वाले अधिकारियों को यह नहीं मालूम कि तीसरी अथवा प्रथम श्रेणी के यात्रियों को क्या क्या सुविधायें देना अपेक्षित है तथा जो इसकी चिन्ता भी नहीं करते, तो ऐसे अधिकारियों को इन कठिनाइयों की जानकारी कराने के उद्देश्य से उन्हें कहा जायेगा कि वे हर वर्ष अथवा छः मास में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी के डिब्बों में यात्रा किया करें ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह एक सुझाव है मैं इसे देखूंगा।

Shri Rabi Roy: The hon. Minister has just now said that the officers and dignitaries travel by these 116 saloons. I want to know from the Hon. Minister as to what is cost of these saloons and what are annual expenses on their maintenance?

श्री चे० मु० पुनाचा : इन वातानुकूलित डिब्बों में से कुछ का मूल्य 1,40,000 रुपये है। दूसरे विशिष्ट श्रेणी के डिब्बे जो कि वातानुकूलित नहीं है उनका मूल्य 34,000 रू० से 40,000 रूपये के बीच है। इनमें अधिकतम तो बहुत ही पुराने हैं प्रायः 30 या 40 वर्ष पुराने ; तथा उनके रख-रखाव

पर भी अधिक खर्च नहीं होता क्योंकि दूसरे साधारण कोचों को भांति इनकी समय समय पर ओवरहाल नहीं की जाती ; सामान्य कोचों पर बड़ी लाइन के लिए तो 3,000 या 3,200 रु० तथा 2,400 से 2,800 रु० मीटर लाइन के लिये लागत आता है। जहां तक निरीक्षण-डब्बों तथा विशिष्ट निरीक्षण डब्बों का संबंध है ओवरहाल की लागत उन पर भी दूसरे डब्बों जितनी ऊंची नहीं है। यह बहुत ही कम है परन्तु उनके अलग-अलग आंकड़े मेरे पास इस समय नहीं हैं।

Shri Shashi Bhushan Bajpai: I want to know the names of those people who have been categorised for saloon entitlement. Besides that, have you included the Lok Sabha Speaker in that category..?

अध्यक्ष महोदय: आप विलम्ब से आये, वह तो बात हो चुकी।

एक माननीय सदस्य : नहीं से तो देरी भली।

अध्यक्ष महोदय : हमारी तेलुगु भाषा में एक कहावत है कि रैड्डी आयेगा तो आपको फिर से शुरू करना होगा।

Shri Kanwar Lal Gupta: The hon. Minister has just now read out the list of the modern kings who have a special privilege of saloon. I want to know whether it has come to his notice that these so-called dignitaries and officers travel in these saloons alongwith their families also? Have you arranged for such an inspection? If so, has any case of misuse of these saloons come to your notice ? If there are no arrangements for such inspection, will you arrange for it?

श्री चे० मु० पुनाचा : हम अवश्य इस पर ध्यान देंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta: Is there any arrangement for inspection or not? If not, will you do it?

श्री चे० मु० पुनाचा : प्रश्न यह है कि इन विशेष सैलूनों के दुरुपयोग की क्या कोई घटनायें हुई हैं...।

अध्यक्ष महोदय : क्या उनको परिवार भी साथ ले जाने की अनुमति है ? केवल यह प्रश्न है।

श्री चे० मु० पुनाचा : कुछ सम्माननीय व्यक्तियों को अपने परिवार साथ ले जाने का विशेषाधिकार रहा है।

Shri Valmiki Chaudhary: Mr. Speaker, with regard to the trend of the House in respect of the use of Saloons it seems that the use of saloons should be banned for all excepting the President. Will the hon. Minister consider it?

अध्यक्ष महोदय : "केवल राष्ट्रपति ही सैलून प्रयोग कर सकेंगे, इस पर क्या विचार किया जायेगा" यह प्रश्न है।

श्री चे० मु० पुनाचा : यह तो विचार करने योग्य मामला है ?

स्कूटरों का निर्माण

*689. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री ओ० प्र० त्यागी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटरों और इसी प्रकार की अन्य गाड़ियों की कमी को दूर करने के लिये उनका निर्माण बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) अन्य प्रकार के स्कूटरों और मोटर साइकिलों के निर्माण के लिये कितने नये लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ग) वर्तमान कारखानों में निर्माण बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या स्कूटरों और मोटर साइकलों के वर्तमान मूल्य कुछ कम होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

लोक सभा में 19-3-68 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० 689 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) और (ग) : स्कूटरों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने स्कूटरों के निर्माण के लिए एक और कारखाने को लाइसेंस देने का निर्णय किया है ।

इसके अतिरिक्त स्कूटर उद्योग को उन प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है जो अपनी स्थापित क्षमता का पूर्ण प्रयोग करने के लिये विदेशी मुद्रा पाने के हकदार हैं । आशा है कि उद्योग को विदेशी मुद्रा की सहायता दिये जाने से विद्यमान एककों में 1968 में स्कूटरों का उत्पादन 1967 की अपेक्षा काफी अधिक हो जायगा ।

(ख) यद्यपि स्कूटरों तथा मोटर साइकिलों के निर्माण के लिए नए लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं फिर भी आटोसाइकलों के उत्पादन के लिए पांच पार्टियों को आशय-पत्र जारी किए गए हैं । आशय-पत्र में निहित शर्तों को पूरा करने पर उन्हें औद्योगिक लाइसेंस दिए जायेंगे ।

(घ) विद्यमान एककों में अपेक्षाकृत कम उत्पादन होने के कारण निर्मित स्कूटरों की कीमत में निकट भविष्य में कमी होने की कोई संभावना नहीं है । अन्य बातों के साथ साथ इसका विचार भी करते हुए कि स्कूटर कम मूल्य पर उपलब्ध हो सकें, सरकार ने बचत करने की दृष्टि से बड़े पैमाने के एक और एकक को जिसकी क्षमता पर्याप्त रूप से अधिक हो, को लाइसेंस देने का निश्चय किया है । नई योजना को चुनने के लिए निर्धारित मापदण्डों में मूल्य भी एक माप दण्ड रखा गया है ।

श्री स० चं० सामन्त : स्कूटरों के मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है :—

> "विद्यमान एककों में अपेक्षाकृत कम उत्पादन होने के कारण निर्मित स्कूटरों की कीमत में निकट भविष्य में कमी होने की कोई सम्भावना नहीं है ।"

विद्यमान एकक तो हैं और हमने तीन-या चार वर्ष पूर्व सुना था कि उनकी स्थापित क्षमता 30,000 वार्षिक है परन्तु वे 19,000 से 20,000 का ही निर्माण करती हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि स्थापित क्षमता के अनुसार उत्पादन न करने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

औद्योगिक विकास तथा समवायकार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : जहां तक लाइसेंस क्षमता का सम्बन्ध है, स्कूटरों और मोटर साइकिलों को मिलाकर वह क्षमता 78,500 है तथा वर्ष 1967 में उन्होंने 65,695 का निर्माण किया। व्यक्तिगत रूप से मैं इसे काफ़ी अच्छा निर्माण समझता हूं तथा निर्माण सम्बन्धी कोई शिकायत नहीं कर सकते। अब हम उन्हें विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने के प्रबन्ध कर रहे हैं तथा वे अपने कार्य को अब बढ़ा भी सकेंगे।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सत्य नहीं है कि इस समय 2,50,000 की मांग है; यदि हां, तो फिर सरकार केवल 20,000 का उत्पादन करके ही कैसे चुप बैठ सकती है ? सरकार कहती है कि वह एक एकक स्थापित करेगी। क्या मैं जान सकता हूं कि इतने दिन तक यह एकक स्थापित क्यों नहीं की गई तथा क्या सरकार पश्चिमी बंगाल तथा सी० एम० पी० ओ० की सिफ़ारिशों पर विचार किया जायेगा ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य ने दो प्रश्न रखे हैं। एक मांग के बारे में है। जहां तक मांगों का सम्बन्ध है, तीसरी पंचवर्षीय योजना तक मांग का अनुमान 60,000 प्रति वर्ष था। चौथी योजना में 1,50,000 का निशाना रखा गया है तथा स्कूटरों व अन्य ऐसे ही परिवहनों के उत्पादन को मांगों के अनुसार विकसित कर रहे हैं। माननीय सदस्य का तो यह कहना है कि अब तक 2,50,000 स्कूटरों के क्रय-आदेश पड़े हैं। यह इसी कारण से है कि सरकार इस मांग को पूरा करने के लिये एक बड़ी एकक को लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

पश्चिमी बंगाल के विशिष्ट प्रस्ताव का जहां तक सम्बन्ध है, हमारे द्वारा विज्ञापन दिये जाने के पश्चात् 190 प्रार्थना-पत्र आ चुके हैं। इनमें से चयन-समिति ने 17 प्रार्थना-पत्रों का चयन किया है तथा इसके बाद एक उप-समिति का गठन किया गया है जो कि ऐसे तीन या चार सुझाव देगी ताकि उनमें से कम से कम एक या दो पर विचार किया जाये।

Shri Om Prakash Tyagi: As stated by the Hon. Minister that existing demand of about two lakhs is not being met and as such a Corruption is prevailing that Rs 3,000 are being charged over the actual price in black market. I would like to know from the Government whether such a scarecity of scooter is not owing to the lack of competition and owing to the monopoly of certain persons provided to them by the Government by giving licence only to them ; and also whether the Government proposes so often the policy of giving licences to the scooter companies so as to increase competition in the market as also the quality and number of scooters?

Shri F. A. Ahmed: The demand of about two and half lakh is not for scooters only but it includes auto cycles and motor-cycles also. At present we are giving licences to five-six people only which includes a licence for manufacturing 50,000 auto-cycles also. Letters of intent have been issued and those are in different states. I hope that the manufacture of auto-cycles

will also start and there shall be an expansion in the existing units too. And after giving two or three licences, the remaining demand will also be met.

Shri O. P. Tyagi: Why are you giving to only one or two? Why not to more?

Shri F.A. Ahmed: The reason is that we want to give the licence only to big units so that the productions may be on a large scale and resultantly the prices will be low and people will be able to purchase them at cheap rates.

श्री रा० बरुआ : वक्तव्य से विदित होता है कि उत्पादन में कमी विदेशी मुद्रा के न मिलने के कारण थी तथा अब सरकार पूर्णत: विदेशी-मुद्रा देने का विचार रखती है। यह क्या बात हुई कि सरकार यह अनुभव करती है कि उत्पादन पूरा होने पर स्कूटरों के दाम नहीं गिरेंगे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: इन एककों की लाइसेंस-क्षमता प्राय: 12,000 है। जब तक कि भारी संख्या में स्कूटरों का उत्पादन नहीं होगा, इन एककों के लिये दाम घटाना सम्भव नहीं। इसीलिये हम सोच रहे हैं कि लाइसेंस किसी ऐसे एकक को दें जो कि स्कूटरों को भारी संख्या में बनाये। इस तरह ही मूल्य घट सकते हैं।

Shri Maharaj Singh Bharati: (a) This Job of manufacturing scooters starts with importing parts and connecting them together which is known as assembling. and it is a consumer's industry which can be absorbed in the country itself. I want to know as to how many factories do you have here which do not import the parts and are manufacturing the scooter fully here ?

(b) In regard to your establishing further more new factories, will the Government see that these will form complete factories so that there is no import of parts. ?

Shri F.A. Ahmed: At present there are following ten factories whom me have granted Licences to manufacture scooter, auto-cycles and mopades:

1. M/s. Automobile Products of India Ltd., Bombay, whose indigenous production is about 91.2.%
2. M/s. Bajaj Auto Ltd., Bombay—94·80.%
3. M/s. Ideal Jawa (India) Ltd., Mysore, indegenous production: 87·08.%
4. M/s. Enfield India Ltd., Madras, indigenous production: 92·00.%
5. M/s. Escorts Ltd., New Delhi, indigenous productions: 87·08.

There are seven such companies which are using sufficient indigenous material and this indigenous material is increasing every year. At present we are not importing scooters excepting however, some components therefor; but we have started manufacturing those components also in India and we want to stop importing those components also as early as possible and we are trying to manufacture all the things here.

Shri Maharaj Singh Bharati: When will we complete it, in 100 years or ten years?

Shri F.A. Ahmed: We propose to complete it within the Fourth Five Year Plan.

श्री सूपाकर : कुछ तो ऐसे स्कूटर हैं जिनकी मांग बहुत अधिक है तथा कुछ इस प्रकार के हैं कि प्रत्यक्षत: उनकी मांग ही नहीं है। यदि उनके पास आंकड़े हैं तो क्या मैं जान सकता हूं कि इन विभिन्न प्रकार के स्कूटरों के लिये प्रतीक्षा करने वालों की सूची में

आदमियों की क्या संख्या है ? दूसरे, इन विभिन्न प्रकार के स्कटरों के पुरजों के लिये कितनी विदेशी मुद्रा नियत है ?

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : धन-राशि सम्बन्धी आंकड़ तो मेरे पास नहीं है परन्तु भारतीय माल से बने पुरजों का प्रतिशत मैं बता चुका हूं । पृथक् पृथक् प्रकार के स्कूटरों की मांग के बारे में भी मेरे पास आंकड़े नहीं हैं परन्तु जितना भी उत्पादन होता है, स ा बिक जाता है ।

श्री संघवीरा : क्या यह सत्य है कि वर्ष 1967 में स्कूटर-कारखानों के पास स्थापित-क्षमता का तथा पुरजों के आयात का लाइसेंस भी, परन्तु फिर भी वे अधिक उत्पादन न कर सके क्योंकि टायरों की कमी थी । यदि यह सत्य है, तो क्या स्थिति सुधार दी गई है तथा यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे कदम उठाये हैं ताकि ऐसी स्थिति फिर नहीं उत्पन्न हो ?

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : टायरों की कमी के बारे में मैंने कुछ दिन पूर्व सभा को जानकारी दी थी कि टायरों की कमी बम्बई की एक कम्पनी में लगातार हड़ताल रहने के कारण हुई थी । स्थिति में सुधार नहीं हुआ है बल्कि मुझे बताया गया है कि एक अन्य कम्पनी ने भी हड़ताल की धमकी दी है । अतः इस कमी को दूर करने के लिये दो-तीन महीने के लिये हमने टायरों के आयात की अनुमति दे दी है । जब तक कि हड़ताल की स्थिति में सुधार नहीं होता, मेरे लिये यह विश्वास दिलाना कठिन है कि किस सीमा तक हम टायरों की आवश्यकता पूरी कर सकेंगे ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य में कहा गया है कि आवश्यक विदेशी मुद्रा दिये जाने पर कारखाना अपनी स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग करेगा । ऐसी अवस्था में स्कूटरों के दामों में कमी की ओर क्या प्रभाव पड़ेगा ? दूसरे, स्कूटर की ठीक कीमत के निश्चय के बारे में सरकार का गैर-सरकारी क्षेत्र पर क्या नियंत्रण है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास मूल्यांकन-लेने का भी प्रबन्ध है ?

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : इस मामले पर विचार तो किया जा सकता है परन्तु मेरा अनुभव है कि ज्योंही हम इस मामले को किसी मूल्यांकन लेखकार अथवा दर-आयोग को सौंपते हैं, तो वे ऐसे आंकड़े देते हैं कि कम्पनी वालों के आंकड़ों से भी अधिक होते हैं । मूल्यों पर प्रभाव पड़ने के बारे में मैंने कहा है कि जब तक उत्पादन अत्यधिक मात्रा में नहीं होगा, उत्पादन मूल्य में कमी होना बहुत कठिन है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मैं जान सकता हूं :—(क) नियंत्रित मूल्यों की तुलना में स्कूटर का काले-बाज़ार में क्या मूल्य है, और (ख) इटली, जापान तथा ब्रिटेन जैसे देशों की तुलना में भारत में स्कूटर का क्या मूल्य है ?

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : मुझे नहीं मालूम कि कोई काला-बाजार भी होता है, अतः मैं नहीं कह सकता कि काले-बाजार में इसका क्या मूल्य है . . . . (व्यवधान)

Shri Madhu Limaye: Hon. Minister does not know what a black market is. He will know, it if he sits on the scooter.

Shri Maharaj Singh Bharati: It is Rs. 4,500.

श्री फ़ख़रूद्दीन अली अहमद : स्कूटरों के मूल्यों का जहां तक सम्बन्ध है, उत्पाद-शुल्क तथा अधिभार को छोड़ कर लैम्रैटा का मूल्य 2,388.63 रु०, वैस्पा का 2,402 रु० तथा फैन्टाबुलुस का मूल्य 3,200 रु० है।

Shri Madhu Limaye: What are there in Italy and Japan?

श्री फ़ख़रूद्दीन अली अहमद : इटली और जापान में जो स्कूटरों के मूल्य हैं, वे मेरे पास नहीं हैं।

Shri Madhu Limaye: Please get those and submit later on.

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि अन्य देशों की तुलना में भारत में स्कूटरों के क्या मूल्य हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने कहा है कि इनके पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इतने बड़े कर्मचारी-वृन्द के साथ इनका मंत्रालय क्या कर रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह मुझे नहीं बताना है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : महोदय, मेरे राज्य पश्चिमी बंगाल में प्रार्थी को स्कूटर के लिये वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जबकि उसी समय स्कूटर काले बाज़ार में मिल जाता है। यदि यह सत्य है तो क्या मंत्री महोदय इस पर विचार कर रहे हैं कि स्कूटर के उत्पादन का कार्य सरकारी क्षेत्र को भी सौंपा जाये ?

श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद : कल ही जबकि में कलकत्ता में था, वहां मुझे कलकत्ता की एक व्यवसाय-संघ द्वारा बताया गया स्कूटर का आदिरूप दिखाया गया। जैसा कि मैंने कहा, लाइसेंस के लिये 191 प्रार्थना-पत्र आये थे जिनमें से लाइसेंस-समिति 17 को ही इस कार्य के लिये लाइसेंस देने योग्य पाया। हमने फिर एक उप-समिति का गठन किया है जो कि लाइसेंस-समिति के समक्ष तीन अथवा चार प्रस्तावों को सरकार के निर्णयार्थ रखेगी।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : महोदय, सरकारी क्षेत्र में कारखाने सम्बन्धी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद : हमारे पास ऐसा कोई सुझाव नहीं है।

Shri Bal Raj Madhok: The Hon. Minister has just now said that he is not aware about the black marketing of scooters. He is not aware also as to how more costly a scooter is in India than in Italy and Japan. I mean that when the hon. Minister does not know about the black market of scooters in the capital or other parts of the country, then what does he know ? Else than that you have stated that the PlanningCommission has told you about the demand of scooters in the country, and also that as many as 50,000 engineers will be required whereas the same number of engineers are starving in the country. If the affairs are to be run on the advice of Plan-

ning Commission only, the Hon. Minister should then quit. The fact is that the price of a scooter in Italy is far less. My point is that when even the middle and low paid people need transports, then why is it so that first you constituted a commuittee and called for 117 applicants who were prepared to start factories for the purpose; later on you appointed another sub-Committee to select the applications again. Why do you adopt a dog in the manger policy and permit the opening of more factories?

Shri F. A. Ahmed: The Hon. Member has made several points and it does not depend upon his own opinion only whether I am fit or unfit. As regards the prices, these are not in public sector. They are in private sectors and being sold at their prices. They fix the prices with respect to their cost of production. As regards the difference in the price, I have said that . I cannot say as to how more those are since I do not have the figures at the moment. Moreover, not only scooters, but we are manufacturing other things alike also, and those too are in the same state of affairs. Our cost of production is high because we manufacture at a small scale, but in Italy or Japan it is less as they produce in large scale. As regards the demands, the Planning Commission, keeping a target, tells us about the quantum anticipated demand and supply and also about how much we should manufacture. After that it is manufactured. Regarding the grant of licences, I may say that it depends upon the availability of foreign exchange and to whom it should be afforded. If the whole of the Foreign exchange is given for scooters only; what will then be given for other things?

श्री लीलाधर कटकी : मंत्री महोदय ने कहा है कि टायरों के कारख़ानों में हड़ताल होने के कारण टायरों के आयात की अनुमति दी गई । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसे उपाय किये गये हैं कि हड़ताल को समाप्त कराया जाये तथा दुर्लभ विदेशी-मुद्रा को टायरों के निर्यात पर नष्ट होने से बचाया जाये जो कि यहां भी बन सकते हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: दोनों पक्षों को मिलाने तथा हड़ताल करने वालों, हड़ताल त्याग देने को राजी करने के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने क़दम उठाये हैं जबकि समाधान-मंडल द्वारा न्यायनिर्णय भी दिया जाना है, परन्तु मज़दूरों ने अपने काम पर वापस आने के बारे में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है ।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न । श्री चन्द्रशेखर सिंह ।

श्री क० ना० तिवारी : महोदय, यह प्रश्न न लिया जाये क्योंकि अब कोई बिहार सरकार नहीं रही है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रशेखर सिंह अनुपस्थित हैं । श्री भोगेन्द्र झा-अनुपस्थित । दोनों अनुपस्थित । अत: वह चिन्ता न करें, प्रश्न नहीं लिया जा रहा ।

संश्लिष्ट (नकली) धागे का आयात

*691. **श्री बलराज मधोक :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापर निगम जापान और इटली से संश्लिष्ट धागे के आयात के लिये इन धागों के मानकीकृत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से अधिक दान दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो मानकीकृत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य और आयात किये जाने वाले विभिन्न किस्मों के धागे के लिये दिये जा रहे मूल्यों में कितना अन्तर है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इससे देश को विदेशी मुद्रा की बहुत हानि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में हानि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) राज्य व्यापार निगम ने जापान तथा इटली से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर खरीद की है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Bal Raj Madhok: How should I take the reply given by the hon. Minister, should I call it a wrong reply or a white lie. May I know whether it is not a fact that a deputation of traders approached you a months ago and they were prepared to supply yarn at a cheaper rate than the rates at which state Trading Corporation buy yarn from foreign Countries, but you rejected their offer? May I know the reasons for not accepting the offer and the reasons for not placing the orders?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: The fact is that nylon has different varities and it goes from 15 Denier , 20 Denier, 40 Denier to 100 Denier and every varity has got different prices. It is possible that there may be difference in prices due to difference in varity. But it is not proper to say that we buy yarn at a higher rate from Japan. I would like to inform the hon. Member that the local yarn which we produce costs Rs. 125 per kilo gram and state trade Corporation supplies the yarn of 15 denier at Rs. 122. The yarn which we import from Japan and Italy costs Rs. 40/- or Rs. 41/- there after that 100% Custom Duty is imposed and 38% excise duty is charged and after-wards the storage expenditure comes in and thereby it costs about Rs. 120 per K.G., here.

Shri Bal Raj Madhok. : The hon. Minister has stated that the difference is not so much. I am to say that it is a different thing that what duty we impose over the International price today and the price at which we can purchase yarn. In comparison to that the price of the yarn supplied by State Trading Corporation is higher, it is somewhere 40% and at others 30% . If the Government do not agree with this then whether the hon. Minister is prepared to establish a Parliamentary Committee to enquire into the matter that how much yarn has been purchased, what is its international price and how much does it costs here? If the hon. Minister is not prepared for this then we will have to say that all he stated was wrong.

Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): Hon. Member is aware that we never refused to construct a Parliamentary Party but we always tiried that members of the Parliament should see whether the work we do is right or wrong. What we do in the Ministry is not hidden from anybody. So far as the prices are concerned I would like to make it clear. Whenever we import synthetic yarn from the foreign countries the price of yarn is different in different Countries. It is possible if we have bought yarns from United States when we imported it from Japan or from any other country, the price would have been little bit different. But from where we imported yarn we have used the money received under tied aid. We did not spend free foreign exchange currency. If we had done so then there would have been a little difference in the price. This is not true that the prices of yarn at that time were less in Countries from where we imported synthetic yarn, but the fact is that we imported the yarn at 15—20% less than the rate which they told us earlier. We have got full facts and figures of that. This is not true that we paid more than the price prevalent in that Country at that time.

श्री बलराज मधोक : मुझे मंत्री महोदय के उत्तर की सत्यता पर संदेह है। एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए और पूरे तथ्यों की जांच होनी चाहिए ।

श्री दामानी : गत दो वर्षों मे संश्लिष्ट (नकली) धागे के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है और बड़ी मात्रा में इसका तस्कर व्यापार हो रहा है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि इस धागे के आयात की क्या आवश्यकता है और यह किस कार्य में लाया जा रहा है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हमें एक करोड़ किलोग्राम संश्लिष्ट धागे की आवश्यकता है लेकिन हमारे यहां नाइलन के लिए जो तीन फैक्ट्रियां हैं उनमें केवल 24 लाख किलोग्राम संश्लिष्ट धागे का उत्पादन होता है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि हमे 60—70 लाख किलोग्राम संश्लिष्ट धागा बाहर से खरीदना पड़ेगा। क्योंकि मांग और पूर्ति के बीच बड़ा भारी अन्तर है इसलिए यह आवश्यक है। नई फैक्ट्रियां भी खुल रही हैं। इसलिए हम नाइलन धागे का आयात कर रहें है क्योंकि हमारे कताई और बुनाई का कार्य करने वाले कर्मकारों को इसकी आवश्यकता है। अगर हम धागे का आयात न करें तो उद्योग की उपलब्ध क्षमता का पूर्ण उपयोग न हो सकेगा तथा बेरोजगारी पैदा होगी।

Shri Madhu Limaye: May I know whether the attention of the Government have been drawn towards this fact that the factories which are at present preparing nylon and synthetic yarn in the Country are earning a lot of profit as it is mentioned in a report of J.K. Group that there was a profit of four crores on the sales of 7 crores. If this profit would have been used for increasing production then possibly there would have been no necessity of imports. Simultaneously I would like to know whether the Government are aware that State Trading Corporation earns adequate profit over the imported yarn with the result that its price in the market is high and due to this very reason a large quantity of nylon yarn is also brought in the Country through smuggling? Is it not one of the reasons that there is no customer for the yarn imported by S.T.C.? If the hon. Minister will accompany me I will make him available nylon yarn in the areas like Daman. It is possible only when he accompanies me.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: So far as the adequate profit earning and nylon yarn manufacturing factories are concerned I would like to say that the fact is that they are no trunning under loss but they are certainly earning some profit.

So far as the question of importing yarn is concerned I have already stated that the yarn is imported because there is shortage of yarn and the local supply is also inadequate.

Shri Madhu Limaye: You do not keep information?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: So far as the profit is concerned, it is a natural phenomenon that when there is shortage of supply and the demand is more than the price naturally goes high. To meet the demand we are importing yarn and factories are also being established so that nylon prices may come down.

Shri Madhu Limaye : My question has not been answered. State Trading Corporation charges high profit at his nylon yarn which has encouraged smuggling and as a result of it nylon yarn is coming into the country in such a large scale that the yarn of S.T.C. is not being sold. I have stated the hon. Minister accompanies me I am ready to get those smuggler on the whole Western border caught.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: So far as the question of smuggling is concerned it cannot be denied that some nylon yarn is being smuggled. So far as the charging of high prices by the State Trading Corporation is concerned I would like to draw the attention of the hon. member to the fact that whereas the price of local synthetic yarn of Narela and J.K. is Rs. 125 per kilo fifteen lineur (1)...

Shri Madhu Limaye: Bring them also down.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: The price of synthetic yarn of State Trading Corporation is Rs. 120 to Rs. 122 per K.G. which means it is selling at Rs. 4/- or Rs. 5/- less than the price of local synthetic yarn. State Trading Corporation does not earn much profit by it. But State Trading Corporation wants if the supply increases and prices come down than the prices of local synthetic yarn will also come down.

श्री शंकरानन्द : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि संश्लिष्ट (नकली) धागे का आयात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मांग की पूर्ति में बड़ा भारी अन्तर है और नये कारखाने भी खुल रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि वे नये कारखाने कौन से हैं जिनके लिए धागे का आयात किया जा रहा है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : माननीय सदस्य धागे को कपड़ा कहकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। मैंने नाइलन धागे के निर्माण के बारे में कहा न कि नाइलन कपड़े के बारे में।

श्री विक्रम चन्द्र महाजन : क्या यह सच है कि नये संयन्त्रों की स्थापना के लिए प्राप्त कई आवेदन पत्र अभी अनिर्णीत पड़े हैं, यदि हां तो अभी तक अनुज्ञा क्यों प्रदान नहीं की गयी ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह मामला सरकार के विचाराधीन है तथा इस पर निर्णय किया जायेगा ।

Shri Prem Chand Verma: Hon. Minister has just stated that there is a profit of 4 crores to a Company on the sale of 7 crores. No reply has been given by the hon. Minister to it. May I know what steps the Government want to take to check the profiteering by the monopolists? Is it not true that S.T.C. does not reduce the price of yarn so that their profit may not lessen.?

May I know what percent of profit S.T.C. earns over the yarn?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: So far as the private company and its profit is concerned no reply can be given at this time but so far as the S.T.C. is concerned I have already stated that it is not selling for profit but it is importing to meet the short supply of yarn in the country....

Shri Prem Chand Verma: What profit it keeps?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: Very little. I think it will not be more than one per cent.

श्री रंगा : वे कितना लाभ कमा रहे हैं ? आप साफ-साफ क्यों नहीं बताते ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए उन्हें पूर्व सूचना चाहिए ।

Shri Hardayal Devgun: Hon. Minister must be having some knowledge about the economics of nylon yarn. Synthetic fibre is purchased at Rs. 5 per Kilo and its yarn is sold at Rs. 125 per kilo by the Mills here. Instead of checking profiteering they kept the price at Rs. 120 of the yarn imported by S.T.C. Somebody says that it is earning 30% profit, some says 500%and in this profiteering it is competing with the factories established here. Due to this reason the nylon yarn imported by S.T.C. is lying in its store and these is no customer to buy it. May I know whether it is a fact?. I would also like to know that it is not a fact that an enquiry is being made against the officials of S.T.C. that they have kept the foreign exchange in the foreign banks?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: So far as the question of yarn by ying in the Stores of S.T.C. is concerned I would like to inform the hon. member that whereas licence worth Rs. 6 crores were issued the goods worth Rs. 5 crores and 30 lacs have arrived and the division of that is as below:

Power Looms Sector	Rs. 4 crores and 18 lacs.
Co-operative Sector	Rs. 43 lacs.
Handloom Sector	Rs. 33 lacs.
Hosiery Sector	Rs. 36 lacs.

This division has been made. It is clear from it now that there is no stock lying with State Trading Corporation.

श्री कृष्णमूर्ति : देश मे लगभग ५ करोड़ रुपये का ब्लीडिंग मद्रास है जिसका उत्पादन विदेशों को निर्यात के लिए किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : नाइलन से ब्लीडिंग मद्रास पर आ गये ! (व्यवधान)

श्री कृष्णमूर्ति : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या संश्लिष्ट धागे के आयात के स्थान पर कोई फर्म ब्लीडिंग मद्रास की न बेची गयी सम्पूर्ण मात्रा का निर्यात करने के लिए तैयार है, यदि हां, तो सरकार पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई ?

श्री मुहम्मद कुरेशी : प्रश्न ब्लीडिंग मद्रास से सम्बधित है । यह सत्य है कि हम प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये के, इस विशेष किस्म के ब्लीडिंग मद्रास का निर्यात कर रहे हैं लेकिन निर्यात कर्त्ताओं की अत्यधिक ईर्ष्यालु प्रकृति के कारण यू०एस०ए० में एक बड़े भारी स्टाक का संचय हो गया था और निर्यात घट कर 10 लाख से 15 लाख रुपये तक आ गया है । मद्रास में बड़ा भारी स्टाक जमा है जिसके लिए एक पार्टी निर्यात करने के लिए तैयार भी हो गयी थी लेकिन उसकी शर्तें बड़ी अजीब थी । पार्टी का कहना था कि वह सारा माल लेकर उसका निर्यात कर देगी लेकिन उसको 100 परसेंट नाइलन यार्न का आयात करने की अनुज्ञा मिलनी चाहिए जिससे वह इसको यहां 300 से 400 परसेंट अधिमूल्य (प्रीमियम) पर बेच सके । हमने उसकी स्वीकृति नहीं दी ।

श्री रंगा : क्या सरकार यह सूचना देगी, यदि इस समय नहीं तो बाद में सही आदि क्या इसे सभा पटल पर रेखेगी कि राज्य व्यापार निगम (एस०टी०सी०) जापान तथा अन्य देशों से किस मूल्य पर नकली धागे, संश्लिष्ट धागे को खरीदती है तथा यहां किस कीमत पर बेच रही है और उसे कितना लाभ हो रहा है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जितना देश में उत्पादन होता है उससे दुगना यह आयात तथा सम्भरण करती है इसे इस स्थिति में होना चाहिए कि कीमतों को इतना कम कर दे कि बिना अधिक लाभ कमाये यह ग्राहकों को उपलब्ध हो सके, कीमतें विद्यमान मूल्यों से कम होनी चाहिएं । माननीय मित्र ने बताया है कि वे कारखानों के मूल्य से 2 या 3 रुपये कम लेते हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कारखानों को अत्यधिक लाभ हो रहा है वे कीमतों को कम क्यों नहीं कर देते ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : जिस भाव पर हमने इस यार्न को खरीदा है मेरे माननीय सहयोगी ने उसका कुछ अनुमान किया है, बात यह है कि जब हम इस संश्लिस्ट धागे को बाहर से खरीदते हैं तो हमे 100% कर तथा 38 परसैंट उत्पाद शुल्क देना पड़ता है और इस से संश्लिष्ट धागे की कीमत मे वृद्धि हो जाती है । मेरे माननीय मित्र श्री मधु लिमये ने तस्कर व्यापार का प्रश्न उठाया । वास्तव में तस्कर व्यापार द्वारा प्राप्त संश्लिष्ट धागा इन करों से मुक्त है और इसीलिए इस के भाव में असन्तुलन है । अब प्रश्न यह है कि जो संश्लिष्ट धागा आयात किया जाता है और जो यहां बनाया जाता है उस के भावों में अन्तर है तथा जो भी वस्तु आयात की जाती है उसके और स्थानीय उत्पादित वस्तु के भावों में अन्तर रहता है । इसका कारण

यह है कि वहां बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और इस से मितव्ययिता के कारण उन्हें लाभ होता है तथा लागत कम पड़ती है, यदि हम आयातित मूल्य पर धाग को बेचना आरम्भ कर दें तो क्या होगा ? यदि हम ऐसा करने लगें तो यह धागा बाजार मे पुन: बिकने लगेगा और चोर बाजारी को बढ़ावा मिलेगा । हमने सभा में इस प्रश्न पर विचार किया था। राज्य व्यापार निगम (एस० टी० सी०) समवायों के मूल्यों से कम मूल्य लेने तथा उनको बनाये रखने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं...

श्री रंगा : वे इस से भी कम मूल्य पर बेच सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye: Bring down the prices of J.K. etc.

श्री दिनेश सिंह : यह बिल्कुल भिन्न बात है, हम इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं कि स्थानीय कीमत कितनी अधिक होनी चाहिए हम इसका ध्यान रखेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अब अल्प सूचना प्रश्न पर आइये ।

श्री नम्बियार : 'लैफ्ट कम्यूनिस्ट नागा' नाम से क्या तात्पर्य है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता हूं । मंत्री महोदय बतायेंगे ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैंने नहीं जाना कि माननीय सदस्य स्वयं ध्यान में निमान थे और इसीलिए उन्हें इस बात का पता नहीं चला ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अल्प सूचना प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं।

अल्पसूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

कुल्टी में इस्पात ढलाई कारखाने का जमीन में धंसना

+

अ० सू० प्र० 10. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : **श्री रविराय :**
श्री निहाल सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल के निकट लोहा तथा इस्पात कम्पनी का इस्पात ढलाई कारखाना शीघ्रता से जमीन मे धंस रहा है, ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है जिस से पूर्ण इस्पात कारखाने को क्षति न पहुंचे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

बताया गया है कि 9 मार्च, 1968 को 9.30 तथा 10 मार्च, 1968 को 11 बजे के बीच जिस स्थान पर मैसर्स इण्डियन प्लाइरन एण्ड स्टील कम्पनी कुल्टी की इस्पात फाउंड्री स्थित है उस में कई जगहों पर दरारें दिखाई दीं । इस बीच कई जगहों पर एक फीट से लेकर 3 फीट की गहराई तक जमीन धंस गई थी। 10 मार्च 1968 को 9 बजे के बाद और जमीन धंसने की कोई घटना नहीं हुई ।

जमीन धंस जाने के फलस्वरूप ढलाई घर के कुछ ढांचों को नुकसान पहुंचा और वे कई जगहों से झुक गये। खानों के मुख्य निर्देशक ने जमीन धंसने के कारणों का पता लगाने के लिए एक विशेष दल नियुक्त कर दिया है और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । पश्चिम बंगाल सरकार के उप मुख्य कारखाना निरीक्षक , आसनसोल भी इस मामले की जांच कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मंत्री महोदय ने हमें विश्वास दिलाया है कि खानों के मुख्य निदेशक ने जमीन धंसने के कारणों का पता लगाने के लिए एक विशेष दल नियुक्त किया है । मैं जानना चाहती हूं कि इस समय कारखाने को कितनी क्षति हुई है तथा सरकार कौन से कदम उठाना चाहती है जिस से कि कारखाने की सरंचना को और अधिक क्षति न हो ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: कारखाने में प्रतिदिन 35,000 रुपये के मूल्य का उत्पादन होता है । जहां तक इस्पात ढलाई कारखाने के जमीन में धंस जाने के कारण क्षति निर्धारण का प्रश्न है, हमने इस कार्य के लिए विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया है तथा उस के रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । रिपोर्ट मिलने पर ही यह बताना सम्भव हो सकेगा कि वास्तविक हानि कितनी हुई है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार अथवा समवाय को इस बात की पूर्व सूचना थी कि जहां ढलाई घर बनाया है उस क्षेत्र में खनन कार्य हुआ था तथा इसके परिणामस्वरूप वहां भूमि के एक बड़े भाग में अन्दर से रिक्तता उत्पन्न हो गई थी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : अगर समवाय को इसकी पूर्व सूचना होती तो वह ढलाई घर वहां कभी न स्थापित करती । जहां तक इस्पात कारखाने से सम्बन्धित दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, जो कि महत्वपूर्ण भी है, मैं बताना चाहता हूं कि इस्पात कारखाना इस स्थान पर नहीं है बल्कि यह बर्नपुर में है जो कि ढलाई घर से 10—12 मील की दूरी पर है ।

Shri Rabi Ray: Will the hon. Minister be pleased to state that how many workers have been laid off due to the sinking of Steel foundry plant near Asansol, and what provision has been made to give them employment and whether any damage has been caused to the railway line which goes by the side of the foundry and who is the owner of that steel foundry?

Shri F.A. Ahmed: So far as the labour is concerned 530 workers were laid off and they have beeen given lay-off compensation. Out of them 100 workers have been given work at another place. No retrenchment has been made there. It is being looked into that how the rest of the labourers should be given work. The railway line which goes by the side of the foundry has also been damaged.

Shri Deven Sen : Whether it is a fact that there are three huge Collieries namely East Victoria, West Victoria and Ramnagar Colliery of two Companies on both the sides of this foundry; and two years back a whole pipe factory and a village were sunk, if so whether the hon. Minister will make an enquiry as to whether proper sand stowing is done in the Collieries and whether the foundry and factory have sunk because there is no proper sand stowing.

Shri F. A. Ahmed: The Suggestion given will be looked into.

श्री रा० बरुआ : यह ढलाई घर कब पूर्ण हुआ था और तब से लेकर अब तक, क्या क्षति के कोई चिन्ह पता लगाये गये हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसे कि मैं बता चुका हूं कि यह ढलाई घर इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड का था । इसलिये मैं इस ब्योरे से अनभिज्ञ हूं कि यह कब पूर्ण हुआ अथवा कब आरम्भ हुआ ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री रविराय को उत्तर देते हुये मंत्री महोदय ने कहा कि 500 मजदूर बेरोजगार हो गये थे और उनमें से कुछ को कुछ दूसरा काम दे दिया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि उनको बेरोजगारी के कारण उनकी मजदूरी का केवल 50 क्षतिपूर्ति के तौर पर क्यों दिया गया जब कि इसमें उनका कोई दोष नहीं ? क्या सरकार नियुक्ता मालिक को राजी करेगी कि वह मजदूरों को पूरी मजदूरी दे क्योंकि यह दैवी संकट था और उनके बस से बाहर था ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मजदूरों की बेरोजगारी के कारण जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जा रही है । प्रबन्धक उनको दूसरे कामों में नियोजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं । 100 मजदूरों को पहले ही काम दिया जा चुका है । मैं देखूंगा कि कितनी और सहायता इनको दी जा सकती है ।

इस विषय से संबंधित जो ताजी सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसे मैं बताना चाहता हूं ।

"कुल्टी में इस्पात ढलाई कारखाने के जमीन में धंसने से सम्बन्धित जाँच कार्यवाही चल रही है । रिपोर्ट तैयार की जा रही है । स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, केवल इसके कि 13 तारीख के बाद भूमि धंसना रुक गया है । यह आशंका है कि मानसून में भूमि कुछ और धंसेगी । कारखाने के प्रबन्धकों ने क्षतिग्रस्त वर्कसाप से तैयार वस्तुओं को उठाना आरम्भ कर दिया है । प्रबन्धकों की रेलवे लाइन को जो क्षति हुई थी उसे पुनः ठीक किया जा रहा है ।"

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न मजदूरों को पूरी मजदूरी देने से सम्बन्धित था । उन्हें बेकारी का भत्ता दिया गया है । विशेष अधिनियम के अन्तर्गत बेकारी के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पर मजदूरी का 50 प्रतिशत दिया जाता है । यह केवल उन मामलों में होता है जब कोई ऐसी आकास्मिकता आ पड़ती है कि या तो माल उपलब्ध नहीं होता अथवा हड़ताल हो जाती है या कोई और

ऐसी ही बात हो जाती है लेकिन यहां इसके सम्बन्ध में न तो प्रबन्धकों द्वारा कारखाना बन्द किया गया और न ही मजदूरों द्वारा कोई हड़ताल की गयी। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि मजदूरों को पूरी मजदूरी क्यों नहीं दी गयी। क्या सरकार इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को इस बात के लिए राजी करेगी कि वह मजदूरों को पूर्ण मजदूरी दे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं कम्पनी के प्रबन्धकों से इस बात पर चर्चा करूंगा ।

श्री शंकरानन्द : कारखाने के जमीन में धंसने के कारण, उसकी जाँच के लिए जो विशेषज्ञों का दल नियुक्त किया गया है क्या उन के रिपोर्ट देने के लिए कोई समय निर्धारित किया गया है अथवा वे अपनी इच्छा से अपने समय के अनुसार रिपोर्ट देंगे जिसके दौरान कारखाने को और भी अधिक हानि हो सकती है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं ।

श्री समर गुह : सरकार को तथा हम सबको कुल्टी में इस्पात ढलाई कारखाने के जमीन में धंसने की एक चेतावनी के रूप में समझना चाहिए। आप जानते हैं कि आसनसोल उप-प्रभाग में एक कोयला-खनन क्षेत्र है तथा एक बड़ा औद्योगिक संश्लिष्ट भी है । कुल्टी ढलाई कारखाने के जमीन में धंस जाने के कारणों का पता लगाने की बजाय क्या सरकार कोयले की खानों के निकटवर्ती क्षेत्रों में अन्य औद्योगिक संश्लिष्टों के धंस जाने और कोयला खनन क्षेत्रों में कुओं की उपस्थिति से उत्पन्न खतरे की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक व्यापक जाँच करेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जब मुझे प्रतिवेदन मिलेगा तब उस समय उस पर विचार करते हुए मैं माननीय सदस्य के सुझावों को ध्यान में रखूंगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Licences for Mica Mines

Shri ChanderaShekhar Singh :
Shri Bhogendra Jha:

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1292 on the 20th February, 1968 and state:

(a) Whether the present Government of Bihar have decided to reconsider the question of issuing licences for mica mines;

(b) Whether Government have wirtten to the Bihar Government to follow their previous directions, and

(c) if so, the result thereof?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy): (a) Yes Sir.

(b) Yes Sir.

(c) The State Government have since reconsidered the matter and have passed orders restoring the lease hold properties to the Indian Mica Supply Company pending final decision of the revision applications by the Central Government.

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से कच्चे माल का आयात

*692. **श्री कृ० मा० कौशिक : औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 नवम्बर, 1967 को हुई लघु उद्योग बोर्ड की बैठक में विभिन्न राज्यों के कुछ लघु उद्योगों ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम अथवा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कच्चे माल का आयात करने का विरोध किया था क्योंकि इसमें लागत बहुत आती है और प्रासांगिक व्यय बहुत होता है; और

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योगपतियों द्वारा सीधा आयात करने के सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) लघु उद्योग बोर्ड की बैठक में लघु उद्योगपतियों द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार विचार कर रही है ।

भारतीय माल के निर्यात के संबंध में प्रचार

*693. **श्री हिम्मत सिंहका : औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने फ्रांस समेत विदेशों का दौरा करते समय यह अनुभव किया था कि भारतीय माल के निर्यात के संबंध में प्रचार-कार्य बहुत कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी मंडियों में व्यापार प्रचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या-क्या मुख्य कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों का एक साथ-संघ स्थापित किया जाय तथा हमारे देश की औद्योगिक गतिविधियों के बारे में सारी आवश्यक जानकारी देने की व्यवस्था करने के लिये और विदेशों की मंडियों की स्थिति का पता लगाने के लिए विदेशों में संयुक्त दल नियुक्त किये जायें, ताकि इन स्थितयों के अनुसार समय-समय पर हमारे उत्पादन तथा आयोजना में संशोधन किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस सुझाव के अनुसार क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री खफरुद्दीन अली अहमद :

(क) अपनी विदेश यात्रा के दौरान मेरी ये धारणा बनी कि जिन देशों में मैं गया था उनमें से कुछ देशों में जिनमें फ्रांस शामिल है, भारत से आयात की सम्भावनाओं विशेषकर तैयार माल के बारे में प्राप्त जानकारी नहीं है । इस जानकारी का न होना ही इन देशों

को हमारा निर्यात बढ़ाने के मार्ग में बाधक रहा है और जो कुछ हम बानते हैं उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कराने में हमारा निर्यात बढ़ने में सहायता मिल सकती है ।

(ख) वाणिज्य मंत्रालय इस बारे में पूरी तरह सजग है । वस्तुतः आयोजन-कार्य को आगे बढ़ाने और मार्ग दर्शन करने तथा विभिन्न माध्यमों के द्वारा निर्यात प्रचार संबंधी कार्यक्रमों को लागू करने में उस मंत्रालय ने अक्तूबर, 1966 में एक स्थायी निर्यात प्रचार सलाहकार समिति बनाई थी । इस समिति की रिपोर्ट मिल गई है । समिति ने कारगर और व्यावहारिक निर्यात प्रचार कार्यक्रम तैयार करने तथा उसे समन्वित रूप में कार्यान्वित करने के लिए कई सिफारिशें की हैं । उनकी जांच उस मंत्रालय द्वारा की जा रही है ।

(ग) मेरा विचार यह है कि भारत में हम किन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और किन वस्तुओं का हम निर्यात कर सकते हैं, शेष रूप से निर्मित माल का, इस बारे में विदेशों के खरीददारों को जानकारी प्राप्त कराने के लिए एक संगठन की आवश्यकता है जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के प्रतिनिधि हों । इस प्रकार का संगठन समय-समय पर विदेशों को दल भेजने का प्रबन्ध कर सकता है जो हमारे औद्योगिक विकास में रुचि रखने वाले मित्र देशों को जानकारी दे सकते हैं और वहां तैयार माल की खपत का पता लगा सकते हैं । इस प्रकार की खपत के बारे में जानकारी मिलने से हमें निर्यात के लिए अपने उत्पादन का आयोजन करने में सहायाता मिलेगी । विदेशों में अपने निर्मित माल का प्रदर्शन करके और निर्मित पदार्थ को जैसे मशीनी औजार तथा मशीनों को विदेशों में उपलब्ध माल गोदाम की सुविधा का इस्तेमाल करके उनमें सामान इकट्ठा करने से निर्यात बढ़ाने के काम में भी सहायता मिल सकती है ।

(घ) मेरे विचार वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विचार किये जाने के लिए उस मंत्रालय की जानकारी में लाए गए हैं ।

पटसन की वस्तुओं के न्यूनतम निर्यात मूल्य

*694. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन मिल संघ इस बात की निरंतर मांग करता आ रहा है कि पटसन की वस्तुओं के निम्नतम निर्यात मूल्य निर्धारित किये जाने चाहियें ;

(ख) क्या यह मांग विदेशों की मंडियों में प्रतिस्पर्धा का मुकाबिला करने के हित में है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) भारतीय पटसन मिल संघ ने पटसन की वस्तुओं के न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित करने का सुझाव दिया है जो विचाराधीन है ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने

Public Sector Steel Plants

*695. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state:

(a) whether it is a fact that strikes and go-slow movements have been going on in the Public Sector Steel Plants due to continuing labour disputes which had resulted in substantial loss of production ; and

(b) if so, the action taken by Government to find out permanent solution of labour disputes in the steel plants in the Public Sector?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy): (a) Yes, Sir. Illegal strikes, gheraoes, stoppages of work, slow-downs etc., have affected the working of the Rourkela and the Durgapur Steel Plants seriously during the year 1967-68.

(b) The question of having an arrangement by which a truly representative union of worker could be recognised in each Steel Plant as the sole bargaining agent empowered to negotiate all collective and general issues with the Management and the estsblishment of a manchinery of Joint Standing Committees for securing settlement of industrial disputes by negotiation, conciliation etc.,has been recently discussed wtih the representatives of the Central Trade Unions. Further consultations and discussions will be necessary for arriving at agreed arrangements.

महाराष्ट्र में ट्रैक्टर कारखाना

*696. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में एक ट्रैक्टर कारखाना लगाने की कोई योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

हैदराबाद और हरिद्वार में हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट

*697. **डा० रानेन सेन :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में हैदराबाद और हरिद्वार में बिजली का भारी सामान बनाने के कारखानों के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इन कारखानों पर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या देश में सरकारी क्षेत्र में विद्यमान बिजली के सामान बनाने के तीनों कारखानों के लिए एक सांझा प्राधिकार बनाने का सरकार का विचार है, ताकि उनका निर्माण, विस्तार और अग्रेतर विकास शीघ्रता से किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) हैदराबाद संयंत्र में निर्माण-कार्य, कुछ छोटी-मोटी समापन संबंधी चीजों को छोड़कर शेष लगभग पूरा हो चुका है।

फरवरी, 1968 के अन्त तक हरिद्वार के संयंत्र में फाउन्ड्री ब्लाक को छोड़कर मुख्य कारखाने के ब्लाकों में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। फाउन्ड्री ब्लाक की नींव तथा खम्भे डाले जा चुके हैं। आक्सीजन तथा एसिटलीन संयंत्रों की, कम्प्रेसर शाला, गैस उत्पादन शाला, संयंत्रों की केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा तापीय बिजली घर की इमारतों के निर्माण में अच्छी प्रगति हुई है।

(ख) इन परियोजनाओं पर दिसम्बर, 1967 के अन्त तक निर्धारित व्यय निम्नलिखित है :—

हरिद्वार	53.30 करोड़ रु०
हैदराबाद	32.84 करोड़ रु०

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मसालों के प्रसिद्ध आयातकर्त्ता

*698. **श्री मधु लिमये :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय लौंग, इलायची, जायफल आदि के राज्यवार कितने प्रसिद्ध आयातकर्त्ता हैं;

(ख) क्या बिहार में ऐसे कोई आयातकर्त्ता हैं ; और यदि नहीं, तो वे अपनी आवश्यकता का माल कहां से तथा किस मूल्य पर प्राप्त करते हैं ;

(ग) क्या इस बारे में भारत सरकार को राज्य सरकार, व्यापारी संस्था आदि से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) क्या भारत सरकार समूचे देश में व्यापारियों को इन मसालों का समान आधार पर आवंटन करने की कोई योजना बना रही है ताकि एकाधिकार, मुनाफाखोरी आदि की प्रवृत्तियों को रोका जा सके; और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये एल० टी० 497/68]।

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि इस समय स्टाक तथा बिक्री के लिए आयातों की अनुमति नहीं दी जा रही है अतः वितरण पद्धति बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे वाणिज्य क्लर्क संस्था का ज्ञापन

*699. **श्री विश्वनाथ मेनन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में अखिल भारतीय रेलवे कामर्शियल क्लर्क संस्था से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनकी मांगें पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हां ।

(ख) वाणिज्य क्लर्कों की मांगें निम्नलिखित हैं :—

(1) वेतन-मान और पदक्रम में संशोधन ;

(2) अपंग कर्मचारियों को किसी पद पर लगाना ;

(3) अधिकृत वेतन-मानों की वार्षिक वेतन-वृद्धियों में सुधार ;

(4) क्वार्टरों के नियतन के उद्देश्य से वाणिज्य क्लर्कों को "अनिवार्य" कोटि में रखने की प्रार्थना ;

(5) पदोन्नत्ति की सारणी ;

(6) वाणिज्य क्लर्कों के आवधिक स्थानान्तरण संबंधी नीति ;

(7) चिकित्सा यूनिट से एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहने वाले वाणिज्य क्लर्कों के लिये चिकित्सा भत्ते की व्यवस्था ;

(8) रोकड़ सम्हालने का काम करने वाले वाणिज्य क्लर्कों को रोकड़ भत्ता देना ; और

(9) काम के घंटे विनियमनों को लागू करना ।

(ग) इन मांगों की फिर से जांच की गयी है और उनमें से कुछ मांगों पर संगठित श्रम संगठनों के साथ बातचीत के परिणामस्वरूप फिर से विचार किया जा रहा है ।

खनन तथा संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड

*700. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन तथा संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड का पनर्गठन करने तथा सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के इंजीनियरों तथा कोयला खनन विशेषज्ञों को उससे संबद्ध करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) निर्माण कार्यों में विविधता लाने की कितनी गुंजाइश है और वर्ष 1967 में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) बिक्री को बढ़ाने के लिए खनन उपकरणों के लिए बाजार का सर्वेक्षण करने के लिये आरम्भ किये गये कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) इस बारे में कोई भी नया प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

(ख) माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन में विविधता लाने की गुंजाइश की कई उच्च भारतीय तथा रूसी विशेषज्ञों ने जांच की है और उनका विचार है कि यदि डिजाइनों के प्रालेख उपलब्ध हों और कुछ संतुलन उपकरणों को और जोड़ दिया जाए तो यह व्यापक इंजीनियरी एकक बन सकता है । परीक्षाधीन वर्ष में कम्पनी ने कोयला धोने की मशीनें तथा साइक्लोन जो कि कोयला धोने के लिए आवश्यक होता है, के निर्माण के लिए पोलैंड की एक फर्म के साथ एक सहयोग करार किया

और दूसरा सहयोग करार हालैंड की फर्म से किया है। कुछ वस्तुओं जैसे प्रौद्योगिकी ढाचे, खान में काम आने वाले उपकरणों आदि के बोकारो इस्पात कारखाने को सम्भरण करने के लिए आर्डर प्राप्त किए गये। ये वस्तुयें इसके उन्पादन के मौलिक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं थी। बन्दरगाहों पर खनिज पदार्थ लाने, ले जाने के उपकरणों के संभरण के लिए पूछताछ की जा रही है।

(ग) कम्पनी द्वारा प्रारम्भ किये गये बाजार के सर्वेक्षण के काम के बारे में ब्यौरा अभी उपलब्ध कहीं है। यह इकट्ठा किया जा रहा है और सभा-पटल पर र दिया जायगा।

पाकिस्तान में भारतीय नागरिकों की नकदी का हस्तांतरण

*701. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय नागरिकों की पाकिस्तान में विभिन्न बैंकों में पड़ी नकदी और पाकिस्तान सरकार के पास चल सम्पत्ति के हस्तांतरण के बारे में पाकिस्तान सरकार के साथ कोई समझौता कर सकी है ;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय नागरिकों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई अचल सम्पत्ति के मुआवजे की शर्तों को तय कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग). दोनों देशों द्वारा कब्जे में ली गई समस्त सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों की वापसी के प्रश्न पर ताशकन्द घोषणा के अनुच्छेद 8 की शर्तों के अनुसार बातचीत करने के लिये भारत सरकार अब भी पाकिस्तान सरकार से आग्रह कर रही है। अतः ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिकों को, जिनकी सम्पत्तियाँ पाकिस्तान द्वारा जब्त कर ली गयी हैं, किसी प्रकार का मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात सौदों के बारे में जांच समिति

702.	**श्री जुगल मंडल:**	**श्री श्रीगोपाल साहू :**
	श्री स० कुण्डू:	**श्री वेणी शंकर शर्मा :**
	श्री कंवर लाल गुप्त :	**श्री रवि राय ।**
	श्री भारत सिंह चौहान:	**श्री चेलराया नायडू :**
	श्री योगेन्द्र शर्मा :	**श्री ज्योतिर्मय बसु :**
	श्री स० मो० बनर्जी:	**श्री ही० ना मुकर्जी :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 20 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1235 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात सौदों के बारे में जाँच करने के लिए नियुक्त समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) से (ग) . जी, हाँ समिति की रिपोर्ट मिल गई है और सरकार के विचाराधीन है । जैसे ही कोई निर्णय किया जायेगा, रिपोर्ट सहित सरकार के संकल्प की एक प्रति सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

टाईरों का लदान

Shipment of Tyres

*703. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Trading Corporation had directed M|s. Ram Kishan Kulwant Rai in their letter dated the 13th October, 1961 to defer shipment till the stock of tyres held at that time was disposed of;

(b) if so, whether it is also a fact that no step was taken by Government to prevent the receipt of any further consignments of tyres; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Public Accounts Committee which enquired into STC's tyre deal have already been informed that the firm had entered into firm commitment with the Hamburg suppliers for the import of 40,000 sets and for which they had also established letter of credit. As the consignment was lying in Rijeka port incurring demourrages, STC permitted the imports, at the same time pointing out to the firm that the responsibility for sale would be that of the firm.

हुगली सोलापुर सैक्शन के स्टेशनों का अपर कृष्णा परियोजना-योजना के जल में डूब जाना

704. **श्री अगाड़ी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण मध्य रेलवे में हुगली-सोलापुर सेक्शन पर सीतामनी और अलमाटटी रेलवे स्टेशन पर अपर कृष्णा परियोजना-योजना के पानी में डूब रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो रेल लाइन का कितना क्षेत्र पानी में डूबेगा तथा कितनी रेलवे लाइन अन्यत्र बनाई जायेगी ;

(ग) क्या कोई नई वैकल्पिक रेलवे लाइन के रेखांकन के लिए सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा हुगली-शोलापुर लाइन के कितने रेलवे स्टेशनों पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा और कृष्णा नदी पर किन किन स्थानों पर नये रेलवे पुल बनाये जायेंगे ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचाः) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 20 किलोमीटर रेलवे लाइन दो टुकड़ों में पानी में डूब जायेगी और उसे कहीं और जगह ले जाना पड़ेगा ।

(ग) और (घ). इस मार्ग-परिवर्तन के संबंध में अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । इस लाइन-के मार्ग परिवर्तन की लागत मैसूर सरकार द्वारा वहन की जायेगी और जब मैसूर सरकार सर्वेक्षण के खर्च के अनुमान पर अपनी सहमति दे देगी, सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया जायेगा । प्रभावित स्थानों और नये कृष्णा पुल के स्थान से संबंधित ब्यौरे का पता तभी लग सकेगा, जब सर्वेक्षण का काम पूरा हो जायेगा ।

रेलवे द्वारा खरीदे गये कोयले की चोरी के कारण हानि

705. **श्री वामानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा खरीदे गये कोयले की चोरी से रेलवे को होने वाली हानि का सरकार ने अनुमान लगाया है ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड को पता है कि रेलवे कर्मचारी रेलवे के कोयले का खूब प्रयोग करते हैं और आरक्षिगण इस चोरी को रोकने में असफल रहे हैं ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड को पता है कि चोरी किया गया कोयला इसके सामान्य मूल्य से आधे दामों पर बाजार में बेच दिया जाता है ; और

(घ) लोको के कोयले के स्टाक की चोरी तथा उसके दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कोयले की उठायी गीरी के कारण रेलवे को वास्तव में कितनी हानि होती है, इसका ठीक ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(ख) रेल कर्मचारियों द्वारा कोयले की उठाईगीरी की घटनाएं हुई हैं । रेल कर्मचारियों को उचित दरों पर कोयला और सिडर देने की व्यवस्था भी मौजूद है । इस संबंध में रेलवे सुरक्षा दल भी चौकसी रखता है और दल ने बहुत से कोयला चोरों को गिरफ्तार किया जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	की गयी गिरफ्तारियाँ		
	बाहरी व्यक्ति	रेल कर्मचारी	जोड़
1965	5149	544	5693
1966	5339	476	5815
1967	5740	542	6282

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) अधिकांश महत्वपूर्ण कोयला शेडों, कोयले के चट्टों और खत्तों पर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं ।

(2) जिन खंडों पर चोरियाँ होती हैं या होने की आशंका रहती है उन पर कोयला ले जाने वाली स्पेशल गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा दल का पहरा रहता है ।

(3) अभ्यस्त कोयला चोरों/उठाईगीरों और कोयले की चोरी की अनदेखी करने वाले रेल कर्मचारियों पर गुप्त रूप से निगाह रखी जाती है ।

(4) महत्वपूर्ण यार्डों में सशस्त्र दस्ते और पहरेदार नियुक्त किये गये हैं ताकि यार्डों में खड़े माल डिब्बों से चोरी न हो ।

(5) कोयला उतारने-चढ़ाने वाले मजदूरों के पूर्व वृत्त की जाँच करने पर जोर दिया जा रहा है ।

(6) रनिंग शेडों में कोयले के ठीक तरह चट्टे लगाने पर ज़ोर दिया जाता है ।

अल्यूमिनियम स्मैल्टर तथा शीट मिल

*706. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन अल्यूमिनियम कम्पनी का एक नये अल्यूमिनियम स्मैल्टर और एक शीट मिल की स्थापना के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा की कमी को पूरा करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से 30 लाख डालर ऋण लेने की अनुमति के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो किन आधार पर; और

(ग) इस परियोजना को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): (क) से (ग) इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता ने अगस्त 1967 से 30 लाख डालर का एक ऋण प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ बातचीत करने के लिए सरकार की आज्ञा माँगी। इस ऋण की आवश्यकता बेलगाँव (मैसूर) से कम्पनी के नये एल्यूमिनियम प्रद्रावक और महाराष्ट्र राज्य में एक नयी रोलिंग मिल के लिए धन की सम्भावित कमी को पूरी करने के लिए थी। भारत सरकार ने कम्पनी के बेलगाँव प्रद्रावक और महाराष्ट्र की रोलिंग मिल के लिए 135 लाख डालर (अर्थात लगभग 10.125 करोड़ रुपये) तक की विदेशी मुद्रा लगाये जाने के प्रस्तावों का पहिले ही अनुमोदन कर दिया था। विभिन्न उपकरणों के देश में ही अधिक उपलब्धि के कारण यह समझा गया कि कम्पनी को 10.125 करोड़ रुपये की राशि, जिस की व्यवस्था पहिले ही हो चुकी है, के अतिरिक्त और विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी। अत: कम्पनी को कहा गया कि वह रोलिंग मिल के लिए आवश्यक उपकरणों का ब्योरा शीघ्र सरकार को दे। कम्पनी ने अब सूचित किया है कि उन्हें रोलिंग मिल के लिए विदेशी मुद्रा की अतिरिक्त रकम की आवश्यकता नहीं होगी।

रेलवे अफसरों के लिये सैलून

*707. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों पर कितने "सैलूनों" का प्रयोग रेलवे अधिकारियों द्वारा किया जाता है;

(ख) इन सैलूनों की पूंजीगत लागत क्या है तथा इनकी देखभाल पर कितना धन व्यय होता है;

(ग) इन सैलूनों में किन सेवाओं तथा उपकरणों की व्यवस्था की जाती है; और

(घ) जिन अफसरों को सैलून दिये जाते हैं क्या उनके यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते में कोई कटौती की जाती है ?

रेलवे मंत्री (श्री वे० मु० पुनाचा): (क) भारतीय रेलों में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और जनता द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले 16 वातानुकूल/अवातानुकूल सैलूनों और विशेष ढंग की 116 पर्यटन कारों के अतिरिक्त लगभग 628 चौपहिये, 58 छ: पहिये और 352 बोगी निरीक्षण यान हैं।

(ख) अलग-अलग निरीक्षण यानों की पूंजीगत लागत विभिन्न तथ्यों जैसे निर्माण की तारीख, टाइप, प्रामान आदि पर निर्भर है। वर्तमान बोगी और चौपहिये निरीक्षण यानों की औसत पूंजीगत

लागत अनुमानत: बड़ी लाइन पर क्रमश: 54,000 रु० और 34,000 रु०, मीटर लाइन पर 38,000 रु० और 18,000 रु० और छोटी लाइन पर 21,000 रु० और 6,000 रु० है। निरीक्षण यान रेलों के कोचिंग स्टाक के अंग हैं जिनके अनुरक्षण के लिए राजस्व व्यय के अन्तर्गत लेखे का केवल एक शीर्षक (नं 2100) है।

(ग) निरीक्षण यानों में अलग-अलग ढंग के उपस्कर की व्यवस्था रहती है। सोने, भोजन पकाने और कार्यालय के काम से सम्बन्धित सुविधाओं के अलावा कुछ निरीक्षण यानों में देखभाल और सफाई करने वाले कर्मचारी और एक स्टेनोग्राफर के लिए भी स्थान की व्यवस्था रहती है।

(घ) निरीक्षण यानों में यात्रा करने वाले रेल अधिकारियों का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता वर्तमान सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नियत किया गया है।

केरल में मोटरगाड़ी पुर्जा निर्माण कारखाना

†708. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चैकोस्लोवाकिया की सहायता से एक मोटरगाड़ी पुर्जा निर्माण कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई करार किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) केन्द्रीय सरकार को ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

†709. **श्री नम्बियार :** **श्री पो० राममूर्ति :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री रमानी :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों ने 27 फरवरी, 1968 से हड़ताल करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं; और

(ग) इस विवाद को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) यह ठीक है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने की एक यूनियन—हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन ने (जिसे अखिल भारतीय मजदूर संघ का समर्थन प्राप्त है) 12 फरवरी, 1966 को प्रबन्धक-वर्ग को 27 फरवरी, 1968 को अथवा अगले छः सप्ताहों में किसी भी दिन एक दिन के लिए हड़ताल करने का नोटिस दिया था।

(ख) हड़ताल के नोटिस में मुख्य माँग यह की गई थी कि मर्चेन्ट मिल के कर्मचारियों का ले-आफ तत्काल हटाया जाय जिससे वे काम पर वापिस जा सकें।

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार के संयुक्त श्रम-आयुक्त द्वारा आयोजित 11 मार्च, 1968 की त्रिदलीय समझौता-वार्ता में, हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन ने उन घटनाओं के लिए खेद प्रकट किया जिनके कारण 31 दिसम्बर, 1967 से मर्चेन्ट मिल के उत्पादन में कमी हुई जिससे मर्चेन्ट मिल के कर्मचारियों को जबरन छुट्टी की की गई थी, इस बात का आश्वासन दिया कि मिल को पुनः चालू करेंगे और सामान्य रूप से कार्य करेंगे और हड़ताल का नोटिस वापिस लेंगे। प्रबन्धक-वर्ग इस बात पर राज़ी हो गया कि मर्चेन्ट मिल के जिन मज़दूरों को जबरी छुट्टी दी गई थी उन्हें 13 मार्च, 1968 से काम पर वापिस आने दिया जायेगा और निलम्बन-आदेश वापिस ले लिये जायेंगे और मर्चेन्ट मिल के 21 निलम्बित मज़दूरों को जिनको नियमों के अन्तर्गत चार्ज-शीट दिये गये हैं, चार्ज-शीटों की जाँच पर किसी किस्म के प्रतिकूल प्रभाव के बिना काम पर वापिस आने दिया जायेगा। सरांधन-अधिकारी ने आश्वासन दिया कि यूनियन के दिनांक 12 फरवरी, 1968 के माँग-पत्र में जो अन्य औद्योगिक विवाद उठाये गये हैं उन्हें भी समझौता-वार्ता द्वारा निपटाया जायेगा।

रेलवे को कोक और कोयले की सप्लाई

*710. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने चालू वर्ष के लिए रेलवे को कोक और कोयले की सप्लाई के लिये जनवरी, 1968 में मंगाये गये टैंडरों को न खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सभी गैर-सरकारी कोयला खानों के मालिकों ने आपस में मिलकर ऊंची दरें बताई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) टैंडर रद्द कर दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

रेलवे कर्मचारियों को यात्रा सम्बन्धी सुविधायें

711. **श्री लोबो प्रभु :**
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री शिवप्पा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब रेलवे कर्मचारी ऊंचे दर्जे में यात्रा करना चाहते हैं तो उनको दोनों दर्जों के किराये के अन्तर का तीसरा भाग देना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप डिब्बों में भीड़ हो जाती है और अन्य यात्रियों को असुविधा हो जाती है;

(ख) जब रेलवे यात्री अपने यात्रा रद्द करते हैं तो क्या उनसे साधारण यात्रा रद्द शुल्क लिया जाता है क्योंकि इससे रेलवे को हानि होती है और अन्य यात्री अपनी यात्रा नहीं कर पाते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी नहीं, केवल उन राजपत्रित अधिकारियों को, जिनके पास पहला दर्जा "ए" का पास होता है, पहले दर्जे और वातानुकूल दर्जे के किराये के अन्तर का एक तिहाई किराया देने पर वातानुकूल डिब्बे में यात्रा करने की अनुमति दी जाती है।

(ख) और (ग). जो रेल कर्मचारी, गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से पहले 24 घंटे के अन्दर सुविधा पास पर किया गया आरक्षण रद्द करते हैं या आरक्षण में परिवर्तन करना चाहते हैं तथा जो अपना आरक्षण रद्द नहीं कराते या आरक्षित स्थान का उपयोग नहीं करते उन्हें निर्धारित मान के अनुसार प्रभार देना पड़ता है।

छोटी कार परियोजना

*712. **श्री तुलसीदास जाधव** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी कार परियोजना के सम्बन्ध में 1962 में स्थापित किये गये पांडे आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख). माननीय सदस्य सम्भवतः पांडे समिति का उल्लेख कर रहे हैं जिसे 1960 में देश में कम मूल्य की कार बनाने की सम्भाव्यताओं की जांच करने के लिये बनाया गया था। समिति का प्रतिवेदन 1961 में प्राप्त हुआ था। समिति ने यह विचार व्यक्त किया था कि 50,000 संख्या तक प्रति वर्ष उत्पादन करने पर कार का कारखाने से चलते समय का मूल्य 5,100 रुपये प्रति कार होगा और यदि उत्पादन 20,000 संख्या तक प्रति वर्ष हो तो इसका कारखाने से चलते समय का मूल्य 6,150 रुपये प्रति कार होगा और दोनों ही दशाओं में उत्पादन-शुल्क इनके अतिरिक्त होगा। इसने यह भी सिफारिश की थी कि फ्रांस की कम्पनी मेसर्स रेनाल्ट की "डाडफिन" नमने की कार बनाने की पेशकश आर्थिक तथा तकनीकी दृष्टियों से सबसे अधिक आकर्षक थी। 1962 में, जैसा कि लोक-सभा में 9 अगस्त को दिये गये वक्तव्य में बताया गया था, कम मूल्य की कार बनाने की परियोजना पर विचार तब तक के लिये स्थगित कर दिया गया था जब तक देश में वास्तव में उपलब्ध साधनों जैसे निर्माण-सामग्री, इस्पात, विद्युत् तथा परिवहन सम्बन्धी स्थिति अनुकूल नहीं हो जाती।

मोटर कार किस्म जांच समिति का प्रतिवेदन

*713. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव** : **डा० म० संतोषम**
श्री शिवप्पा : **श्री अ० वीपा** :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री 13 फरवरी, 1968 के अतारांकित

प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटरकार किस्म जांच समिति के 1967 के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख)सरकारी संकल्प सहित पाण्डे समिति की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि जिसमें रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों पर सरकार के निर्णय दिये गये हैं, 16-2-1968 को सभा-पटल पर रख दी गई थी ।

मध्य प्रदेश में पन्ना खाने

*714. **श्री महंत दिग्विजय नाथ :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मध्य प्रदेश में पन्ना खनन क्षेत्र में हीरों के योजनाबद्ध उत्पादन का काम अपने हाथ में ले रही है;

(ख) यदि हां, तो आयोजित ढंग से कब उत्पादन आरम्भ होगा;

(ग) हीरों का उत्पादन अनुमानतः कितना होगा; और इससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाने की सम्भावना है; और

(घ) वहां कितने मूल्य की मशीनरी लगी हुई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :(क) से (ग). राष्ट्रीय खनिज विकास निगम प्रति वर्ष क्रमशः 12,000 और 11,250 कैरेट हीरों का उत्पादन करने के लिये पन्ना की माझगवन और रामखेड़िया खानों की विकास कर रहा है । इन खानों के क्रमशः जुलाई 1968 और जनवरी 1969 तक चालू होने की आशा है । यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं कि इन हीरों की बिक्री से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ।

(घ) इन खानों के लिये संयंत्र और मशीनरी की लागत का अनुमान 31.40 लाख रुपये है ।

जूता उद्योग में मशीनों का प्रयोग

*715. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बने जूतों की मांग विदेशों में बहुत घट गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस उद्योग में मशीनों का प्रयोग न किया जाना भी मांग घटने का एक कारण है;

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग में मशीनों के प्रयोग की व्यवस्था करने के लिये अब तक क्या प्रयत्न किये गये थे अथवा किये जा रहे हैं; और

(घ) इन प्रयत्नों का क्या परिणाम निकला है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) अप्रैल से नवम्बर, 1967 में गत वर्ष की अपेक्षा चमड़े के जूतों के निर्यात में कुछ कमी हुई है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). चमड़े के जूते बनाने का उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में होने के कारण इसके एककों का मशीनीकरण करने के लिये सरकार द्वारा कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के जरिये लघु एककों को किराया-खरीद योजना के अधीन आयातित मशीनें दी जा रही हैं। निर्यातोन्मुख एककों को मशीनों का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस के रूप में आवश्यक सहायता दी जाती है। भूतपूर्व निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत कुछ एककों ने आधुनिकीकरण/सन्तुलन/प्रतिस्थापन के लिये मशीनें आयात की हैं।

सूक्ष्म औजार कारखाने को पालघाट से कोटा के जाया जाना

*716. **श्री श्रीधरन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सूक्ष्म औजार कारखाने को पालघाट, केरल से कोटा, राजस्थान में स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). उद्योग में समूचे विनियोजन में भारी कटौती किये जाने तथा यंत्रों की अनुमानित आवश्यकता में कमी होने के कारण सरकार ने इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के कोटा, राजस्थान तथा पालघाट, केरल के दो एककों के उत्पादन के प्रश्न पर पुनः विचार किया है। कोटा एकक जिसका निर्माण कार्य पूरा होने को है और जिसमें शीघ्र ही उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है, को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने के लिये सरकार ने ऐसा आवश्यक समझा है कि पालघाट के मशीनी यंत्रों के संयंत्र को फिलहाल स्थगित किया जाय और कुछ अतिरिक्त विनियोजन करके पालघाट एकक के यंत्रों का उत्पादन भी कोटा एकक में ही किया जाय। यह और भी अत्यावश्यक हो गया है क्योंकि इन दोनों संयंत्रों के यंत्रों का क्षेत्र एक दूसरे का अनुपूरक है। इस पर तथा इससे सम्बन्धित मामलों पर अन्तिम निर्णय अभी किया जाना है।

रूस को जूतों का निर्यात

*717. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस को घटिया किस्म के जूतों का निर्यात किये जाने के कारण भारत का बाजार घट रहा है और भारतीय माल के स्थान पर पाकिस्तान, ब्रिटेन तथा अन्य देशों के माल की मांग बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो गुण प्रकार नियंत्रण सुनिश्चित करने, रूस में बाजार बनाये रखने और जूतों के निर्यात के लिये पूर्वी यूरोप के बढ़ते हुए बाजारों में अपने माल की मांग बढ़ाने हेतु सरकार ने किया कार्यवाह की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) सर्वोत्तम किस्म के उपलब्ध सामान का प्रयोग करने के लिये और ऐसे कदम उठाने के लिये भारत में प्रयत्न किये जा रहे हैं जिनसे हमारे प्रतियोगियों द्वारा सप्लाई किये जाने वाले जूतों की अपेक्षा हमारे जूतों की किस्म और फिनिश अच्छी हो। राज्य व्यापार निगम में एक डिजाइन तथा गवेषणा अनुभाग है जो ऐसे नमूने बनाने में लगा हुआ है जिनकी किस्म एवं बनावट विदेशी खरीदारों को स्वीकार्य हो। जूतों के उत्पादन के विभिन्न चरणों का पर्यवेक्षण करने के लिये उन्होंने एक निरीक्षणालय की स्थापना की है। रूस को निर्यात किये जाने वाले जूतों की किस्म में सुधार के सम्बन्ध में सोवियत विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया गया है।

माचरेला और नागार्जुनसागर के बीच यात्री यातायात

4269. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार माचरेला और नागार्जुनसागर के बीच माल-यातायात के साथ-साथ जो कि इस समय वहां चालू है यात्री यातायात भी आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं।

(ख) माचेरला नागार्जुनसागर रेलवे साइडिंग आंध्र प्रदेश सरकार की मलकीयत है। इस लाइन पर सवारी गाड़ियां चलाने के लिये रेलवे को इसे अधिग्रहण करना पड़ेगा, रेल-पथ को फिर से बनाना होगा और बड़ी भारी रकम खर्च करके दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। इस समय इस साइडिंग का अधिग्रहण करने और इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये यातायात सम्बन्धी औचित्य नहीं है।

दक्षिण एक्सप्रेस

4270. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1968 से एक महीने पहले और एक महीने बाद जिस तारीख

को दक्षिण एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाई गई थी उस समय हैदराबाद और दिल्ली के बीच कितने यात्रियों ने यात्रा की; और

(ख) आरम्भ किये जाने से अब तक यह रेलगाड़ी कितनी बार समय पर चलती रही ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अलग-अलग गाड़ियों या सवारी डिब्बों के लिये आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते ।

(ख) 68 दिनों में, जब से इन गाड़ियों का चलना शुरू हुआ, (10 मार्च, 1968 तक) 22 अप नयी दिल्ली-हैदराबाद दक्षिण एक्सप्रैस 29 दिन ठीक समय पर हैदराबाद पहुंची और हैदराबाद से नयी दिल्ली आने वाली नं० 21 डाउन एक्सप्रैस 5 दिन ठीक समय पर नयी दिल्ली पहुंची ।

हैदराबाद में सरकारी क्षेत्र में उद्योग

4271. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में सरकारी क्षेत्र में केन्द्रीय सहायता से कितने उद्योग चल रहे हैं;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है और कितनी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं; और

(ग) उनकी पूर्णता के लिये राज्य सरकार ने किन-किन सुविधाओं की व्यवस्था की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

ट्रैक्टरों का मूल्यों

4272. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 से 35 अश्वशक्ति वाले पहियेदार ट्रैक्टरों का मूल्य बहुत ऊंचा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इनके मूल्य कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) यह कहना ही नहीं होगा कि देश में निर्मित पहियेदार ट्रैक्टरों के मूल्य बहुत अधिक हैं । फिर भी, इन ट्रैक्टरों के मूल्य इसी नमूने के आयातित ट्रैक्टरों के मूल्य की अपेक्षा अधिक हैं ।

(ख) उत्पादन लागत में कमी करने के लिए उत्पादकों को अपने उत्पादन को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

देश में निर्मित ट्रैक्टरों के उचित विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकारी लागत लेखा परीक्षा अधिकारियों ने ट्रैक्टर बनाने के एककों की लागत सम्बन्धी जाँच की थी। इन सिफारिशों के आधार पर देश में इस समय बन रहे सभी प्रकार के वर्तमान विक्रय मूल्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिये गये थे। दूसरी रोक के रूप में तटकर आयोग से भी औपाचारिक जाँच करके उचित विक्रय मूल्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए निवेदन किया गया था। आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उसकी जाँच की जा रही है।

चाय बोर्ड

4273. श्री बाबूराव पटेल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में देश के विभिन्न केन्द्रों में कुल कितनी या कितने मूल्य की चाय खरीदी गई ; और

(ख) इसी अवधि में कुल कितनी तथा कितने मूल्य की चाय का निर्यात किया गया और किन-किन देशों को किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) एक विवरण (अंग्रेज़ी में) संलग्न है जिसमें जानकरी दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 498/68]**

चाय बोर्ड

4274. श्री बाबूराम पटेल: : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में चाय-बोर्ड के प्रबन्ध पर कुल कितना खर्च आया और इसकी शाखाएं अथवा प्रतिनिधि कहाँ-कहाँ हैं;

(ख) चाय बोर्ड के बीस सर्वोच्च अधिकारियों को कितना-कितना वार्षिक वेतन तथा यात्रा भत्ता दिया जाता है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में उपरोक्त अधिकारियों में से प्रत्येक के नाम सहित किन-किन तारीखों को विदेशों के दौरे किये और वे किन-किन देशों में गये और प्रत्येक दौरे पर कितना खर्च आया और भारतीय तथा विदेशी मुद्रा के रूप में कितना विमान भाड़ा देना पड़ा ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष चाय बोर्ड ने भारत तथा विदेशों में प्रचार तथा विज्ञापनों पर कितना धन खर्च किया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) से (ख) : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे में चोरियां

4275. श्री बाबूराम पटेल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों में रेलगाड़ियों में चोरी तथा डाकुओं द्वारा रेलगाड़ियों को रोक कर लूट लिये जाने की राज्यवार कुल कितनी घटनायें हुईं तथा उन गाड़ियों के नाम क्या हैं और ये घटनायें किन रेलवे लाइनों पर हुईं ;

(ख) कुल कितने व्यक्ति, पुरुष तथा स्त्रियाँ, हताहत हुए और कुल कितने मूल्य की सम्पत्ति चुराई गई ;

(ग) रेलगाड़ियों में, राज्यवार, प्रतिदिन रेलवे सुरक्षा पुलिस दल के कुल कितने कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किये जाते हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ चोरियाँ और गाड़ी रोक कर लूट की जाने की घटनायें रेलवे सुरक्षा दल के कुछ सदस्यों की सहायता और मिलीभगत से की गई थीं और यदि हाँ, तो उक्त अवधि में रेलवे सुरक्षा दल के कितने कर्मचारी पकड़े गये और उन्हें क्या दण्ड दिया गया ; और

(ङ) रेलगाड़ियों को रोक कर लूट लिये जाने से रोकने के लिए तथा रेलगाड़ियों का निर्बाध चलना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) से (घ). सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। अपेक्षित सूचना इकट्ठी करने में बहुत अधिक श्रम करना पड़ेगा ।

(ङ) रेल परिसरों में कानून और व्यवस्था बनाये रखना तथा रेल सम्पत्ति और यात्रियों तथा रेल कर्मचारियों के जीवन तथा उनकी सम्पत्ति की संरक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार तथा रेलवे पुलिस की है। फिर भी, विभिन्न स्तरों पर उनके साथ आवश्यकतानुसार गिकट सहयोग रखा जाता है ।

तेल तथा तिलहनों के वायदे के सौदे

4276. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 दिसम्बर, 1967 को अथवा इसके आसपास वणिज्य मंत्रालय के प्रवर्तन विभाग ने हैदराबाद और सिकन्दराबाद में किन-किन फर्मों पर छापे मारे थे, उनके मालिकों के नाम क्या हैं और तेलों तथा तिलहनों के गैर-कानूनी वायदे के सौदों में पाये गये साक्ष्य का स्वरूप क्या है और उनसे कितनी नकदी जब्त की गई ;

(ख) गैर-कानूनी व्यापार से संबंधित कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे अन्य नगरों में भी बड़े पैमाने पर ऐसे गैर-कानूनी सौदे हो रहे हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो इन गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) वायदा बाजार आयोग के प्रवर्तन निदेशालय के कहने पर आन्ध्र राज्य की पुलिस ने 20 दिसम्बर, 1967 को मूंगफली के तेल में कथित अवैध वायदा व्यापार तथा वस्तुओं के आपशन के सौदों के सम्बन्ध में हैदराबाद की 10 फर्मों के स्थानों पर छापा मारा

छापे में 46,116 रु० नकद तथा अभिशंसी कागजात पकड़े गये। चूंकि मामले की अभी जाँच की जा रही है अतः फर्मों तथा उनके मालिकों के नाम बताना वाँछनीय नहीं है। पकड़े गये कागजातों की जाँच करने के बाद ही पता लग पायेगा कि इन मामलों में किस प्रकार के साक्ष्य हैं तथा किस प्रकार के उल्लंघन किये गये हैं। सिकन्दराबाद में कोई छापे नहीं मारे गये।

(ख) छापे में 50 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। चूंकि मामले की अभी जाँच चल रही है अतः उनके नाम बताना वाँछनीय नहीं होगा। वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अधीन इन में से उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिनके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किये गये अपराध का अभिशंसी साक्ष्य मिल जायेगा।

(ग) बम्बई तथा कलकत्ता के बारे में अवैध वायदा व्यापार होने की सूचनाएं मिली हैं लेकिन मद्रास के बारे में नहीं।

(घ) राज्य पुलिस तथा वायदा बाजार आयोग का प्रवर्त्तन निदेशालय, अवैध वायदा व्यापार पर नजर रखता है और वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य पुलिस प्रवर्त्तन निदेशालय की सहायता से सम्बद्ध पार्टियों के विरुद्ध कार्यवाही करती है।

भारत में निर्बाध पत्तन

4278. **श्री किरुत्तनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने निर्बाध पत्तन हैं और उन के नाम क्या हैं;

(ख) इन निर्बाध पत्तनों के कृत्य क्या हैं और उन्हें अब तक कितना लाभ अथवा घाटा हुआ है; और

(ग) क्या सरकार भारत के दक्षिणी भाग में, विशेष रूप से मद्रास राज्य में, कोई निर्बाध पत्तन स्थापित करने का विचार कर रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारत में कोई भी निर्बाध पत्तन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

तिरुपति रेलवे बुकिंग आफिस से मुद्रा की चोरी

4279. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के तिरुपति रेलवे बुकिंग आफिस से हाल ही में दिन के समय 1500 रुपये की चोरी हो गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सभी रेलवे स्टेशनों पर क्या सुरक्षा उपाय किये गये हैं?

रेलवे मंत्री (श्री के० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस मामले की रिपोर्ट फौरन रेनिगुन्टा सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन को कर दी गयी थी, जिन्होंने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380/447/379 के अन्तर्गत इस मामले को अपराध सं० 84/68 के रूप में दर्ज कर लिया । अभी इसकी जाँच हो रही है ।

इस मामले से जिन पेशेवर अपराधियों का सम्बन्ध हो सकता है उनकी जासूसी के लिए राज्य पुलिस द्वारा विशेष खुफिया दल तैनात किये गये हैं ।

(ग) नकदी रकम की हिफाजत के सम्बन्ध में जो हिदायतें जारी की गयी हैं उनका कड़ाई से पालन करने के लिए सभी स्टेशन मास्टरों को सजग कर दिया गया है । राज्य पुलिस द्वारा अपराधियों के अड्डों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ।

New Industries in Rajasthan

4280. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs be** pleased to state :

(a) the number of licences issued by Government for the setting up of new industries in the private sector in Rajsthan during the last two years ; and

(b) the names of the persons and firms to whom licences have been given and the names of such industries ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Four.

(b) A statement is given below.

STATEMENT

Sl. No.	Names of the persons/firms to whom licences have been granted	Industries for which the licences have been granted.
1	2	3
1	Shri Gurudeo Khemani, Calcutta	Cotton Yarn.
2	M/s. The Rajasthan Cotton Press (P) Ltd., Sriganganagar.	Cotton seed Oil.
3	Shri S. P. Gupta [M/ Beldla Flour Mills & Allied Industries (P) Ltd], New Delhi.	Wheat Products.
4	M/s. Shri Keshoraipatan Sahakari Sugar Mills Ltd., Jaipur.	Sugar.

Separate Railway Zone For Rajasthan

4281. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that leaders of Rajasthan have demanded the creation of a separate Railway zone for Rajasthan ;

(b) whether it is also a fact that Government have accepted the demand ; and

(c) if so, the broad details thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

Publication of "Indian Railways 1966-67"

4282. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the reasons for using inferior quality of paper for the Hindi version of 'Indian Railways' 1966-67" vis-a-vis its English version ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : In spite of our best efforts to maintain same standards in the English and Hindi versions, we were confronted with limitation in our resources in the Hindi publication which could not be surmounted.

Retirement Rules in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi.

4283. Shri J. Sundar Lal : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the rules regarding the grant of superannuation pension are applicable to the staff of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi ;

(b) if so, the date of their application and whether some employees were retired before these rules were applicable ;

(c) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken by the Khadi and Village Industries Commission in this regard ; and

(d) whether these rules are applicable in other Semi-Government business establishments also ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Safi Qureshi) : (a) No, Sir. The staff of the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi are governed by the Khadi & Village Industries Commission (Contributory Provident Fund) Regulations, 1958.

(b) to (d). Do not arise.

Khadi Workers' Conference, Panipet.

4284. Shri J. Sundar Lal : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the total amount spent on the Khadi Workers' conference held at Panipet in March, 1968 under the auspices of the Khadi and Village Industries Commission ;

(b) the number of Khadi workers and supporters of khadi who attended the said conference ; and

(c) the advantages which accrued as a result of the said conference ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

विशाखापत्तनम में निर्बाध व्यापार क्षेत्र

4285. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा औद्योगिकीकरण की गति तेज करने के लिए निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने तथा विशाखापतनम जैसी बन्दरगाहों में निर्बाध व्यापार की अनुमति देने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार का विचार कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र के परिणामों की प्रतीक्षा करने का है जिसकी प्रगति पर इस समय नजर रखी जा रही है ।

रेलवे कर्मचारियों की भरती

4286. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री नम्बियार :
श्री चक्रपाणि :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई भरती पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद से 500 रुपये मासिक तथा उससे अधिक वेतन मान के सभी रेलों पर कितने कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

टिटेनिया उत्पाद उद्योग समूह के लिये संयुक्त राष्ट्र सहायता

4287. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बड़े टिटेनियम उत्पाद उद्योग समूह की स्थापना के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) परियोजना का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी लागत आयेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) जी, हां ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र के प्राधिकारियों के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) भारत में टिटेनियम उत्पाद उद्योग की स्थापना करने के लिये एक-एक व्यक्ति महीने के लिये निम्नलिखित विशेषज्ञों की सेवाएं मांगी गई हैं :—

(1) टिटेनियम डायोक्साइड, टिटेनियम मल, टिटेनियम स्पंज उत्पादन की स्थापना तथा विस्तार करने की अर्थव्यवस्था पर विचार करने के लिये, रासायनिक इंजीनियर ।

(2) इल्मेनाइट उत्पादों के विस्तार कार्यक्रम को आरंभ करने तथा टिटेनियम पर आधारित नये उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये, भू-वैज्ञानिक

(3) नये औद्योगिक कारखानों की, जो स्थापित किये जाएं, निर्यात उपार्जन क्षमता का विश्व बाजार सर्वेक्षण के आधार पर पता लगाने के लिये, बाजार विश्लेषक ।

प्रत्येक विशेषज्ञ के लिये अनुमानित व्यय लगभग 5000 डालर होगा ।

हिन्दुस्तान मोटर्स के जाली शेयर

4288. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मोटर्स के बाजार में कितने जाली शेयर हैं और उनमें से कितने दिल्ली सट्टा बाजार के सदस्य श्री हरबंस सिंह मेहता द्वारा जारी किये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डालमिया जैन उद्योग समूह के धोखाधड़ी के सौदों के लिये श्री विवियन बोस आयोग द्वारा श्री मेहता को ही जिम्मेदार ठहराया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) बाजार में चालू, कम्पनी के जाली हिस्सों की संख्या के बारे में निश्चित सूचना प्राप्त नहीं है । मामले की जांच-पड़ताल से पता चलता है कि यह अपराध दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता तथा बम्बई में किये गये थे । दिल्ली में पंजीकृत मामलों की शिकायत, 15 अक्तूबर 1965 को मैसर्स हरबंस सिंह मेहता एण्ड कम्पनी, शेयर दलाल, दिल्ली के, श्री हरबंस सिंह मेहता द्वारा, की गई थी । उसने रिपोर्ट की, कि एक व्यक्ति की प्रेरणा पर, जो उसके पास 6 अप्रैल, 1965 को पहुंचा व उसने हिन्दुस्तान मोटर्स के, 1000 हिस्से दिल्ली शेयर बाजार के एक अन्य सदस्य को बेच दिये, तथा उसे चैक द्वारा पैसे दे दिये । इसके पश्चात्, यह पता चला कि यह हिस्से जाली थे । वह उस व्यक्ति के बारे में, जो हिस्सों को लाया, तथा अपने दिये हुये पते पर उसने चैक प्राप्त किया, पता लगाने में असफल रहे ।

(ख) विवियन बोस आयोग ने, श्री मेहता के बारे में, विशेषकर मैसर्स ग्रलीनबैरी एण्ड कम्पनी, भारत कालरीज, व डालमियां सीमेंट एण्ड पेपर मार्केटिंग लिमिटेड के मध्य, शेयरों के कुछ सौदों के सम्बन्ध में, प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं । इस सौदे में ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध, भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कोई मामला नहीं बताया जा सका, क्योंकि पर्याप्त साक्ष्य प्राप्य नहीं था, एवं डालमियां सीमेंट एण्ड पेपर मार्केटिंग लिमिटेड, बोस आयोग की स्थापना के पहले ही विघटित हो गया था ।

(ग) भाग (क) तथा (ख) के उत्तरों में स्थिति बता दी गई है ।

Amrit Vanaspati Company Limited

4289. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :**

(a) whether it is a fact that Amrit Vanaspati Company Ltd., has not been declaring any dividend on ordinary shares for the last about 17 years, whereas other Vanaspati Manufacturing Companies have been declaring dividends ; and

(b) if so, the reasons therefor and Government's reaction thereto?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Amrit Vanaspati Company Limited has not declared any dividend on ordinary shares for the last 17 years; however some of the other companies have been declaring dividends.

(b) The reasons revealed in the report of Directors is annexed. [*placed in Library. see No. LT-49/68*]. Under the Companies Act, the directors have to recommend under section 217, the dividend, if any, which they propose for declaration. The recommendation of the Directors is to be considered at the annual General Meeting of the Shareholders. It is purely a matter between the Directors and the General Body of Shareholders at a meeting to be held under section 166 of the Companies Act and the Government does not come into the picture.

दूसरे संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के मार्गदर्शकों को विदेशी भाषा का ज्ञान

4290. **श्री रवि राय :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होटलों में विभिन्न भाषायें जानने वाले मार्गदर्शक ठीक ढंग से नहीं लगाये गये हैं और इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में आये कुछ अफ्रीकी प्रतिनिधियों को कठिनाई हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) विदेशी यात्रियों के लिये होटलों द्वारा दिये गये भाषा जानने वाले मार्गदर्शकों के अतिरिक्त, भारत सरकार ने पांच प्रमुख होटलों में, जहां अंकटाड के अधिकांश प्रतिनिधि ठहरे हुए थे, 27 जनवरी से 9 फरवरी, 1968 तक और दो होटलों में 20 फरवरी, 1968 तक फ्रांसीसी भाषा जानने वाला सम्पर्क कर्मचारी वर्ग नियुक्त किया था । इस सम्पर्क कर्मचारी वर्ग ने प्रतिनिधियों को उनके ठहरने की शुरू कि अवधि में सहायता तथा मार्गदर्शन दिया । ऐसी आशा की गई थी कि उन फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले प्रतिनिधि, जिनके पास उनके अपने दुभाषिये नहीं थे, इस अवधि में इन प्रतिनिधियों की सहायता के लिये फ्रांसीसी जानने वाले दुभाषिये रख सकेंगे । परन्तु फ्रांसीसी जानने वाले मार्गदर्शकों को ढूंढने अथवा नियुक्त करने में सहायता देने के लिये उनमें से किसी से भी सरकारी तौर पर कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) फ्रांसीसी बोलने वाले प्रतिनिधियों को विशेष रूप से सहायता देने के लिये विज्ञान भवन में सरकार द्वारा फ्रांसीसी बोलने वाला एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

Bokaro Steel Plant

4291. Shri Gunanand Thakur : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) the names of the countries who have collaborated in the setting up of the Bokaro Steel Plant and the terms therefor; and

(b) the number of persons employed therein and the proportion of the people from Bihar therein ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) the Government of U.S.S.R. who are collaborating have agreed to render assistance in the construction of Bokaro Steel Plant in the following manner:

(i) Extend a credit up to 200 million roubles for meeting the foreign exchange cost of the first stage of the plant. It bears an interest of 2·5 per cent and is repayable in twelve equal annual instalments.

(ii) Prepare a detailed project report for the construction of Bokaro Steel Plant. The detailed project report shall be for a 4 million tonne plant.

(iii) Prepare working drawings for construction of Works within the scope and the time to be determined by the Soviet and Indian Organisations. The working drawings shall be prepared for the complex of shops and units for production of 1·5 to 2 million tonnes of steel per year.

(iv) Render assistance to Indian organisations in : The construction of the Works by carrying out the designers' supervision and by providing the advisory services during construction; the erection, adjustment and commissioning of the equipment. The performance of the equipment shall be in accordance with their stated capacities.

(v) Promote the maximum participation of Indian organisations in the designing of the works, and in the supply of equipment and materials.

(vi) Assist in the training of Indian specialists and workers both in the U.S.S.R. and in India.

(b) Requisite information is furnished below:

	Name of the Company	Number of persons in position as on 31st Jan., 1968	Percentage of employees from Bihar State
1.	Bokaro Steel Ltd.	3,473	72·7
2.	Hindustan Steel works Construction Ltd. (including those engaged by Contractors)	11,934	59·0

Rehabilitation of Weavers of Maheshwar Area

4292. Shri Shashi Bhushan Bajpai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the nature of facilities being provided by the Central Government to rehabilitate skilled weavers of Maheshwar area of Western Nimad?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd, Shafi Qureshi) : The Central Government are not providing any such facilities.

औद्योगिक सहकारी समितियां

4293. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में औद्योगिक सहकारी समितियां विपणन और ऋण सुविधाओं के अभाव के कारण घाटे में चल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें ये सुविधायें उपलब्ध कराने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने औद्योगिक सहकारी समितियों के लिये वित्त-व्यवस्था करने की समस्या की जांच करने और उन्हें पर्याप्त निधि बराबर मिलते रहने का सुनिश्चिय करने हेतु आवश्यक ठोस उपायों का सुझाव देने के लिये एक कार्यकारी दल बनाया है । अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक सहकारी समितियों के उत्पादों की बिक्री का काम करने के लिये औद्योगिक सहकारी समितियों का एक राष्ट्रीय फेडरेशन भी स्थापित किया गया है।

लघु उद्योगों को वित्तिय सहायता

4294. **श्री स० चं० सामंत** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों तथा अन्य उद्योगों के लिये अधिक वित्तीय सहायता देने तथा ऋण की सुविधाओं को उदार बनाने के बारे में किसी पक्ष से सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उद्योग की मांगों की कितनी पूर्ति करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । लघु उद्योग समितियों, संघों तथा लघु उद्योगों के विकास में रूचि रखने वाले कुछ अन्य व्यक्तियों के अनेक प्रस्ताव मिले थे जिन में लघु उद्योग क्षेत्र के प्रति उदारता तथा वित्त बढ़ाने सम्बन्धी अनेक उपाय किये जाने के बारे में सुझाव दिये गये हैं ;

(ख) और (ग). इन प्रस्तावों पर लघु उद्योग बोर्ड की ऋण सुविधा सम्बन्धी स्थायी समिति की एक उप-समिति द्वारा विचार किया गया था । समिति द्वारा सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत किये जाने के बाद तत्काल ही उपयुक्त कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी ।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड

4295. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में जस्ते की छड़ों और सुपरफासफेट उर्वरक का कितना-कितना उत्पादन हुआ ।

(ख) उत्पादित कितना माल बिक गया है और कितना स्टाक बिना बिका पड़ा है ; और

(ग) शेष स्टाक को बेचने में कितना समय लगेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के जस्ता प्रद्रावक में 1967 में परीक्षण के तौर पर चलाये जाने के दौरान निम्न उत्पादन हुआ :—

उत्पाद और उपोत्पाद	परिमाण
	(मीटरिक टनों में)
(1) ज़िंक कैथोड की चादरें	90
(2) जस्ते के पिंड	कुछ नहीं
(3) सुपर फौस्फेट उर्वरक	2,600

(ख) और (ग). जिंक कैथोड की चादरें बेची जा चुकी हैं। सुपर फौस्फेट का निपटान अप्रैल, 1968 तक दी जाने की आशा है ।

रूरकेला इस्पात कारखाना

4296. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन क्षमता के होते हुए भी रूरकेला इस्पात कारखाने में वर्ष 1966-67 में 1.9 करोड़ रुपये का घाटा रहा है जब कि गत वर्ष इस कारखाने में 5 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस स्थिति पर काबू पाने के लिये गत वर्ष कोई उपचारात्मक उपाय किये गये थे और यदि हां, तो क्या-क्या उपाय किये गये थे ; और

(घ) क्या चालू वर्ष में स्थिति में कोई सुधार हुआ दिखाई देता है और 1967-68 के कार्य के कैसे परिणाम प्राप्त होने की आशा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): (क) वर्ष 1966-67 में राउरकेला इस्पात कारखाने को 19.38 मिलियन रुपये का घाटा हुआ जब कि वर्ष 1965-66 में 50 मिलियन रुपये का लाभ हुआ था । यद्यपि विक्रेय इस्पात का उत्पादन निर्धारित क्षमता का 96.4 प्रतिशत हुआ, वर्ष 1965-66 की तुलना में उत्पादन, प्रेषण और विक्रय मूल्य में काफी कमी हुई ।

(ख) घाटे के कई कारण हैं जैसे कम उत्पादन, मांग-प्रतिमान में परिवर्तन कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि, अवमूल्यन के पश्चात आयात किये जाने वाले साज-सामान और फालतू पुर्जों के मूल्य में वृद्धि, काम बन्द रहना, कार्य भंग आदि ।

(ग) और (घ). कारखाने के काम और वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए कई उपाय किये गये हैं। इन में घटती हुई आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिए निर्यात बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न, उधार की पर्याप्त सुविधायें, मालिक-मजदूर सम्बन्धों में सुधार, बरसुआ की लौह खनिज की खानों में अभिशोधन संयंत्र लगाना, विशेष प्रकार के इस्पात का उत्पादन बढ़ाना और इन के लिए अतिरिक्त पूंजी का प्रबन्ध करना आदि शामिल है । अगस्त, सितम्बर, और अक्तूबर 1967 में श्रमिक अशांति के कारण वर्ष 1967-68 में कारखाने के परिचालन पर भारी प्रभाव पड़ा जिस से कारखाने को 33.9 मिलियन रुपये का लगभग घाटा हुआ । ऐसा प्रतीत होता है कि कारखाना इस वर्ष भी लाभ नहीं दिखा सकेगा ।

Hindustan Zinc Smelter in Udaipur

4297. Shri Onkar lal Bohra : Will the Minister of **Steel Mines and Metals** be pleased to state:

(a) the extent of collaboration extended by the Metal Corporation of India in the Hindustan Times Smelter set up in Udaipur;

(b) the additional amount invested after being taken over by Centre and the extent of work completed thereafter; and

(c) the extent to which the office expenses and expenses on the new appointments have increased after being taken over by the Central Government?

The Minister of Steel Mines, and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) The Metal Corporation of India has not collaborated in the completion of the Zinc Smelter after its taking over by the Hindustan Zinc Ltd.

(b) The amount invested in the Smelter after its taking over is Rs. 372 lakhs. The construction of the plant was completed and regular production commenced from 1st January, 1968. The work on the erection of two sections of the Plant, namely, Sice Furnace and Cadmium Plant is still in progress and is likely to be completed by May, 1968.

(c) Due to increased activities all round, office expenses have gone up by about 80% and expenses on new appointments, mainly required for operational purposes, by about Rs 1·25 lakhs monthly.

Mineral based industries in Rajasthan

4298. Shri Onkarlal Bohra : Will the Minister of **Industrial Dovelopment and Company Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government have any scheme for the development of the mineral-based industries in Rajasthan;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the amount given by the Central Government for the development of mineral-based industries in Rajasthan during 1967-68?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Railway Lines

4299. Shri Onkarlal Bohra: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the details of the net-work of railway lines in the country State-wise;

(b) the expenditure incurred on the expansion of the railway lines in Rajasthan after the 15th August, 1947; and

(c) the details of the schemes which had been approved for the erstwhile States and the extent to which they have been implemented so far?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) The information about length of Railway lines is not compiled State-wise but Railway-wise. Full particulars of the route and track length of the Railway Zones are given in Statement No. 8 of the 'Supplement to the Report by the Railway Board on Indian Railways—Statistical Statements for the Year, 1966-67' copies of which are available in the Library of Parliament.

(b) Information on Railway matters is not maintained State-wise, but Railway-wise. However, the following new Railway lines, falling wholly or partly in the State of Rajasthan have either been completed or are under construction since independence:—

	Name of line	Gauge	Length (in Kms.)	Estimated cost (Rs. in lakhs)	Remarks
1.	Mavli Jn.-Bari Sadri	MG	82·00	0·39	Completed and opened to traffic.
2.	Sanganer-Torde Sagar	MG	81·62	135·00	
3.	Tordi Sagar-Toda Rai Singh	MG	24·34	120·00	
4.	Fatehpur-Churu	MG	42·88	64·92	
5.	Raniwara-Bhildi	MG	69·79	119·45	
6.	Udaipur-Himmatnagar	MG	215·00	1141·00	
7.	Pokaran-Jaisalmer	MG	105·00	250·00	
8.	Hindumalkot-Sriganganagar.	BG	27·56	101·00	In progress
	Total		648·19	1931·76	

(c) Railway development is not based on any State-wise and region-wise concepts but on overall development considerations. The schemes for new lines which had been approved by the Planning Commission and funds for which have been made available by them have already been taken up for execution.

Liaison Officers of Industrial Houses

4300. Shri Ram Charan: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state the names of the groups of industries whose Liaison Officers have been issued regular passes for meeting the officials of his Ministry and also the number of the Liaison Officers of each group of industries ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) : It is presumed that the Hon'ble Member wants information regarding the passes issued by the Ministry of Home Affairs for admission to Government Offices. On this basis the names of the group of Industries whose Liaison Officers have been recommended by the Ministry of Industrial Development and Company Affairs for issue of regular passes for meeting officials are given in the attached statement. [Placed in Library. See No. LT—500/66] The Statement covers only the cases of those described as Liaison Officers and not others *e. g.* Chairmen, Resident Representatives, Managers etc.

Generally the passes issued are valid for a calendar year, and they expire on the 31st December of the year. The statement, therefore, includes only those cases who have so far been recommended for passes for 1968.

In addition passes valid for any particular day can be had at the reception counters of the Ministry.

Cement Factories

4301. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Industrial Development and Company** affairs be pleased to state :

(a) Whether any scheme for the setting up of cement factories during the current year is under consideration of Government; and

(b) if so, the names of the places where these factories are likely to be set up ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b).A Statement is laid on the Table of the House **[Placed in library . see No L.T.—501/68]**

कच्चे रेशम का आयात

4302. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान और इटली से कच्चे रेशम के आयात पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण देश में रेशम उद्योग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप रेशमी कपड़े के मूल्यों में वृद्धि हुई है और इस प्रकार विभिन्न किस्मों के रेशमी कपड़े के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो प्रतिबन्ध लगाये जाने से अब तक विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई है; और

(ङ) इस उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) जापान तथा इटली से कच्चे रेशम के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

रेलवे अधिकारियों द्वारा धातु से बने रेलवे पासों का दुरूपयोग

4303. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रेलवे अधिकारियों को स्थायी आधार पर धातु से बने रेलवे पास दिये गये हैं ताकि वे अपने परिवार के लोगों के साथ सरकारी कार्यों के लिये विभिन्न स्थानों की यात्रा कर सकें;

(ख) क्या ऐसे पासों का दुरुपयोग किये जाने की शिकायतें भी सरकार को प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) बहुत कम शिकायतें मिली हैं ।

(ग) हिदायत यह है कि ऐसे रेल कर्मचारियों को निवारक दण्ड दिये जाने चाहिएं जो रेलवे पास का दुरुपयोग करते पकड़े जांय ।

Increase in the Rent of Railway retiring rooms

4304. **Shri R. S. Vidyarthi :**
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri N. S. Sharma :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the rent of Railway Retiring Rooms was revised some months back ;

(b) if so, the extent of the increase and the reasons therefor; and

(c) the authority under which this increase was made ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, at some stations.

(b) and (c). The increase varies from station to station between fifty paise and Rs. 6 per bed per day in case of non-airconditioned Retiring Rooms and between Rs. 2 and Rs. 8 per bed per day in case of air-conditioned rooms.

Railway Administrations have instructions to review the rates for the occupation of retiring rooms and fix the charges at a level which is reasonable with reference to the conditions of the locality and the facilities provided in the Retiring Rooms.

Allotment of Accommodation to Railway Employees

4305. **Shri R. S. Vidyarthi :**
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri N. S. Sharma :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of railway employees who have been allotted accommodation in Delhi:

(b) the number of houses proposed to be constructed during the next three years and the number likely to be constructed for railway employees in Delhi:

(c) whether it is a fact that the houses in the Railway Colony, Delhi are not in good condition; and

(d) if so, the amount proposed to be spent by Government next year for providing civic amenities there as also for the repair of these quarters ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) 7485.

(b) It is not possible to indicate, the total number of quarters likely to be constructed on all Indian Railways during the next three years as the same would depend upon allocation of funds. During '68-69 about 6700 units of quarters are likely to be completed on the Indian Railways. As far as Delhi is concerned subject to availability of funds about 750 units of quarters are likely to be constructed during the next three years.

(c) and (d). No. However a total sum of Rs. 15 lakhs has been provided for improvement of sanitation and water supply and carrying out annual repairs and maintenance of the quarters in Delhi.

अयस्कों का निर्यात

4306. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1967-68 में विभिन्न देशों में विभिन्न किस्मों के अयस्कों का कितना निर्यात किया गया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई;

(ख) क्या भारत अयस्कों से बनाया गया कोई तैयार माल उन देशों से आयात करता है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा अन्य अयस्कों के संबंध में जानकारी दिखलाने वाले तीन विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न हैं ?

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 502/68]

(ख) और (ग). जी, हां । जापान द्वारा भारत के लौह अयस्क की काफी मात्रा में खरीद को देखते हुए तथा हमारी ओर से बदले में वैसा ही व्यवहार करने की दृष्टि से, खनिज तथा धातु व्यापार निगम जापान की इस्पात मिलों से जो लौह अयस्क खरीदती है इस्पात की थोड़ी सी मात्रा खरीद रहा है ।

नई रेलवे लाइनें

4307. **श्री सीताराम केसरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में कुल कितने मीटर लम्बी नई रेलवे लाइनें बिछाई गईं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० म० पुनाचा) : 242.40 किलोमीटर ।

Transfer of Railways Security and Police to Central Government

4308. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri G. C. Dixit :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government have suggested the transfer of work connected with Security and maintenance of law and order on the Railway to the Central Government ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) and (b). The Union Government have not received any request from the Madhya Pradesh Government in this connection.

Import of Fertilizers from West Germany

4309. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Trading Corporation has concluded a long term agreement with East Germany for the import of fertilizers ;

(b) if so, the terms thereof ;

(c) the quantity of fertilizers likely to be imported during 1968; and

(d) the names of other countries with which agreements have been concluded on this account ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) STC has concluded a long term agreement with East Germany for import of Muriate of Potash.

(b) It is not in the public interest to give the details of the agreement.

(c) STC expects to import in 1968, 215,000 tonnes of Mariate of Potash.

(d) No agreement has been concluded by STC in 1968 with any other country for import of Muriate of Potash . However, against contracts between STC and USSR and West Germany/

France in 1967 some quantity of imported Muriate of Potash will be arriving in 1968. STC has signed contracts for supply Urea from Bulgaria and Poland in 1968. Against contracts signed by it in 1967 with DGR and USSR some quantity of Ammonium Sulphate will also be arriving in India in 1968.

Posting of Attendants in 1st Class Compartments

4310. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an attendant is not now posted on duty in each 1st Class Compartment separately ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government propose to post an attendant in each 1st Class compartment separately keeping in view the murder of the President of Bhartiya Jana Sangh; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Coach Attendants are provided only in full corridor type first class coaches. Attendants are not provided in other first class coaches or compartments.

(b) Coach Attendants have been provided in all full corridor type first class coaches because in such coaches it is necessary to ensure that unauthorised persons do not occupy the corridor to the inconvenience of the authorised occupants. Also it is necessary in such a coach to have an attendent for ensuring that the main enterance and exit doors of the coach are properly secured and for looking after the safety of the different compartments when the occupants go to the bath-room. Such a provision of an attendant in non-corridor first class coaches is not justified as each compartment in such coaches is a self-contained unit.

(c) and (d). No, because the priovision is not justified and an attendant in a compartment will be a cause of inconvenience to the passengers as they will have to put up with his presence all the time and will suffer loss of essential privacy. The provision of a watchman for each compartment will also put up the cost of rail travel as this expenditure will have to be recovered through enhanced fares.

बोकारो इस्पात कारखाना

4311. श्री हरदयाल देवगुण : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोकारो इस्पात कारखाने के लिये भूमि को समतल करने पर अब तक कुल कितना खर्च हुआ है; और

(ख) बोकारो इस्पात कारखाने के वर्तमान स्थान से लगती हुई भूमि के मालिक कौन हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जनवरी 1968 के अन्त तक स्थल को समतल करने पर 82.72 मिलियन रुपये खर्च हो चुके थे ।

(ख) इस प्रकार का ब्यौरा नहीं रखा जा रहा है ।

विदेशी सहयोग संबंधी करार

4312. श्री स० च० सामन्त : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फैक्टरियां, कारखाने आदि लगाने में भारतीय सहयोग के संबंध में किन-किन देशों के साथ करार किये गये हैं ।

(ख) किन-किन उद्देश्यों की स्थापना के लिये भारतीय सहयोग स्वीकार किया गया है;

(ग) इन करारों के अंतर्गत तैयार माल पर होने वाले लाभ का कितने प्रतिशत भाग भारत को भेजा जा सकेगा; और

(घ) इन की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) फैक्टरियां, कारखाने आदि लगाने में भारतीय सहयोग के संबंध में भारत सरकार ने किसी भी विदेशी के साथ कोई करार नहीं किया है ।

(ख) से (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

यात्री डिब्बों और माल-डिब्बों का निर्यात

4313 **श्री स० च० सामन्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निर्मित यात्री डिब्बों तथा माल-डिब्बों के निर्यात से 1967-68 में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई और 1968-69 में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है;

(ख) क्या रेलवे इंजनों का जिनमें बिजली से चलने वाले रेलवे इंजन भी शामिल हैं; निर्यात किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो चालु वर्ष में कितने इंजनों का निर्यात किया गया तथा 1968-69 में कितने इंजनों को निर्यात करने का वचन दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) 1967-68 (अप्रैल-दिसम्बर, 1967) की अवधि में 55.46 लाख रुपये के रेल के वैगन कोचों का निर्यात हुआ । वर्ष 1968-69 के लिये 7.50 करोड़ रुपये के माल का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ख) और (ग). अभी तक इंजिनों का, जिनमें बिजली से चलने वाले इंजिन भी शामिल हैं, न तो कोई निर्यात हुआ है और न कोई निर्यात आर्डर ही प्राप्त हुआ है ।

Agreement with Coal development Corporation

4314. Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that even after correspondence for eight years, the Railways Department could not reach any agreement with the National Coal Development Corporation;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether coal is available to the Railways on easier terms than those offered by the said Corporation ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) No.

Import of Railway Engines

4315. Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India occupies first place in the world from the point of view of importing railway engines; and

(b) whether there is any proposal to make India self-sufficient in this regard during the next ten years ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Number or cost of Locomotives imported by all the other countries of the world is not known to the Ministry of Railways. As such it is not possible to state whether or not India occupies first place in the World from the point of view of importing Railway Engines .

(b) Yes. The production capacity already created in the country meets the requirement of steam locomotives. For diesel and electric locomotives also, some production capacity has been developed and is being steadily expanded. It is expected that in the next 4 to 5 years' time adequate capacity will be available to meet the full requirement of the Railways except for any special type of locomotive that may be required to meet any special demand of traffic.

Khetri Copper Project

4316. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sulphuric acid is proposed to be produced as a by-product in the Khetri Copper Project and will be utilized for producing chemicals fertilizers ;

(b) if so, the place where the said fertilizer factory is likely to be set up and the quantity and type of fertilizer likely to be produced there; and

(c) the investment involved in the entire project, and when it is likely to be completed and the programme made so far ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) Yes, Sir.

(b) Alongside the Copper Project, a fertilizer plant for the production of 2,14,500 tonnes of triple super phosphate fertilizer per annum will be set up at Khetri.

(c) The Khetri Copper Complex estimated to cost Rs. 85.93 crores is expected to be commissioned in 1970-71 achieving full production by 1972-73. A statement giving the progress made is attached.

STATEMENT

1. The mine development work at Khetri has been started according to the programme drawn up involving a total cost of Rs. 617.62 lakhs. The Total development achieved in different levels and belt incline etc. is 3129.50 meters. The work has also been started on the main adit for the Kolihan mine.

2. Two shafts are being sunk for carrying the men and equipment into the mine and taking out the daily production of ore from mine. So far, production and service shafts have been sunk to the depth of 191.21 meters and 130 meters respectively. Two service stations have been opened in the service shafts, one at 300 mertes level and the second at 240 metres level involving a drivage of about 80 meters. Necessary equipment has been installed and commissioned to achieve faster rate of shaft of sinking.

3. An agreement has been reached with a French Group of Companies for the design of the whole plant.

4. An agreement has also been signed with Messrs Outokumpu Oy of Finland for the use of Flash Smelting Process for which they hold world's patent rights.

5. Contracts have been signed with the French Group for the supply of equipment of the value of about Rs. 1.16 crores, other bids are under examination and order for such equipment as is necessary to be imported will be placed soon. An agreement regarding General Engineering and General Enterprise has also been signed with the French Group which has come ino force from 30-6-1967.

6. Action for procurement of indigenous equipment which have longer delivery period has been initiated.

7. To meet the immediate requirements of the Corporation and Consultant's staff, construction of 561 residential units has been completed. Construction of additional 958 quarters has also been taken up.

8. Tenders for construction of concentrator and allied building work were invited and are under scrutiny.

9. A water supply scheme for supply of about 9 million gallons of water per day from Chaonara and Jodhpura at a cost of Rs. 269 lakhs has been drawn up and work is progressing.

Chandsara Halt on Meerut-Hapur Line

4317. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) when Chandsara halt was providedt on the Meerut-Hapur line and average monthly income from this halt at present ;

(b) whether it is a fact that the contractor there issues tickets in an open lawn and there is no shed either for the booking office or for the passengers ;

(c) whether it is also a fact that at the time of arrival of each train, the Contractor carries with him the machine for stamping the date on the tickets and other peraphernalia from a village half a mile away; and

(d) if so, when Government propose to make arrangements for the accommodation of the staff and passengers at the said halt ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Chandsara Halt was provided on the Meerut-Hapur line in 1929. The average monthly income at this halt during 1967 was Rs. 1,088.

(b) and (c) Yes.

(d) The question of providing a booking office-*cum*-waiting shed for the use of the contractor and passengers is being looked into.

विदर्भ में कपड़ा मिलें

4318. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा विदर्भ में चलाई जा रही कपड़े की दो मिलें गंभीर वित्तीय संकट में से गुजर रही हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इन मिलों को जबसे सरकार ने अपने कब्जे में लिया है तबसे लेकर आज तक सरकार ने उनमें कितनी पूंजी लगाई है और उत्पादन में कितनी वृद्धि/कमी हुई है; और

(ग) इस समय उनके पास कितना बिना बिका माल पड़ा हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार द्वारा इन मिलों में कोई नई लगाई गई है। राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी सम्बन्धी अद्यतन स्थिति, उत्पादन में वृद्धि/गिरावट तथा मिलों के पास पड़े हुए बिना बिके माल का ब्योरा एकत्र किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति

4319. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी हित निधि से वर्ष 1966-67 और 1967-68 में क्रमशः खुर्दा डिवीजन में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा के लिए कितनी छात्र-वृत्तियाँ दी गईं ;

(ख) उक्त अवधि में छात्रवृत्तियों के रूप में कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) तकनीकी शिक्षा के लिए इन छात्रवृत्तियों को प्राप्त करने वालों की सूची क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क)

वर्ष	छात्रवृत्तियाँ
1966–67	28
1967–68	35

(ख)

वर्ष	खर्च की गयी रकम
1966-67	11,900 रुपये
1967-68	12,107 रुपये

(ग) एक सूची संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 503/68]**

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम जांच समिति

4320. **श्री दामानी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम जाँच समिति ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) यह समिति अपना अन्तिम प्रतिवेदन कब तक दे देगी ; और

(घ) क्या इस समिति ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कार्य प्रणाली के किसी पहलू का अध्ययन करने के लिए कोई अध्ययन दल अथवा उपसमिति नियुक्त की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम जाँच समिति ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट दे दी है । समिति की मुख्य सिफारिशों / निर्णयों पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ग) समिति द्वारा अन्तिम रिपोर्ट 30-4-68 तक दिये जाने की सम्भावना है ।

(घ) नहीं , महोदय ।

माथुर समिति

4321. **श्री विश्वम्भरन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन कुछ विभागों की कार्य-प्रणाली का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गई माथुर समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ख) उनमें से कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार तथा कार्यान्वित की गई हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य श्री एच० सी० माथुर की अध्यक्षता में तकनीकी विकास के महानिदेशालय की कार्य-प्रणाली की जाँच करने के लिये नियुक्त अध्ययन दल की सिफारिशों का उल्लेख कर रहे हैं । अध्ययन दल ने दो भागों में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कुल 242 सिफारिशें की जो तकनीकी विकास के महानिदेशालय के कार्यों और संगठन सम्बन्धी नमूने के बारे में थीं ।

(ख) कुल 242 सिफारिशों में से सरकार ने 225 सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं, जिनमें से कुछ को उनमें कुछ संशोधन के पश्चात स्वीकार किया गया था । 126 सिफारिशें पहले ही अमल में लाई जा चुकी हैं । स्वीकार की गई शेष सिफारिशों में से कुछ सामान्य किस्म की सिफारिशों को छोड़ कर बाकी कार्यान्वित किये जाने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने

4322. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **इस्पात खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों द्वारा लोहे और इस्पात की आन्तरिक माँगों की पूर्ति की जाती है; और

(ख) लोहे और इस्पात के उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग निर्यात करने के लिये रखा जाता है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) (क) जी, नहीं । सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने लोहे और इस्पात की आन्तरिक माँग की पूरी तरह पूर्ति नहीं कर सकते । निजी क्षेत्र के उत्पादन को मिलाकर भी कुछ प्रकार के इस्पात की माँग कुल उत्पादन से बढ़ जाती है। फिर भी कुछ दूसरी प्रकार के इस्पात का देशीय उत्पादन घरेलू माँग से अधिक है जिसमें निर्यात के लिये पर्याप्त गुंजाइश है ।

(ख) निर्यात के लिये कोई निश्चित मात्रा नहीं रखी गई है। वर्ष 1966–67 में 0.47 मिलियन टन के लगभग लोहा और इस्पात निर्यात किया गया जबकि कुल आन्तरिक उत्पादन 5.5 मिलियन टन था।

अलौह धातुओं की कमी

4323. **श्री श्रद्धाकर सुपकार** : : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अलौह धातुओं की बहुत कमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन धातुओं के लिये विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चक्रा रेड्डी) : (क) हाँ, महोदय। भारत मुख्यतः अलौह धातुओं का आयात करता रहा है और एल्युमिनियम को छोड़ कर, जिसके उत्पादन के लिये देश में पर्याप्त अयस्क आरक्षण, जैसे कि बोक्साइट, विद्यमान है, अधिकांश धातुओं के आयात करते रहने की संभावना है।

(ख) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा अलौह धातुओं के निक्षेपों के लिये देश के बहुत से भागों में बड़े पैमाने पर मानचित्रण द्वारा, गड्ढे और खाइयां खोद कर, भूरसायनिक और भूभौतिकीय सर्वेक्षण, व्यपन और अन्वेषण–खनन कार्य द्वारा, अन्वेषण जारी रखा जा रहा है। देश में अलौह धातुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित निश्चित कार्यवाहियाँ की जा रही हैं :—

1. एल्यूमिनियम :—देश में एल्यूमिनियम के लिये अधिष्ठापित क्षमता इस समय 115,800 टन वार्षिक है। 327,500 टन वार्षिक (115,000 टन सरकारी क्षेत्र में और 177,500 टन निजी क्षेत्र में) की अतिरिक्त क्षमता पूरी किये जाने की विभिन्न अवस्थाओं में है। चौथी योजना के अन्त तक अथवा पाँचवीं योजना के आरम्भ के समय तक अधिष्ठापित क्षमता को बढ़ा कर 443,300 टन वार्षिक तक ले जाने की संभावना है।

2. ताँबा—इस समय देश में केवल एक ताम्र प्रद्रावक है जो कि सिंघभूम (बिहार) ताम्र निक्षेपों पर आधारित है लगभग 9,000 टन वार्षिक धातु का उत्पादन करता है। इस एकक को, जोकि निजी क्षेत्र में है, ताँबा उत्पादन करने के उद्देश्य से एक 16,500 टन वार्षिक प्रस्फुरण प्रद्रावक स्थापित करने के लिये उद्योग अधिनियम के अधीन एक लाइसेन्स दिया गया है। एक 31,000 टन वार्षिक ताम्र प्रद्रावक खेतरी (राजस्थान) में सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजनाएं चौथी योजना के अन्त तक पूरी हो जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त, बिहार के राखा क्षेत्र में, आँध्र प्रदेश के अग्निगुन्दला में और राजस्थान के दरीबो में ताँबे के निक्षेपों के विकास के लिये कार्यवाहियाँ की जा रही हैं।

3. सीसा और जस्ता—इस समय देश में एकमात्र सीसा प्रद्रावक तुन्दू (बिहार) में स्थित है जिसकी क्षमता लगभग 5,400 टन वार्षिक है। तथापि प्रद्रावक का वर्तमान

उत्पादन 2,600 टन वार्षिक के आस पास है। प्रद्रावक जावर खानों (राजस्थान) के सीसा-जस्ता निक्षेपों पर आधारित है।

आयातित संकेन्द्रकों पर आधारित एक 20,000 टन वार्षिक जस्ता प्रद्रावक में, जोकि अलवेई (केरल) में निजी क्षेत्र में है, मई–जून, 1967 में उत्पादन आरम्भ हो गया था। सरकारी क्षेत्र में, जावर (राजस्थान) निक्षेपों पर आधारित एक और नया 18,000 टन वार्षिक क्षमता वाला जस्ता प्रद्रावक हाल ही में चालू किया गया है। इस क्षेत्र में अतिरिक्त अयस्कों के आरक्षणों की सीमा निर्धारित करने के लिये की गई विस्तृत उपपादन और पूर्वेक्षण कार्यवाहियों से संकेत मिले हैं कि ये आरक्षण अन्त में 75,000 टन वार्षिक से अधिक धातु उत्पादन का पोषण कर सकते हैं। अलवेयी (केरल) प्रद्रावक की 60,000 टन वार्षिक तक की वृद्धि (दो प्रक्रमों में) का प्राप्त हुआ एक प्रस्ताव और आयातित सकेन्द्रकों पर आधारित एक 30,000 टन जस्ता प्रद्रोवक सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

देश में अलौह धातुओं के क्षेत्र में संगाव्य, खनिज संसाधनों को ढूंढने और विकसित करने के लिये एक सर्वतोमुखी वातानीत सर्वेक्षण और भूमि अनुवर्ती सवक्षण कार्यक्रम बनाया गया है। इसके अनुसार राजस्थान में अरवली क्षेत्र में आँध्र प्रदेश के पूर्वी कदापा बोसिन में और बिहार उच्चस्थली में जिसका क्षेत्रफल 120,000 वर्ग किलो मीटर है, वातानीत सर्वेक्षण करने का कार्यक्रम है। वातानीत सर्वेक्षण के अतिरिक्त, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था 234 पूर्वेक्षणों के विषय में भूसर्वेक्षण आरम्भ करने की आशा रखती है।

रूस को माल डिब्बों का निर्यात

4324. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने आठ पहियों वाले 10,000 माल डिब्बों की सप्लाई के लिये क्रयादेश दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हाँ। तकनीकी तथा उत्पादन की समस्याओं को देखते हुए ऐसी आशा है कि प्रारंभिक रूप से 1969–70 में 2,000 माल डिब्बों का निर्यात किया जायेगा। 10,000 माल डिब्बों के वार्षिक निर्यात का स्तर 1972–73 में पहुंच जाने की संभावना है। 13–3–1968 को एक भारतीय–सोवियत संधि पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसमें माल डिब्बों के निर्यात का समयानुक्रम दिया गया है।

(ख) अभी यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकेगी।

रेलवे लाइनों के पास पड़े हुए इस्पात तथा लकड़ी के स्लीपर

4325. **श्री बलराज मधोक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों के पास इस्पात और लकड़ी के स्लीपर बहुत बड़ी संख्या में जमा हो गये हैं, और उनका अधिकांश स्टाक विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के पास खराब हो रहा है;

(ख) क्या इस स्टाक का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो नये स्लीपरों के लिये क्रयादेश देने से पहले इस स्टाक को काम में लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Sub-overseers, Mistris and Draftsman on Northern Railway

4326. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that nearly 205 sub-overseers, Mistris Grade-I and Draftsman of Northern Railway have been transferred from technical side to clerical side with effect from December, 1967, and their previous service and scales of pay have not been accounted for ;

(b) whether it is also a fact that their former posts carried a scale of Rs. 170 p. m.whereas they are now being paid at Rs. 110-p. m. and they have not also received their pay for December, 1967 and January, 1968;

(c) the reasons for transferring the aforesaid employees from technical side to clerical side; and

(d) whether Government propose to reinstate the aforesaid employees on their former posts and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) 95 Sub-Overseer Mistries and 23 Draftsmen have been rendered surplus on the Northern Railway due to completion of certain works. The posts of Sub-Overseer Mistries Grade I and Asstt. Draftsman Grade 'B' carry the scale of Rs. 150-240 -. As no equivalent posts in technicsl grades were available, they have been absorbed in non-technical posts. The question whether higher pay could be allowed on their absorption in lower posts is under consideration. There is no complaint from these staff against non-payment of their pay for December, 1967 and January 1968, but the matter is being looked into further and necessary action will be taken where such dues have not yet been paid to staff.

(d) This aspect of the problem is receiving Government's consideration.

Mines in Bihar

4327. Shri Nihal Singh : will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state ;

(a) the number of Mines in Bihar and the names of minerals they contain;

(b) the number and names of mines which are owned by the son of the former Chief Minister of Bihar,Shri Krishna Ballabha Sahai and the names o minerals obtained from those mines; and

(c) the quantity of minerals obtained from the above mines annually ?

The Minister of Steel, Mines aad Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) to (c) The information is beking collected and will be placed on the Table of the House.

Leather Manfacturing Companies

4328. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons working in the leather manufacturing companies in the country and quantity of goods exported by these companies during the last five years and the names of the countries to which the goods were exported and the amount of foreign exchange earned therefrom:

(b) the amount of investment with which these comapines were started and the amount of present investment in these comapanies; and

(c) the amount of foreign exchange sanctioned to each of the aforesaid Companies during the last five years ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The bulk of production of leather is being carried in the Small Scale and Cottage Industries Sectors. Precise information about the number of persons employed in the produection of leather in the entire industries is not available. However there are 47 units in the organised sector of the industry manufacturing leather and the number of workers in these units is about 13,500 . The exports of leather from the country made during the last 5 years are given in the attached statement. (Placed in Library See. No. LT—504 68)

(b) Since the leather industry is in the Private Sector and the major portion of production of elather is done in the Small Scale and Cottage Industtries Sectors, details of the invesmeent of the various units are not available. It is estimated that the investment in the fixed assets in the organised sector of the Industry would be about Rs. 100 million.

(c) Detsails of foreign exchange allotted to the various units in the organised sector during the last 5 years are given below:—

1962—63	Rs. 203.96 lakhs
1963—64	Rs. 231.52 lakhs
1964—65	Rs. 191.44 lakhs
1965—66	Rs. 9,73 lakhs
*1966—67	Rs. 45.33 lakhs

*From June' 66, the import of raw hides and skins, wattle extract, bark, etc. is on O. G. L.

(Some of those units are producing leather footwear and leather goods also).

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

4329. श्री बाबूराव पटेल : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके अनुरोध पर ब्रिटिश विशेषज्ञों का जो 7 सदस्यीय दल दुर्गापुर इस्पात कारखाने का अध्ययन करने के लिये जल्दी ही भारत आने वाला है, उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है ;

(ख) विदेशी विशेषज्ञों के दल को बुलाना आवश्यक क्यों समझा गया, जबकि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के उप-प्रधान, श्री ए० एन० बनर्जी ने हाल मे कहा है "दुर्गापुर इस्पात कारखाना अब एक बीमार बच्चा नहीं है यह बहुत शीघ्रता से स्वस्थ होता जा रहा है; और

(ग) क्या इस्पात कारखानों के कार्य-संचालन के सम्बन्ध मे सलाह देने तथा मार्ग दर्शन के लिये भारतीय विशेषज्ञ नहीं है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): (क) ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन की टीम का जो फरवरी 1968 मे दुर्गापुर आई थी भारत आने और वापिस जाने का खर्च, विशेषज्ञों का वेतन

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार ने दिया है। विशेषज्ञ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अतिथि के रूप में रहे और भारत में उनके ठहरने पर 6,700 रुपये के लगभग खर्च आया।

(ख) टीम को यह काम सौंपा गया था कि वह इस बात का पता लगाये कि कारखाने के कुशल संचालन के लिए उपकरणों और तकनीकी सहायता के रूप मे ब्रिटेन क्या सहायता दे सकता है।

(ग) कारखाने के कुशल संचालन के लिए उपलब्ध भारतीय विशेषज्ञता का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। इस बात को देखते हुये कि हमारे विशेषज्ञ कारखानों के विस्तार कार्यों तथा मिश्र-इस्पात कारखाने के कुशल संचालन कार्यों में पूरी तरह लगे हुये हैं। यह आवश्यक समझा गया कि कारखाने को शीघ्रता से पूरी उत्पादन क्षमता पर लाने के लिए उपकरणों और तकनीकी सहायता के रूप में कुछ चुनी चुनी सहायता लेना अनिवार्य है।

आयात नीति

4330. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात की जाने वाली वस्तुओं की स्वीकृत सूची में कुछ और वस्तुओं को सम्मिलित करने के लिए हाल में आयात नीति में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पहले की आयात नीति में क्या-क्या मुख्य संशोधन किये गये हैं; और

(ग) संशोधित आयात नीति के परिणामस्वरूप 1968-69 के निर्यात में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) अप्रैल, 67—मार्च, 68 की अवधि के लिए घोषित की गई आयात नीति मे हाल में कोई मुख्य परिवर्तन नहीं किए गए हैं। अप्रैल, 68—मार्च, 69 की अवधि के लिए आयात नीति विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस समय इसका अनुमान नहीं लगाया गया जा सकता।

स्टेनलैस इस्पात का कोटा

4331. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्टेनलैस इस्पात के कोटे के दुरुपयोग के बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इस दुरुपयोग को रोकने तथा दुरुपयोग करने वालों को और कड़ी सजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल में इंजीनियरी कारखाने

4332. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के तीन इंजीनियरी कारखानों के प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लेने के बारे में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Bhind-Chirgaon Railway Line

4333. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any survey has been conducted for laying railway lines from Bhind to Chirgaon *via* Lahar Bhandare ; and

(b) if not, when the survey is proposed to be conducted ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Due to paucity of funds, the construction of the suggested line is not likely to merit sufficient priority for consideration duringt he Fourth Plan. Any survey undertaken for this line now will become out of date if at all the construction of the lines is to be considered at a distant future date only, thus rendering the expenditure on the survey infructuous which the Railways can hardly afford in the present difficult ways and means position .

पश्चिम बंगाल में इंजीनियरी कारखाने

4334. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में बहुत से इंजीनियरी कारखाने कई महीनों से बन्द पड़े हैं अथवा उनमें ताला बन्दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन कारखानों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने राज्य अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि इन कारखानों को फिर से चालू कराने के लिये सभी सम्भव सहायता दी जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

बोकारो इस्पात कारखाना

4335. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार के प्रश्न के कारण बोकारो इस्पात कारखाने में दंगे होते रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो स्थानीय लोगों को रोजगार देने के सम्बन्ध में, जिनकी भूमि परियोजना के लिये अर्जित कर ली गई है, प्रबन्धकों द्वारा क्या नीति अपनाई जा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं। 8 फरवरी 1968 को केवल एक प्रदर्शन हुआ था। बाद में स्थानीय लोगों के मुखियों और अन्य प्रतिनिधियों को बोकारो इस्पात कारखाने की रोजगार सम्बन्धी नीति और प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में समझाया गया जिससे वे पूरी तरह सन्तुष्ट हो गये। आन्दोलन अब बिल्कुल समाप्त हो गया है।

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति के अनुसार बोकारो स्टील लिमिटेड में रोजगार के मामले में अकुशल और अर्द्ध-कुशल नौकरियों में विस्थापित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। इस उद्देश्य से कि विस्थापित लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिलें उनको प्रशिक्षण देने के लिए एक विशेष योजना बनाई गई है और 31 जनवरी 1968 को इस योजना के अधीन 307 विस्थापित व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। दुकानों के नियतन में भी विस्थापित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है। दूसरे कामों और छोटे-मोटे ठेके देने के मामले में भी उनको प्राथमिकता दी जा रही है। इनके अतिरिक्त उनके पुनर्वास के लिए भी बोकारो स्टील लिमिटेड पुनर्वास पर आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत दे रहा है जिस पर 4.2 मिलियन रुपये खर्च आने का अनुमान है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

4336. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश विशेषज्ञ दल ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने का अपना अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ख) दल को कौन-कौन सी समस्यायें सौंपी गई थीं;

(ग) क्या दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, हाँ।

(ख) टीम से कहा गया था कि वह इस बात का पता लगाये कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कुशल संचालन के लिए उसकी आवश्यकतायें क्या हैं और कारखाने की संगठनात्मक, प्रबन्धकीय, प्रशासनीय और अन्य बातों को देखते हुये, जिनमें औद्योगिक सम्बन्ध भी शामिल हैं, यह बतायें कि इस बारे में ब्रिटेन से उपकरणों और तकनीकी सहायता के रूप में क्या सहायता आवश्यक होगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स गुजदार काजोरा कोल माइन्स लिमिटेड और मैसर्स कलकत्ता सेफ डिपोजिट कम्पनी लिमिटेड

4337. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स गुजदार काजोरा कोल माइन्स लिमिटेड तथा मैसर्स कलकत्ता सेफ डिपाजिट कम्पनी लिमिटेड गत कई वर्षों से न तो अपनी वार्षिक सामान्य बैठकें ही बुलाती हैं और न ही वार्षिक प्रतिवेदन तथा सन्तुलन पत्र जारी करती है ;

(ख) क्या इन फर्मों ने समवाय अधिनियम के अन्य उपबन्धों का भी उल्लंघन किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) सदन के पटल पर एक विवरण पत्र प्रस्तुत है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 505/68]**

Price of Cotton

4338. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Ministrer of Commerce be pleased to state:

(a) whether Government have received a memorandum from Cotton Federation, Central Zone, Amravati protesting against the policy of control on indigenous cotton and new cotton and restrictions on grant of loan; and

(b) if so the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) The Federation has recently addressed two memoranda, one of them to ICMF making a plea *inter alia* for reconsideration of the decision regarding restraint on buying cotton by its members and withdrawing their objections to relaxation of credit for cotton. Government have not reduced the stock levels for cotton fixed for the current season. However, members of ICMF are as a measure of self-discipline not purchasing cotton upto these levels. The level of bank credit is determined keeping in view the interests of all concerned. Prices of cotton are still ruling well above the level of last year's ceillngs. However, the situation is under constant review by Government and at the appropriate time steps, as may be necessary, will be considered .

न्यू विक्टोरिया मिल्स बंद होना

4339. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वाणिज्य** मन्त्री 13 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 153 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की गई समिति की सिफारिशों पर इस बीच कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस मिल के बन्द हो जाने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मिल को अधिक कुशलतापूर्वक चलाने के लिये प्रबन्ध व्यवस्था में मजदूरों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। इस मिल का बन्द होना विधि के दांडिक उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आता।

(घ) जब तक सरकार मिल को अपने हाथ में नहीं लेती तब तक मिल के प्रबन्ध में मजदूरों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रश्न नहीं उठता।

अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड

4340. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 20 फरवरी 196 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1295 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार की वर्तमान सरकार ने अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड को अपने अधिकार में लेने के सम्बन्ध में पिछली सरकार द्वारा किये गये निर्णय को बदलने का निश्चय किया है;

(ख) क्या इस मिल का परिसमापन होने देने का निर्णय किया गया है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि बिहार की वर्तमान सरकार ने बिड़ला सार्थ-समूह को प्रसन्न करने के लिये जो बिना कोई कीमत दिये इस मिल को हथियाना चाहते हैं, ऐसा निर्णय किया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मिल को स्वयं अपने हाथ में लेने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हाँ। इस मन्त्रालय को बिहार सरकार से 22-2-68 को मिली सूचना के अनुसार यह मालूम हुआ है कि उन्होंने इस मामले में पहले के निर्णय को बदल दिया है।

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान आज सभा-पटल पर रखे गए विवरण की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें 20-2-68 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1295 के उत्तर को ठीक किया गया है।

(ख) यह कम्पनी गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाई गई थी और सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि प्रबन्धकों ने इसे बन्द कर देने का निश्चय किया है अथवा नहीं।

(ग) हमें कोई भी जानकारी नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

कोयला खानों का बन्द होना

4341. श्री भोगेन्द्र, झा : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री 20 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1291 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गिरिडीह में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कई कोयला खानें बन्द कर दी गई हैं अथवा बन्द की जायेंगी क्योंकि उनका उत्पादित कोयला नहीं बिका है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गैर-सरकारी कोयला खाने सरकारी उपक्रमों से अधिक मूल्य लेती हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों को प्राथमिकता न देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) नहीं, महोदय।

(ख) कुछ गैर सरकारी कोयला खानें जो दो सरकारी उद्योगों को कोकिंग/ब्लैंडेबल कोयला भेजती हैं, वे कोयला धोने के और इस्पात संयन्त्रों से लिये जाने वाले मूल्यों से अधिक मूल्य ले रही हैं। नान-कोकिंग कोयले के विषय में ऐसी कोई बात सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ग) ऊंची श्रेणी के कोकिंग कोयले की सप्लाई करने के विषय में राष्ट्रीय कोयला/विकास निगम की क्षमता पूरी हो चुकी है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयले को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कांडला में अबाध व्यापार क्षेत्र

4342. श्री रा० की० अमीन :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री द० रा० परमार :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला में अबाध व्यापार क्षेत्र विकसित करने के काम में विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस काम को शीघ्र पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं। कांडला में अबाध व्यापार क्षेत्र में विकास कार्य की प्रमुख मदें पूर्ण हो गई हैं और उद्योगों की स्थापना के लिये आवश्यक विकसित प्लाट, सड़कें, जल तथा बिजली आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रियायती टिकटों का दुरुपयोग

4343. श्री रा० की० अमीन :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री द० रा० परमार :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा करने के लिये पाँच अथवा पाँच से अधिक व्यक्तियों के किसी दल को दिये गये रियायती टिकटों का उपयोग एक से अधिक दलों के लिये किया जा सकता है;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन ने इस सुविधा के दुरुपयोग के मामलों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकार ने और क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री वे० सु० पुनाचा): (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय सर्कुलर यात्रा टिकटों से है। ये टिकट तभी जारी किये जाते हैं जब सर्कुलर यात्रा की दूरी 2,400 कि० मी० या इससे अधिक हो लेकिन यात्रियों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गयी है। वास्तव में ये टिकट व्यक्तिगत यात्रियों को दिये जाने के उद्देश्य से हैं।

ऐसे टिकट हस्तान्तरणीय नहीं होते।

(ख) हाल ही में श्री रा० की० अमीन ने यह बात मेरे ध्यान में लायी है कि इन टिकटों का दुरुपयोग हो रहा है।

(ग) जाँच में कड़ाई बरतने और शर्तों को और अधिक कठोर बनाने के प्रश्न की जाँच की जा रही है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा तांबे की छड़ों की सप्लाई

4344. श्री रा० की० अमीन :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री द० रा० परमार :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहाजों के छोटे निर्माताओं को राज्य व्यापार निगम से ताँबे की छड़ें प्राप्त करने में कठिनाई होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा जो मूल्य लिया जा रहा है, वह बाजार भाव से बहुत अधिक है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) राज्य व्यापार निगम ताँबें की छड़ों का आयात अथवा सम्भरण नहीं करता। यह कार्य भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम उनके द्वारा आयातित ताँबे को लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा दिये गये निकासी आदेशों पर बेचता है। 1968 के मध्य से निगम के पास कोई स्टाक नहीं है। उससे पूर्व यदि जहाजों के छोटे निर्माताओं को सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा ताँबा आवंटित किया जाता था तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम छोटे उत्पादकों को यह सामग्री देता था।

(ख) ताँबे के आयात की अनुमति केवल वास्तविक उपभोक्ताओं अथवा खनिज तथा धातु व्यापार निगम को दी जाती है। इसलिये कानूनी रूप से इस धातु के लिये कोई मुक्त व्यापार नहीं है। मई 1967 से फरवरी 1968 के दौरान बाजार भाव 11,500 रु० से 12,500 रु० प्रति मे० टन के बीच रहे। फरवरी 1968 के अन्त से बाजार भाव 12,600 रु० से 13,000 रु० प्रति मे० टन के बीच रहे। खनिज तथा धातु व्यापार निगम का विक्रय मूल्य विद्युत्-विश्लेषण का ताम्र-पिण्ड छड़ों के लिये 12,100 रु० प्रति मे० टन तथा अग्निशोधित ताँबे के लिये 11,500 रु० प्रति मे० टन है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

वस्तु-विनिमय व्यापार करार

4345. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन देशों के साथ वस्तु-विनिमय व्यापार करार हैं;

(ख) इन करारों के विरुद्ध भारत से कितनी-कितनी तथा किन-किन कृषि आधारित तथा औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ग) क्या अन्य देशों के साथ, जिन को इस समय भारत को आयात के लिये विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है, ऐसे करार करने के लिये प्रयत्न किये गये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) भारत और अन्य देशों के बीच सरकारों के स्तर पर कोई वस्तु-विनिमय करार नहीं हैं । राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने वस्तु-विनिमय करार किये हैं । ये करार सं० रा० अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन के साथ हैं ।

(ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 506/68]**

(ग) जी, हाँ ।

(घ) पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, यूनान, नार्वे, फिनलैण्ड, जापान तथा सं० रा० अमेरिका के के साथ वस्तु-विनिमय करारों की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये कार्यवाही चल रही है । प्रयत्न अब भी जारी हैं अतः इस समय कोई ब्यौरे नहीं दिये जा सकते ।

रूस के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत

4346. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री कोसीगिन की हाल की भारत यात्रा के दौरान उनके साथ उन्होंने क्या बातचीत की थी;

(ख) क्या नवीन संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिये भारत तथा रूस द्वारा कोई सुझाव दिये गये थे;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) उन सुझावों के प्रति श्री कोसीगिन की क्या प्रतिक्रिया थी और उन्होंने किन-किन क्षेत्रों में ऐसे संयुक्त उपक्रमों को व्यवहार्य समझा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (घ). सोवियत प्रधान मन्त्री श्री कोसीगिन के साथ जो बातचीत हुई, उसमें पटसन के माल, जूते तथा चमड़े के अन्य माल, सिले सिलाये वस्त्रों तथा फलों के रस के क्षेत्रों में भारत तथा रूस के बीच संयुक्त औद्योगिक सहयोग

का विषय शामिल था । सिद्धान्त रूप में वे इस विचार पर सहमत थे । प्रधान मन्त्री श्री कोसीगिन ने एक यह आश्वासन भी दिया है कि सोवियत रूस उन सभी रेलवे माल डिब्बों को खरीदने के लिए तैयार है जितने भारत सोवियत रूस को दे सकता है । इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप सोवियत प्रधान मन्त्री विभिन्न क्षेत्रों में बातचीत करने तथा योजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए अपने विशेषज्ञ भेजने पर सहमत हो गये ।

Stopping of Trains by Students at Raipur

4347. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in the "Nav Bharat Times" of the 14 th January, 1968 that the students stopped a train at Rajpur;

(b) if so, the reasons for which the train was stopped and the time for which the train was late as a result thereof; and

(c) the action proposed to be taken by Government to check the recurrence of such incidents?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No such item has appeared in the "Nav Bharat Times" dated 14th Jan. 68. However, in the "Nav Bharat" dated 10-1-1968, published at Raipur, there was a reference to stoppage of a train at Virdhi colony near Raipur on 9-1-68.

(b) On 9-1-68, 353 Up Howrah-Dongargarh Passenger was detained for 7 minutes at, Kms. 851/7 near the Virdhi colony, 2·7 Kms. from Raipur, due to alaram chain pulling by some students. The reason for this action of the students is not known .

(c) Such cases of unauthorised pulling of alarm chain are reported to the State Government and police authorities for necessary action .

Export of Engineering Goods to U.S.S.R.

4348. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) the value of engineering goods exported by India to the U.S.S. R. during the years 1966 and 1967 ;

(b) the amount of foreign exchange earned therefrom ; and

(c) the value of engineering goods likely to be exported till the end of 1968-69 and the estimated foreign exchange earnings therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) & (b). The value of engineering goods exported by India to USSR during 1966 was of the order of Rs. 3·21 million. During January to November, 1967, exports were made to the extent of Rs. 29·12 million which includes beams and channels also .

(c) During the calender year 1968, Rolled Steel products (Beams, channels and angles) worth Rs. 130 million will be exported to USSR in addition to other engineering goods like accumulators, auto- ancillaries, small lathe instruments, miniature lamps etc. worth Rs 14 million.

Export of Shoes

4349. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the demand for Indian shoes is increasing in U.S.S.R. and U. S. A. ;

(b) if so, the value of shoes likely to be exported up to the end of 1967-68 and the estimated foreign exchange earnings thereform ; and

(c) the value of Indian shoes exported to U.S.S.R and U.S.A during 1966 and 1967 and the amount of foreign exchange earned there from ?

The Deputy Minister in the Ministy of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) (a) Yes, Sir.

(b) Value of export of shoes to the USSR and the USA up to the end of the 1967-68 are estimated to be of the order of Rs. 3·50 crores and Rs 50 lakhs respectively.

(c)

	Value in Rs. lakhs	
	1966	1967 (Jan-Nov.)
U.S.S. R.	475	306
U.S. A.	62·96	104·71

Coal and Iron Mines in Madhya Pradesh

4350. **Shri Hukam Chand Kachwal** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** b pleased to state :

(a) the number of coal and iron mines in District Sarguja, Sidhi and Panna of Madhya Pradesh ;

(b) the annual output of iron and coal in these mines ;

(c) the number of employees and labourers working in these mines ;

(d) the time after which the labourers working in these mines are declared permanent; and

(e) the number of labourers confirmed during the period from 1965 to 1967 ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi): (a) to (e). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Industrial Development of Bihar

4351. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Industrial Dovelopment and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the position of the industrial development of Bihar prior to Independence and at present ;

(b) the number of large and small scale industries separately, before Independence and at present in the State ; and

(c) the position of Bihar in the field of industrial Development in the country ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the house.

Stocks of M. M. T. C.

4352. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the details of articles in the possession of the Minerals and Metals Trading Corporation at present, per quintal price of each article the time for which they have been lying in their stores; and

(b) the rules regarding the distribution of various articles to the States and traders through the Minerals and Metals Trading Corporation and existing stock of those articles with Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd: Shafi Qureshi) : (a) A statement is laid on the Table of the House . **[Placed in Library See No. LT-507/68.]**

(b) Raw materials imported by the MMTC are distributed to actual users directly or through the State Small Industries Corporation in accordance with the recommendations of the concerned sponsoring authorities. Government do not carry stocks of these raw materials .

Import licences for Small Scale Industries

4353. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3615 on the 8th December, 1967 and state :

(a) the total value of import licences recommended by the Director of Industries, Kanpur to 1573 applicants and the value of import licences actually issued ;

(b) the criteria for the grant of licences to these applicants ;

(c) whether the applications for import licences of some applicants have been rejected; if so, the reasons therefor in each case; and

(d) whether any representation to this effect has been received and if so the action taken by Government thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (d), The information is being collected and will be furnished later.

शक्तिचालित हलों का निर्माण

4354. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिये वर्ष 1967–68 में 12 डी० बी० एच० पी० से कम शक्ति के शक्तिचालित हलों/छोटे ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस दिये गये हैं, उन्हें स्वीकार किया गया है;

(ख) इस समय विचाराधीन योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) विचाराधीन योजनाओं के बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) मेसर्स जे० के० काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, कानपुर को प्रतिवर्ष 6000 एल बी 17 हैंड ट्रैक्टर बनाने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस 29-4-67 को मंजूर किया गया था ।

(ख) निम्नलिखित पार्टियों द्वारा भेजी गई योजनाओं पर विचार किया जा रहा है:—

(1) पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, चण्डीगढ़ द्वारा लुधियाना में स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक उपक्रम में चार पहियें वाले शक्ति चालित हलों का निर्माण करने के लिये ।

(2) मेसर्स एफ डब्ल्यू हीलगर्स प्रा० लि०, नई दिल्ली द्वारा उड़ीसा राज्य में स्थापित किये जाने वाले एक नये उपक्रम में कुबोटा शक्ति चालित हलों का निर्माण करने के लिये ।

(3) मैसर्स इन्डिक्विप इंजीनियरिंग कं० लि०, अहमदाबाद द्वारा गुजरात राज्य के अहमदाबाद में उनके मौजूदा औद्योगिक उपक्रम में राबिन शक्ति चालित हलों का निर्माण करने के लिये ।

(ग) इन योजनाओं पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ।

Import of Cotton

4355. **Shri Deorao Patil:** Will the the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the total requirements of the country for cotton and the quality of cotton for which indents have been placed with foreign countries ;

(b) the quantity of cotton imported during the year 1967-68 and in the months of January and February, 1968 under P. L. 480. funds ;

(c) whether it is a fact that cotton is imported at such a time when there is marketing season of indigenous cotton as a result of which a downward trend is seen in the prices of indigenous cotton; and

(d) whether Government propose to change their policy regarding import of cotton and if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Country's requirement of cotton during the year 1967-68 excluding the normal quantum of carry-over stocks is estimated at 68 lakh bales of which 64 lakh bales is the estimated mill consumption. An import of 9. 76 lakh bales is programmed for the year. It is not possible to indicate the quantity for which orders have been placed by the mills.

(b) As ascertained from trade sources, PL-480 cotton imports from September 1967 to February 17, 1968 are estimated at 167,598 bales out of which 23,202 bales and 51,489 bales arrived during January and Februaty (upto 17th) respectively.

(c) and (d) No, Sir, Import of cotton is arranged only to the extent necessary to meet the shortfall of supply of indigenous cotton for meeting the requirements of the industry. The timing of import, *inter-alia.* depends upon the picking and marketing seasons in the foreign countries from which cotton is imported .

लौह मैंगनीज उद्योग

4356. **डा० रानेन सेन :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह-मैंगनीज उद्योग में काफी बिना बिके स्टाक के जमा हो जाने के कारण संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड चालू वर्ष में लगाये गये 62,000 टन लौह मैंगनीज को उठाने में असफल हो गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस उद्योग की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि इसका वर्तमान संकट दूर हो सके ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) फैरो-मैंगनीज के उत्पादकों के पास स्टाक जमा हो गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) ऐसी सम्भावना है कि सामान्य अर्थ-व्यवस्था में सुधार होने से अपव्यय धीरे-धीरे बढ़ जाएगा । फरो-मैंगनीज के निर्यात के लिए भी यथा सम्भव उपाय किये जा रहे हैं ।

उद्योगों में ईंधन और भाप का प्रयोग

4357. **डा० रानेन सेन :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियन प्रोडक्टिविटि आर्गेनाइजेशन के ईंधन क्षमता विशेषज्ञ डा० तनाका अनेक भारतीय उद्योगों में ईंधन और भाप के ज्वलन के बारे में अध्ययन करने के लिये हाल में भारत आये थे;

(ख) यदि हाँ, तो उनके अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या उन्होंने भारतीय उद्योगों में ईंधन और भाप के प्रयोग के बारे में कोई सुझाव दिये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उनके मुख्य सुझाव क्या हैं और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (घ) डा० कुसुवाता तनाका, चीफ कमीश्नर, डिवीजन, रिसोर्सेज रिसर्च इंस्टीटयूट, एजेंसी आफ इंडस्ट्रियल साइन्स एण्ड टैक्नोलाजी, जापान ने हाल ही में एशियाई उत्पादिता संगठन (ए० पी० ओ०) के जरिये राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद (एन० पी० सी०) के निम-त्रण पर हाल ही में भारत की यात्रा की थी। डा० तनाका सर्वप्रथम अपनी रिपोर्ट एशियाई उत्पादिता संगठन को प्रस्तुत करेंगे जो बाद को अंग्रेजी में उसका अनुवाद करवा कर राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद को भेजेगा। राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद अभी उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है। डा० तनाका ने जिन उद्योगों और कारखानों को देखा उनके सम्बन्ध में ईंधन और भाप का अधिक अच्छा इस्तेमाल करने के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं। जिन्हें उन्होंने गोपनीय माना है। 22 फरवरी, 1968 को भारत से जाने से पहले 21 फरवरी, 1968 को एक प्रेस सम्मेलन बुलाया था जिसमें डा० तनाका ने सम्वाददाताओं से अपनी बातचीत के दौरान निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया :—

1. ईंधन का अधिक कारगर प्रयोग करने का पहला कदम यह होगा कि इंजीनियरों और ईंधन प्रयोग करने वाले मन्यंत्रों के प्रभारी चालकों को बड़े पैमाने पर जलने में काम आने वाले ईंधन के उपयुक्त तरीके के बारे में शिक्षा दी जाय और इस मामले में बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाय। डा० तनाका ने यह आशा प्रकट की कि राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद ईंधन क्षमता सेवा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

2. भारत को चाहिए कि वह देश में उपलब्ध ईंधन पर आधारित वायलरों तथा उच्च क्षमता वाली भट्टियों के उपयुक्त नमूने तैयार करे जिससे वे बहुत दिनों से इस्तेमाल में आने वाले ईंधन प्रयोग करने वाले संयंत्रों जैसे लंका-नायर वायलर तथा पुराने नमूने की भट्टियों के स्थान पर इस्तेमाल किए जा सकें।

3. जहां तक सम्भव हो सके भारत को निम्नस्तर के कोयले का अधिकाधिक प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिये और सरकार को चाहिए कि वह उन ईंधन इस्तैमाल करने वालों को प्रोत्साहन दे जो कि निम्नस्तर वाले कोयले का इस्तैमाल करना चाहते हैं। ऐसा वह उच्च स्तर वाले कोयले और निम्नस्तर वाले कोयले के मूल्यों में अन्तर रख-कर कर सकती है।

4. कोयला सम्भरण करने वालों को कोयले के कुछ स्तर बनाए रखने चाहिए जिससे उपभोक्ताओं को उनका कारगर इस्तेमाल करने में सहायता मिल सके।

5. भारतीय उद्योग को चाहिए कि वह कम्बश्चन क्षमता पर नियन्त्रण रखने के लिए "एनालाइजर" और "ड्राफ्ट वाज" जैसे साधारण यन्त्र रखे।

6. जलाने के काम आने वाले तेल का प्रयोग करना भारत के लिए अन्ततोगत्वा लाभदायक नहीं होगा। क्योंकि इस तेल की सम्पूर्ण मांग देश से पूरी नहीं हो सकती और चूंकि भारत को विवश होकर पर्याप्त मात्रा में इसका आयात करना पड़ता है जिस पर काफी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का व्यय होता है। इसलिए उन्होंने यह अनुभव किया कि जब तक भारत का विदेशों के साथ अनुकूल व्यापार सन्तुलन नहीं हो जाता तब तक ईंधन का इस्तेमाल केवल कुछ विशिष्ट प्रयोगों तक सीमित रखा जा सकता है।

7. डा० तनाका ने कोयले के नमूने और उसके विश्लेषण पर व्यवहारिक रूप से कठोर नियंत्रण लागू करने के उपयुक्त मानक निर्धारित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद ईंधन क्षमता इंजीनियरी उद्योग का ध्यान इन बातों की ओर आकर्षित कर रहे हैं।

धातुओं को जंग लगना

4358 **श्री वीरेश्वर कालिता :** क्या **इस्पात, खान तथा** धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया है कि भारत की धातुओं को जंग लगने के कारण प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपये से अधिक हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो धातुओं को जंग लगने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Shifting of North Eastern Railway Samastipur Distt Headquarters

4359. **Shri K. M. Madhukar ;** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it was decided sometime ago to shift the Headquarters of the the Samastipur District of North Eastern Railway to Muzaffarpur and land had also been acquired for the purpose ; and

(b) if so, the reasons for not shifting the Headquarters to Muzffarpur ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No such decision was taken by the Railway Ministry.

(b) Dose not arise.

Railway Line Between Hajipur and Bhainsalotan

4360. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it has been decided that a railway line between Hajipur and Bhainsalotan, the source of Gandak Canal *Via.* Lalganj, Sahebganj and Govindganj on the North Eastern railway will be an economic proposition ; and

(b) if so, when the construction of this line will be taken up ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) and (b): No surveys for the proposal as such have been carried out in the past. Hajipur and Bagaha are already connected by a metre gauge line *Via* Muzaffarpur, Sugauli and Narkatiaganj . It may, however, be stated that in 1962 the North Eastern Railway had carried out reconnaissance engineering and traffic surveys for an metre gauge line from Bagaha to Bhainsalotan at the cost of the Government of Bihar who had mooted the proposal mainly with a view to facilitating transport of materials for execution of their Gandak Project. This proposal was then found to be heavily unremunerative. When the results of the surveys were communicated to the State Government the State Government intimated that they were no longer interested in the construction of this rail link at their cost. There is, therefore, no justification for construction of the rail link between Bagaha and Bhainsalotan .

ईराक के साथ व्यापार

4361 **श्री रा० बरुआ :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक को भारतीय वस्तुओं का निर्यात कुछ बढ़ गया है ;

(ख) क्या भारत और ईराक के बीच व्यापार बढ़ाने तथा विभिन्न मदों का व्यापार करने की सम्भावनाओं का पता लगाया गया है ;

(ग) क्या दोनों देशों में जो व्यापार बढ़ाया जायेगा उसको संयुक्त रूप से स्थापित होने वाले उद्योगों की स्थापना के साथ सम्बद्ध किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). दोनों देशों के बीच व्यापार का विस्तार संयुक्त उद्यमों की स्थापना के साथ विशेष रूप से सम्बद्ध नहीं है, परन्तु संयुक्त उद्यमों के कारण पूंजीगत माल तथा मशीनरी का निर्यात होता है जो व्यापार विस्तार में सहायक होता है । इन देशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के इच्छुक भारतीय उद्योगपतियों को सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रोत्साहन दिया जाता है ।

Fire in Cotton Textile Factory, Jawra

4362. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that cotton worth Rs. 28 lakhs was reduced to ashes on account of fire that broke out in a cotton textile factory in Jawra town in Ratlam district of Madhya Pradesh;

(b) if so, the cause of the fire;

(c) whether it is also a fact that this factory was insured and the payment of the amount assured has not so far been made ;

(d) whether this factory is in public sector of State or Central Government; and

(e) if so, the amount of assistance Government have agreed to sanction to this factory ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

रेलवे अधिकारियों का स्थानांतरण

4363, **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे अधिकारियों की एक स्थान से दूसरे स्थान को तबदीली के बारे में क्या नीति है; और

(ख) कलकत्ता तथा दिल्ली क्षेत्र में अधिकारी कितनी अवधि तक रह सकते हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) स्थानान्तरण केवल तभी किये जाते हैं जब प्रशासनिक दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है। इसके लिए कोई ठोस सीमा नहीं है लेकिन जो अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हैं उन्हें आम तौर पर अनावश्यक रूप से लम्बी अवधि तक एक स्थान पर नहीं रखा जाता।

(ख) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Steel Plants

4364. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the expansion of three steel plants in the public sector during the Fourth Five Year Plan ;

(b) the amount invested therein so far ;

(c) whether the Bhadravati Plant is also being expanded ; and

(d) if so, the main feature of the extension programme of these plants ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) (a) and (b): The expansions of the three public sector steel plants and the total investment during the Fourth Plan on them as envisaged in the draft Fourth Five Year Plan outline are indicated below :

(Rs. crores)

Name of the Plant	Million tonnes of steel ingot capacity	Total investment
Bhilai Steel Plant	2·5 to 3·2	62·90
6th Blast furnace *complex	*	23·00
Durgapur Steel Plant	1·6 to 3·4	312·20
Rourkela Steel Plant	1·8 to 2·5	100·00

2. Implemention of the expansion of the Durgapur and Rourkela Steel Plants have been deferred in view of the slow growth in the demand for steel and the paucity of resources. The detailed project report for Bhilai Steel Plant's expansion in steel has yet to be prepared. In the meanwhile, the first phase of its expansion programme being the coke and iron making facilities has already been undertaken. The total cost this programme is estimated at Rs. 254·52 million. As against this the expenditure incurred upto March 31, 1967 was Rs. 45·7 million.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(*) Bhilai Steel Plant's expansion beyond 2·5 million tonne is envisaged in two phases —the first phase being installation of sixth blast furnace complex.

[Export duty on Tea

4365. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact tht the export duty on tea has been reduced ;

(b) if so, whether Indian tea would be able to compete in the international market as result thereof ; and

(c) the prices of tea of similar qualities of Ceylon, East Africa and India prevailing at present in the international market?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) It is hoped so , Sir.

(c) In the absence of any standard grading for determining the qualities of tea it is not possible to compare each quality of tea marketed by one country with teas produced . and marketed by others.

Manufacture of Sugar Plants and Machinery

4366. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state:

(a) the existing capacity in respect of manufacture of sugar plants and machinery in the country;

(b) whether a scheme has been drawn up for the export of sugar machinery ;

(c) the names of countries which are prospective buyers of this machinery;

(d) whether any target has been fixed for export and production of this machinery for the next three years; and

(e) if so, the broad features thereof?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The industry can manufacture sugar mill machinery worth Rs. 150 Million a year.

(b) and (c). The possibility of exporting complete sugar plant as well as components and spares is being continuously explored. Th re has been indication of interest in sugar machinery manufactured in India from Uganda, Philippines, Ghana, Ceylon, Nigeria, Federal Republic of Germany, Burma, Indonesia and German Democratic Republic.

(d) and (e):. No such targets have been fixed. The Fourth Five Year Plan which will take shape towards the end of this year may indicate the targets in these respects over the new Plan period.

रोल ग्राइंडिंग मशीनें

4367. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने रोल ग्राइंडिंग मशीनें बनाने के लिये तकनीकी सहयोग प्राप्त करने हेतु पश्चिम जर्मनी की एक फर्म से एक करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) (1) विदेशी कम्पनी को 11·25 लाख डयूश मार्क जो चालू विनिमय दर पर 21·22 लाख रुपये के बराबर है निम्न प्रकार एक मुश्त देय होगा :—

(क) 20 प्रतिशत करार पर हस्ताक्षर किए जाने के 30 दिन के अन्दर देय होगा ।

(ख) 20 प्रतिशत पूरे डिजाइन तथा तकनीकी प्रलेखों के भेजे जाने पर देय होगा ।

(ग) शेष 60 प्रतिशत 6 बराबर अर्द्धवार्षिक किश्तों में देय होगा जिसकी प्रथम किश्त अन्तिम माल तथा औद्योगिक प्रलेख के भेजे जाने के 6 मास के बाद देय होगी ।

(2) निर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए निर्बाध अनुमति होगी ।

(3) करार अवधि हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से आठ वर्ष तक लागू रहेगी । इस करार के केवल भारत सरकार की पूर्वानुमति से ही और आगे बढ़ाया जा सकेगा ।

कागज उद्योग

4368. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों से कागज उद्योग की लाभकारिता कम होती जा रही है तथा हाल में अनेक कारखानों को घाटा होने लगा है; और

(ख) यदि हां, तो कागज उद्योग को उचित लाभ हो, इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है, ताकि इस उद्योग के विस्तार में बाधा न होने पाये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कागज उद्योग तथा कागज, लुग्दी और सम्बद्ध उद्योगों की विकास परिषद् ने भी यह बताया है कि इस उद्योग की लाभदायकता पिछले कुछ वर्षों से कम होती जा रही है तथा कुछ कारखाने बन्द हो गये हैं ।

(ख) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

स्कूटरों का निर्माण

4369. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 150 सी०सी० के स्कूटर बनाने की क्षमता बढ़ाने के लिये मार्च, 1965 में जारी की गई अधिसूचना के बावजूद सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि क्षमता बढ़ाने के लिये स्कूटर आवेदकों की चुनींदा सूची की जांच करने के लिये सितम्बर, 1967 में नियुक्त की गई तकनीकी उपसमिति ने अपनी सिफारिशों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है; और

(घ) यदि हां, तो लाइसेंस देने सम्बन्धी तथा अन्य औपचारिकताएं कब तक पूरी करने का सरकार का विचार है ताकि नए उद्योगपति कारखानों का निर्माण आरम्भ कर सकें ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, हां।

(ख) से (घ). मार्च, 1965 में जारी की गई अधिसूचना के परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन इसलिए रोक रखी गई थी कि चौथी योजना में स्कूटरों के लक्ष्य निर्धारित किये जा सकें और इस बात का निश्चय किया जा सके कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मौजूदा कारखानों से कहां तक आशा की जा सकती है। इनके अलावा अन्य बातों के साथ साथ प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना था। लाइसेंस देने वाली समिति की उप-समिति जिसकी स्थापना विचाराधीन योजनाओं की जांच करने के लिए की गई थी, ने अपना निर्णय दे दिया है और उसकी रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में प्रस्तुत कर दी जायेगी। उप-समिति की रिपोर्ट मिल जाने और उस पर लाइसेंस समिति द्वारा विचार करके सिफारिशें कर देने के पश्चात् ही सरकार इस बारे में अन्तिम निर्णय कर सकेगी।

रेलगाड़ी के मासिक टिकट

4370 **श्री यशपाल सिंह** : : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली से मेरठ तक, जो दिल्ली से 60 मील दूर है मासिक टिकट की दर 21 रुपये है जबकि दिल्ली से सोनीपत के लिए जो, दिल्ली से 29 मील है, यह दर 18 रुपये मासिक; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) दिल्ली से मेरठ सिटी तक (दूरी 68 किलोमीटर) तीसरे दर्जे के मासिक सीजन टिकट का किराया 22·80 रुपये है और दिल्ली से सोनीपत तक (दूरी 44 किलोमीटर) मासिक सीजन टिकट का किराया 15.60 रुपये है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

छपाई मशीनों का निर्माण

4371 **श्री शिवचन्द्र झा** :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री नायनार :
श्रीमती सुशीला गोपालन,:
श्री चक्रपाणि :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में छपाई मशीन के निर्माण के लिए एक कारखाना लगाने के संबंध में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और पश्चिम जर्मनी के मैसर्स एल्बर्ट फ्रेंकनथाल के बीच कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० का पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स एल्बर्ट फ्रेंकनथाल के संयोग से छपाई मशीनों

की कुछ वस्तुएं बनाने के लिए एक सहायक कम्पनी की स्थापना करने का विचार है । करार की शर्तें अभी अन्तिम रूप से तय की जानी हैं।

अमरीका को रेडियो सेटों का निर्यात

4372. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अमरीका तथा अन्य देशों को रेडियो का निर्यात करता है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967 में किन-किन देशों को तथा कितने-कितने रेडियो का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत में प्रतिवर्ष किस-किस देश से तथा कितने रेडियो का आयात किया जाता है और उन पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) और (ख). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1312/68**]

(ग) भारत में रेडियो सेटों के आयात पर रोक लगी हुई है।

रूरकेला इस्पात कारखाना

4373. **श्री यशपाल सिंह** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूरकेला इस्पात कारखाने में कुछ और एकक स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये एकक वहां कब स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) उन पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग). आजकल राउरकेला इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड की क्षमता 1 मिलियन टन से बढ़ा कर 1.8 मिलियन टन तक की जा रही है। विस्तार कार्यक्रम में वर्तमान कारखानों को बड़ा किया जाएगा तथा कुछ नये कारखाने लगाये जायेंगे। नये लगाये जाने वाले कारखानों में इलेक्ट्रोलिटिक टिन्निंग लाइन, कान्टीन्युअस गेलवेलाइजिंग लाइन, इलेक्ट्रिकल शीट मिल और स्पेशल स्टील प्लेट प्लाण्ट शामिल है। विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत से कारखानों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है और शेष कारखानों के 1968 के मध्य तक उत्पादन आरम्भ करने की संभावना है। कुछ समय पहले सरकार ने विस्तार योजना के लिए 1125·6 मिलियन रुपये की रकम मंजूर की थी (इसमें बस्ती, खानें आदि शामिल नहीं हैं)। ऐसा लगता है कि कई कारणों से यह रकम बहुत ऊपर चली जाएगी। इन कारणों में अतिरिक्त और पहले न शामिल की गई आइटमों का खर्च, अवमूल्यन का प्रभाव, सीमा शुल्क में वृद्धि आदि कारण शामिल हैं।

मोर पंखों का निर्यात

4374. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विदेशों को मोर पंखों का निर्यात करता है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक देश को मोर पंखों का कितना निर्यात किया गया ; और

(ग) इससे प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 508/68]**

बिड़लाओं को लाइसेंसों का दिया जाना

4375. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में बिड़लाओं ने कितने तथा कौन-कौन से नये उद्योगों के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के लिये सरकार को आवेदन किया है ; और

(ख) उन्हें उक्त अवधि में कितने तथा किन उद्योगों के लिये नये लाइसेंस दिये गये हैं तथा ये लाइसेंस दिये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) छः महीनों सितम्बर, 1967 से फरवरी, 1968 की अवधि में बिड़ला समूह की फर्मों से नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने के लिए पांच आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। ये आवेदन निम्नलिखित उद्योगों के बारे में थे :—

1. बेन्ज़ालडीहाइड
2. बेन्ज़ोइक एसिड
3. बेन्ज़ल अल्कोहल
4. बैन्ज़ाइल बेन्ज़ाटे
5. एक्रीलोनीटाइल मेनामेर
6. एसीटोनिट्राइल
7. हाइड्रोजन सायनाइड
8. संश्लिष्ट रेशों के लिये सयंत्र और मशीनें
9. गलीचे का तागा
10. वनस्पति
11. साबुन, और
12. ग्लिसरीन।

(ख) सूत उद्योग के लिये एक ।

मिदनापुर में नया उपक्रम लगाने के लिये पार्टी के पास एक लाइसेंस पहले से ही था। मिदनापुर वाला लाइसेंस लौटा दिये जाने के बदले यह लाइसेंस पार्टी को चम्पादनी के मौजूदा एकक का विस्तार करने के लिये दिया गया था।

Theft of Goods from Goods Trains and Goods Sheds

4376. **Shri O.P. Tyagi :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the value of goods stolen from goods trains and goods sheds during the last 5 years ; and

(b) the further measures proposed to be taken to prevent such thefts ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a)

Year	Value of goods stolen in trains including from wagons in yards.	Value of goods stolen in goods sheds, etc.
	Rs.	Rs.
1962-63 . .	15,86,038	1,82,681
1963-64 .	12,57,801	1,58,080
1964-65 .	13,27,277	1,68,208
1965-66 .	15,08,691	1,69,958
1966-67 . . .	24,17,116	2,54,969

(b) (i) Intensifying armed escorts on all night goods trains :

(ii) round-the-clock patrol of important yards and sheds by armed and unarmed staff ;

(iii) stricter use of the security sections for preventing unauthorised entry into yards, goods sheds and platforms ;

(iv) best use of the plain-clothes and crime intelligence staff for collation, dissemination of information regarding crime and criminals ;

(v) provision of dire basic security needs namely :
fencing of unprotected yeards, adequate lighting arrangements and setting up of watch towards, wherever found necessary.

Industries in Adivasi Areas

4377. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up any scheme for the setting up of industries in Adivasi areas with a view to improve the economic conditions of the people in these areas.

(b) if so, the salient features thereof ; and

(c) the names of areas where the scheme has proved successful ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir. A number of programmes have been undertaken in the State Sector to help backward classes and the Scheduled Tribes in promoting Village and Cottage Industries.

(b) The nature and content of schemes differ from State to State although generally these schemes are of the nature of Training Institutes and Production Centres and aim at giving financial assistance and technical training to enable the native to set up or improve their own trades or business. The technical training and guidance is given in trades like rope-making, basket-making, shoe-making, tailoring and garment-making, weaving, spining, tanning, leather-work, carpentry, blacksmithy, handloom, handicrafts, lime and coke etc. During the training period, subsidies and stipends ranging from Rs. 20/- to Rs. 50/- per month per trainee are given. In certain cases, the trained artisans are also helped to form industrial societies by granting them share capital upto Rs. 2,500/- each or grant for equipments/administrations etc. upto Rs. 6,000/.

In addition, five of the forty-nine Rural Industries Projects set up by the Planning Commission are located in areas mainly populated by Adivasis.

(c) Industrial Training Institutes, set up under the Backward Classes Sector, have been very popular in Madhya Pradesh. The State Government had incurred an expenditure of Rs. 11·20 lakhs during the year 1966-67 and an expenditure of Rs. 11·35 lakhs is anticipated during the current year (1967-68). The development of Secriculture has also been very fruitful in the State of Madhya Pradesh as it has provided employment to Scheduled Tribes.

Laying of Railway Lines in Belladilla (M. P.)

4378. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Soviet experts who visited Belladilla (Madhya Pradesh) have hinted the possibilities of large deposits of iron ore at Belladilla and have suggested the laying of railway lines in that area at the earliest ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b). The Railway Board are not aware of any such suggestion. Presumably the Honourable Member has in mind "Bailadilla" in Madhya Pradesh. There are large iron ore deposits at Balladilla. The deposits have already been connected to Visakhapatnam by the construction of a 444 Km. long railway line.

Gramodyog Co-operative Societies in M. P.

4380. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some institutions named as Gramodyog Co-operative Societies and Gramodyog Ashrams have been set up in Madhya Pradesh and a huge sum has been invested by the Khadi & Village Industries Commission in these institutions ;

(b) if so, the details thereof and whether all these institutions are still functioning ; and

(c) if not, the number of those institutions which have been wound up and the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

अखिल भारतीय रेलवे अवर्गीकृत (अनग्रेडेड) एकाउण्ट्स क्लर्क सम्मेलन

4381. **श्री विश्वानाथ मेनन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेलवे अवर्गीकृत एकाउन्ट्स क्लर्क सम्मेलन का एक प्रतिनिधि-मण्डल सरकार से मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) इनकी मांगें इस प्रकार हैं : रेलों पर संगणक लगाने के प्रस्ताव को वापस लेना, लेखा क्लर्कों के वेतन-मानों को एक में मिलाना, एपेन्डिक्स II-ए परीक्षा को समाप्त करना, ऐसे उपाय करना जिससे निम्नतम ग्रेड क्लर्क अपने वेतन की उच्चतम सीमा पर पहुंच कर रुके न रहें, लेखा क्लर्कों के लिए उच्चतर वेतनमान और लगातार तीन वर्ष की सेवा पूरी होने पर स्थायी किया जाना।

(ग) इन मांगों की जांच की गयी हैं और इनमें से कुछ मांगों पर रेलवे बोर्ड ने रेल कर्मचारियों के दोनों संघों के साथ बातचीत भी की है।

दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ की एर्णाकुलम शाखा

4382. **श्री विश्वनाथ मेनन:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ की एर्णाकुलम शाखा द्वारा 15 फरवरी, 1968 को पारित संकल्प सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्मिक संघ ने क्या मांगें रखी हैं ; और

(ग) उनकी शिकायतें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) संकल्प में कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित कुछ स्थानीय समस्याओं, जैसे क्वार्टरों की व्यवस्था, कर्मचारियों की गाड़ी, रात में ड्यूटी करने के भत्ते की मंजूरी आदि, का जिक्र है।

(ग) ये ऐसे मामले हैं जिनको निबटाने में रेल प्रशासन सर्वथा सक्षम है।

एर्णाकुलम के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

4383. **श्री विश्वानाथ मेनन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे प्रार्थनापत्र मिले हैं कि एर्णाकुलम आई० पी० एन० में काम करने वाले सभी रेलवे कर्मचारियों को वहीं पर क्वार्टर मिलने चाहियें, जहां पर वे काम करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) कुल 79 (51 सारभूत और 28 असारभूत) कर्मचारियों में से 28 सारभूत कर्मचारियों को पहले ही क्वार्टर दिये जा चुके हैं। इरिमबानम में 37 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की मंजूरी भी दी जा चुकी है। इस बीच जो कर्मचारी एरणाकुलम में और इसके आस-पास स्थित क्वार्टरों में रह रहे हैं और इरिमबानम में काम कर रहे हैं उन्हें तब तक ये क्वार्टर रखने की अनुमति दे दी गयी है जब तक उन्हें इरिमबानम में क्वार्टर नहीं दे दिये जाते।

एर्णाकुलम में कर्मचारियों की विशेष रेलगाड़ी

4384. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन ने एर्णाकुलम, आई० पी० एन० में कर्मचारियों की विशेष रेलगाड़ी को बन्द करने की कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन कर्मचारियों को आई पी० एन० में क्वार्टर नहीं दिये गये हैं, क्या उनके आने-जाने के लिये अधिकारियों ने कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) कोई वैकल्पिक प्रबन्ध करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है। लेकिन ज्योंही रेल संरक्षा के अपर आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त होगी, जिसके लिए आवेदन किया गया है, स्पेशल गाड़ी को फिर से चालू करने का विचार है।

Private Investment

4385. Shri Bharat Singh Chauhan : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no incentive for private investment in the country ;

(b) whether any scheme has been drawn up to utilise the industrial capacity and to increase the return on private investment to the maximum in the country ; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Measures to utilise installed industrial capacity fully and to provide a reasonable return on investment are being continuously reviewed by Government.

आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले उद्योग

4386. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश में कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) उन पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). चौथी योजना, जो अप्रैल, 1969 से शुरू की जाने वाली है, का कार्य अभी प्रारम्भ किया गया है। सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के कार्यक्रम पर तभी विचार किया जायगा जब कि चौथी योजना का विस्तृत अध्ययन पूरा हो जायगा।

ओंगल हैदराबाद रेलवे लाइन

4387. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव मिला है जिसमें ओंगल तथा हैदराबाद के बीच नागार्जुन सागर से होकर एक नई रेलवे लाइन बिछाने का सुझाव दिया गया है ; और

(ख) यह प्रस्ताव कितनी अवधि से विचाराधीन है और इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) 1960 में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की सिफारिश की थी। चौथी योजना में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए बहुत सीमित मात्रा में धन मिलने की संभावना है, जिस में तीसरी योजना की बाकी बची अनेक लाइनों को और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, औद्योगिक विकास, अयस्क दोहन योजनाओं आदि के लिए आवश्यक विभिन्न अग्रता परियोजनाओं को भी शामिल करना होगा। अत : इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अधिक अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी होगी।

उद्योगों में लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त करना

4388. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत वर्ष 1967-68 में किन-किन उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया गया है ; और

(ख) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि देश में कृषि संबंधी मशीनरी तथा औजारों की कमी को दृष्टि में रखते हुए उन से संबंधित सभी उद्योगों के लिये लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी जाये।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 के अधीन 1967–68 में केवल पहिएदार खेती के ट्रैक्टर और शक्ति चालित हल उद्योग से लाइसेंस हटा लिया गया है।

(ख) ऐसा कोई भी प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उद्योगों का विकेन्द्री करण

4389. **श्री कृष्णन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिले-वार आधार पर उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करने का सरकार का विचार है; और

(ख) क्या इस योजना की व्यवहारिकता का अध्ययन करने के लिये संसद् सदस्यों को मिलाकर एक तकनीकी समिति नियुक्त करने का भी सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के व्यापक विकास द्वारा उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करना सरकार की स्वीकृत नीति रही है किन्तु उद्योगों का जिलावार विकेन्द्रीकरण का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

कृषि पर आधारित उद्योग

4390. **श्री कृष्णन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन विकास तथा संवर्धन करने के लिये जिले के आधार पर कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कृषि पर आधारित कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) क्या देश म कृषि पर आधारित कोई उद्योग चल रहे हैं और यदि हां, तो कितने और कौन-कौन से तथा वे कहां-कहां है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी, कृषि औद्योगिक निगमों की स्थापना आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, हरियाना, महाराष्ट्र, मद्रास, पंजाब, उड़ीसा, मैसूर तथा उत्तर प्रदेश में की गई है। इन निगमों के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं :—

(1) ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देना तथा चलाना जिनका खाद्य उत्पादन, परिरक्षण तथा सम्भरण पर प्रभाव पड़ता हो ;

(2) कृषि तथा उस से संबंधित कामों में लगे व्यक्तियों को अपने कामों में आधुनिकीकरण के साधन अपनाना।

(3) परिष्करण, डेयरी, मुर्गी खाना, मछली पालना तथा कृषि संबंधित अन्य उद्योगों की मशीनों, औजारों तथा उपकरणों का वितरण।

(4) कृषि में काम आने वाली आवश्यक सामग्री का कुशल वितरण करना या इस में उनकी सहायता करना;

(5) किसानों तथा ऐसे व्यक्तियों का तकनीकी मार्ग-दर्शन करना जिसमें कि वे अपने उद्यम को कुशल रूप से चलाने में समर्थ बन सकें।

(ग) देश के विभिन्न भागों में कृषि पर आधारित उत्पादों के कई औद्योगिक एकक हैं। संगठित औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे एककों की संख्या लगभग 325 है। इनमें फलों तथा सब्जियों के उत्पाद, अनाज उत्पाद, मछली के उत्पाद, डेयरी उत्पाद, स्टार्च तथा डेकस्ट्रोज और काजू परिष्करण आदि उद्योग सम्मिलित हैं।

विदेशी कम्पनियां

4391. श्री जुगल मंडल : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्होंने पटसन, इंजीनियरी कागज, अल्युमिनियम, लोहा तथा इस्पात के क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है;

(ख) वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में इन कम्पनियों को अपने उद्योगों के विस्तार के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी; और

(ग) देश में ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिये भारतीयों को प्रोत्साहन देने के हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) एकाधिकार जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो 8-12-1965 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई थी, के विवरण-पत्र 2 में, विभिन्न औद्योगिक समूहों के अन्तर्गत अनेक एकाकी उत्पादनों से संबंधित, पाँच शीर्षस्थ उद्यमों की सूची दी थी। विस्तृत शीर्षकों के अन्तर्गत, समूहित, जूट, इन्जीनियरी, कागज, अल्यूमीनियम, लोहा तथा इस्पात के बारे में आंकड़े बताती हुई, विदेशी कम्पनियों की एक सूची, सदन के पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 09/68]।**

(ख) 1966—67 तथा 1967—68 के वर्षों की सूचना प्राप्य नहीं है।

(ग) औद्योगिक नीति संकल्प, 1949 व 1956 तथा औद्योगिक (विकास एवं विनियम) अधिनियम के उपबन्धों व उसके अन्तर्गत निर्मित विनियमों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Automatic Machines on the Railways

4392. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that automatic machines have been installed in the Railway Offices at Madras and in some other Offices;

(b) if so, the number thereof;

(c) the number of persons rendered jobless or deprived of the prospects of employment as a result thereof ;

(b) whether Railway employees opposed the installation of these machines ; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) and (b). Eight computers have been installed on the Indian Railways viz., one each on the Northern, Central, Western, Southern (Madras) and South Eastern Railways and the Integral Coach Factory Perambur, the Diesel Locomotive Works, Varanasi, and the Chittaranjan Locomotive Works.

(c) The number of persons rendered jobless is nill. The installation of computers has had no effect so far on employment. Even in the Future the employment potential of the Railway as a whole is not likely to be affected significantly by any reduction in ministerial staff that may be possible due to the use of computers.

(d) and (e). Some representations were received. Organised Labour has been advised that the interests of serving staff are fully protected, since there will be no consequent retrenchment of staff, their prospects of promotion as they stood on 20th August '66 will be preserved unimpaired and that any staff who may be released from their present duties and put to work in other posts due to the use of computers will not be transferred to a different station without their consent.

Railway Over-bridge near Ordnance Factory, Katni

4393. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a security official of the Ordnance factory, Katni was run over by a train while he was crossing the railway line ;

(b) whether it is also a fact that the employees of this factory have gone on strike to stress their demand for the construction of an over-bridge there ;

(c) if so, whether Government propose to construct an over-bridge near the factory ; and

(d) if not, the reasons thereof?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) On 14-2-1968 while an employee of Ordnance Factory, Katni was crossing the railway line at level crossing gate near the Ordnance Factory, he was run over by train No. 27 Down Kashi Express.

(b) No ; the demand for an over-bridge was, however, stressed by the factory workers.

(c) and (d). It would be feasible to replace the level crossing at Katni South Station, which is providing access to the Ordnance Factory also, by a road over/bridge. Under the rules, proposals for construction of road over under-bridges in replacement of existing busy level crossings are required to be sponsored by the State Government/Road Authority concerned, indicating the relevant priority and the year in which the road authority would be able to take up, at their cost, the work on sloping approaches.

As far as the scheme for a road over-bridge in replacement of the level crossing at Katni South Station is concerned there is no firm proposal either from the State Government or from the Authorities of the Ordnance Factory.

रेलवे बोर्ड के कार्यालय में निःसवर्ग पद

4394. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1968 को रेलवे बोर्ड के कार्यालय में कितने निःसवर्ग पद थे;

(ख) इन पदों के लिये चयन का तरीका क्या है ;

(ग) क्या विभिन्न निदेशालयों में सभी पदालियों को ऐसे निःसवर्ग पदों पर हुई नियुक्ति के विरुद्ध रेलवे कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 271। इनमें से अधिकतर पदों को ऐसे तकनीकी कार्मिकों द्वारा भरने की जरूरत होती है जिन्हें रेलवे के काम का व्यापक अनुभव हो।

(ख) ऐसे पदों को भरने के लिए, प्रवरण सामान्यतः पात्र रेल कर्मचारियों या बोर्ड कार्यालय के कर्मचारियों में से इस प्रयोजन के लिये गठित प्रवरण समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। राजपत्रित पदों के मामले में ऐसे प्रवरण स्वीकृत भर्ती नियमों और कार्यविधियों के अनुसार किये जाते हैं।

(ग) जी हाँ; कुछ थोड़े से।

(घ) ऐसे प्रत्येक अभ्यावेदन पर इस दृष्टि से समुचित विचार किया गया कि मौजूदा स्थिति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं।

रेलवे सेवा आयोग

4395. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न रेलवे सेवा आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों की नियुक्ति का तरीका क्या है ;

(ख) अध्यक्षों के निदेशपद तथा सेवा की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या इलाहाबाद रेलवे सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के सेवाकाल में कोई वृद्धि की गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो कितनी अवधि के लिये ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर नियुक्त किये जाते हैं।

(ख) अध्यक्ष रेल सेवा आयोग का प्रशासी प्रधान होता है जिसे रेलों के लिए तीसरे दर्जे के कर्मचारियों की भर्ती करने का काम सौंपा गया है। अध्यक्ष नियुक्ति की तारीख से चार वर्ष या 62 वर्ष की आयु पर पहुंचने की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले पड़े, के लिए नियुक्त किया जाता है। इस पद का वेतनमान 1800 रु० प्रति माह (नियत) है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में निचले तथा उपरि पुल

4396. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में 1967–68 में किन-किन स्थानों में निचले तथा उपरि पुलों का निर्माण आरम्भ किया गया था ;

(ख) उनमें से कितने पुल बन कर पूरे हो गये हैं; और

(ग) 1968–69 में मध्य प्रदेश में किन-किन स्थानों पर निचले तथा उपरि पुलों का निर्माण किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कहीं नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) 1968-69 में दो ऊपरी सड़क पुल बनाने का विचार है—एक इन्दौर में और दूसरा पेंडा चिरिमिरि रोड में ।

यात्री रेलगाड़ियां

4397. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली-कलकत्ता, दिल्ली-मद्रास, दिल्ली-बम्बई, बम्बई-मद्रास, कलकत्ता-मद्रास और बम्बई—कलकत्ता लाइनों पर कितनी यात्री रेलगाड़ियां चल रही हैं ; और

(ख) उनमें से कितनी रेलगाड़ियां प्रत्येक सेक्शन में 1950 से पृथक्-पृथक् चलाई गई?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). सूचना नीचे दी गयी है :—

मार्ग	इस समय हर ओर से चलने वाली सीधी गाड़ियों (खंडीय गाड़ियों को छोड़कर) की संख्या	1950 के बाद चलायी गयी गाड़ियों की संख्या
(i) दिल्ली—कलकत्ता (मुख्य लाइन के रास्ते)	4	—
(ग्रांड कार्ड के रास्ते)	2	1
(ii) दिल्ली—मद्रास . . .	3	2
(iii) दिल्ली—बम्बई (पश्चिम रेलवे के रास्ते) .	4	2
(मध्य रेलवे के रास्ते) . .	2	—
(iv) बम्बई—मद्रास	4	2
(v) कलकत्ता—मद्रास	4	3
(vi) बम्बई—कलकत्ता (नागपुर के रास्ते) .	3	2
(इलाहाबाद के रास्ते) .	2	1

कटनी और इटारसी यार्डों से माल गुम हो जाना

4398. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में कटनी और इटारसी यार्डों से कुल कितने मूल्य का माल गुम हुआ था ;

(ख) इन यार्डों में कितने-कितने माल डिब्बे आये थे और उनमें से कितने-कितने माल डिब्बे प्रत्येक यार्ड में 4 दिन अथवा उससे अधिक दिनों तक रोके गये थे;

(ग) क्या इन यार्डों में माल डिब्बों को अनधिकृत रूप से रोके जाने के बारे में शिकायतें आई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्रवाही की गई है?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) 6,884 रुपये।

(ख)

	आने वाले माल डिब्बों की संख्या		4 दिन या अधिक रुके रहने वाले माल डिब्बों की संख्या	
	1966	1967	1966	1967
न्यू कटनी यार्ड	4,38,718	4,29,057	4,284	4,740
न्यू इटारसी यार्ड	7,42,384	7,60,258	3,153	3,203

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

शिमला कालका तथा मेत्तपालाइयम ऊटाकमंड रेलवे लाइन से घाटा

4399. **श्री नेजा गौडर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में शिमला-कालका तथा मेत्तपालाइयम-ऊटाकमंड रेलवे लाइनों को कितना-कितना घाटा हुआ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :—

(लाख रुपये में)

लाइन का नाम	हानि, पूंजी पर ब्याज सहित		
	1964–65	1965–66	1966–67
शिमला-कालका	31.18	39.21	आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे
मेट्टुप्पालयम-उदकमंडलम	28.01	31.39	34.87

Allotment of Quarters to Railway Employees

4400. **Shri Chandra Shekhar Singh** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of Railway employees have not so far been allotted quarters even after completion of more than 10 years service at Patna, Gaya, Dhanbad and Jamalpur on Eastern Railway ;

(b) if so, the number of such employees in the above cities ;

(c) the reasons for which quarters have not been allotted ; and

(d) the time by which quarters will be allotted to them ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Allotment of Class III quarters to Railway Officers

4401. Shri Chandra Shekhar Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Railway Officers are still residing in type III quarters;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the time by which type III quarters would be got vacated from these officers by allotting them quarters of the type to which they are entitled ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) yes.

(b) (i) Shortage of officers' quarters.

(ii) Some officers were allotted quarters before their promotion from class III. They have to be permitted to continue their occupation due to paucity of the higher types of quarters to which they are normally entitled.

(c) No time limit can be laid for this purpose. As and when the appropriate type of officers' quarters become available, class III quarters are got vacated.

Allotment of quarters to Railway employees

4402. Shri Chandra Shekhar Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of quarters generally allotted to Railway employees every year ;

(b) the number of quarters which are allotted out-of-turn every year ; and

(c) the criteria for making out-of-turn allotment ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Allotment of quarters to staff every year depends on the number of quarters completed during the year and this in turn depends on the funds made available for the construction of new quarters during the year. During the Third Five Year Plan about 70,913 quarters were constructed. In the year 1967-68, 9266 more quarters are likely to be completed. In addition, quarters that fall vacant as a result of retirement, death, transfer etc. of the staff are also allotted to the staff on the waiting list in the order of their registration.

(b) A small percentage of quarters is set apart for allotment on out-of-turn basis.

(c) No criteria has been laid down for allotment of quarters on out-of-turn basis; however, quarters on out-of-turn basis are allotted out of those at (b) above in cases of hardship such as prolonged sickness of an employee or a member of his family on the relative merits of each case.

In addition the son/daughter/wife/husband/ father of a Railway servant who has been allotted Railway quarter and who retires from service or dies while in service, is allotted a Railway quarter on out-of-turn over-riding priority basis provided the said relation of the retired/ deceased employee in a Railway servant eligible for railway accommodation and had been sharing accommodation with the retiring or deceased employee for at least six months before the date of his/ her death or retirement.

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों को कम किया जाना

4403. **श्री बे० कु० दास चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के डी सेक्शन में स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों की संख्या कम कर दी गयी है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितने पद कम किये गये हैं ;

(ग) क्या इसके विरुद्ध स्टेशन मास्टरों की संस्था से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख).जी नहीं, लेकिन इस खण्ड में स्टेशन मास्टरों के चार पदों का ग्रेड घटाकर सहायक स्टेशन मास्टर का ग्रेड कर दिया गया है।

(ग) और (घ). ग्रेड घटाने के विरुद्ध एक अभ्यावेदन मिला है । मामले की जाँच की जा रही है।

Grant of Import Licences to S.T.C.

4404. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the state Trading Corporation is given preference in the matter of giving import licences irrespective of the fact whether they have experience of a particular field or not; and

(b) if so, the percentage of commission on an average charged by the State Trading Corporation on such licences?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Import of Ammonium Sulphate

4405. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4961 on the 7th July, 1967 and state :

(a) whether Government propose to find out some substitute to save the huge amount spent on the imports of Ammonium Sulphates and Potassium Chloride ;

(b) whether Government propose to suggest to the farmers to make use of cow-dung as manure by making available to them about 40 crores of rupees, which are being annually spent on the import of fertilizers ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes Sir. The Government has been trying to become self-sufficient in production of nitrogenous fertilizers such as urea, nitro-phosphate, calcium ammonium nitrate, and also potassium chloride and potassium schoenite which will serve as substitutes for ammonium sulphate and potassium chloride.

(b) and (c). A great stress has been laid on full utilisation of cow-dung and other cattle shed and farm wastes for compost production. With a view to achieve this, a scheme for development and Utilisation of Local Manurial Resources for compost production in rural areas has

been in operation on an all-India basis. This is a Centrally aided State Plan Scheme, which has been making steady progress through the Plan periods

Export of Beef and Calf Leather

4406. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the value of beef and calf leather exported to foreign countries during the last five years;

(b) whether Government propose to impose restrictions on the export of beef and calf leather with a view to remove the shortage of milk and milk-products in the country and also of good calves for the farmers; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Valu of export of bovine cattle meat and calf leather from 1962-63 upto 1967-68 (upto November 1967) is given in the attached statements 'A', "B"-I, and "*B*"-*II* [*Placed in library see no L. T. 510/68*]

(b) and (c) While export of beef is banned, it is not considered desirable to restrict the export of calf leather which is an important foreign exchange earning item .

बोकाजन (आसाम) में सीमेंट कारखाना

4407. **श्री रा० बरुआ :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आसाम के बोकाजन में एक सरकारी क्षेत्र का सीमेंट कारखाना स्थापित करने की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना में कितनी पूंजी लगाई जायेगी तथा इसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) बोकाजन में सरकारी क्षेत्र में 858 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 2 लाख मी० टन क्षमता वाले सीमेंट के एक कारखाने की स्थापना करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

खादी ग्राम उद्योग भवनों का बन्द होना

4408. **श्री अगाड़ी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाये जा रहे कुछ ग्रामोद्योग भवन बंद किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और ये भवन किन-किन अधिकरणों को सौंपे जा रहे हैं; और

(ग) इस अधिकरण व्यवस्था की शर्तें और निबंधन क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का विचार किसी भी भवन को बंद करने का नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Watch Factories in Madhya Pradesh and Rajasthan

4409. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have permitted an industrialist from Rajasthan to set up watch factories in Madhya Pradesh and Rajasthan ;

(b) Whether it is also a fact that Governmment have accorded permission in this regard to a foreign Company ; and

(c) if so, the time by which the factories are likely to be set up ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

4410. **श्री सुदर्शनम्** : क्या **इस्पात खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में एक कार्यकारी बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्नारेड्डी) : (क) और (ख) जी, हाँ । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के संचालक–मण्डल को, जिसमें इस समय केवल अध्यक्ष ही एक पूर्णकाल-संचालक है, कुछ और पूर्णकाल-संचालक नियुक्त करके सबल बनाने का प्रस्ताव है।

विदेशी सहयोग

4411. **श्री वामानी** :
श्री रा० बरुआ :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशी सहयोग के बारे में नीति सम्बन्धी संकल्प के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह संकल्प विदेशी पूंजी विनियोजन के क्षेत्र तथा शर्तें निर्धारित करेगा;

(ग) क्या इसकी क्रियान्विति के लिये कोई पृथक निकाय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) किन-किन मदों में विदेशी पंजीपतियों को आधो से अधिक पूंजी लगाने की अनुमति दी जायेगी?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) से ( ) प्रश्न ही नहीं उठते।

निर्यात-प्रधान कताई मिल

4412. **श्री वासुदवन नायर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री निर्यात-प्रधान कताई मिलों के बारे में 24 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1699 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात-प्रधान कताई मिलों की स्थापना के बारे में सरकार ने इस बीच कोई अन्तिम निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो कितने मिल स्थापित करने का विचार है और कहाँ कहाँ लगाये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Memorandum from Teachers of Eastern Railway Boys High School, Danapur

4413. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 17 teachers of Eastern Railway, Railway Boys High School, Danapur had sent a memorandum to the Chairman, Railway Board on the 14th September, 1966; and

(b) if so, the decision taken thereon?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) It has not been possible to lay hands on any such memorandum.

(b) Does not arise.

छोटी कार परियोजना

4414. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री देवराज पाटिल :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग का विचार पुन: छोटी कार परियोजना को खटाई में डालने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) योजना आयोग ने जिसमें हाल ही में छोटी कार परियोजना के लिए साधन उपलब्ध कराने के बारे में परामर्श लिया गया था, अभी तक अपने अन्तिम विचार नहीं बताए हैं।

Steel Plant at Bailadilla (Madhya Pradesh)

4415. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a scheme has been formulated for the setting up of a steel factory at Bailadilla in Madhya Pradesh ;

(b) whether it is also a fact that preliminary survey in regard to the said factory has also been completed; and

(c) the reasons for not starting the construction of the said factory?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy): (a) to (c). Government have obtained several feasibility studies for setting up of new iron and steel plants in new locations including the Bailadilla region. The matter has however yet to be examined along with other projects in the light of the overall demand for iron and steel and the resources available for the implementation of the development programme in the country as a whole.

Sleeper Coach Attached to 33 Up Train

4416. Shri Ram Avtar Sharma: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that only 32 seats have been provided in the sleeper coach attached to 33 Up train which starts from Indore for Bilaspur;

(b) whether it is also a fact that the said seats are very inadequate to meet the demand of the travellers;

(c) whether it is further a fact that prior to this, sleeper coach attached to this train had a capacity of 75 seats:

(d) if so, the reasons for the withdrawal of 75 seats sleeper coach; and

(e) whether Government propose to reintroduce the 75 seats sleeper coach with a view to remove the difficulties of the travellers; and if not, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) No. The number of III class sleeper berths available on the train in question is 56, viz 32 in a partial 3-tier III class sleeper coach and 24 in a two-tier III class sleeper coach.

(b) No.

(c) Yes.

(d) Inadequate utilisation of the coach having 75 berths.

(e) No, because the present provision of 56 berths is adequately meeting the demand.

Woollen Liveries to Ticket Examiners of Central Railway

4417. Shri Ram Avtar Sharma: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that overcoats along with woollen liveries are provided to the Ticket Examiners on the Northern, Western and North Eastern Railways;

(b) whether it is also a fact that this facility is not provided to the Ticket Examiners on the Central Railway; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Overcoat is a 'protective clothing' which has not been standardised and each Railway provides them according to local conditions.

Prices of H.M.T. watches

4418. Shri Ram Avatar Shastri: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Hindustan Machine Tools Ltd., has increased the prices of Janata, Citizen, Sujata and other watches manufactured by it; and

(b) if so, by how much and the reasons therefor?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed): (a) and (b). Consequent on raising the freight by I.A.C., the Hindustan Machine Tools increased the prices of their watches to that extent. After protracted negotiations I.A.C. have now agreed to drop the increase. The increased rates were in force from middle of November 1967 to middle of March 1968. Watches are now being sold at old rates.

North-Eastern Railway Passengers Safety Council

4419. **Shri Ram Avatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether North Eastern Railway Passengers Safety Council have sent a letter addressed to him in connection with their fifteen point demands;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) Yes.

(b) A statement is attached. [*Placed in Library. See No. LT-511/68*]

(c) A statement will be laid on the Table of the Sabha.

श्री लंका में औद्योगिक विकास के लिए सहयोग

4422. **श्री दामानी :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार ने अपने यहां औद्योगिक विकास के लिये तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं.

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

सीमेन्ट आवंटन तथा समन्वय संगठन

4423. **श्री जुगल मंण्डल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 20 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 167 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट आवंटन तथा समन्वय संगठन के विरुद्ध इस बीच जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मामला परीक्षान्तर्गत है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कागज का दाम

4424. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** 20 फरवरी, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 155 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज के मूल्य के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) अभी, नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में नये उद्योग

4425. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में कितने तथा कौन-कौन से नये उद्योग आरम्भ किये गये हैं ;

(ख) क्या राज्य के औद्योगिक विकास की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) निकट भविष्य में इस राज्य में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कौन-कौन से नये उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Imports and Exports to U.K., U. S. S. R. and—West Germany

4426. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) the commodities imported by India from the U.S.S.R., U.S.A., U.K. and West Germany from January, 1967 to date and the quantities thereof;

(b) the commodities which would be exported to these countries during 1968-69; and

(c) the amount of foreign exchange likely to be earned therefrom?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) A Statement is attached. [*Placed in Library. See No. LT-512/68*]

(b) All permissible items for export can be exported to U.S.S.R., U.S.A., U.K., West Germany during 1968-69 as required by them.

(c) It is not possible to estimate the earnings of foreign exchange during 1968-69 precisely.

बैटरी सेलों का निर्माण

4427. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में बैटरी सैल बनाने वाले विदेशी और भारतीय मालिकों के कारखानों की संख्या और उनके नाम क्या हैं तथा वे किन-किन स्थानों में हैं और प्रत्येक कारखाने में कितनी पूंजी लगी हुई है;

(ख) उनके निदेशकों के नाम क्या हैं और यदि उनमें कोई विदेशी सहयोग है, तो प्रत्येक का ब्यौरा क्या है तथा पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक कारखाने द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किये गये उत्पादों के नाम उनका ब्यौरा तथा उनकी मात्रा और मूल्य क्या है; और

(ग) प्रत्येक कारखाने द्वारा उपरोक्त अवधि में प्रतिवर्ष कितने मूल्य के बैटरी सैलों का किन-किन देशों को निर्यात किया गया?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बैटरी सैलों का निर्माण करने वाले कारखानों में कर्मचारी

4428. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैटरी सैल बनाने वाली कम्पनियों में प्रत्येक कम्पनी में कितने-कितने कर्मचारी काम करते हैं और उनके वेतन आदि का वार्षिक बिल कितना है; और

(ख) प्रत्येक कम्पनी में कितने विदेशी कर्मचारी काम करते है, उनका वेतन कितना है तथा वे विदेशों को प्रतिवर्ष कितना धन भेजते हैं?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बैटरी के सैलों का निर्माण करने वाली कम्पनियों द्वारा मुनाफा

4429. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैटरी सैलों का निर्माण करने वाली विदेशी कम्पनियों ने पांच वर्षों में विदेशों को मुनाफे की कितनी धनराशि भेजी; और

(ख) प्रत्येक कम्पनी को उक्त अवधि में प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई और किन-किन वस्तुओं का आयात किया गया तथा ये वस्तुएं किन विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आयात की गई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

4430. **श्री चं० चु० देसाई** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण जनवरी, 1968 में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, धनबाद की कोयले की कुल खरीद 9.156 लाख टन रही जबकि दिसम्बर, 1967 में यह मात्रा 9.165 लाख टन थी;

(ख) क्या यह सच है कि खानों के मुहानों पर कोयले की मात्रा दिसम्बर, 1967 के अन्त में 10.106 लाख टन से बढ़ कर जनवरी, 1968 के अन्त तक 10.663 लाख टन हो गई थी;

(ग) क्या 1967-68 में कोयले का अधिक उत्पादन होने के बावजूद भी स निगम ने इस वर्ष वित्तीय घाटा दिखाया है;

(घ) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा हाल में आरम्भ किये गये विभिन्न परियोजनाओं की पूंजी लागत में पर्याप्त वृद्धि के साथ-साथ 1968–69 के लिये तैयार किये गये बजट में अधिक घाटा दिखाया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयले का अपकर्ष स्थैतिक रहा। तथापि, कुछ क्षेत्रों में कम संख्या में रेल के डिब्बों के मिलने के कारण उत्पादन और प्रेषण दोनों पर दुष्प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप दिसम्बर, 1967 के 8.94 मीटरिक टन की तुलना में जनवरी 1968 में 8.91 लाख मीटरिक टन कोयले का प्रेषण हुआ। इस के परिणामस्वरूप गर्त-मुख संग्रह जो 31 दिसम्बर, 1967 को 10,10,665 मीटरिक टन था, 31 जनवरी, 1968 को बढ़ कर 10,67,132 मीटरिक टन हो गया।

(ग) इस समय यह संकेत देना संभव नहीं जो इस वर्ष निगम को वित्तीय हानि होगी या लाभ।

(घ) और (ङ). 1968–69 के बजट प्रस्तावों से पर्याप्त हानियों के संकेत नहीं मिलते। तथापि, कुछ ऐसे मामले ध्यान में आए हैं जहां पर कुछ प्रायोजनाओं पर पूंजीगत लागत मूल प्रायोजना अनुमानों से बढ़ गई थी। इस अधिकता के मुख्य कारण यह हैं—(1) मजदूरी और सामग्री के मूल्य में वृद्धि; (2) डिजाईन और विशिष्ट विवरणों में परिवर्तन; (3) मूल प्रायोजना रिपोर्टों अनुमानों में आपरिवर्तन; और (4) अवमूल्यन के कारण आयातित उपकरणों और फालतू पुर्जों के मूल्य में वृद्धि।

कोयले का न मिलना

4431. **श्री चं० चु० देसाई :** क्या **इस्पात खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि बढ़िया कोटि का कोयला उपलब्ध न होने के कारण, उप-भोक्ता ईंधन तेल का उपयोग करते हैं, यद्यपि वह महंगा होता है;

(ख) क्या यह देश के अहित की बात नहीं कि अपनी तेल सम्बन्धी आवश्यकताओं को स्थानीय उत्पादन से पूरा न कर सकने के कारण, पर्याप्त मात्रा में तेल का आयात करना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार का विचार आयात से निर्यात अधिक करने की स्थिति तक कोयले का अधिक उपयोग करने तथा ईंधन तेल का उपयोग कुछ विशेष कार्यों के लिए नियमित करने का है;

(घ) क्या यह भी सच है कि बिहार सरकार ने कोयले की रायल्टी दरों में प्रति टन 50 पैसे की और वृद्धि कर दी है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) नहीं महोदय।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विभिन्न प्रकार के कोयलों का प्रयोग मुख्यत: एक दूसरे के उपयोग के तुलनात्मक आर्थिक प्रतिफलों पर निर्भर होता है।

(घ) नहीं, महोदय।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भेजीपुत में रेलवे स्टेशन

4432. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में गरजाम तथा पुरी ज़िलों की सीमा पर दक्षिण-पूर्व रेलवे में भेजीपुत में एक रेलवे स्टेशन खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यह स्टेशन कहाँ स्थापित करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ।

(ख) हावड़ा से 538/8 किलोमीटर पर खड़गपुर-वालतेरु खंड के चिल्का और खल्लीकोटा स्टेशनों के बीच भेजीपुत में हाल्ट स्टेशन खोलने के लिये 1962 में प्रस्ताव मिला था और उसकी जाँच की गयी थी। यह प्रस्ताव इंजीनियरी दृष्टिकोण से व्यावहारिक नहीं पाया गया क्योंकि इसके लिये काफी दूरी में रेल-पथ की रीग्रेडिंग करनी पड़ती और कुछ पुलों पर प्रभाव पड़ता। इसलिये यह प्रस्ताव छोड़ दिया गया।

दिल्ली से भुवनेश्वर को सीधी रेलगाड़ी

4433. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली से भुवनेश्वर को कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं जाती;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली से पुरी को सीधी रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो कब ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिल्चर नगर के निकट रेल का ऊपरी पुल

4434. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता तथा क्षेत्रीय उपभोक्ता रेलवे सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा सिल्चर नगर के निकट रेल का उपरि-पुल बनाये जाने की माँग की जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हाँ, असम सरकार ने, नवम्बर 67 में, अनन्तिम रूप से सिल्चर टाउन में रेलवे लाइन के ऊपर एक सड़क पुल बनाने की माँग की थी।

(ख) रेलें, वर्तमान समपारों की जगह रेलवे लाइन के ऊपर/नीचे पुल तभी बनाती हैं जब ऐसी योजनाएं राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित की जाय और साथ ही, वर्तमान नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार–सड़क प्राधिकारी निर्माण लागत में अपना हिस्सा देने को राज़ी हों। रेलवे लाइन के ऊपर/नीचे पुलों के निर्माण का वार्षिक कार्यक्रम राज्य सरकार के परामर्श से अन्तिम रूप से तैयार किया जाता है। तदनुसार रेलवे ने असम सरकार की स्थिति से अवगत करा दिया है। उक्त ऊपरी सड़क पुल के बारे में राज्य सरकार का अन्तिम निर्णय अभी नहीं मिला है।

अखबारी कागज का उत्पादन

4435. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखबारी कागज की हमारी कुल आवश्यकता को 80 प्रतिशत कागज़ विदेशों से आयात करके पूरा किया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो देश में अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि उसका आयात काफी कम हो सके ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हाँ।

(ख) देश में अखबारी कागज का उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) अखबारी कागज उद्योग को, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस प्राप्त करने वाले उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है।

(2) अखबारी कागज पर से उत्पादन शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(3) देश में वर्तमान अखबारी कागज कारखाने की क्षमता 30,000 मी० टन से बढ़ा कर 75,000 मी० टन प्रति वर्ष कर दी गई है।

(4) सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज परियोजना के लिए एक सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(5) हिमाचल प्रदेश में एक प्राइवेट पार्टी द्वारा अखबारी कागज का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए वह हिमाचल प्रदेश के प्राधिकारियों के साथ कच्चे माल की पूर्ति के बारे में बात-चीत कर रही है।

अखबारी कागज का उत्पादन

4436. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोई ऐसा समवाय है जो गन्ने की खोई से अखबारी कागज का निर्माण कर रहा है और यदि हां, तो यह कागज की हमारी मांग कितनी प्रतिशत पूर्ति कर रहा है;

(ख) क्या खोई से अखबारी कागज के उत्पादन के लिये और बड़े कारखानों की स्थापना में कोई कठिनाइयां हैं; और

(ग) यदि हां, तो व क्या है और कुछ कारखानों की स्थापना में क्या कठिनाइयां हैं क्योंकि भारी मात्रा में खोई का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) देश मे खोई पर आधारित अखबारी कागज का कारखाना लगाने में निम्नलिखित कठिनाइयां हैं :—

चीनी मिल अखबारी कागज बनाने के लिए खोई को बेचना आर्थिक तथा तकनीकी दृष्टि से कम आकर्षक समझती है क्योंकि वे खोई को तैयार तथा सस्ते ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। इस ईंधन का विकल्प तेल भट्टी अथवा कोयला भट्टी है। भट्टी मे इस्तेमाल होने वाला तेल अधिक महंगा है और इसके लिए वर्तमान बायलरों को बदलना पड़ेगा। जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, चीनी मिलों को इस पूर्ति को नियमित तथा कम मल्य पर मिलने में संदेह है।

(2) संसार मे खोई के मुख्य कच्चे माल पर आधारित अखबारी कागज का व्यालसायिक उत्पादन अभी स्थापित किया जाना है इसलिए इस दिशा में हमें सोच-समझ कर कदम बढ़ाना होगा ।

(3) गन्ने की खेती में धीरे-धीरे कमी होने तथा गन्ने के बहुत बड़े अंश का गुड़ और खांडसारी बनाने में इस्तेमाल किए जाने के कारण चीनी मिलों को कम गन्ना मिला है । इस लिए भविष्य मे कागज/अखबारी कागज उद्योग के लिए खोई का मिलना अनिश्चित हो गया है ।

मशीनी औजार निर्माताओं तथा उपभोक्ताओं की गोष्ठी

4437. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में मशीनी औजार निर्माताओं तथा उपभोक्ताओं की एक गोष्ठी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) गोष्ठी अगस्त, 1967 में हुई थी और इसका आयोजन सरकार द्वारा किया गया था ।

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों की ग्यारह परियोजनाओं की मशीनी औजारों की आवश्यकताओं पर सम्मिलित रूप से चर्चा हुई थी जिससे यह पता चला कि ये आवश्यकता अधिकांश रूप से देश में ही पूरी की जा सकती हैं । मशीनी औजार निर्माताओं औजारों के आर्डर प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है । यह गोष्ठी उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को इकट्ठा करने का प्रथम प्रयास थी और इसका परिणाम यह निकला है कि एक दूसरे की क्षमता तथा समस्याओं के बारे मे जागरूकता उत्पन्न हो गई है ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

4438. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बाजार में मैंगनीज अयस्क के निर्यात में ब्राजील ही हमारा एकमात्र प्रतियोगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मूल्यों तथा निर्यात के बारे में नीति अपनाने के लिये ब्राजील के साथ कोई विचार-विमर्श करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) मैंगनीज अयस्क के निर्यात से सम्बन्धित सामान्य समस्याओं पर ब्राजील तथा अन्य सम्बद्ध निर्यातक देशों के साथ बातचीत करने का सरकार का विचार है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अरब देशों के साथ व्यापार

4439. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरब देश भारत के साथ व्यापार बढ़ाने का विचार कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बारे मे कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). अरब देशों के भारत के साथ बड़े मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध है और वे हमारे साथ व्यापार को और आगे बढ़ाने का स्वागत करेंगे । इस सम्भावना पर, उन देशों के साथ परामर्श करके निरन्तर विचार किया जाता है।

किन्तु सरकार को अरब देशों से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

ग्रेफाइट क्रूसिबल कारखाना

4440. **श्री नरसिन्हा राव** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार विदेशी सहयोग से एक ग्रैफाइट क्रूसिबल कारखाना चालू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कारखाने की स्थापना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और विदेशी कम्पनी का नाम क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

Setting up of New Cement Fectories

4441. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a private firm has been given licence for a Cement factory at Bundi;

(b) whether it is also a fact that three other cement actories are likely to be set up in the country. ;

(c) if so, the names of the places where these factories are a likely to be set up; and

(d) when the cement factory at Bundi is likely to be set up?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F A Ahmed): (a) and (d). In November, 1965, the scheme of a private party (of the Birla Goup) for setting up a cement factory at Bundi in Rajasthan with an annual capacity of 200,000 tonnes was approved and a letter of intent was also issued. The cement industry has been exempted from [the licensing provisions of Industries (Development and Regulation) Act, 1951 with effect from [13th May, 1966, and it is no longer necessary for anyone to obtain a licence for the setting up of cement factories. The party is understood to have completed detailed prospecting operations for limestone and applied for loans to the financial institution. It has also placed a provisional order on the machinery manufacturer for the supply of plant and machinery. In the meantime

the Ministry of Railways have informed that the proposed Kota-Bundi-Chittorgarh line will be heavily unremunerative and hence the railway line from Kota to Bundi and Chittorgarh has been dropped for the present. In view of the above, the party has now informed that they have deferred the idea of the setting up of a cement factory at Bundi till the construction of a railway line materialises.

(b) and (c). The following new cement factories are likely to be set up in the country during the Fourth Five Year Plan period:

	Place		*Capacity (in million tonnes)*
1.	Ramagundam	(A.P.).	0·20
2.	Mandhar	(M.P.)	0·20
3.	Karur	(Madras)	0·40
4.	Alangulam	(Madras)	0·40
5.	Ghugus	(Maharashtra)	0·40
6.	Wadi	(Mysore)	0·40
7.	Kurkunta (Seram)	(Mysore)	0·20
8.	Udaipur	(Rajasthan)	0·20
9.	Dalla	(U.P.)	0·46

रूस को खेल के सामान का निर्यात

4442. **श्री राजदेव सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से देश भारत से खेल के सामान का आयात करते हैं और प्रत्येक देश द्वारा प्रति वर्ष कितने मूल्य के खेल के सामान का आयात किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि रूस इस देश के खेल के सामान का बहुत पहले से आयात करता रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या रूस ने यह क्रयादेश अब पाकिस्तान को देना आरम्भ कर दिया है और भारत को इस वर्ष कोई क्रयादेश नहीं दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) गत तीन वर्षों की अवधि में खेल के सामान का आयात करने वाले मुख्य देशों को उसके निर्यात का मूल्य दर्शन वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 513/68]**

(ख) रूस में 1963 मे पहली बार भारतीय खेल सामान में दिलचस्पी दिखलाई। इस देश को निर्यात निम्न प्रकार रहा है :—

वर्ष	मूल्य लाख रुपये में
1963	4.04
1964	0.15
1965	7.90
1966	5.40
1967	—

(ग) ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि रूस ने खेल का सामान अब पाकिस्तान से खरीदना आरम्भ कर दिया है ।

दिल्ली क्षेत्र में उपनगर सेक्शन पर रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना तथा अधिक गाड़ियां चलाना

4443. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली क्षेत्र में उपनगर सैक्शन पर रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाई जाये तथा अधिक गाड़ियां चलाई जायें ;

(ख) क्या यह सच है कि सरोजनी नगर से दिल्ली मेन स्टेशन तक 15 किलोमीटर की दूरी तर करने में औसतन एक घंटे से भी अधिक समय लगता है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा): (क) दिल्ली क्षेत्र में उत्तर रेलवे के उपनगरीय खंडों पर गाड़ियों का आना जाना बढ़ाने के उद्देश्य से 1-12-1967 से नयी दिल्ली और गाज़ियाबाद, नयी दिल्ली हापुड़, नयी दिल्ली और बल्लभगढ़, और दिल्ली और गढ़ी हरसरू के बीच चार जोड़ी अतिरिक्त गाड़ियां चलायी गयी हैं । साधनों की परिमित उपलब्धता के भीतर इन में और वृद्धि करने का विचार है ।

रेल-पथ और कर्षण के वर्तमान प्रकार और सीज़न टिकट पर यात्रा करने वालों की सुविधा के लिए आवश्यक गाड़ियों के न्यूनतम ठहरावों के अनुसार दिल्ली क्षेत्र में उपनगरीय गाड़ियों की अनुमत रफ्तार निर्धारित की जाती है, इसलिए फिलहाल इन गाड़ियों की रफ्तार में वृद्धि करने की कोई गुंजाइश नहीं है ।

(ख) जी हां । एक घंटे से अधिक के यात्रा-समय में रास्ते के 7 ठहरावों का समय और विकास सम्बन्धी कामों के लिए इंजीनियरिंग समय शामिल हैं ।

(ग) जब कभी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, रफ्तार बढ़ाने के प्रश्न पर यथोचित विचार किया जायेगा ।

रेलवे में "कंटेनर सर्विस"

4444. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में अब तक आरम्भ की गई कंटेनर सर्विस पर अब तक कुल कितना धन व्यय हुआ है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में कंटेनर सर्विस से कितनी आय हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) भारतीय रेलो में शुरू की गयी तीन कन्टेंनर सेवाओं पर 29 फरवरी, 1968 तक कुल संचालन व्यय लगभग 8 22,701 रुपये है ।

तीनो सेवाओं के लिये कंटेनर और फ्लैट, सड़क वाहन, गैराज आदि परिसम्पत्तियो पर लगभग 28,90,814 रुपये खर्च हुए ।

(ख) 29 फरवरी, 1968 तक तीनों कंटेनर सेवाओं से रेलों को लगभग 11,33,395 रु० की आमदनी हुई है

रूस के साथ व्यापार प्रणाली

4445. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968 के लिये नई व्यवस्था में रूस तथा भारत के बीच व्यापार प्रणाली तथा प्रक्रिया में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य परिवर्तन किये गये हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) भारत और सोवियत रूस के मध्य हाल में कोई नया व्यापार करार नहीं हुआ है क्योंकि 10-6-63 को हुआ चालू करार 31 दिसम्बर 1970 तक वैध है। वर्ष 1968 में दोनों देशों के मध्य परस्पर आदान-प्रदान की जाने वाली वस्तुओं के बारे में 26-12-67 को निर्णय किया गया था। इस प्रकार वर्ष 1968 में भारत तथा सोवियत रूस के मध्य व्यापार की पद्धति एवं क्रियाविधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

पश्चिमी बंगाल में इंजीनियरिंग उद्योग

4446. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग उद्योग के संकट के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई रिपोर्ट भेजी है;

(ख) क्या इस रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि केन्द्र से कम क्रयादेश प्राप्त होना ही इस संकट का एक मुख्य कारण है; और

(ग) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) भारत सरकार के निवेदन के उत्तर में पश्चिमी बंगाल सरकार ने इंजीनियरी उद्योगों में मन्दी के मोटे तौर पर कारण बताते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इनमें आर्डरों में कमी किन्तु केन्द्रीय सरकार के संगठनों से मिलने वाले आर्डरों में उतनी कमी नहीं गई है जिससे सामान्य बाजार के भावों पर असर पड़े निर्यात की संभावना कम हो जाना ऋण संबंधी सुविधाओं का अभाव तथा खाद्य एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के सामान्य रूप से मूल्य बढ़ जाना आदि कारण शामिल हैं।

(ग) मंदी के प्रभाव को कम करने के लिये भारत सरकार द्वारा पहले ही किये गये उपायों में विभिन्न विधान कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करना है ताकि पूंजीगत वस्तुओं की मांग यथासम्भव उत्पन्न की जा सके। प्रभावित उद्योगों के उत्पादन क्रम में विविधता लाना सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में और अधिक सुदृढ़ ढांचा निर्यात की मण्डियों के विकास पर बल देना तथा उस सीमा तक आयात पर रोक लगाना जहां तक देश की स्थापित क्षमता से आवश्यकता पूरी हो सकती है। इसमें ऐसे आयात जिनके लिए पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है किन्तु उसके लिए

बचन नहीं दिया गया का पुनरीक्षण करना और उदार ऋण नीति घोषित करना जिसमें बैंक दर में की गई कमी की घोषणा भी सम्मिलित है ।

डम डम से प्रिन्सेसघाट और डमडम से बालीगंज तक रेलवे लाइनें

4447. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री अब्दुल हमीद :
श्री भगवान दास :
श्री अनिरुद्धन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में डमडम से खारी झील क्षेत्र में से होकर बालीगंज जाने वाली और दूसरी डम डम से प्रिंसेसघाट जाने वाली रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण-कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण-कार्य कब पूरा होने की सम्भावना है;

(ग) क्या इस परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) लगभग 75 प्रतिशत ।

(ख) सितम्बर, 1968 तक ।

(ग) और (घ) योजना आयोग इस प्रायोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के सम्बन्ध में विनिश्चय उस समय करेगा जब सर्वेक्षण पूरा हो जाये और योजना आयोग का महानगर परिवहन दल जिसके संरक्षण में यह कार्य हो रहा है रिपोर्टों की छान-बीन कर ले ।

रेलवे विद्युतीकरण परियोजना, कलकता के कर्मचारी

4448. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री भगवान दास :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विद्युतीकरण परियोजना कलकत्ता, के कर्मचारियों ने 12 फरवरी, 1968 को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कलकत्ता के कार्यालय में सामुहिक रूप से धरना दिया;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं; और

(ग) उनकी पूर्ति के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा): (क) और (ख) मालूम हुआ है कि रेल बिजली योजना के कुछ लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने, रेल बिजली संगठन के ढांचे के पुनर्गठन से सम्बन्धित आदेशों

के विरोध में, 12-2-68 को मुख्य प्रशासी अधिकारी, रेल बिजली योजना, कलकत्ता के कार्यालय में 'बैठे रहो' हड़ताल की थी ।

(ग) कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है ।

दुर्गापुर स्टेशन पर पहले दर्जे के महिला प्रतीक्षालय में काम करने वाली आया

4449. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री भगवान दास :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर स्टेशन पर पहले दर्जे के महिला प्रतीक्षालय के लिये आया नियुक्त की जाती थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि फरवरी, 1968 में आया का पद समाप्त किये जाने से महिला यात्रियों को असुविधा हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो उस पद के समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) देखा गया था कि महिला प्रतीक्षालय का उपयोग कभी कभी किया जाता है इसलिए मितव्ययता के आधार पर 'आया' का पद खत्म कर दिया गया । पास में स्थित पुरुषों के प्रतीक्षालय का बेयरा महिलाओं के प्रतीक्षालय से सम्बन्धित काम का भी ध्यान रखता है । अभी तक, इसके कारण असुविधा होने की कोई शिकायत नहीं मिली है ।

कपड़ा निगम

4450. **श्री अब्राहम :**
श्री अनिरुद्धन :
श्री उमानाथ :
श्री रमानी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा निगम बनाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इसके कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) वस्त्र निगम की स्थापना करने का निर्णय किया जा चुका है । इस समय इसके पंजीकरण से सम्बन्धित औपचारिकताओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है और लगभग एक महीने में निगम के स्थापित हो जाने की आशा है ।

मोडल वूलन मिल्स, बम्बई

4451. **श्री अब्राहम :**
श्री नम्बियार :
श्री नायनार :
श्री उन्नानाथ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री मोडल वूलन मिल्स, बम्बई के 13 फरवरी, 1968 के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय जांच विभाग के जांच प्रतिवेदन की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा जांच कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) मामला अभी विचाराधीन है ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं के आयात के लिये लाइसेंस

4452. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री अनिरुद्धन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 13 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं के लिये आयात लाइसेंस देने के बारे में भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक संस्था, कोचीन से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) उद्योग की मांग को, जिस में निर्यातक एककों की मांग भी शामिल है और जिसके लिये अभ्यावेदन दिया गया है, पूरा करने के लिये मछली पकड़ने की नौकाओं (ट्रालरों) के आयात के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

कन्नानूर सहकारी कताई मिल

4453. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० गोपालन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्नानूर सहकारी कताई मिल का विकास करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस योजना के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई है ; और

(घ) कब तक काम आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (घ) केरल सरकार का इस मिल की वर्तमान क्षमता को 25,000 तकुओं तक बढ़ाने का विचार है, जिसके लिये उसके पास दो बार में, लगभग छः छः हजार तकुएं लगाने का एक लाइसेंस है । पहले चरण में 34.77 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है और इस के शीघ्र ही क्रियान्वित किये जाने की संभावना है । राज्य सरकार पहले ही इस मिल के लिये 1 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर कर चुकी है ।

केरल में क्षेत्रीय व्यापार निगम

4454. **श्री प्र० क० गोपालन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री म० गोपालन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने राज्य व्यापार निगम के नमूने का एक क्षेत्रीय राज्य व्यापार निगम बनाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार को सूचित किया गया है कि राज्य सरकार का विचार एक वाणिज्यिक निगम स्थापित करने का है ।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बड़ोदा के मैसर्स साराभाई मार्क को आयात लाइसेंस

4455. **श्री नम्बियार :**
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री नायनार :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री जार्ज फरनेंडीज :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 13 फरवरी, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा के मैसर्स साराभाई मार्क द्वारा आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के आरोपों के बारे में जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मैसर्स कूपर एलन कम्पनी

4456. **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री पी० राममूर्ति :
श्री गणेश घोष :
श्री रमानी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने मैसर्स कूपर एलन कम्पनी लि०, कानपुर को खरीदने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सौदे की शर्तें तथा निबन्धन क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से एक पत्र मिला है जिसमें सुझाव दिया गया है कि राज्य व्यापार निगम, कूपर एलन कम्पनी लि०, कानपुर को अपने हाथ में ले कर अपने प्रबन्ध में चलाए । निगम के परामर्श से मामला सरकार के विचाराधीन है ।

खेत्री तांबा खान में एक मजदूर की मृत्यु

4457. **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री चक्रपाणि :
श्री रमानी :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेत्री तांबा खानों में काम करने वाला एक मजदूर 31 जनवरी, 1968 को एक दुर्घटना में मर गया था;

(ख) यदि हां, तो उस की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई;

(ग) क्या खेत्री तांबा खान के मजदूरों ने 1 फरवरी, 1968 को प्रदर्शन किया था और यह मांग की थी कि जिन डाक्टरों ने इस मजदूर की चिकित्सा से इन्कार कर दिया था उनको मुअत्तिल कर दिया जाये; और

(घ) यदि हां, तो प्राधिकारियों ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): (क) और (ख) खेत्री तांबा परियोजना की कर्मशाला का एक ड्राइवर, जो ट्रक के आगे खड़ा था, 31 जनवरी, 1968 के दोपहर के दो बज कर 15 मिनट पर उस ट्रक और एक स्कूल बस के आगे के भागों में फंस गया । उसे तत्काल हस्पताल पहुंचाया गया और चूंकि चोट के कारण बड़े आपरेशन की आवश्यकता थी, अतः

उसे चिकित्सा सहायता देने के बाद एम्बुलेन्स गाड़ी में कम्पाउंडर के साथ पिलानी हस्पताल भेजा गया । वह पिलानी हस्पताल में अगले दिन अर्थात् 1 फरवरी, 1968 को प्रातः पांच बजे मर गया ।

(ग) दाह संस्कार कर के वापस आ रहे कर्मचारियों के एक दल ने परियोजना हस्पताल के दो डाक्टरों पर आक्रमण कर दिया और तदन्तर हस्पताल के भवन को घेर लिया । उन्होंने आरोप लगाया कि मृतक को दी गई चिकित्सा सहायता अपर्याप्त थी और डाक्टरों को निलम्बित करने की मांग की ।

(घ) परियोजना अधिकारियों ने राज्य सरकार से प्रार्थना की कि वह मृतक को अपर्याप्त चिकित्सा सहायता दिये जाने के आरोप के विषय में पूछताछ करने के लिए एक डाक्टर को नियुक्त करें । पुलिस ने भी डाक्टरों पर आक्रमण और दंगा आदि के विषय में छानबीन की है और 12 व्यक्तियों का चालान किया है ।

केरल में सहकारी कताई मिल

4458. **श्री अनिरुद्धन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री प० गोपालन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में दो सहकारी कताई मिल चालू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मिलों के लिये कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) केरल राज्य के सहकारी क्षेत्र में स्थापित करने के लिये 25,000 तकुओं वाली दो कताई मिलों का नियतन किया गया था । राज्य सरकार का विचार इन मिलों में से एक को हैन्डलूम अपेक्स सोसाइटी के माध्यम से त्रिवेन्द्रम में तथा दूसरी को एक सहकारी सोसाइटी के माध्यम से, जो गठित की जानी है, कोजीकोड में स्थापित करने का है । त्रिवेन्द्रम में मिल की स्थापना करने का प्रस्ताव क्रियान्वित किया जा रहा है ।

(ग) केरल सरकार से पता चला है कि किसी धनराशि का नियतन नहीं किया गया है ।

कोकिंग कोयला

4459. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोकिंग कोयले के उत्पादकों को 'सैंट स्टोइंग' के कारण हानि हो रही है, क्योंकि 'स्टोइंग' के लिये दी जाने वाली राज सहायता वर्तमान लागत से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि होती है; और

(ग) कोंकिग कोयले के जो कि 'पिलरो' में पड़ा है और जिस की इस्पात संयत्रों को तुरन्त आवश्यकता है खनन हेतु 'स्टोइंग' को प्रोत्साहित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) राज सहायता की अपर्याप्तता के विषय में कुछ प्रतिवेदन हुए हैं । यह सारा प्रश्न विस्तृत अध्ययन के लिए एक अध्ययन दल को सौंपा गया है। अध्ययन दल की रिपोर्ट मिल जाने पर इस बारे में जांच की जायेगी कि राज सहायता संबंधी योजना को किस सीमा तक उदार या युक्तिसंगत बनाये जाने की आवश्यकता है । तथापि कोयला बोर्ड ने कोयला खानों को नौभरण के लिए रेत देने के लिए उसके अधिक परिमाण में परिवहन की एक महत्वकांक्षी योजना को हाथ में लिया है।

उड़ीसा में क्रोमाइट के लिये खनन पट्टा

4460. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67, 1967-68 और 1968–69 में उड़ीसा में क्रोमाइट के लिये कोई खनन पट्टा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस को और कहां ;

(ग) क्या उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र में विदोहन के लिये क्रोमाइट अयस्क वाले क्षेत्रों को आरक्षित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना उड़ीसा राज्य सरकार से मंगवाई गई है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अमरीका द्वारा प्रैस-ब्रेकों का आयात

4461. **श्री दे० अमात** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हैदराबाद से प्रैस-ब्रेकों के आयात के कोई क्यादेश दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और कितने मूल्य के प्रैस-ब्रेकों का निर्यात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) जी, हां । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हैदराबाद को प्रैस-ब्रेकों की पूर्ति के लिए सं०रा० अमरीका से एक आर्डर मिला है। आर्डर का मूल्य लगभग 10 लाख रु० है ।

राजस्थान में जिप्सम के भण्डार

4462. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में जिप्सम के भण्डार पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में खुदाई कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ग) प्रति वर्ष कितना जिप्सम निकालने की सम्भावना है; और

(घ) क्या सरकार का विचार जिप्सम का निर्यात करने का है और यदि हां, तो उस से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सिगनल तथा दूर-संचार शाखा के कर्मचारी

4463 **श्री क० कृ० नायर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिगनल और दूर-संचार शाखा के कर्मचारियों को सिगनल तथा दूर-संचार उपकरणों के खराब हो जाने तथा ठीक काम न करने पर उनको ठीक करने के लिये उनके ड्यूटी के नियमित समय के बाद भी बुलाया जाता है और उनको अतिरिक्त काम के लिये न तो समयोपरी भत्ता दिया जाता है और न ही उन्हें अतिरिक्त छुट्टी अथवा अतिरिक्त विश्राम के रूप में किसी प्रकार का मुआवजा दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे के सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों के लिये वर्दी

4464. **श्री क० कृ० नायर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिगनल और दूर-संचार क्षेत्र कर्मचारियों को किसी प्रकार की वर्दी नहीं दी जाती है जबकि गाड़ी परीक्षक, यार्ड फोरमैन, बिजली मिस्त्रियों और केबिन कर्मचारियों आदि को वर्दी दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अखिल भारतीय रेलवे अनुसचिवीय कर्मचारी एसोसिएशन

4465. **श्री नंजा गौडर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय रेलवे अनुसचिवीय कर्मचारी एसोसिएशन ने "क्लर्क" के पदनाम को बदल कर "असिस्टेंट" बनाने के लिये रेलवे बोर्ड से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री के० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इस अनुरोध को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं पाती।

मद्रास में बड़ी औद्योगिक परियोजनायें

4466. **श्री नंजा गौडर :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने (एक) इलैक्ट्रानिक उपकरण (दो) हैवी प्लेट तथा वेसेल तथा (तीन) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, मंगलौर के दूसरे कारखाने के निर्माण के लिए कुछ बड़ी औद्योगिक परियोजनाए स्थापित करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). हैवी प्लेट तथा वैसल्स निर्माण की परियोजना तथा इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज के दूसरे एकक को मद्रास में स्थापित करने हेतु मद्रास सरकार से निवेदन प्राप्त हुआ था । फिर भी इलेक्ट्रानिक उपकरणों के निर्माण की परियोजना स्थापित करने के लिए कोई निवेदन नहीं मिला था।

प्रथम हैवी प्लेट्स तथा वैसल्स के निर्माण की परियोजना की स्थापना विशाखापतनम में करने का निर्णय पहले ही किया जा चुका था। सरकार ने हैवी पलेट्स तथा वैसल्स की दूसरी परियोजना को मद्रास में स्थापित किए जाने पर विचार किया था किन्तु फिलहाल इस परियोजना को लागू न करने का निश्चय किया गया है।

लम्बी दूरी वाले संचार उपकरणों के निर्माण के लिये इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज के दूसरे एकक के स्थापना स्थल पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

Export of Steel

4467. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether the export of steel is likely to be increased because many countries have agreed to place orders for it;

(b) if so, the names of those countries; and

(c) the articles in respect of which offers have been received?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) (a) to (c): The increase in the export from year to year is due to the efforts of Indian exporters of Steel in general and Hindustan Steel Limited in particular to secure orders from foreign markets on a competitive basis. Recently a bulk contract for export of 6 lakh tonnes of steel at the rate of 2 lakh tonnes for the year 1968, 1969 and 1970 has been secured from U.S.S.R. The export will comprise steel sections such as beams, channels and angles for 1968. For subsequent years, the description and specifications of the items to be exported will be settled later.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

4468. **श्री क० लकप्पा :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से बाहरी देशों ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को जो क्रयादेश दिये थे उन्हें रद्द कर दिया है और अपने क्रयादेश अन्य गैर-सरकारी फर्मों को दे दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन देशों के नाम क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसूर में सरकारी उद्योग

4469. **श्री क० लकप्पा :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसूर में कई सरकारी उद्योगों के बारे में गैर-सरकारी उद्योगपति बातचीत कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगपतियों के नाम क्या हैं तथा बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

रेलवे में रेलगाड़ी परीक्षक

4470. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ी परीक्षकों के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के आदेश भेदभावपूर्ण हैं;

(ख) क्या इन आदेशों के विरुद्ध प्राप्त हुए अनेक अभ्यावेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है; और

(ग) क्या एक लेख याचिका प्रस्तुत होने पर सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेशों को रद्द कर दिया है और यदि हां, तो इन आदेशों को वापिस न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) से (ग). सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि पहले के अप्रेंटिस गाड़ी परीक्षकों को 205–280 रु० के वेतनक्रम में तरक्की देने के सम्बन्ध में रेल मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेश संविधान की शक्ति से परे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं और आवश्यक अनुदेश जारी किये जायेंगे ।

मनीपुर के मन्त्रियों को कारों की खरीद के लिए ऋण

4471. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 15 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4576 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिए 1 मार्च, 1968 को सभा-पटल पर रखे गये विवरण के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भूतपूर्व मंत्रियों ने जिन्होंने कार खरीदने के लिए ऋण लिये थे, अपने ऋण ब्याज समेत चुकता दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इन ऋणों को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

शराब का निर्यात और आयात

4472. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से कितने देशों को भारतीय शराब का निर्यात किया जा रहा है तथा कितने देशों से विदेशी शराब का आयात किया जा रहा है तथा उसकी मात्रा कितनी-कितनी है; और

(ख) शराब के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई तथा [उसके] आयात से कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख). विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 514/68**]।

आम के लदान से रेलवे को आय

4473. **श्री बे० ना० कुरील** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 से 1966-67 की अवधि में पश्चिम और दक्षिण रेलवे में आम की ढुलाई से रेलवे को कुल कितनी आय हुई ;

(ख) इसी अवधि में आप की ढुलाई के बारे में संबंधित पार्टियों को दावों की कितनी राशि दी गई;

(ग) 1967-68 के लिये इन दावों के विरुद्ध रेलवे को कुल कितनी धनराशि देनी है; और

(घ) आम की ढुलाई से पश्चिम और दक्षिण रेलवे को कितना शुद्ध मुनाफा हुआ ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) आम के परेषणों से होने वाली आमदनी के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते । स्टेशन के मूल अभिलेखों से इन आंकड़ों को छांटना एक भारी काम होगा । इसके अलवा इस अवधि के एक अंश के अभिलेख अब उपलब्ध नहीं होंगे । अतः खेद है कि यह सूचना नहीं दी जा सकती ।

(ख) और (ग). भुगतान किये गये दावों के आंकड़े वस्तु समूहों के कुछ मोटे वर्गों के अनुसार रखे जाते हैं । आमों के परेषणों के सम्बन्ध में पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । अलग-अलग

दावों की फाइलों मे सूचना निकालना व्यावहारिक नहीं होगा, क्योंकि उनकी संख्या हर वर्ष कोई छः लाख रहती है । अतः खेद है कि अपेक्षित सूचना नहीं दी जा सकती ।

(घ) भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में जो कुछ कहा गया है, उसे देखते हुए यह सूचना नहीं दी जा सकती ।

रेलवे में भ्रष्टाचार का उन्मूलन

4474. **श्री बे० ना० कुरील** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये बनाये गये सतर्कता विभाग में इस समय कितने कर्मचारी हैं;

(ख) इस विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है; और

(ग) रेलवे में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में यह विभाग कहां तक सफल रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 31-12-1967 को भारतीय रेलों के चौकसी संगठन के कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नलिखित थी :—

राजपत्रित—69

अराजपत्रित—755

(ख) भारतीय रेलों के चौकसी संगठन के सभी राजपत्रित और जांच करने वाले कर्मचारी रेलों के विभिन्न विभागों, जैसे यातायात, इंजीनियरिंग, भण्डार आदि से तथा राज्य पुलिस एवं प्रशासनिक संवर्गों से निश्चित अवधि के आधार पर लिये जाते हैं ।

(ग) इस बात का सही-सही अनुमान सम्भव नहीं है कि चौकसी संगठन की गतिविधियों के परिणामस्वरूप रेलों में भ्रष्टाचार किस सीमा तक समाप्त हुआ है ।

पत्थरों के लदान से रेलवे को आय

4475. **श्री बे० ना० कुरील** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65, 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में पत्थरों के लदान से रेलवे को कुल कितनी आय हुई ;

(ख) इसी अवधि में भारतीय रेलवे ने पत्थरों के लदान पर कुल कितनी धनराशि के दावे का भुगतान किया ; और

(ग) इसी अवधि मे मंगलौर की टाइलों पर रेलवे ने कुल कितनी धनराशि के दावों का भुगतान किया ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1964-65, 1965-66, 1966-67 में और 1967-68 की पहली छमाही में रेलों को संगमरमर सहित पत्थर के परेषणों से कुल जितनी

आमदनी हुई, वह इस प्रकार है :—

1964–65	7.77 करोड़
1965–66	8.46 करोड़
1966–67	10.42 करोड़
1967–68	4.48 करोड़

(अप्रैल से सितम्बर, 1967 तक)

(ख) और (ग). पत्थर और मंगलौर टाइलों के परेषणों के सम्बन्ध में दावों के भुगतान के आंकड़े अलग नहीं रखे जाते । सूचना तैयार करने के लिए अलग-अलग दावों की फाइलें देखनी होंगी जिनकी संख्या हर वर्ष पांच लाख से अधिक रहती है । इसलिए खेद है कि अपेक्षित सूचना नहीं दी जा सकती ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा जूतों का समाहार

4476. **श्री विद्याधर वाजपेयी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने कलकत्ता में एक कार्यालय खोला है जहां से वह प्रतिवर्ष 10,000 जोड़े जूतों का समाहार करता है ;

(ख) क्या 1967 में लुधियाना और करनाल से 70,000 जोड़े जूतों का समाहार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो करनाल और लुधियाना में पृथक्-पृथक् कारखाने न खोले जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कलकत्ता में राज्य व्यापार निगम का क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न देशों को निर्यात के लिए जूतों तथा चमड़े के संघटकों के प्राप्त करने का कार्य करता है । 1967 में राज्य व्यापार निगम ने कलकत्ता में 21,000 जोड़े जूतों तथा काउबाय अपर लैदर के 1,82,000 जोड़ों के आर्डर दिये ।

(ख) 1967 में लुधियाना तथा करनाल में संभरणकर्ताओं को क्रमशः 7,320 तथा 33,760 जोड़ों के आर्डर दिये गये थे ।

(ग) करनाल तथा लुधियाना के जूतों की प्राप्ति राज्य निर्यात निगम के माध्यम से की जाती है तथा राज्य व्यापार निगम इस कार्य के लिए एक पृथक् कार्यालय खोलना आवश्यक नहीं समझता । निगम ने इन क्षेत्रों में एक वरिष्ठ निरीक्षक रखा है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा लिये गये जूतों का मूल्य

4477. **श्री विद्याधर वाजपेयी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने 1956 से लेकर 1967 की अवधि के दौरान रूस और बुल्गारिया को निर्यात किये गये जूतों की प्रति जोड़ी पर 10 से लेकर 15 रुपये तक कमीशन ली थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Enquiry Office at Banda Junction

4478. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no Enquiry Office at Banda Junction ; and

(b) if so, the time by which it would be provided there ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) There is no separate Enquiry Office at Banda. Public telephones are, however, provided at the station and public enquiries are attended to by the station staff.

(b) There is no proposal to provide a separate Enquiry Office.

Lucknow-Banda Express and Kanpur-Banda Passenger Trains

4479. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Lucknow-Banda Express and Kanpur-Banda Passenger trains, starting from Lucknow and Kanpur, respectively on the Northern Railway are daily leaving late from these stations consequent to which the passengers travelling by these trains are not able to catch trains running on Jhansi-Manikpur section on the Central Railway ; and

(b) if so, the steps Government propose to take to check the late running of the said trains ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No, not daily. While the connections with 522 Up/523 Dn. Manikpur-Jhansi Passengers were maintained on all but one day, the maintenance of connections with 521 Dn./524 Up has not been satisfactory.

(b) A special watch is kept on the punctuality of these trains and maintenance of connections with the trains running on Jhansi-Manikpur section. Since the punctuality performance of Lucknow-Banda Express and Kanpur-Banda passenger trains has been appreciably affected by heavy incidence of alarm chain pulling, special steps to minimise such cases are being taken in consultation with the State Governments and Police Authorities.

सल्फर का आयात करने के लिये लाइसेंस

4480. **श्री शिवप्पा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने करोड़ों रुपये की सल्फर, अमोनिया और फासफेट का आयात करने के लिये हाल में बम्बई में किन्हीं कम्पनियों को आयात लाइसेंस दिये हैं ;

(ख) क्या इस बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) सल्फर के आयात के लिये दिये गये आयात लाइसेंसों का एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है [पुस्तकालय में रखा गया।

देखिये संख्या एल०टी० 515/68] अमोनिया तथा फासफेट के आयात के लिये बम्बई की किसी भी फर्म को कोई लाइसेंस नहीं दिया गया ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हसन-मंगलोर रेलवे लाइन

4481. श्री शिवप्पा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में हसन-मंगलोर रेलवे लाइन के निर्माण कार्य की कितनी प्रगति हुई है तथा उस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितनी सुरंगें बनाई गईं ; और

(ग) इस लाइन के निर्माण कार्य में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

रेल-मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1967 में मंगलूर-पानाम्बूर सम्पर्क लाइन और हसन से मगलूर तक मुख्य लाइन के निर्माण में क्रमशः 8 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत प्रगति हुई। 1967–68 में (फरवरी, 1968 तक) इस परियोजना पर 96·49 लाख रुपये खर्च हुए ।

(ख) 1967 में कोई सुरंग पूरी तरह तैयार नहीं हुई ।

(ग) इस परियोजना से सम्बन्धित काम इस क्रम से किया जा रहा है, ताकि यह मेंगलूर बन्दरगाह परियोजना के काम के साथ साथ पूरा हो । आशा है, मेंगलूर से पानाम्बूर तक की सम्पर्क लाइन नवम्बर, 1968 तक बन कर तैयार हो जायेगी ।

रेलगाड़ी के माल डिब्बों से कोयले की चोरी

4482. श्री शिवप्पा :
डा० म० सन्तोषम :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में प्रतिदिन औसतन कितने माल डिब्बों का प्रयोग कोयला ढोने के लिये किया जाता है ;

(ख) रेल के माल डिब्बों से प्रतिदिन औसतन कितने कोयले की चोरी होती है ;

(ग) इस चोरी के फलस्वरूप प्रतिवर्ष रेलवे को कितनी हानि उठानी पड़ती है ; और

(घ) क्या इस बारे में रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) प्रतिदिन बड़ी लाइन के 2125 माल डिब्बे ।

(ख) और (ग). यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि माल डिब्बों से प्रतिदिन औसतन कुल कितना कोयला चोरी गया और उसके कारण रेलवे को अनुमानतः कितनी हानि हुई ।

(घ) जब ड्यूटी पर रेल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कोयले की उठाईगीरी होती है, तो सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है जिसमें उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया या निकाला भी जा सकता है ।

रेलवे सुरक्षा दल का समाप्त किया जाना

4483. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रेलवे सुरक्षा दल को समाप्त करने और उसके कुछ कार्य राज्य पुलिस दल को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी बचत होगी और इस योजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

जापानी औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल

4484. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1967 में एक जापानी औद्योगिक प्रतिनिधिमण्डल भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो जापान के गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा भारत में पूंजी विनियोजन की क्या सम्भावनाएं हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में मनीपुर हस्तशिल्प बिक्री केन्द्र

4485. श्री मेघ चन्द्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नई दिल्ली म कनाट प्लेस में मनीपुर हस्तशिल्प बिक्री केन्द्र के निर्माण के लिये भूमि का एक छोटा सा प्लाट मुफ्त आवंटित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मनीपुर सरकार ने इस बारे में कोई प्रार्थना की थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों को इर्विन रोड पर एम्पोरियम स्थापित करने के लिए कुछ प्लाटों का आवंटन किया है । इनमें से मनीपुर सरकार को सामान्य मूल्य का भुगतान करने पर एक प्लाट का आवंटन करने का अनन्तिम रूप से निश्चय किया गया । मनीपुर सरकार को मुफ्त भूमि देने का प्रश्न नहीं है और न राज्य सरकार ने ऐसी कोई प्रार्थना ही की है ।

मनीपुर में उद्योग

4486. **श्री मेघ चन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968–69 में मनीपुर में कितने तथा कौन कौन से उद्योग स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में मनीपुर को कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मणिपुर को 1968–69 की वार्षिक योजना में वस्त्र, सीमेंट और कागज की कुछ औद्योगिक परियोजनायें चलाने की सम्भावनाओं के बारे में अध्ययन करने की व्यवस्था की गई है । इस अवधि में लघु क्षेत्र में हथकर्घा, दस्तकारी, रेशम के कीड़े पालने, लघु ग्रामीण तथा खादी उद्योगों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाएं अमल में लाई जायेंगी ।

(ख) इन उद्योगों के लिये वर्ष 1968–69 में 17 लाख रुपये की अस्थाई रूप में व्यवस्था की गई है ।

बल्लाडिल्ला में पैलट बनाने का कारखाना

4487. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्लाडिल्ला में पैलट बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) बैलाडिला के भंडार 14 की खान में से पिंड अयस्क के उत्पादन के दौरान निकलने वाले सूक्ष्मक को काम में लाने के लिए एक गुल्लिका बनाने वाले संयंत्र लगाये जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) इस समय जापान की एक कम्पनी बैलाडिला के भंडार 14 के सूक्ष्मक के भंडार के विषय में सम्भाव्यताओं का अध्ययन कर रही है । इस कम्पनी ने अमरीका की बैटल मेमोरियल इंस्टीट्यूट लेबोरेटरीज में गुल्लिका बनाने सम्बन्धी परीक्षणों का प्रबन्ध किया है । यह परीक्षण इस समय प्रगति पर है और इस वर्ष लगभग जून तक सम्भाव्यता रिपोर्ट मिल जाने की आशा है ।

रेलवे गार्ड

4488. **श्री इसहाक सम्भाली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों का एक शिष्टमंडल 23 दिसम्बर, 1967 को रेलवे में राज्य मंत्री से मिला था और उसने उनके साथ रेलवे गार्डों की उचित माँगों के बारे में बातचीत की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दो अवसरों पर इस सम्बन्ध में उनको लगभग 50 संसद् सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त ज्ञापन दिया गया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ । संसद् सदस्यों का एक शिष्टमंडल 22 दिसम्बर, 1967 को उनसे मिला था ।

(ख) जी हाँ । दो ज्ञापन मिले थे, जिनमें से एक पर लगभग 37 संसद् सदस्यों और दूसरे पर लगभग 34 संसद् सदस्यों के हस्ताक्षर हैं ।

(ग) सभी वर्गों के रनिंग कर्मचारियों (जिनमें गार्ड भी शामिल हैं) के रनिंग भत्ते से सम्बन्धित नियमों और दरों पर पुनर्विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की गयी है और आशा है कि इस समिति की रिपोर्ट मई, 1968 के अन्त तक मिल जायेगी ।

निर्यात गृह

4489. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात गृहों के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए गैर-परम्परागत उत्पादों के निर्यात के आँकड़ों की न्यूनतम सीमा को सरकार ने हाल में 10 लाख रुपये से बढ़ा कर 25 लाख रुपये कर दिया है ;

(ख) क्या उसी प्रयोजन के लिए परम्परागत वस्तुओं की सीमा बढ़ा कर दो करोड़ रुपये कर दी गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, नहीं । निर्यात गृहों के रूप में मान्यता सम्बन्धी पहिले की योजना के अनुसार केवल परम्परागत माल का निर्यात करने वाले निर्यातक मान्यता के पात्र कदापि नहीं थे । अब यह सुविधा उन्हें भी प्रदान की गई है बशर्ते कि वे एक न्यूनतम निर्यात निष्पादन पूरा करे। अतः इस मामले में न्यूनतम अर्हताओं को संशोधित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सामान्य निर्यात संवर्द्धन उपाय के रूप में निर्यात गृह योजना संशोधित की गई है ताकि उत्पादों का विदेशों में विपणन करने में निर्यात गृह अधिक सफल हो सकें ।

रूस को बैगनों का निर्यात

4490. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस को आठ पहियों वाले 10,000 वैगनों की सप्लाई के लिये उत्पादन कार्यक्रम तैयार कर लिये गये हैं ;

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिये उत्पादन लक्ष्य क्या होंगे ;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र की ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं और प्रत्येक फर्म द्वारा कितने वैगन बनाए जायेंगे ; और

(घ) इस सौदे से प्रति वर्ष अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग). रूस को वैगनों की सप्लाई के लिये उत्पादन कार्यक्रम, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिये उत्पादन का नियतन करने का प्रश्न अथवा निर्मित की जाने वाली वैगनों की संख्या, इन सभी विषयों पर अभी बातचीत होनी है। एक रूसी रेलवे प्रतिनिधि मण्डल, जो भारत में है, विभिन्न प्राधिकारियों के साथ इन विषयों पर विस्तृत रूप से बातचीत कर रहा है। 13-3-1968 को एक भारत-रूस सन्धि पर हस्ताक्षर हुए थे जिसमें 1969-70 में 2000 वैगनों के निर्यात का कार्यक्रम दिया गया था जिसे अनुगामी वर्षों में बढ़ाया जायेगा ताकि 1972-73 में इनके आँकड़े प्रति वर्ष 10,000 वैगन हो जायें।

(घ) यह अनुमान इतना शीघ्र नहीं लगाया जा सकता कि इस सौदे से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

Calcite Deposits in Saugar District

4491. Shir Nihal Singh : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1643 on the 24th November, 1967 and state :

(a) whether Government have since appointed or propose to appoint a survey team to find out Calcite deposits said to be present in a seven-mile long range in Saugar District ; and

(b) the other deposits found on conducting the survey ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) No, Sir. However during 1967-68 field season, the Geological Survey of India proposes to undertake mineral survey in Saugar district.

(b) Does not arise.

रूसी रेलवे प्रतिनिधि मण्डल की भारत की यात्रा

4492. श्री यशपाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी रेलवे प्रति निधि मण्डल मार्च, 1968 में भारत आया था ;

(ख) क्या इस प्रतिनिधि मण्डल के साथ कोई बातचीत की गई थी ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) फरवरी, 1968 के अन्त में रूसी रेलों के उपमंत्री के नेतृत्व में सोवियत संघ का एक शिष्टमण्डल भारत आया था। यह शिष्टमण्डल भारत से सोवियत संघ को रूसी अभिकल्प और विशिष्टियों के रेल माल-डिब्बों के निर्यात की सम्भावनाओं पर तकनीकी बातचीत करने के लिए आया था। इस बातचीत के परिणामस्वरूप 13-3-68 को राज्य व्यापार निगम और मशीनो-इम्पोर्ट सोवियत संघ के बीच एक संलेख पर हस्ताक्षर किये गये, जिसमें सोवियत संघ को माल-डिब्बों की सप्लाई के सम्बन्ध में आगे बातचीत करने की कार्यविधि निर्धारित की गयी है।

जूतों के निर्यात पर राज्य व्यापार निगम द्वारा लिया गया कमीशन

4493. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैकिंग, भाड़ा, निरीक्षण, विकास तथा प्रचार पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये राज्य व्यापार निगम अपने मुनाफे के रूप में एक जोड़ी जूते पर 10 रु० अपने पास रख लेता है ;

(ख) क्या जूता उद्योग ने यह अभ्यावेदन किया है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा भारी लाभ लिये जाने के कारण उसके लिये बहुत कम मुनाफा बचता है ;

(ग) राज्य व्यापार निगम इस प्रकार प्रति वर्ष कितनी धन राशि वसूल करता है ; और

(घ) इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य व्यापार निगम के निर्माताओं ने सोवियत रूस को भेजे जाने वाले जूतों के लिये उनको दिये जाने वाले समाहार मूल्यों में वृद्धि करने के लिये अभ्यावेदन किया था। समाहार मूल्य 1967 में अपनाई गई विधि के अनुसार ही निर्धारित किये गये थे और उन्हें निर्माताओं के लिये उचित समझा जाता है ।

(ग) और (घ). इस जानकारी को देना राज्य व्यापार निगम के व्यापारिक हित में नहीं है ।

मैसूर लोहा तथा इस्पात वर्क्स, भद्रावती

4494. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर लोहा तथा इस्पात वर्क्स, भद्रावती की वित्तीय स्थिति कैसी है और क्या इसको कोई हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस कम्पनी के कार्य संचालन के बारे में जांच कराने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड लाभ में जा रहा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते

Sale of Goods in Khadi Bhavan, New Delhi

4495. **Shri J. Sunder Lal** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the goods sold in the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi are purchased from certain unapproved organisations who are making huge profits by charging arbitrary prices which are many times higher than those prevailing in the market for similar goods ;

(b) whether a huge stock of the said goods ing unsold ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to remedy the situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The Government is not aware of such purchase.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

निमियाघाट स्टेशन के निकट मालगाड़ी का लूटा जाना

4496. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 मार्च, 1968 को पूर्व रेलवे के भोलिडीह तथा निमियाघाट स्टेशनों के बीच बदमाशों के एक दल ने एक मालगाड़ी पर छापा मारा था तथा उसे लूटा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसी स्थान पर वही गाड़ी 26 फरवरी, 1968 को भी लूटी गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण कितनी हानि हुई ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). यह सच है कि 26-2-68 को और फिर 2-3-68 को भोलीडीह और निमियाघाट स्टेशनों के बीच कुछ बदमाशों ने एक मालगाड़ी नं० 1173 को रोक लिया था और कुछ गांव वालों ने अस्थायी गैंगमैनों की सहायता से उठाई-गीरी की कोशिश की थी लेकिन रेलवे सुरक्षा दल की सामयिक कार्यवाही के फलस्वरूप ऐसा न कर सके। 2 गैंगमैनों सहित 6 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और सरकारी रेलवे पुलिस गोमो ने इस सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143/379 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) भोलीडीह और निमियाघाट रेलवे स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा दल के दस्ते तैनात कर दिये गये। प्रभावित खण्ड की माल गाडियों में साथ चलने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात किये गये हैं।

मुगलसराय स्टेशन पर बम विस्फोट

4497. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 मार्च, 1968 को मुगलसराय रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफार्म पर एक बम विस्फोट हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति घायल हुए और कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या इस मामले की जांच हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) एक पटाखे के विस्फोट से 2 व्यक्तियों के घायल होने की रिपोर्ट मिली है। लेकिन सम्पत्ति को क्षति पहुंचने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) और (घ) सरकारी रेल पुलिस, मुगलसराय, ने इस मामले को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5/6 के अधीन 7-3-68 को मामला संख्या 95 के रूप में दर्ज कर लिया है। अभी तक दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। राज्य पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है।

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९५ के उत्तर में शुद्धि

Correction of Answer to Unstarred Question No. 1295

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : 20-2-1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1295 के उत्तर में मैंने कहा था कि बिहार सरकार ने अशोक पेपर मिल्स लि० को अपने अधिकार में लेने का निर्णय किया है। यह सूचना बिहार सरकार द्वारा पहले दी गई जानकारी पर आधारित थी। उसने अब सूचित किया है कि उन्होंने अपने पहले निर्णय पर पुनः विचार किया है और 13-2-1968 को यह निर्णय किया है कि उनके लिए अशोक पेपर मिल्स को अपने अधिकार में लेना सम्भव नहीं होगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

वामपंथी साम्यवादी नागाओं द्वारा संपूर्ण प्रभुत्वसंयन्त्र नागालैंड की मांग

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मेरा नियम 173 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न है। जैसा मैंने पहले भी कई अवसरों पर बताया है कि इस मामले को बार-बार यहां पर चर्चा के लिये लाया जा रहा है। नागालैंड में 'वामपंथी साम्यवादी नागा' नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस प्रकार के प्रस्तावों को बार बार क्यों स्वीकार किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक सदस्य से नहीं बल्कि कम से कम 30 सदस्यों से प्राप्त हुए हैं। वहां इस प्रकार का कोई दल है अथवा नहीं इस बात की जांच करना मेरा काम नहीं है। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में जवाब देंगे कि नागालैंड में कौन-कौन से दल हैं और उनकी गतिविधियां क्या-क्या हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of Urgent Public Importance and I request that he may make a statement thereon :

'Demand for sovereign Nagaland by Left Communist Nagas and in that context recovery of high explosive Bomb'.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): आसाम राज्य से प्राप्त समाचार के अनुसार 6 मार्च, 1968 को जिला शिवसागर, थाना टिटाबर, गांव पनीनोरा के बापुटे सैकिया नामक

(श्री यशवन्त राव चव्हाण)

व्यक्ति को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह विद्रोही नागाओं से तोड़फोड़ के कामों का प्रशिक्षण लेकर अपने गांव लौट रहा था। इस के बाद तेरह अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिन पर संदेह है कि उन्होंने भी इसी प्रकार का प्रशिक्षण लिया था। गिरफ्तार व्यक्तियों में से एक के पास से फ्यूज तार के साथ एक प्लास्टिक बम बरामद हुआ। एक दूसरे व्यक्ति के पास से एक नोट बुक बरामद हुई जिस में बम तथा अन्य विस्फोटक पदार्थों के बनाने तथा इस्तेमाल के बारे में हिदायतें लिखी थीं। इस सम्बन्ध में और आगे जांच की जा रही है।

Shri Madhu Limaye : No reply to my Call Attention Notice has been given. It appears as if he has replied to some other motion. In the reply nothing has been mentioned regarding the demand for sovereign Nagaland. He has only replied to the Question regarding plastic bombs.

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं कि सरकार के पास इस सम्बन्ध में जानकारी है अथवा नहीं। मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता कि वह इसका उत्तर दें।

Shri Madhu Limaye : What is the procedure in this regard ? The Hon. Minister has given reply to my notice, but has not replied to the questions asked by me.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अनुपूरक प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकता हूं लेकिन केन्द्र से सम्बन्धित तथ्यों के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव--प्लास्टिक बमों के बारे में रखा जाता है--आप कुछ राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : विभिन्न सदस्यों ने विभिन्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे हैं जिन में विभिन्न बातों पर जोर दिया गया है। किसी सदस्य ने आसाम पर तो किसी सदस्य ने नागालैंड के बारे में अधिक जोर दिया है। गृह-कार्य मंत्री ने उसका उत्तर दे दिया है।

Shri Madhu Limaye : The attitude of the Government towards Naga problem has given a rise to the destructive elements in the country. Whether Government has any information which are the countries from where these bombs are being smuggled into Nagaland ? Whether there is CPI (M) unit in Nagaland ? Whether some arrests have been made in this connection and what steps Government intend to take to prevent these incidents ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक मेरी जानकारी है नागालैंड में सी० पी० आई० (मार्क्सिसट) नाम की कोई पार्टी नहीं हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछ ताछ की गई है। पूछताछ से यह पता चला है कि कुछ गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) दल से सम्बन्ध था। दो ऐसे व्यक्तियों के नाम का भी पता लगा है जिनका इन घटनाओं के पीछे सक्रिय हाथ रहा है और उनका भी भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) से सम्बन्ध रहा है। जहां तक नागालैंड में शस्त्रों के पहुंचने का सम्बन्ध है, इन विद्रोहियों ने चीन से सम्पर्क स्थापित किये हैं और उन के कुछ सदस्य चीन में रह रहें हैं। मेरे विचार से ये हथियार चीन से आ रहे हैं। इस सम्बन्ध म की गई जांच से पता लगता है कि नागालैंड और आसाम में ऐसे लोगों के दल हैं जो विध्वंसक कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और विद्रोही नागाओं द्वारा

हथियार प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि पृथक आसाम राज्य की स्थापना के लिये अभियान चलाया जा सके। इस को रोकने के लिये हम आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति देने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध मे प्रत्येक समाचारपत्र ने कुछन न कुछ समाचार प्रकाशित किया है। इसके विरोध मे यह भी प्रकाशित किया गया है कि वे लोग भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के नहीं हैं। अतः इसकी अनुमति दी जानी आवश्यक थी।

Shri Madhu Limaye : I want reply regarding the recent plastic bombs. I want to know from which country it has been smuggled here.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस विशेष बम के सम्बन्ध में जांच जारी है।

Shri Balraj Madhok (South-Delhi) : It is a well known fact that Chinese and Pakistani elements are behind these incidents. Whether it is a fact that hostile Nagas are spreading their activities in Shiv Sagar area aso. If it is a fact then the steps Government have taken to prevent it ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमें उन तत्वों की कुछ जानकारी है जो अपना विस्तार नागालैंड और आसाम में करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको रोकने के लिये हम कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री नि० रं० लस्कर (करीमगंज): समस्त देश में मार्क्सवादी साम्यवादियों की गतिविधियां जोरशोर पर हैं। उन्होंने जो नक्सलबाड़ी में किया उसे ही वे आसाम, नागालैंड और मनीपुर में भी दोहराना चाहते हैं। सरकार ने नक्सलबाड़ी जैसी गतिविधियों को रोकने के लिये आसाम में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती है। सरकार अब तक सम्बन्धित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में असफल रही है। हम उन लोगों के नाम तक जानते हैं (अन्तर्बाधाएं)

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस सम्बन्ध में हम आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : ऐसा विदित हुआ है कि कुछ गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों ने अपने दोष स्वीकार किये हैं। और उनके पास से कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि उनका दोष स्वीकार करना और उनसे प्राप्त हुए दस्तावेज मेल खाते हैं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: अन्य व्यक्ति के पास से एक नोटबुक प्राप्त हुई है जिसमें बमों के बनाने और उनके प्रयोग करने के सम्बन्ध में कुछ जानकारी दी गई है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

कम्पनियों इत्यादि के कार्य और प्रशासन के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुये वर्ष के लिये उक्त अधिनियम के प्रवर्तन तथा लागू करने सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 493–1968]

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत वर्ष 1965–66 के लिये निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक एक प्रति :—

(एक) मोटर गाड़ियों, मोटर गाड़ियों के सहायक पुर्जों के उद्योगों, परिवहन यान उद्योगों, ट्रेक्टरों तथा मिट्टी खोदने के उपकरणों सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(दो) खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् ।
(तीन) हैवी इलैक्ट्रिकल उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् ।
(चार) मशीन औजार उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् ।
(पांच) तेलों डिटरजेंटस तथा रंग-रोगन सम्बन्धी विकास परिषद् ।
(छः) कागज लुगदी तथा सहायक उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् ।
(सात) कपड़ा मशीन उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् ।
(आठ) नकली रेशम उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् ।
(नौ) ऊनी उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् ।
(दस) भेषज तथा औषधालय-निर्माण सम्बन्धी विकास परिषद् ।
(ग्यारह) कार्बनिक रसायन उद्योगकों सम्बन्धी विकास परिषद् ।
(बारह) चीनी उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् ।

[पुस्तकालय मे रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 389/1968]

1966-67 के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उन पर सरकारी टिप्पणियां

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : —

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची के वर्ष 1966–67 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) वर्ष 1966-67 के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 494-68]

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1884 की एक प्रति जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(2) उक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रख गये । देखिये संख्या एल० टी० 495--1968]

प्राक्कलन समिति

Estimates Committee

सैंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री पे० वेंकटासुब्बाया : मैं गृह-कार्य मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग के बारे में प्राक्कलन समिति का 47वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मुंगेर के निकट गंगा नदी में हाल ही में आग लगने के बारे में वक्तव्य

Statement re. recent blaze in Ganga near Monghyr

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया) : मैंने पहले गंगा नदी में 3 मार्च, 1968 को आग लगने और मुंगेर (बिहार) में पानी सप्लाई के दूषित होने के बारे में, उस समय की उपलब्ध सूचना सभा को दी थी। प्रशासकों तथा विशेषज्ञों के अलावा, जिन्होंने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया, मैंने खुद, जो कुछ हुआ उससे परिचित होने के लिये, पटना, मुंगेर और बरौनी का दौरा किया है। वास्तव में क्या हुआ . इसका सही तौर से पता लगाने, जहां कहीं जरूरी है जिम्मेवारी ठहराने और आगे के लिये ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने इन मामलों पर पूरी जांच करने का फैसला किया है। यह जांच एक त्रि-सदस्य आयोग द्वारा की जायेगी। इस आयोग की नियुक्ति कमिशन आफ इंक्वारीज एक्ट के अन्तर्गत की जायेगी। आयोग की अध्यक्षता हाई कोर्ट के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश करेंगे और जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के दो विशेषज्ञ इस के सदस्य होंगे इन दो विशेषज्ञों में से एक व्यक्ति बिहार राज्य सरकार द्वारा नामित होगा।

आयोग के विचारार्थ विषय सामान्यतः निम्नलिखित होंगे :—

(क) फरवरी के अन्तिम सप्ताह या पहले और मार्च 1968 के पहले सप्ताह के दौरान बरौनी शोधनशाला के पास और अनुप्रवाह, गंगा नदी के तेल से दूषित होने के सही तथ्यों का निर्धारण करना ;

(ख) बरौनी शोधनशाला इन घटनाओ के लिये किस हद तक उत्तरदायी है; इसका निर्धारण करना ;

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये अपनाये जाने वाले उपायों की सिफारिश करना;

(घ) इस बारे में परामर्श देना कि क्या शोधनशाला के प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों से निर्धारित कर्त्तव्यों का पालन करने में किसी प्रकार का प्रमाद या असावधानी हुई है ;

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार की आगामी कार्यवाही करने की आवश्यकता हो, तो उसके लिए सिफारिश करना;

(च) नदी के दूषित जल से जनता को हुई हानि या क्षति की रिपोर्ट देना तथा भारतीय तेल निगम को उन लोगो को, जो इस से बुरी तरह प्रभावित हुए है, यदि कोई क्षतिपूर्ति करनी हो, तो उसकी सिफारिश करना;

(छ) आयोग के विचार में इस से संबंधित यदि कोई अन्य मामला हो, तो सामान्यता उस पर रिपोर्ट देना।

हम जांच समिति को प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अपने विमर्श को यथाशीघ्र मुकम्मल करने का यत्न करें।

जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) विधेयक

Jammu and Kashmir Representation of the People (Supplementary) Bill

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरित) अधिनिय, 1957 के अनुपूरक विधेयक पर चर्चा होगी?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 के संशोधन संख्या 2 पर विचार किया जाये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : इस सम्बन्ध में फिर गड़बड़ हो गई है। मैं संविधान के अनुच्छेद 327 का उल्लेख करूंगा। उसमें विधान सभाओं के चुनाव के सम्बन्ध में संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है। परन्तु संविधान के अनुसार अनुच्छेद 327 जम्मू और काश्मीर पर लागू नहीं होता है। यदि संसद् को जम्मू और काश्मीर की विधान सभा के चुनाव के सम्बन्ध में कोई कानून बनाना हो तो उपबन्धों में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है।

अधिनियम केवल जम्मू और काश्मीर तक ही सीमित है अतः हम संवैधानिक उपबन्धों का उल्लंघन कर रहे हैं। अतः यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

श्री मु० यूनस सलीम : इस सम्बन्ध में संविधान के सातवें अनुच्छेद में की गई प्रविष्टि पर भी विचार किया जाना चाहिये।

श्री श्रीनिवास मिश्र : माननीय मंत्री गलती पर हैं इसके आदेश द्वारा प्रविष्टि में भी संशोधन किया गया है।

श्री मु० यूनस सलीम : राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से इन आदेशों के जारी किये जाने के बाद यह कठिनाई दूर हो गई है।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं उससे असन्तुष्ट नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह संवैधानिक मामला है। उद्घोषणा उस अनुच्छेद से सम्बन्धित नहीं है। वह सूची में की गई ऐन्टरी से सम्बधित है। मैं यह सुझाव देता हूं कि उस पर कुछ समय के लिये चर्चा स्थगित कर देनी चाहिये।

संसदीय तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : माननीय मंत्री संवैधानिक कठिनाई को स्पष्ट करने के लिये तैयार होकर आयगे और इस पर 6 बजे चर्चा की जानी चाहिये।

अनुदानों की मांगें, रेलवे 1968-69 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1967-68

Demands for Grants Railways, 1968-69 and Demand for Supplementary Grants (Railways) 1967-68

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) मैं, वर्ष 1968–69 के लिये रेलवे की अनुदानों की मांगों को सभा में चर्चा के लिये रखना चाहता हूं।

मैं यह भी निवेदन करता हूं कि मुझे वर्ष 1967-68 की रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगो को भी सभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुपूरक मांगों की पुस्तक में बताया गया है, चालू वर्ष में राजस्व कार्य संचालन व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता 25.42 करोड़ रुपये (कुल) से घटकर 21.94 करोड़ रुपये कर दी गई है। यह केवल सीमान्त कटौती है जो नवीनतम अनुमान के आधार पर की गई है। इस खर्च का ब्यौरा पिछले सप्ताह के अन्त में रेलवे से प्राप्त राशि के रूप में चालू वित्तीय वर्ष में दिखाया गया है। यह कटौती आकस्मिक कार्यालय व्यय में कमी, इंजन डिब्बों आदि की मरम्मत में कमी, कार्य संचालन कर्मचारियों की नियुक्ति में कमी और ईंधन की व्यवस्था में परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप हुई है।

इन कटौतियो के परिणाम स्वरूप चालू वर्ष में रेलवे की शुद्ध आय, जिस में ऋण पूंजी पर लाभांश दिया गया है, बढ़ जायेगी। राजस्व रक्षित निधि से 22.59 करोड़ निकाले जाने का अनुमान था लेकिन अब उसमें 3.48 करोड़ रुपये की कमी की जायेगी। चूंकि उपलब्ध बजट अनुदान से पहले ही कम है अतः इस मद के लिये कोई अनुपूरक अनुदान की मांग नहीं की गई है।

वर्ष 1968-69 के लिये रेलवे मंत्रालय की अनुदानो की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	रेलवे बोर्ड . . .	1,39,93,000	रुपये
2	विविध व्यय	5,15 49,000	रुपये
3	चालित और दूसरी लाइनों को भुगतान . .	18,91,000	रुपये
4	संचालन-व्यय—प्रशासन . . .	70,35,22,000	रुपये
5	संचालन-व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण . .	2,26,8 0,59,00 0	रुपये
6	संचालन-व्यय—परिचालन कर्मचारी . .	1,42,54,12,000	रुपये
7	संचालन व्यय—परिचालन (ईंधन) . .	146,08,20,000	रुपये
8	संचालन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	41,41,28,000	रुपये
9	संचालन-व्यय—विविध व्यय .	32,09,27,000	रुपये
10	संचालन-व्यय—कर्मचारी हित . .	23,8 9,36,000	रुपये
11	संचालन-व्यय—मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	100,00,00,000	रुपये
11-क	संचालन-व्यय—पेंशन निधि में विनियोग .	10,00,00,000	रुपये
12	सामान्य राजस्व को लाभांश .	152,00,25,000	रुपये
13	चालू लाइन निर्माण (राजस्व) .	9,00,03,000	रुपये
14	नयी लाइनों का निर्माण . .	28,8 3,59,000	रुपये
15	चालू लाइन निर्माण, पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	533,15,92,000	रुपय
16	पेंशन-प्रभार—पेंशन निधि . . .	5,38,37,000	रुपये
17	सामान्य राजस्व से लिये गये कर्ज और उस पर सूद का भुगतान—विकास निधि . .	1,23,8 4,000	रुपये
18	विकास निधि में विनियोग . . .	1,00,00,000	रुपये
20	राजस्व आरक्षित निधि से निकासी—अनुपादक पूंजी के परिशोधन के लिये अदायगियां . . .	1,36,08,000	रुपय

वर्ष 1968–69 के लिये रेलवे मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	रेलवे बोर्ड	6,57,000 रुपये
2	विविध व्यय	14,24,000 रुपये
4	संचालन व्यय—प्रशासन	2,17,33,000 रुपये
5	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	8,08,59,000 रुपये
6	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी	2,83,71,000 रुपये
7	संचालन व्यय—परिचालन (ईंधन)	9,45,86,000 रुपये
8	संचालन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	2,86,91,000 रुपये
14	नयी लाइनों का निर्माण	1,000 रुपये
16	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि	1,17,40,000 रुपये
20	राजस्व आरक्षित निधि से निकासी	10,14,000 रुपये

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्ली) : रेलवे मंत्री ने न केवल तीसरे दर्जे के यात्री किराये और स्लीपर किराये में वृद्धि की है बल्की भाड़े की दरों में भी वृद्धि की है। इसके परिणाम स्वरूप आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं। यदि रेलवे की आमदनी में कमी हो रही है तो उन्हे रेलवे की कार्या व्यवस्था में सुधार कर उसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये।

रेलवे मंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि सड़कों में सुधार किये जाने के परिणाम-स्वरूप ट्रकों की संख्या में वृद्धि हुई है और रेल और सड़क की प्रतियोगिता में वृद्धि हुई है। देश में सड़क परिवहन में सुधार हुआ है और रेल द्वारा भेजे जाने वाले माल में कमी हुई है। हमें रेल की क्षमता में इस हद तक सुधार करना चाहिये कि लोग सड़क द्वारा माल न भेज कर रेल द्वारा माल भेजना पसन्द करें।

उन्हें यह समझ लेना चाहियें कि रेल के किराये और माल भाड़े में वृद्धि किये जाने से रेलवे की आय में वृद्धि न हो कर कमी ही होगी क्योंकि इसके परिणामस्वरूप अधिक से अधिक जनता सड़क द्वारा यात्रा करेगी और सामान भेजेगी।

प्लेटफार्म टिकट की कीमत बढ़ाये जाने के परिणामस्वरूप जन साधारण को कठिनाई होगी। इससे प्लेटफार्म टिकट की बिक्री कम हो जायेगी और लोग बिना प्लेटफार्म टिकट खरीदे प्लेटफार्म पर चले जाया करेंगे ।

अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय को प्लेट फार्म टिकट की कीमत 15 पैसे ही रखी जानी चाहिये ।

रेलवे बोर्ड के सदस्यों से मुझे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है परन्तु उन्हें एसे अधिकार दे दिये गये हैं कि वे नौकरशाही हो जाते हैं इसका कारण यह है कि वे अपनी सेवा के अन्त में रेलवे बोर्ड के सदस्य बना दिये जाते हैं और उस आयु में वे कोई नया काम नहीं करना चाहते। रेलवे के यातायात में सुधार के लिये वे कोई ठोस काम नहीं करते। इसीलिये रेलवे की व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। यदि कोई मंत्री कुछ परिवर्तन करना चाहता है तो वे उसे उल्टा सीधा समझा देते हैं। अत : मेरा अनुरोध है कि रेलवे मंत्री को कुछ कठोरता से प्रशासन चलाना चाहिये और मंत्री ऐसा बनाया जाये जिसे रेलवे के बारे में कुछ तकनीकी ज्ञान हो। रेलवे बोर्ड के सदस्यों का काम सलाह देना है, निर्णय करने की शक्ति मंत्री को होती है। रेलवे व्यवस्था में सुधार तभी होगा जबकि मंत्री स्वविवेक से अन्तिम निर्णय लेने लगेंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock

---

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

श्री नम्बियार : अब मैं रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं पर आता हूं। यद्यपि उन्हें कुछ आर्थिक लाभ दिया गया है, फिर भी वे संतुष्ट नहीं हैं। रेलवे कर्मचारियों की बड़ी पैमाने पर छंटनी की तैयारी की जा रही है। नैमित्तिक श्रमिकों को काम से हटाया जा रहा है। अनेक रेलवे कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सेवा 5 से 12 वर्ष की हो चुकी है और जो अभी तक स्थायी नहीं बनाये गये हैं। रेलवे कर्मचारियों की कुछ श्रेणियाँ ऐसी हैं जिन्हें 12 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता है, हालाँकि हम "प्रति दिन 8 घंटे के काम" के सिद्धांत को मान चुके हैं। रेलवे के अधिक से अधिक कर्मचारियों को,जिनमें ड्राइवर, फायरमैन, पोइंटमैन, रोलिंग स्टाक स्टाफ, लिवरमैन और गेट कीपर आदि की श्रेणियाँ सम्मिलित हैं, प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक काम करना पड़ता है। यदि इन कर्मचारियों के के घंटे घटा दिये जाये तो छंटनी की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। दूसरे अधिक समय तक कामकाम करने से कर्मचारी थक जाते हैं और दुर्घटना की गुंजाइश अधिक हो जाती है। वे ऐसी स्थिति में कार्यकुशलता से काम नहीं कर सकत हैं। अधिकतर एक्सप्रेस तथा पैसन्जर गाडियों के ड्राइवरों को 12 घंटे से अधिक काम करना पड़ता है। मंत्री महोदय ऐसा आश्वासन दें कि रेलवे कर्मचारियों से 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जायेगा।

रेलवे कर्मचारियों की यूनियन को मान्यता देने का क्या सिद्धान्त है? मेरे विचार से कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं है। मंत्री महोदय अथवा रेलवे बोर्ड अपनी इच्छा से जिसे मान्यता देना चाहती है, दे देती है और जिसे मान्यता नहीं देना चाहती, उसे मान्यता नहीं दी जाती। जिस यूनियन को अधिकतर रेलवे कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त हो, उसे मान्यता मिलनी चाहिये। एक अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह कर्मचारियों की कार्मिक स्थिति के सम्बन्ध में है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार एक डिविजनल पर्सोनेल अफसर होता है जिसके अधीन 15,000 कर्मचारी होते हैं। क्या एक अधिकारी 15,000 कर्मचारियों को जो 800 से 900 मील की दूरी पर फैले होते हैं, शिकायतों, अभ्यावेदनों और याचिकाओं पर ध्यान दे सकता है? यह सम्भव नहीं है।

अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो गुफानुमा क्वार्टर रेलवे कर्मचारियों के लिये अंग्रेजों ने बनवाये थे और जिनका उस समय मामूली किराया लिया जाता था, आज उनका किराया 2 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये और 3 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया गया है। स्टेशन मास्टर और पोइन्टमैन जिन्हें पहले क्वार्टर मुफ्त मिलते थे अब उनसे भी किराया लिया जाता है। अब कर्मचारियों को क्वार्टर के किराये के रूप में अपने वेतन का 10 प्रतिशत देना पड़ता है।

मेरा रेलवे मंत्री से यह अनुरोध है कि वह रेलवे कर्मचारियों की उपरोक्त समस्या की ओर ध्यान दें और जो अपेक्षित हो वह करें।

उपाध्यक्ष महोदय: जिन सदस्यों को रेलवे बजट पर बोलने का अवसर नहीं मिला था, उन्हें पहले अवसर दिया जायेगा। जो सदस्य स्थानीय समस्याओं के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं उन्हें भी अवसर दिया जायेगा। परन्तु प्रत्येक सदस्य को केवल दस मिन्ट मिलेंगे।

श्रीमती तारा सप्रे (बम्बई पूर्वोत्तर) : मैं अपने आप को बम्बई महानगर की रेलवे सम्बन्धी समस्याओं तक ही सीमित रखूंगी। बम्बई नगर की जनसंख्या जिस तीव्रता से बढ़ रही है, वहाँ की यातायात की समस्या उतनी ही जटिल होती जा रही है। नगर की जनसंख्या और यातायात समस्या परस्पर सम्बद्ध होते हैं। इस समय नगर में 66 प्रतिशत यातायात रेल गाड़ियों से होता है और 23 प्रतिशत बसों के द्वारा। रेलवे ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जनता की यातायात की समस्या को हल किया जा सकता है। इस समय पश्चिमी रेलवे की एक घंटे में 20 स्थानीय गाड़ियाँ अधिक यातायात के समय चलती हैं तथा मध्य रेलवे की 16 गाड़ियाँ एक घंटे में चलती हैं। चर्चगेट और वी० टी० टर्मीनस पर रेलों के वापिस न आने के कारण कठिनाई उपस्थित होती है। इसलिये यह सुझाव दिया गया है कि चर्चगेट और वी० टी० टर्मीनसों को भूमिगत रेलवे से जोड़ दिया जाये। ऐसी ही व्यवस्था घाटकोपर और अंधेरी के बीच तथा मामखला और फ्लोरा फाउन्टेन के बीच ठीक रहेगी। इस प्रकार की व्यवस्था होने पर स्थानीय गाड़ियां 3 मिनट के अन्तर के बजाय 1 या 1½ मिनट के अन्तर पर छूटने लगेंगी।

बम्बई से गांवों तक गोबर की खाद भेजने के लिये राज सहायता प्राप्त दरों पर सुविधाएं दी जानी चाहिएं। उपनगरीय रेलगाड़ियों में विद्यार्थियों के लिये भी पृथक् डिब्बे होने चाहिये। मैं मंत्रियों से अनुरोध करूंगी कि वे मेरे साथ चल कर वहां की गाड़ियों की हालत देखें।

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : उस समय तक सभी अधिकारी सतर्क हो जायेंगे।

श्रीमती तारा सप्रे: उन्हें वेश बदल कर यात्रा करनी चाहिये। मैं जनता से भी अनुरोध करूंगी कि वह रेलगाड़ियों को आग न लगाय ।

श्री द० रा० परमार (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय चूंकि रेलवे प्रशासन ने गुजरात राज्य में कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं किये हैं इसलिये मैं ने सभा के विचारार्थ अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं । भावनगर-तारापुर लाइन, जसदन-राजकोट लाइन, नादिया-धोलका लाइन का निर्माण कार्य रेलवे को शीघ्र आरम्भ करना चाहिये क्योंकि गुजरात राज्य की जनता एक लम्बे समय से इसकी मांग कर रही है। भावनगर की वर्तमान प्रगति और भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए भावनगर तारापुर रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होना चाहिये। इस लाइन पर कई लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं और परियोजना प्रतिवेदन भी तैयार हो गया है, फिर भी समझ में नहीं आता कि इस संबंध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। हमने जसदन-राजकोट लाइन की भी मांग की है। यदि इन दोनों स्थानों को मिला दिया जाये, तो अहमदाबाद और राजकोट के बीच सीधा और सब से छोटा मार्ग स्थापित हो जायेगा। बागडोड से भिलाड़ी की दूरी केवल 20 किलोमीटर की है। यदि इन दोनों स्थानों को रलवे लाइन द्वारा मिला दिया जाये, तो अहमदाबाद से दिल्ली तक एक सीधा समानान्तर मार्ग स्थापित हो जायेगा। इसके अतिरिक्त सैनिक दृष्टि से भी यह लाइन आवश्यक है।

माननीय मंत्री ने यह भी कहा है कि माल डिब्बों की मांग इनकी सप्लाई की अपेक्षा कम है। फिर क्या कारण है कि माल डिब्बे सरलता से उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें प्राप्त करने में कठिनाई होती है। फसल के दिनों में गुजरात के उत्तरी भाग में लगभग 300 वैगन भार अनाज ऊंझा स्टेशन पर माल डिब्बे न मिलने के कारण पड़ा रहा था। अतः मेरा निवेदन है कि फसल के दिनों में गुजरात को पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे दिए जाने चाहिएं।

स्थानीय जनता को सुविधा देने के लिये यह आवश्यक है कि शाहीबे और केयल के स्थानों पर फ्लैग स्टेशन स्थापित किये जायें। 21 जुलाई, 1967 को माननीय मंत्री ने इस सभा में कहा था कि पर्याप्त औचित्य न होने के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने इस संबध में उनसे पूछा था कि उन्हें क्या ब्यौरा चाहिये। किन्तु पिछले पांच महीने से मुझे उनसे कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। कालोल के स्टेशन के दूसरी ओर 8,000 से भी अधिक की जनसंख्या है और रेलवे लाइन नगर के आबादी वाले भागों के बीच में है, एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता है। इस काम के लिए योजना और प्राक्कलन तैयार करने के लिये 1,410 रु० भी जमा कराये थे और इसके अतिरिक्त 1,190 रु० की अपेक्षित राशि भी दी थी। फिर भी इस मामले में अब तक कुछ नहीं किया गया है। समाचारपत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि गुजरात के मुख्य मंत्री ने कहा है कि उन्हें रेलवे मंत्री ने यह आश्वासन दिया है था कि छोटी रेलवे लाइन को उनकी सम्मति के बिना बन्द नहीं किया जायेगा। रेलवे मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था। अब प्रश्न यह है कि हमें किसका विश्वास करना चाहिये। कालोल स्टेशन के उत्तरी सिरे पर सिगनल केबिन गलत जगह पर स्थित है और स्टेशन पर खड़े यात्री आने वाली गाड़ियों को नहीं देख पाते हैं। इसकी शीघ्र जांच होनी चाहिये। कालोल और अहमदाबाद के बीच गाड़ियों की गति तेज़ की जानी चाहिये। इससे व्यापारियों को काफी सुविधा होगी।

श्री दशरथ राम रेड्डी (कावली): मेरे जिले में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो किसी भी रेलवे स्टेशन से 40 से 60 मील की दूरी पर स्थित हैं। इसी प्रकार से कड़पा जिले में भी अनेक गांव रेलवे स्टेशन से

लगभग 50 मील की दूरी पर स्थित हैं। माननीय रेलवे मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इन क्षेत्रों तक रेल सुविधाएं बढ़ाने पर विचार करें।

मेरे राज्य में नहरों की सुविधा उपलब्ध होने से बड़े क्षेत्रों में खेती की जाने लगी है जिससे अनाज का उत्पादन काफी बढ़ गया है। इस अनाज को पास के जिलों में ले जाने के लिये कोई रेलवे लाइन नहीं है। इस संबंध में राज्य सरकार ने सिफारिश की था कि नागार्जुनसागर से काज़ीपेट और हैदराबाद को मिलाने वाली एक रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिये।

श्री एस० एम० जोशी पीठासीन हुए ।

(Shri S.M. Joshi in the chair)

मेरे जिले में कालकीवाई वितरागुन्ता नाम का एक स्थान है जो एक बड़ा गांव है और जिसकी आबादी 5000 है। इसी प्रकार से कड़पा जिले में भी त्रैलीवेडू और बोराकरापल कोटा नाम के स्थान हैं जिन की आबादी पांच पांच हजार है। इन स्थानों के लोग यहां स्टेशन खोलने की मांग काफी समय से कर रहे हैं। ग्रामवासियों और छात्रों के लिये इन स्टेशनों का खोला जाना अत्यावश्यक है।

Shri O.P. Tyagi (Moradabad) : It is ironical that the III class passengers who contribute 75 to 80 percent to the Railway earnings are the most neglected ones. In most of the trains there are only one or two III class bogies and the rest Reserved bogies which are mainly used by the pass-holders of Railway Department or M.Ps. and they cancel their reservations at the eleventh hour. My suggestion is that change or cancellation of reservation should not be allowed unless another ticket is purchased. I do not grudge running of air-conditioned trains, but Janta Trains should also be run for III class passengers ; especially between Varanasi and Haridwar a daily passenger express should be run for the convenience of pilgrims.

As regards the goods transport, people do not like to despatch their goods by train, but by road transport. Railway transport is not safe and secure and moreover there is corruption in the Railway. From the figures given by the hon. Minister it is manifest that the earnings from the goods transport are sharply coming down. Proper arrangements should be made for the movement of fruit from Madhya Pradesh and Bombay to Delhi. At present the wagons are not made available in time as a result plenty of fruit goes waste. This matter should be looked into.

The hon. Minister has tried to show that the number of accidents in Railways are coming down. As a matter of fact the loss of life and property has progressively increased during the last three years. It does not behave the hon. Minister to draw a comparison between the road transport and the railway transport in the matter of accidents as the former has to run through congested areas.

It is heartening to note that a vigilance Department has been set up in the railways. but it is not a healthy practice to depute railway officials to this Department as they always try to shield each other. The staff to this Department should be recruited direct.

At a number of railway stations there are no goods sheds as a result the goods are spoilt due to exposure to sun and rain. In view of the increased responsibilities of the railway guard his pay should be enhanced and be should not be equated with drivers, commercial clerks etc. and he should also be provided with an assistant.

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : The Railway Protection Force and such other departments should be vested with more powers and administrative machinery tightened if matters are sought to be imporved in the Railway. The present Railway Board should be replaced by a Technical Board. The Ministry should exercise its full authority and not simply ditto what has been recommended by the Railway Board. The Railway is paying enormous amounts in the form of claims against it. If persons responsible for the loss are compelled to make good the loss, the amount of claims will be considerably reduced.

The number of theft cases in the first Second and Third class compartments in the Railways are increasing day by day. These thefts are committed with the help of police and railway employees. Necessary steps should be taken against some officers should be put in this job and they should see that these thefts may be checked.

The Railway Schools run by the Ministry are being run on the whims of the officer. It is not seen whether the teacher is capable to teach certain subject or not. The Department should see whether a teacher is capable to teach a certain subject or not.

The Ministry should look into the matter and the steps should be taken in this matter.

*श्री **दीवीकन** (कल्लाकुरिच्चि) : सम्भव है कि रेलवे ने पिछले वर्षों में कुछ प्रशंसनीय कार्य किये हों। लेकिन रेलवे विकास निधि में काफी कमी आ गई है। पिछले वर्ष उसमें से लगभग 37 करोड़ रुपया निकाला गया और उसमें केवल 3 करोड़ रुपया बाकी रह गया। इससे रेलवे के धूमिल चित्र का ज्ञान होता है।

मद्रास राज्य ने चौथी योजना के अन्तर्गत चेंगलपुट से चोनिया सेलम के बीच रेलवे लाइन के निर्माण को प्राथमिकता देने की सिफारिश की थी। इस लाइन पर यातायात का सर्वेक्षण किया जा चुका है। अत: इस लाइन के निर्माण कार्य में तेजी की जानी चाहिये। पहली तीन योजनाओं में तामिलैण्ड में केवल तीन नई रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश में 8, उड़ीसा में और राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल तथा आसाम में 8 लाइनों का निर्माण किया गया है।

मद्रास ऐगमोर और मद्रास सेन्ट्रल स्टेशन में रेल सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिये। दोनों ही रेलवे स्टेशन ऐसे स्थानों पर हैं जहां आगे प्रसार संभव नहीं।

विलिपुरम ताम्बरम लाइन पर रोशनी की व्यवस्था की जा चुकी है लेकिन गाड़ियां तेजी से जब तक नहीं चल सकतीं जब तक दोहरी रेलवे लाइन की व्यवस्था न हो। अत: दोहरी पटरी बिछाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

त्रियूकोइलूर स्टेशन पर यात्रियों के लिये शेड की शीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिये।

मद्रास और ऐगमोर से चलने वाली गाड़ियों में और अधिक डिब्बे जोड़े जाने चाहियें।

मद्रास को जाने वाली जनता ऐक्सप्रेस की रफ्तार बढ़ाई जानी चाहिये। लोगों की कठिनाई को दूर करने के लिये अतिरिक्त गाड़ियां चलाई जानी चाहियें।

*कुछ शब्द तामिल में बोले।

रेलों में खान पान की व्यवस्था ठीक नहीं है। चीजों के मूल्य बहुत ऊंचे हैं तथा वह अच्छी किस्म की नहीं है।

यह कहा गया है कि और देशों की तुलना में हमारे देश में यात्री किराया बहुत कम है। ऐसा कहते समय इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि उन देशों का स्तर क्या है, उन देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है?

Dr. Mahadev Prasad : (Maharajganj) When the railway fares are being raised it is also necessary that proper attention should be paid to provide facilities to the passengers. Their difficulties have not been removed. There are not even light and water arrangements in the compartments. The administration is not doing all that is necessary to remove the difficulties and inconvenience to the passengers.

Either the Railway Ministry should be abolished or the Railway Board should be abolished. So that the direct responsibility may be fixed. There is a problem of overcrowding in trains. This situation will not improve unless more trains are introduced.

The railway employees are not happy with the conditions of their work. The subordinate staff is not being treated well. Their seniority is not maintained and their promotions are not made according to the set procedure. As a result there is a feeling of discontent amongst the railway employees.

Proper attention is not paid to the health and welfare of the railway employees.

Railway hospital should be opened at places where a large number of railway employees may utilise it.

Nautana station should be electrified.

Chainpulling in the trains should be stopped. Strict arrangements should be made to check it.

It is good that a proposal to make a halt station between Maniram and Piplgang station is being considered.

The Railway Administration is considering to close uneconomic lines, but attention should also be paid to open new lines in the regions where they can prove beneficial.

There is no platform at the Anandnagar junction. A platform should be constructed there.

There are many causes for the losses in the railways, but the main cause is that the railway workshops are not working according to their capacity. A committee should be formulated to investigate the capacity of the railway factories.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): The railway fares are continuously increasing for the last two, or three years. There is over-crowding in every train. Inspite of it, these are losses in the railways. It appears as if there is something wrong in the railway administration, otherwise under the present circumstances there is hardly any possibility of losses in the railways.

The cases of theft are increasing Although there is Railway Protection Force, yet the thefts are increasing. It is, therefore, proper if an enquiry committee is set up to find out the causes of thefts and losses, and the responsibility may be fixed upon.

Proper investigation should be made in this matter.

[Shri S. M. Banerjee]

The railway employees have been demanding to appoint a wage Board for them. Their demand is proper and should be met.

As regards the casual labour, the policy should be that whosoever put in more than one year's service, should be regularised. Casual labour is not being absorbed on regular basis and as a result there is discentment amongst them. It is, therefore, necessary to take some steps in this regard.

It has been said that no retrenchment will be made as a result of automation. It is so, how is it necessary ?

All the employees in the railways are against automation.

Light Railways sould be nationalized.

In Chitranjan railway workshop, there is a unions of more than 90 percent, but it has not been recognised so far. When the union fulfills the necessary conditions for recognition, it should be given recognition.

Cheap grain shops should be provided for railway employees.

The railway fares and the platform ticket fares should be reduced. People have not the capacity to pay more.

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj) : Most of the grievances mentioned in the House can be met in the consultative Committee. The difficulty is that the railway officers who participate in the deliberations generally react adversly to the suggestions made there. It is, therefore, necessary that recognition should be given to the Consultative Committee and it should be asked to take serious note of the suggestions and to do whatever is possible in that direction.

Railways are the public utility service. But in practice it does not appear to be. It is, therefore, requested that efforts should be made to make the railways a public utility service in the real sense.

There is lot of discontentment amongst the railway employees. The main reason is that neither they are treated well by their officers nor due facilities are provided to them. Effective steps should be taken to remove this feeling of discontenment. There should be uniformity in the decisions. The behaviour with the staff should be praiseworthy.

Facilities should be provided to the railway passengers.

The consumption of fuel is increasing day by day. The fuel is being misused. All these things should be stopped. As a result the burden on passengers is increasing day by day.

Twenty five percent passengers travel without ticket in railways. Twenty five percent chargeable goods without any freight. All these things reduce the income of the railways. Necessary stetps should be taken in this regard.

Employees have not been confirmed since long. As a result there is discontentment amongst the employees. One of the causes of loss to railways is under production in railway workshops. We should look into the production capacity of the workshops ; the actual production thereof, the expenditure being spent thereon and the income being earned therefrom. After going through all these matters the existing loopholes should be plugged. Then production will go up and you will not be forced to present a deficit budget.

Shri Deven Sen (Asansol) : Sir, there had been no loss in Railways during First, Second plan periods and in the beginning of Third Plan. It began to occur in 1966-67. Since

then it is recurring year after year. The railway traffic has doubled since 1956. From Rs. 583 crores it has increased to Rs. 1141 crores in 1967. While the income of Railways is going up, the loss is not decresaing. The losses to Railways should have decreased with the ncrease in income. I canpot understand why there is a loss to Railways. An inquiry Committee should be set up to make a thorough enquiry into the causes of loss. I see two obvious causes for it. First is the poor return on the investment made during three plans. There is an ivestment of 3470 crores of rupees. The return is not in proportion to the investment thereon. There must be some ratio between investment and return. The other reason of the loss to railways is the pilferage to the railway goods and properties. Railways have to pay the demurrage to public for the lost or damaged goods in crores of rupees. If pilferage is checked and return is increased, the loss will be compensated and there will be no more deficit.

In Asansol the orders were passed for retrenchment of 1000 class III and IV employees. The Minister should touch this point while replying. The two over bridges on the eastern and western side of Asansol Railway Station are too narrow vertically as well as horizontally. They should be widened. There should be an over bridge at Kulti Junction because it is urgently rquired there.

I cannot enter into Chitranjan, because I am a trade union leader. Outsiders are allowed to go inside the Durgapur or Bhilai Steel plants. But Chitranjan is the only concern in India where a trade union leader from outside cannot enter. The workers are being victimised there. An inquiry should be instituted into the whole railway administration. With these words I put my cut Motion.

श्री जी० एस० रेड्डी (मिरियालगुडा) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो नालगोंडा जिले में है, रेलवे लाइनों की बहुत कमी है। केवल कुछ मील के क्षेत्र में ही रेलवे लाइन है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने के संबंध में कार्यवाही की जानी चाहिये। इस क्षेत्र में नागार्जुनसागर परियोजना है जिसके अधीन अयाकट धान की अत्यधिक उपज होती है। इसका देश के अन्य भागों में निर्यात करने के लिये भी रेलवे लाईन की आवश्यकता है। गुन्टर से मचेरेला तक रेलवे लाइन है। इसे नागार्जुनसागर और नालगोंडा से होकर काजीपेट तक बढ़ा दिया जाना चाहिये। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि उस क्षेत्र के उत्पादल को केरल, महाराष्ट्र और बिहार जैसे देश के अन्य भागों में भेजा जा सकेगा। मंत्री महोदय ने यह कठिनाई अपने पत्र के द्वारा बताई थी कि इस रेलवे लाइन के लिये कृष्णा नदी पर एक पुल बनाना होगा जिस पर लगभग 20 से 30 लाख रुपये की लागत आयेगी। इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि इस क्षेत्र और पूरे देश के हित को ध्यान में रखते हुए 20 या 30 लाख रुपये की राशि अधिक नहीं है। इस लाइन से रेलवे को लाभ भी बहुत अधिक होगा क्योंकि वहां यातायात बहुत अधिक है जो अब बसों द्वारा किया जाता है। दूसरा सुझाव यह है कि मचेलरा और नागार्जुनसागर के बीच जिस लाइन पर केवल मालगाड़ी चलती है, उस पर यात्री गाड़ियां भी चलनी चाहिये। एक अन्य लाइन ओंगोल से काजीपट तक है। इस रेलवे लाइन को मचेलरा तक बढ़ाया जा सकता है। मनमाढ़ और सिकन्दराबाद के बीच भारी यातायात होता है। इसलिए वहां की मीटर गेज वाली लाइन के स्थान पर बड़ी लाईन बिछायी जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री दिनकर देसाई (कनेरा) : मुझे खेद है कि अनुपूरक मांगों के लिये मैं वित्त मंत्री को बधाई न दे सकूंगा। गत वर्ष बजट में 2 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। इस वर्ष वह 21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मागों को लेखानुदान के रूप में पेश कर रहेहैं। इस प्रकार 2 करोड़ रुपये से बढ़

कर घाटा 23 करोड़ रुपये का हो गया है। ऐसा बजट किस प्रकार से तैयार किया जाता है? घाटा इतना अधिक बढ़ने का कारण यह है कि रेलवे मंत्रालय बजट तैयार करने पर समुचित ध्यान नहीं देता है। यह बिल्कुल गलत बात है कि आप बिना संसद की स्वीकृति के पूरे वर्ष खर्च करते चले जाते हैं और वर्ष के अन्त में संसद से उसका अनुमोदन करने के लिये कहते हैं। यह लोकतन्त्रात्मक तरीका नहीं है। इस देश में बजट का वास्तविक स्थिति से कोई संबंध नहीं होता और उसे मजाक समझा जाता है।

घाटे के बजट के लिये दो कारण बताये हैं। पहला आर्थिक मन्दी का और दूसरा महंगाई भत्ते में वृद्धि का। परन्तु इन दोनों बातों का ध्यान बजट तैयार करते समय मंत्री महोदय को रखना चाहिये था। क्योंकि इन दोनों बातों का ज्ञान मंत्री महोदय को पहले से ही होना चाहिये था। जब तक मूल्यों में वृद्धि होती रहेगी और मुद्रास्फीति बढ़ती रहेगी तब तक रेलवे क्या, कोई भी सरकारी उपक्रम लाभ नहीं दिखा सकता। मन्दी की आड़ ली जाती है। वास्तव में रेलवे में कार्यकुशलता और समुचित अर्थव्यवस्था का अभाव है। जब तक रेलवे की कार्यकुशलता और अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होता, तब तक रेलवे का भविष्य अच्छा नहीं है। रेलवे के लिये वह अच्छी बात है कि हमारे यहां जनसंख्या अधिक होने के कारण 60 लाख लोग प्रतिदिन रेल से यात्रा करते हैं। इससे रेलवे को लाभ होना चाहिये। परन्तु रेलवे को घाटा क्यों होता है, इसका मंत्री महोदय को पता लगाना चाहिये।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

[Mr. Speaker in the chair]

यह सोचना भी गलत है कि मन्दी के समाप्त हो जाने पर रेलवे की आर्थिक स्थिति सुधर जायेगी। रेलवे का यातायात घटता जा रहा है। आपने बताया कि 17 करोड़ रुपये का घाटा माल यातायात में कमी के कारण हुआ। अनाज के आयात में कमी होने से इस पर और अधिक प्रभाव पड़ेगा। माल यातायात के घटने का मुख्य कारण है सड़क यातायात और रेलवे यातायात में प्रतिस्पर्द्धा। लोगों को सड़क यातायात से रेलवे की तुलना में तीन लाभ होते हैं। सड़क यातायात सस्ता है, उसमें चोरी की सम्भावना कम है और माल के यातायात में देर नहीं होती है। यही कारण है कि रेलवे यातायात घटता और सड़क यातायात बढ़ता जा रहा है। एक समय वह आयेगा जबकि लोहा, कोयला, नमक, सीमेंट और अयस्कों को छोड़ कर शेष सब उपभोक्ता वस्तुएं सड़क यातायात से आने-जाने लगेंगी। रेलवे की आर्थिक दशा तभी सुधर सकती है जबकि उसका संचालन व्यय कम होगा।

प्रतिरक्षा और क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से रेलवे के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हैं। रेलवे लाइनों का मानचित्र देखने से ज्ञात होता है रेलवे लाइनें सम्पूर्ण देश के विभिन्न प्रदेशों में ठीक से वितरित नहीं हैं। हम यह चाहते हैं कि देश का प्रत्येक भाग आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से विकसित हो। यह तभी सम्भव है जबकि प्रत्येक क्षेत्र में रेलवे लाइन हो। बंगलौर-पूना लाइन के बड़ी लाइन न होने की वजह से यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। हालांकि इस क्षेत्र में पर्याप्त खनिज सम्पदा और जलविद्युत क्षमता विद्यमान है। कृषि उत्पादन भी इस क्षेत्र में बहुत अधिक होता है इस क्षेत्र में श्रावती, काली गंगावली तथा अघनाशिनी परियोजनाएं हैं। हुबली से कारवार तक एक नई रेलवे लाइन बिछाई जाये। यह केवल 88 मील का टुकड़ा है और इस पर केवल 19 करोड़ रुपये खर्च आयेगा। जो 6 वर्ष में लौह अयस्क के करवर बन्दरगाह तक ढोने में ही पूरी हो जायेगी।

अतः मेरा निवेदन है कि ऐसे प्रत्येक पिछड़े क्षेत्र में नई रेलवे लाइन बिछाई जाये जो सम्पदा सम्पन्न हो। निश्चय ही रेलवे को कुछ सफलताएं मिली हैं। परन्तु उन्हें सफलता तभी मिलेगी जबकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये रेलवे में कार्यकुशलता और मितव्ययिता को बढ़ाना होगा।

श्री अरूमुगम (टेंकासी) : रेलवे की मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ विशेष बातों का जिक्र करना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि रेलवे मंत्री तीसरे दर्जे की स्लीपर सीटों पर से अधिभार हटाने के प्रश्न पर पुनः विचार करने के लिये तैयार हो गये हैं।

तिरुनेलवेली से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव है। तामिलनाड के लोगों को यह आशा थी कि यह रेलवे लाइन इस वर्ष तैयार हो जायेगी। परन्तु इस वर्ष के बजट में इसको स्थान नहीं दिया गया। मंत्रालय कहता है कि उसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से सभा में यह आश्वासन चाहता हूं कि इस रेलवे लाइन पर काम शीघ्र ही शुरू कर दिया जायेगा। तिरुनेलवेली से मद्रास तक की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का भी प्रस्ताव है। अब तूतीकोरिन बन्दरगाह बड़ा बन्दरगाह बन गया है। जब तक यह लाइन बड़ी नहीं बनाई जाती तब तक बन्दरगाह से वांछित लाभ न होगा। अत: तूतीकोरिन, मद्रास और कोचीन को बड़ी लाइन से जोड़ दिया जाये। तिरुनेलवेली से मद्रास तक रेलगाड़ियों में बहुत अधिक भीड़ रहती है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि तिरूनेलवेली से मद्रास के बीच दिन में एक और एक्सप्रस गाड़ी छोड़ी जानी चाहिये। तिरुनेलवेली-लोनकोटा रेलवे लाइन पर केट्टेरीपट्टी के पास जो रेलवे क्रासिंग है, उसे चौड़ा किया जाना चाहिये। पोहलपुर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा धार्मिक केन्द्र है। जहां प्रतिवर्ष हजारों यात्री जाते हैं। उसके समीपस्थ रेलवे स्टेशन, रावनसमुद्रम पर यात्रियों के लिये पर्याप्त सुविधाएं दी जानी चाहियें। स्वास्थ्यवर्द्धक स्थान कोर्टलम के समीपस्थ रेलवे जंक्शन तैनकशी पर भी सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहियें। मेट्टीपलयम-ऊटी रेलवे लाइन बन्द न की जाये, क्योंकि उटकमंड एक ऐतिहासिक स्थान है। अधिकारियों को रेलवे गार्डों की शिकायतों को शीघ्र से शीघ्र दूर करना चाहिये। अन्त में, मेरा यह निवेदन है कि रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने के लिये अधिकारियों को हर सम्भव कदम उठाना चाहिये।

Shri Mahant Digvijai Nath (Gorakhpur) : Nepal can be called as a buffer State between Gorakhpur and China. It is very important place from strategic point of view. Therefore Gorakhpur should be connected with broad gauge line. It will facilitate the troop movement and it will add to the transport facilities.

Second thing which I would like to mention is that Chitoni, Maharajganj and Anandnagar should be connected with a railway line as it would bring additional revenues to the Railways.

There is great need of another platform at Tulsipur where every year a big fair of Devi Bhagvati is held for 15 days. It will be helpful for the passengers if a platform is constructed with an overbridge.

The train running from Tulsipur to Gonda is without lights, resulting in many accidents. Government should look into this matter.

Due to pilferage there are many losses on Railways. The cases of pilferage has been increased since the introduction of Railways Protection Force. I feel that if R.P.F. is also given the same powers which police is having at present, the pilferage will further increase. The Government should, therefore, reconsider this matter.

Government is deriving maximum income from the passengers travelling in third class but even then their fares have been increased which is unfair. The burden of increased fares should have been on the rich people travelling by 1st Class. Moreover there is overcrowding in the third class compartments. Railways should issue tickets in conformity with the seats available in the compartments in order to avoid overcrowding. There should be more facilities for the passengers travelling by third class.

The condition of narrow-gauge line in Gwalior is deplorable. The bogies of these trains are in broken condition. Either this line should be transferred back to Maharaja of Gwalior or Railways should convert it into broad-gauge line and improve its working.

There is healthy competition between Railway and road transport. As Railways could not ensure safety of goods and provide adequate facilities to the public, they are sending goods by road transport. Government should give serious thought to this problem.

There are many gates which were unmanned and many accidents occur due to this. Government should consider this matter and provide attendants at all the gates.

The drivers of the trains should be given due rest to which they are entitled. This will help in reducing the number of accidents.

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई

Arrest and Release of Members

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं आपका ध्यान श्री कुण्डू और श्री रामचरण की गिरफ्तारी की ओर दिलाना चाहता हूं इस संबंध में यहां पर कोई सूचना नहीं दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी पता चला है। हम इस संबंध में बाद में चर्चा करेंगे।

अनुदानों की मांगे, रेलवे, 1968–69 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1967–68

Demands for Grants (Railway) 1968-69 and Demand for Supplementary Grants (Railways) 1967—68

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh): It has become an annual feature that losses to Railways have been increasing and fares and freights on railways have also been increasing. We have never bothered to go deep into the reasons of this malady. One of the reasons of losses to Railways is that there is no railway line at the places which are rich in natural resources. Madhya Pradesh has potential resources of coal and iron ore. At present there is no railway line at Bastar and Bundelkhand areas to enable them to develop industrially. If railway lines are constructed in these areas it would encourage trade and provide employment opportunities. The development of rural areas of our State is being ignored. Government should pay more attention to this aspect and establish industries there so that these areas are fully developed.

There is a Niwari Railway Station. The platform of this Station is very low and therefore it is very difficult for the women, children, old and sick passengers to board the train. Moreover there is no arrangement of drinking water at this station which causes

great inconvenience to the passengers who have to wait there for pretty long time. Railways should pay necessary attention towards these things and do the needful. Due to lack of facilities for the goods traffic the same is being converted to road transport.

It has been observed that Manikpur-Jhansi train is being stopped at outer signal of Jhansi Station daily for one hour and as a result ticketless passenger get down there. No body checks them. Government should take necessary steps to stop ticketless travelling. Then there is great bungling in the Railway administration which should be looked into.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) The Railways should pay special attention to provide Railway lines keeping in view the defence preparedness. There should be more railway lines in the border areas of the country.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

There is no railway line between gurgaon and Alwar. The people living in this area have to experience great difficulty. Railways should pay special attention to this difficulty.

I would suggest that there should be a direct railway link between Hissar, Rohtak and Delhi which will help in the movement of foodgrains. It will also provide more facilities to the passengers.

Unless the passengers travelling by third class are provided with more amenities. The increase in the fares in their case is not justified. The number of trains should be increased keeping in view the increase in population. The speed of the trains should also be increased.

It has been observed that in Delhi itself goods clerks are working at one place for the last 12 years. As this post has become extra source of income for the incumbents, they do not want to be transferred. The Railways Board should look into this matter.

It may be pointed out that deficit budget is a matter of concern and bureaucrats of of Railways are responsible for it. The hon'ble Minister should not provide cover to the defaulting officials of Railways. He should try to remove their shortcomings. I would suggest that a committee should be set up to find out the causes of this deficit budget.

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी और रिहाई

Arrest and Release of Members

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के दो सदस्यों श्री स० कुण्डू तथा श्री राम चरण को गिरफ्तार किया गया था परन्तु बाद में रिहा कर दिया गया है। इसकी सूचना बुलेटिन में दी जायेगी।

श्री समर गुह : उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और जुर्माना किया गया। इस प्रकार यह सूचना सभा को बहुत देर से दी गई है। यह एक प्रकार का सभा का अपमान है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस घटना को अभी दो घण्टे हुए हैं। सूचना मिलने में भी तो समय लगता है।

अनुदानों की मांगें, रेलवे, 1968–69 तथा अनुदानों अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1967–68

Demands for Grants (Railways), 1968-69 and Demand for Supplementary Grants (Railways) 1967-68.

उपाध्यक्ष महोदय : रेलवे मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	10	श्री मुहम्मद इस्माइल	रेलवे प्रशासन के अधिक व्यय को देखते हुए वरिष्ठ तथाउच्च अधिकारियों की परिलब्धियों में कमी ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	11	श्री मुहम्मद इस्माइल	रेलवे बोर्ड के स्टाफ मेम्बर के पद को समाप्त करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	12	श्री रामावतार शास्त्री	अखिल भारतीय गार्ड परिषद् की शिकायतों तथा अभ्यावेदनों पर शीघ्र निर्णय लेने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	13	,,	रेलगाड़ियों पर कार्य करते हुए जिन रेलवे गार्डों की निर्मम हत्या की गई अथवा जिन पर निर्मम प्रहार किये गये उनके जीवन की रक्षा की व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	14	,,	रेलवे बोर्ड को समाप्त न करना	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	15	,,	रेलवे बोर्ड के अधिकारियों द्वारा लिये जा रहे मोटे वेतनों में कमी करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	16	,,	रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।

1	2	3	4	5
1	17	श्री रामावतार शास्त्री	जनता की सुविधाओं की ओर कोई ध्यान न दिया जाना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	18	,,	रेलवे बोर्ड पर रुपये की फजूलखर्ची	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	19	,,	संसद् सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर कोई ध्यान दिया जाना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	20	,,	रेलवे बोर्ड की मनमानी कार्यवाही और अनियमितताओं को रोकने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	21	,,	रेलवे बोर्ड के नौकरशाही रवैये को रोकने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	22	,,	रेलवे बोर्ड के सामान्य कर्मचारियों को अधिक सुविधायें प्रदान करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	23	,,	रेलवे बोर्ड के सदस्यों के वेतन को 1,000 रुपये तक सीमित करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	24	श्री चन्द्र शेखर सिंह	यात्रियों के किराये में वृद्धि ।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	25	,,	रेलवे बोर्ड को समाप्त न करना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	26	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	घाटे के रेलवे बजट को देखते हुये रेलवे बोर्ड के प्रत्येक सदस्य और अधिकारी को वेतन के रूप में अधिक से अधिक 1,000 रुपये प्रति मास देने की आवश्यकता ।	3,21,000 रुपये घटा दिये जायें

1	2	3	4	5
1	43	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	प्लटफार्म टिकट की दर और तीसरी श्रेणी के यात्री किराये में वृद्धि तथा तीसरी श्रेणी के लम्बी यात्रा वाले यात्रियों को सोने की सुविधाओं से वंचित करना ।	100 रुपये
1	77	श्री रामावतार शास्त्री	लखखी सराय स्टेशन (बिहार) पर रेल दुर्घटना को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
1	78	,,	रेल दुर्घटनाओं को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
1	79	,,	रेलवे बोर्ड के सदस्यों के वेतन को कम करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	80	,,	रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्यों के वेतन को कम करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	81	,,	रेलवे बोर्ड के अन्य उच्च अधिकारियों के वेतन को कम करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	83	श्री चन्द्र शेखर सिंह	रेलवे बोर्ड को फिर से गठित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	84	,,	रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के वेतनों को कम करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	85	,,	रेलवे बोर्ड में रेलवे कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	86	,,	रेल के प्रत्येक डिब्बे में पीने के पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	87	,,	रेलवे प्रशासन में कार्यक्षमता बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	88	,,	रेलवे अस्पतालों की हालत में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	89	,,	रेलवे कर्मचारियों को क्वार्टरों के आवन्टन में अनियमितता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
1	90	श्री चन्द्र शेखर सिंह	तीसरी श्रेणी के यात्री किराये में वृद्धि ।	100 रुपये
1	91	,,	तीसरी श्रेणी के यात्रियों को अधिक सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	92	,,	वातानुकूल डिब्बों का चलाना बन्द करन की आवश्यकता।	100 रुपय
2	109	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	गुना-माक्सी लाइन के निर्माण-कार्य की गति बढ़ाने की आवश्यकता।	100 रुपये
2	110	,,	बीना-झांसी आगरा लाइन पर दोहरी लाइन बिछाने के कार्य की गति बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	111	,,	भिंड (मध्य प्रदेश) तथा इटावा (उत्तर प्रदेश) के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने सम्बन्धी निर्माण कार्य के लिये सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	112	,,	भिंड (मध्य प्रदेश) तथा चिरगाँव (उत्तर प्रदेश) के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने के लिये सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	116	श्री रामावतार शास्त्री	'विविध व्यय" के नाम में व्यय को कम करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	117	,,	बिहार में नई लाइनों के सर्वेक्षणों की ओर उचित ध्यान देने में असफलता ।	100 रुपये
2	118	,,	उत्तर विहार में बड़ी लाइन की व्यवस्था करने के लिये सर्वेक्षण की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	119	,,	बिहार के पटना तथा गया जिलों में नई लाइनों की व्यवस्था करने के लिए सर्वेक्षणों की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
2	120	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार स्टेशन, उत्तर रेलवे, से जहानाबाद तक बरास्ता बिक्रम, पालो, अरवल, कूरथा और वहां से राजगिरि तक नई लाइन की व्यवस्था करने के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	121	,,	बिहार स्टेशन (उत्तर रलवे) से दाउदनगर और औरंगाबाद तक, बरास्ता अरवल, नई लाइन की व्यवस्था करने के लिये सर्वेक्षण की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	122	,,	आगरा-सासाराम लाइट रेलवे के क्षेत्र में बड़ी लाइन की व्यवस्था करने के लिये सर्वेक्षण को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	123	श्री रामावतार शास्त्री	समस्ती पुर से दरभंगा तक पूर्वोत्तर रेलवे बड़ी लाइन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	124	श्री रामावतार शास्त्री	बरौनी से कटिहार तक पूर्वोत्तर रेलवे बड़ी लाइन की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
2	125	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्वी रेलवे में बिजली से चलने वाली गाड़ियां चलाना आरम्भ करने में असफलता ।	100 रुपये
2	126	श्री रामावतार शास्त्री	चिकित्सा सेवाओं की ओर उचित ध्यान देने में असफलता ।	100 रुपये
2	127	श्री रामावतार शास्त्री	कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा कल्याण पर किये जा रहे खर्च में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	128	श्री रामावतार शास्त्री	कर्मचारियों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	129	श्री रामावतार शास्त्री	कर्मचारियों के लिए कैंटीनों में कुप्रबन्ध को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	130	श्री रामावतार शास्त्री	कर्मचारियों के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए प्रबन्ध करने की आवश्यकता	100 रुपये

1	2	3	4	5
2	131	श्री रामावतार शास्त्री	प्रशासनिक व्यय में कमी करने में असफलता ।	100 रुपये
4	154	श्री मुहम्मद इस्माइल	रेलवे प्रशासन के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या की आवश्यकता से अधिक होना ।	100 रुपये
4	155	श्री मुहम्मद इस्माइल	वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही जिसके कारण रेल दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है ।	100 रुपये
4	156	श्री मुहम्मद इस्माइल	पर्याप्त संख्या में गाड़ियों की व्यवस्था न किये जाने और गाड़ियों के आने जाने के समय उपयुक्त न होने के कारण गाड़ियों में बढ़ती हुई भीड़-भाड़ ।	100 रुपये
4	157	श्री मुहम्मद इस्माइल	वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों की ओर ध्यान न दिये जाने के कारण गाड़ियों का नियत समय के बाद चलना ।	100 रुपये
4	158	श्री मुहम्मद इस्माइल	कर्मचारियों की उचित शिकायतों को ध्यान से सुनने में प्रशासन की असफलता ।	100 रुपये
4	159	श्री मुहम्मद इस्माइल	रेलवे विद्युती करण मुख्यालय को दिल्ली से कलकत्ता ले जाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	160	श्री मुहम्मद इस्माइल	सैलून सुविधायें रेलवे के उच्च अधिकारियों के लिए समाप्त करने और उन्हें नियमित बोगियों का रूप देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	161	श्री मुहम्मद इस्माइल	रेल कर्मचारियों के लिए वर्दियां ठेकेदारों को देने की बजाय खण्डीय आधार पर विभागों द्वारा तैयार कराये जाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	162	श्री मुहम्मद इस्माइल	अधिकारियों के लिए विशेष पदों की व्यवस्था करना समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
4	163	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे सेवा आयोग बम्बई के अधिकारियों के वेतनों में कमी करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	164	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे सेवा आयोग कलकत्ता के अधिकारियों के वेतनों में कमी करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	165	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे सेवा आयोग, इलाहबाद के अधिकारियों के वेतनों में कमी करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	166	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे सेवा आयोग, मद्रास के अधिकारियों के वेतनों में कमी करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	167	श्री रामावतार शास्त्री	विभिन्न रेलवे सेवा आयोगों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	168	श्री रामावतार शास्त्री	विभिन्न रेलवे सेवाआयोगों के साधारण कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार करने तथा उन्हें अन्य सुविधायें देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	169	श्री श्रीनिवास मिश्र	बीना, कटनी, बिलासपुर, झारसुगुडा खड़गपुर, पुरी से होते हुये उड़ीसा से दिल्ली एक सीधी एक्सप्रैस सेवा आरम्भ करने में प्रशासन की असफलता ।	100 रुपये
4	170	श्री श्रीनिवास मिश्र	उड़ीसा राज्य में दिन के समय एक भी द्रुतगामी गाड़ी चलाने का प्रबन्ध न करना ।	100 रुपये
4	171	श्री चन्द्र शेखर सिंह	सभी श्रेणीयों के यात्रियों के लिये पृथक-पृथक प्रतीक्षालयों की व्यवस्था करने की आवश्यकता	100 रुपये
4	172	श्री चन्द्र शेखर सिंह	किशनगंज रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों के लिये एक अस्पताल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
5	174	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	ग्वालियर और भिंड, ग्वालियर और शिवपुर कलां तथा ग्वालियर और शिवपुरी के बीच छोटी लाइनों पर चलने वाली गाड़ियों में मरम्मत पर ध्यान देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
5	175	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	ग्वालियर और भिंड, ग्वालियर और शिवपुर कलां तथा ग्वालियर और शिवपुरी के बीच छोटी लाइनों पर चलने वाली गाड़ियों में सफाई, पंखों और प्रकाश का प्रबन्ध करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
5	176	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	ग्वालियर और भिंड, ग्वालियर और शिवपुर कलां तथा ग्वालियर और शिवपुरी के बीच छोटी लाइनों पर चलने वाले बहुत पुराने इंजनों और गाड़ियों को बदलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
5	177	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	ग्वालियर और भिंड, ग्वालियर और शिवपुर कलां तथा ग्वालियर और शिवपुरी के बीच छोटी लाइनों पर चलने वाली गाड़ियों की गति धीमी करने का प्रश्न ।	100 रुपये
5	178	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	ग्वालियर और भिंड, ग्वालियर और शिवपुर कलां तथा ग्वालियर और शिवपुरी के बीच छोटी लाइनों पर चलने वाली गाड़ियों में और डिब्बे लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
5	180	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे सम्पत्ति की रक्षा करने में असफलता ।	100 रुपये
5	181	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे सम्पत्ति की चोरी रोकने में असफलता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
5	182	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे सम्पत्ति की चोरी की बढ़ रही घटनाओं को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
5	183	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे की इमारतों की मरम्मत के नाम पर धन का अपव्यय रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपय
5	184	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों में की जाने वाली मरम्मत की ओर ध्यान देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
5	191	श्री के० एम० अब्राहम	बम्बई से कोचीन तक सीधी रेल-गाड़ियों चलाने में असफलता ।	100 रुपये
6	193	श्री मुहम्मद इस्माइल	निर्माण-कार्य पूरा हो जाने पर उसके लिये रखे गये श्रमिकों को खपाने में असफलता ।	100 रुपये
6	194	श्री मुहम्मद इस्माइल	यातायात लेखा क्लर्क ग्रेड II के लिये पदोन्नति सुविधाओं का अभाव ।	100 रुपये
6	195	श्री मुहम्मद इस्माइल	किसी कर्मचारी के रेलवे सेवा आयोग में उम्मीदवार के मामल में उसकी सेवा की अवधि को ध्यान में रखने में असफलता ।	100 रुपये
6	196	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे कुलियों को उनके जीविका उपार्जन की सुविधा प्रदान करने में असफलता ।	100 रुपये
6	197	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे कुलियों की सेवाएं नियमित करने में असफलता ।	100 रुपये
6	198	श्री रामावतार शास्त्री	लोको मैकेनीकल स्टाफ के 110—180 रुपये के वर्तमान वेतन-मान में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
6	199	श्री रामावतार शास्त्री	जमालपुर लोको शैड के मेकैनीकल स्टाफ के वेतनों में की गई कटौती को बहाल करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
6	200	श्री रामावतार शास्त्री	लोको मेकैनीकल स्टाफ के वेतन-मानों में वृद्धि करने में असफलता ।	100 रुपये
6	201	श्री रामावतार शास्त्री	भारतीय रेलवे मैकेनीकल स्टाफ एसोसियेशन की पूर्व रेलवे जोनल मेकैनीकल स्टाफ समिति की साझा बैठक में की गई मांगों को स्वीकार करने में असफलता ।	100 रुपये
6	202	श्री रामावतार शास्त्री	स्थानापन्न श्रमिकों को स्थायी आधार पर काम देने में असफलता ।	100 रुपये
6	203	श्री रामावतार शास्त्री	स्थानपन्न श्रमिकों के रहते बाहर के श्रमिकों को काम पर न लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
6	204	श्री रामावतार शास्त्री	'लोको रनिंग स्टाफ' की दशा में सुधार की आवश्यकता ।	100 रुपये
6	205	श्री रामावतार शास्त्री	'लोको रनिंग स्टाफ' समिति द्वारा प्रेषित मांगों को मान लेने की आवश्यकता ।	100 रुपये
6	206	श्री रामावतार शास्त्री	लोको शैडों में फोरमनों द्वारा हो रहे अत्याचार तथा अनियमितताओं को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
6	207	श्री रामावतार शास्त्री	जमालपुर (पूर्व रेलवे) में काम कर रहे फोरमैनों को तुरन्त स्थानान्तरित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
6	208	श्री रामावतार शास्त्री	गया (पूर्व रेलवे) के लोको स्टाफ के विरुद्ध पुलिस द्वारा चलाये गये मुकदमों को वापस लेने में असफलता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
6	209	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे कर्मचारियों के लिये सस्ते अनाज की दुकाने पुन: खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
6	210	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे कर्मचारियों के वेतन-मान उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप निश्चित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
6	211	श्री रामावतार शास्त्री	सिगनलमैनों तथा गैंगमैनों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
6	212	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे कर्मचारियों के साथ उनके अफसरों द्वारा किये जाये वाले दुर्व्यवहार को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
6	213	श्री रामावतार शास्त्री	लोको मकनीकल स्टाफ का कार्य-भार कम करने में अस-फलता ।	100 रुपये
6	214	श्री रामावतार शास्त्री	स्टीमरों तथा पत्तनों पर कार्य कार्य करने वाले कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
6	215	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्व रेलवे, दानापुर के 40 प्रति-शत ट्रेन क्लर्कों की छंटनी को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
6	216	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे गार्डों के पद के स्तर को ऊंचा करने में असफलता ।	100 रुपये
6	217	श्री रामावतार शास्त्री	अखिल भारतीय रेलवे गार्ड संघ की मांगें स्वीकार करने में असफलता ।	100 रुपये
6	218	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे कर्मचारियों को मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुसार अधिक मंहगाई भत्ता देने में असफलता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
6	219	श्री रामावतार शास्त्री	अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा रखी गई मांगें स्वीकार करने में असफलता ।	100 रुपये
6	220.	श्री रामावतार शास्त्री	पहल, दूसरे तथा तीसरे दर्जे के शयनयानों में कार्य कर रहे इलाहाबाद के सम्वाहकों की ड्यूटी में परिवर्तन संबंधी डिविजनल सुप्रिटेंडेंट द्वारा जारी किये गये परिपत्र को वापस लेने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	222	श्री रामावतार शास्त्री	आवश्यकता का सारा कोयला राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से ही खरीदने में असफलता ।	100 रुपये
7	223	श्री रामावतार शास्त्री	गर-सरकारी कोयला खानों से अधिक मूल्य पर कोयला खरीदा जाना समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	224	श्री रामावतार शास्त्री	डीजल तेल की चोरी रोकने में असफलता ।	100 रुपये
7	225	श्री रामावतार शास्त्री	कोयले की बड़ी पैमाने पर हो रही चोरी रोकने में असफलता ।	100 रुपये
7	226	श्री रामावतार शास्त्री	कोयले की खरीद में फैले भ्रष्टाचार को बन्द करने में असफलता ।	100 रुपये
7	227	श्री रामावतार शास्त्री	इंजन के ईंधन के लिये निश्चित 4-इंच कोयला खरीदने में असफलता ।	100 रुपये
7	228	श्री रामावतार शास्त्री	कोयले के बड़े टुकड़ों के कारण इंजन के कोयले की अधिक खपत रोकने में असफलता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
7	229	श्री रामावतार शास्त्री	कोयला तथा उसकी राख ठेकेदारों को नाममात्र मूल्य पर बेचने की प्रथा बन्द करने में असफलता।	100 रुपये
7	230	श्री रामावतार शास्त्री	कोयले की बड़े पैमाने पर हो रही चोरी रोकने में असफलता।	100 रुपये
8	231	श्री मुहम्मद इस्माइल	सभी रेलवे खंडों में इलैक्ट्रानिक संगणकों के चलाये जाने पर रोक लगाना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
8	233	श्री रामावतार शास्त्री	लेखन-सामग्री तथा प्रपत्रों का अपव्यय रोकने में असफलता।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाये
8	234	श्री रामावतार शास्त्री	माल की चोरी रोकने में असफलता।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाये
8	235	श्री रामावतार शास्त्री	माल चढ़ाने-उतारने मे आवश्यक सावधानी बरतने की आवश्यकता।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाये।
8	236	श्री रामावतार शास्त्री	मुआवजे के नाम पर धन का अपव्यय रोकने की आवश्यकता।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाये।
8	237	श्री रामावतार शास्त्री	सभी रेलवे कर्मचारियों को वर्दियां देने की आवश्यकता।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाये।
8	238	श्री रामावतार शास्त्री	वर्दियां देने में सुधार की आवश्यकता।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाये।
8	239	श्री रामावतार शास्त्री	कर्मचारियों को बनी-बनाई वर्दियां देने के स्थान पर अपेक्षित कपड़ा देने की आवश्यकता।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाये।

1	2	3	4	5
8	240	श्री रामावतार शास्त्री	सभी कर्मचारियों को ऊनी बर्दियां देने में असफलता ।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाये ।
8	241	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे कुलियों को ऊनी बर्दियां देने में असफलता ।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाये ।
8	246	श्री रामावतार शास्त्री	लक्खी सराय रेल दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिवारों को पूरा पूरा मुआवजा देने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाये ।
8	247	श्री रामावतार शास्त्री	रेल दुर्घटनाओं मे घायल हुए यात्रियों को दी जाने वाली राशि में बृद्धि करने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 100 रुपये कर दी जाये ।
8	251	श्री मुहम्मद इस्माईल	तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये अपर्याप्त आवास-संबंधी सुविधायें ।	100 रुपये
8	252	श्री मुहम्मद इसमाईल	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों क लिये अपर्याप्त आवास-सम्बन्धी सुविधायें ।	100 रुपये
8	253	श्री रामावतार शास्त्री	चिकित्सा-सेवा की असन्तोषजनक दशा में सुधार करने में असफलता ।	100 रुपये
8	254	श्री रामवतार शास्त्री	रेलवे अस्पतालों में मरीजों को अधिक अच्छा भोजन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
8	255	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे अस्पतालों में मरीजों को दिये जाने वाले भोजन की चोरी रोकने में असफलता ।	100 रुपये
8	256	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे अस्पतालों में मरीजों को पेटेंट दवाइयां दिये जाये की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
8	257	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त मात्रा में फल तथा दूध दिये जाने की आवश्यकता।	100 रुपये
8	258	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे अस्पतालों में दवाइयों की चोरी तथा चोर-बाजारी रोकने में असफलता।	100 रुपये
8	259	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे स्वास्थ्य केन्द्रों तथा औष-धालयों में कुप्रबन्ध रोकने में असफलता।	100 रुपये
8	260	श्री रामावतार शास्त्री	सभी रेलवे स्वास्थ्य केन्द्रों में महिलाओं के उपचार तथा उनके लिये शय्याओं की व्यवस्था करने में असफलता।	100 रुपये
8	261	श्री रामावतार शास्त्री	सभी रेलवे स्वास्थ्य केन्द्रों में पुरुष तथा महिला डाक्टरों की पर्याप्त व्यवस्था करने में असफलता।	100 रुपये
8	262	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अस्प-तालों में घटिया किस्म का भोजन दिया जाना रोकने में असफलता।	100 रुपये
8	263	श्री रामावतार शास्त्री	स्टेशनों पर सफाई बिल्कुल न होना।	100 रुपये
8	264	श्री रामावतार शास्त्री	प्रतीक्षालयों में सफाई की अस-न्तोषजनक दशा।	100 रुपये
8	265	श्री रामावतार शास्त्री	समस्तीपुर रेलवे अस्पताल में डाक्टरों के तत्काल स्थानां-तरण की आवश्यकता।	100 रुपये
8	266	श्री रामावतार शास्त्री	समस्तीपुर अस्पताल के डाक्टरों द्वारा स्वच्छता कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने में असफलता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
8	267	श्री राम अवतार शास्त्री	समस्तीपुर अस्पताल के मुअत्तिल किये गये कर्मचारियों को पर्याप्त जीवन-निर्वाह भत्ता दिये जाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
8	268	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्वी रेलवे के जमालपुर स्टेशन पर शौचालयों में सफाई सुनिश्चित करने में असफलता ।	100 रुपये
8	269	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे में सफाई सुनिश्चित करने में असफलता ।	100 रुपये
12	270	श्री न० चा गौंडर	अलाभप्रद लाइनें	100 रुपये
14	271	श्री मुहम्मद इस्माइल	ठेकेदारी प्रथा समाप्त किये जाने तथा श्रमिक सहकारी समितियों को काम दिये जाने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
14	289	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	भिण्ड तथा ग्वालियर के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में असफलता ।	100 रुपये
14	291	श्री मुहम्मद इस्माइल	डम डम से सीरहाट तक दोहरी रेलवे लाइन बिछाने में असफलता ।	100 रुपये
14	292	श्री मुहम्मद इस्माइल	मालदा से बालवेहात तथा दिल्ली तक रेलवे लाइन बिछाने में असफलता ।	100 रुपये
14	306	श्री चन्द्रशेखर सिंह	पूर्व रेलवे में डेहरी-ओन सोन से नसरीगंज शहर नारायनपुर तथा अगियाबों होते हुये आरा जक्शन तक नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	307	श्री चन्द्रशेखर सिंह	पूर्व रेलवे में पटना-गया लाइन पर मुढेर के निकट लैवल-क्रासिंग पर चौकीदार वाला फाटक बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
14	308	श्री चन्द्रशखर सिंह .	पूर्व रेलवे में मख़दुमपुर स्टेशन से खिदर सराय और सबाहदा होते हुये राजगीर तक छोटी लाइन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	309	श्री चन्द्रशेखर सिंह .	पूर्व रेलवे में गया जंकशन से शेर-घाटी होते हुये हजारीबाग शहर तक नई लाइन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	310	श्री चन्द्रशेखर सिंह	पूर्व रेलवे की पटना-गया लाइन पर जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर पहले तथा दूसरे दर्जे के प्रतिक्षालयों की दशा सुधारने तथा वहाँ पर्याप्त फर्नीचर रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	311	श्री चन्द्रशेखर सिंह .	पूर्व रेलवे की पटना-गया लाइन पर जहानांबाद कोर्ट स्टेशन पह पहले तथा दूसरे दर्जे के प्रतिक्षालय बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	312	श्री चन्द्रशेखर सिंह .	पूर्व रेलवे में अरोआल से जहानाबाद होते हुये बिहार शरीफ तक नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	313	श्री चन्द्रशेखर सिंह	पूर्व रेलवे में बिहाटा स्टेशन से दाउदनगर होते हुये बरौनी जंकशन तक नई लाइन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	314	श्री चन्द्रशेखर सिंह .	पूर्व रेलवे में रफीगंज को टिकारी तथा किंजर होते हुए बिहटा जंकशन से मिलाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	315	श्री चन्द्रशेखर सिंह	पूर्व रेलवे में गया जंकशन से टेकारी शहर होते हुये गोह, दाउदनगर तक नई लाइन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
14	315	श्री चन्द्र शेखर सिंह	पूर्व रेलवे में गया जंकशन से टेकारी शहर होते हुए गोह, दाउद नगर तक नई लाईन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	316	श्री चन्द्र शखर सिंह	पूर्व रेलवे में औरंगाबाद से नवी नगर शहर तक छोटी लाइन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	317	श्री श्रीनिवास मिश्र	कटक स्टेशन के दक्षिणी छोर पर रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी पुल बनाने में असफलता ।	100 रुपये
14	318	श्री के० एम० अब्राहम	केरल राज्य में एरणाकुलम तथा त्रिवेन्द्रम स्टशनों के बीच वर्तमान मीटर गेज लाइन को समाप्त करने एरणाकुलम से कोट्टयम होते हुये त्रि-वेन्द्रम तक बड़ी लाइन बनाने में असफलता ।	100 रुपये
14	319	श्री के० एम० अब्राहम	त्रिवेन्द्रम, केरल राज्य में कन्या कुमारी, मद्रास राज्य, के बीच नई लाइन बनाने में असफलता ।	100 रुपये
14	320	श्री के० एम० अब्राहम	केरल राज्य में पुनोलर तथा तिरुवाल्ला के बीच नई लाइन बनाने में असफलता ।	100 रुपये
14	321	श्री के० एम० अब्राहम	केरल राज्य में एल्लेप्पी होते हुए कोचीन तथा क्विलोन के बीच नई लाइन बनाने की आव-श्यकता ।	100 रुपये
14	322	श्री के० एम० अब्राहम	कोट्टायम, केरल राज्य तथा मदुरै, मद्रास राज्य के बीच कोट्टायम कुमाली रोड के साथ साथ एक नई लाइन बनाने में असफलता ।	100 रुपये
14	323	श्री के० एम० अब्राहम	कोचीन, केरल, राज्य, से मुन्नार, केरल राज्य, होते हुए बोदी-नैकानूर मद्रास राज्य तक एक नई लाइन बनाने में असफलता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
14	324	श्री चन्द्र शेखर सिंह	यमुना नदी पर एक और पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	325	श्री चन्द्र शेखर सिंह .	सभी रेलवे में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	337	श्री के० एम० अब्राहम	केरल राज्य में नीलिमंगलम के निकट कोट्टायम में रेलवे स्टेशन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	338	श्री के० एम० अब्राहम	केरल राज्य स्थित काडुथुरुथी में रेलवे स्टेशन बनाने में असफलता ।	100 रुपये
1	391	श्री नम्बियार .	रेलवे बोर्ड का असंतोषप्रद कार्य	100 रुपये
1	392	श्री नम्बियार .	महा प्रबन्धकों को अधिक शक्तियां प्रदान कर रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	393	श्री नम्बियार .	कर्मचारी कार्मिक संघों को मान्यता देने के लिये फार्मूला बनाना तथा पक्षपात और राजनीतिक भेदभाव दिखाने की वर्तमान स्थिति में सुधार करना ।	100 रुपये
1	394	श्री नम्बियार .	रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तथा रेलवे के वित्तीय आयुक्त को समान वेतन-मान देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	395	श्री नम्बियार .	जिन कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया गया हो, नौकरी से हटा दिया गया हो, अनिवार्य-रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया हो, और जिनकी नौकरी समाप्त कर दी गई हो, अथवा	100 रुपये

1	2	3	4	5
			उन को कोई और शिकायत हो, उनकी अन्तिम अपीलों की सुनवाई के लिये रेलवे बोर्ड के स्तर का अपीलीय न्यायाधिकरण नियुक्त करने की आवश्यकता ।	
1	396	श्री नम्बियार	. प्रभागीय कार्मिक अधिकारी के अधीन सभी मजदूरों और कर्मचारियों को हटाकर और प्रभाग अधिकारियों को कार्मिक सम्बन्धी कार्य का प्रभार देकर जोनल रेलवे के प्रभागीय कार्मिक व्यवस्था पुनर्गठन करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	414	श्री नम्बियार	. डाक के डिब्बों की अपर्याप्त व्यवस्था जिसके परिणामस्वरूप तीसरी श्रेणी के डिब्बों का उपयोग डाक लाने-ले-जाने के लिए किया जा रहा है ।	100 रुपये
1	415	श्री नम्बियार	डाक के डिब्बों में रोशनी की अपर्याप्त व्यवस्था ।	100 रुपये
1	416	श्री नम्बियार	डाक के डिब्बों से खतरे की जंजीर हटाना, जिससे कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है ।	100 रुपये
1	417	श्री नम्बियार	महत्वपूर्ण रेलवे जंकशनों पर रेलवे डाक सेवा के लिए इमारतें बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	418	श्री नम्बियार	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निदेश के अनुसार सभी श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों के लिए कार्य के 8 घंटे निश्चित करने	100 रुपये

1	2	3	4	5
			और पुराने राजाध्यक्ष पंचाट को समाप्त करने की आवश्यकता ।	
1	419	श्री नम्बियार	इरोड—सथिया मंगलम—सम्राजनगर की नई लाइन का कार्य आरम्भ किये जाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	420	श्री श्रीधरन	तेल्लिचेरि—मैसूर रेल मार्ग का सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	421	श्री नम्बियार	कन्या कुमारी रेल मार्ग का कार्य शीघ्र आरम्भ करने की आवश्यकता क्योंकि इसका सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है ।	100 रुपये
1	422	श्री श्रीधरन	मंगलूर—हस्सन रेल मार्ग को प्रस्तावित मीटर लाइन के स्थान पर बड़ी लाइन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	423	श्री श्रीधरन	लम्बी यात्रा करने वाले दर्जे के यात्रियों पर शयन स्थानों के लिये शुल्क लगाने का सुझाव वापस लेने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	424	श्री नम्बियार	यात्री किराये और माल भाड़े में वृद्धि करने के प्रस्ताव वापस लेने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	441	श्री नम्बियार	सभी रेलवे विभागों में अस्थायी कर्मचारियों और नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी का गम्भीर ख़तरा ।	100 रुपये
4	442	श्री नम्बियार	कोयम्बतूर नगर (दक्षिण रेलवे) में अवनासी रोड के रेलवे फाटक पर एक उपरि-पुल या नीचे का पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
4	443	श्री नम्बियार	कोयम्बतूर के निकट इएगुर स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर पक्का स्टेशन बनाने की आवश्यकता, जहाँ सभी यात्री सुविधायें हों ।	100 रुपये
4	444	श्री श्रीधरन	दक्षिण रेलवे की तिरुपुर रेलवे स्टेशन पर वेस्ट कोस्ट एक्सप्रैस को रोकने की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	445	श्री नम्बियार	कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन के जमादारों और सफाई करने वालों को क्वार्टर देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	446	श्री श्रीधरन	कोयम्बतूर से मद्रास और मंगलौर की ओर जाने वाली गाड़ियों में तीसरी श्रेणी में यात्रा करने के स्थान को बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	447	श्री श्रीधरन	भारी वर्षा के बावजूद भी दक्षिण रेलवे के पश्चिम तट तर बहुत से स्टेशनों में प्लैटफार्मों का छतदार बनाने में उपेक्षा ।	100 रुपये
4	448	श्री नम्बियार	विशेषकर दक्षिण रेलवे के पश्चिम तट पर स्थित पुराने रेलवे क्वार्टरों की मरम्मत, उन्हें नये ढंग का बनाने तथा उनके पुन-र्निमाण की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	449	श्री श्रीधरन	दक्षिण रेलवे की वैस्ट कोस्ट एक्सप्रेस की समय-सारणी में सुधार की आवश्यकता ताकि वह पश्चिम तट क्षेत्र के यात्रियों के लिये ठीक सिद्ध हो ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
4	450	श्री श्रीधरन	क्विलन्दी पर मंगलूर-मद्रास मेल, मंगलूर कोचीन एक्सप्रेस तथा वैस्ट कोस्ट एक्सप्रेस को ठहराने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	451	श्री श्रीधरन	वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस के बडगरा पर ठहरने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	452	श्री श्रीधरन	चेमनचारी रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	453	श्री श्रीधरन	चेमनचारी रेलवे स्टेशन पर प्लैट-फार्म पर छत बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	454	श्री नम्बियार	डीज़ल इंजन आरम्भ किये जाने के कारण लोको शेड में काम करने वाले कर्मचारियों की बड़ी संख्या में छंटनी का भय ।	100 रुपये
4	455	श्री नम्बियार	गोल्डन राव (दक्षिण रेलवे) में रेलवे कालोनी के 'सी' टाइप क्वार्टरों में बिजली का कार्य पूरा करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	456	श्री नम्बियार	गोल्डन राक वर्कशाप (दक्षिण रेलवे) में प्रोत्साहन योजना के नाम पर कुशल कारीगरों की छंटनी से उत्पन्न स्थिति ।	100 रुपये
4	457	श्री नम्बियार	इंजन परिचालक—वर्ग के लिये आठ घंटे का कार्य-काल निर्धारित करने से इंकार; जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है ।	100 रुपये
4	458	श्री नम्बियार	इंजन फायरमैनों की उचित शिकायतें सुनने से इंकार जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों में गंभीर बेचैनी पैदा हो गई है और काम रुक गया है ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
4	459	श्री नम्बियार	दक्षिण रेलवे के इंजन फायरमैनों को साधारण पदोन्नति देने तथा उन्हें स्थायी करने से इंकार जिसके परिणाम स्वरूप गाड़ियों की संचालन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है।	100 रुपये
4	462	श्री नम्बियार	रेलवे कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को रेलवे अस्पतालों में रोग-शय्या दिये जाने पर उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सहायता तथा भोजन दिये जाने की आवश्यकता जैसा कि पहले शासन-काल में किया जाता था।	100 रुपये
4	463	श्री नम्बियार	तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की तरह ही सेवा-निवृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी एक निःशुल्क रेलवे पास दिये जाने की आवश्यकता जैसा कि पहले ब्रिटिश शासन-काल में किया जाता था।	100 रुपये
4	464	श्री नम्बियार	स्टेशन मास्टरों, क्वांटसमैन जैसे परिचालन कर्मचारियों को किराये मुक्त क्वार्टरों के देने की आवश्यकता जैसा कि पहले ब्रिटिश शासन-काल में किया जाता था।	100 रुपये
4	465	श्री नम्बियार	हर रेलवे कर्मचारी के कम से कम एक पुत्र को नौकरी में रखने की आवश्यकता जैसा कि पहले ब्रिटिश शासन-काल में किया जाता था।	100 रुपये
4	466	श्री नम्बियार	दसियों वर्ष पहले बनाये गये क्वार्टरों के किरायों का उस समय निर्धारित की गई किराया-	100 रुपये

1	2	3	4	5
			सीमा तक घटाये जाने की आवश्यकता जैसा कि ब्रिटिश शासन-काल में किया जाता था ।	
4	467	श्री नम्बियार	रेलवे कर्मचारियों की संस्थाओं को निःशुल्क पानी तथा बिजली सप्लाई करने की आवश्यकता जैसा कि ब्रिटिश शासन-काल में किया जाता था ।	100 रुपये
1	527	श्री किरुतिनन	प्लेटफार्म शुल्क, तीसरे दर्जे के किराये और लम्बी यात्रा करने वाले तीसरे दर्जे के यात्रियों को सोने संबंधी सुविधाओं से वंचित करना ।	100 रुपये
1	528	श्री किरुतिनन	तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये सुविधाओं का अभाव ।	100 रुपये
1	529	श्री किरुतिनन	टिकट चैकरों की मांगें पूरी करने और उन्हें परिचालन कर्मचारी वर्ग में रखने में असफलता ।	100 रुपये
1	530	श्री किरुतिनन	रेलवे खान-पान की खराब व्यवस्था ।	100 रुपये
1	531	श्री किरुतिनन	अनौपचारिक सलाहकार समितियों में संसद-सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों की ओर ध्यान देने में असफलता ।	100 रुपये
1	532	श्री किरुतिनन	मानामदुरै, दक्षिण रेलवे पर, वैगई नदी पर एक नया पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	533	श्री किरुतिनन	दक्षिण रेलवे में मदुरै-मानामदुरै लाइन पर पीसरपटनम, थिरुपाचेटी, पाप्पनकुलम के निकट रेलवे फाटक बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
1	534	श्री किरूतिनन	दक्षिण रेलवे के करैकुडि-मानाम-दुरै लाइन पर शिवगंगा कालेज तथा मदुरै-मानामदुरै लाइन पर राजागम्हिरम तथा लाडनेडल स्थानों पर हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता।	600 रुपये
1	535	श्री किरूतिनन	सभी डिब्बों में पेय जल की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	545	श्री किरूतिनन	रेलवे मे स्वचालित यंत्रों का लगाया जाना ।	100 रुपये
2	546	श्री किरूतिनन	मद्रास राज्य में दिण्डुक्कल और मरैक्मुडी अथवा मदुरै से कारै-क्कुडि (बरास्ता) तिरुपात्तूर तक नया रेल मार्ग बनाने हेतु सर्वेक्षण करने की आवश्यकता।	100 रुपये
2	547	श्री किरूतिनन	मद्रास राज्य में कारैक्कुडि-तोंडी तथा अरतांगी तोंडी के बीच रेल-मार्ग बनाने हेतु सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	548	श्री किरूतिनन	मद्रास राज्य में अरता से मंडप्पम के बीच तटीय रेल-मार्ग के लिये सर्वेक्षण करने की आवश्यकता।	100 रुपये
4	550	श्री किरूतिनन	दक्षिण रेलवे में परामाक्कुडि स्टेशन के प्लेटफार्म पर छत डालने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	551	श्री किरूतिनन	दक्षिण रेलवे के विरूदुनगर से अरुप्पुकोटै, मनामदुरै-लाइन होते हुये मद्रास तक सीधी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने में असफलता ।	100 रुपये
4	552	श्री किरूतिनन	दक्षिण रेलवे में मदुरै से रामे-श्वरम तक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने में असफलता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
4	553	श्री किरूतिनन	दक्षिण रेलवे के त्रिचिनापल्ली डिवीजन के फायरमैनों की कठिनाइयां दूर करने में असफलता ।	100 रुपये
4	554	श्री किरूतिनन	दक्षिण रेलवे में मदुरै तथा शेंकोटा स्टेशनों के बीच 143 और 144 के लिये चार एस०एच० डाक डिब्बों की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
5	555	श्री किरूतिनन	सभी रेलवे "फीडर" सड़कों के लिये तारकोल की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
5	556	श्री किरूतिनन	दक्षिण रेलवे में मनामदुरै तथा त्रिचनापल्ली के बीच डीजल गाड़ियों के डिब्बों की मरम्मत की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
5	557	श्री किरूतिनन	दक्षिण रेलवे में अरनमदैन सिरूवायल पर स्टेशन की स्थायी इमारत बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
9	558	श्री किरूतिनन	दक्षिण रेलवे में पूर्व-मनामदुरै पर स्टेशन की स्थायी इमारत बनाने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
9	563	श्री पी० विश्वम्भरन	तीसरे दर्जे के यात्री-किराये में वृद्धि ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
9	564	श्री किरूतिनन	मद्रास-तिरुवेन्द्रम, मद्रास-कोचीन तथा मद्रास-मंगलूर के बीच चलने वाली गाड़ियों में नए डिब्बे लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
10	569	श्री किरूतिनन	दक्षिण रेलवे में मनादुरै में एक महिला डाक्टर नियुक्त करने में असफलता ।	100 रुपये
10	570	श्री किरूतिनन	दक्षिण रेलवे में मनामदुरै पर कर्मचारियों के लिये आवास-सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
14	572	श्री किरूतिनन	मद्रास राज्य में तिरुनेलवेलि से कन्याकुमारी तक नई रेलवे लाईन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	573	श्री किरूतिनन	मद्रास राज्य में मानामदुरै से तूतीकोरिन तक एक नई रेलवे लाईन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	574	श्री किरूतिनन	पामगन से धनुषकोडि तक उखाड़ी गई रेलवे लाईन को पुनः बिछाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	575	श्री पी० विश्वम्भरन	तिरुवेन्द्रम से कन्याकुमारी तक एक नई रेलवे लाईन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	576	श्री पी० विश्वम्भरन	एरणाकुलम से तिरुवेन्द्रम के बीच मीटर गेज लाईन को बड़ी लाईन में बदलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	577	श्री किरूतिनन	कुछ विद्यमान रेल मार्गों को अलाभकारी होने के नाम पर उखाड़ने के प्रस्ताव को वापस लेने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	578	श्री किरूतिनन	नेडुनगुलम, दक्षिण रेलवे, के स्टेशन को पुनः खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	596	श्री पी० श्रीकांतन नायर	दक्षिण रेलवे की शेंकोटा-त्रिवेन्द्रम सैक्शन पर प्लेटफार्मों पर छत बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
			ताकि यात्रियों का, विशेषकर वर्षा से, बचाव हो सके ।	
4	597	श्री नम्बियार	जिन कर्मचारियों ने दक्षिण मध्य रेलवे से दक्षिण रेलवे में जाने की इच्छा प्रकट की थी उन्हें उनको पूर्ववत दिये गये वचन के अनुसार वहां स्थानांतरित करने में असफलता ।	100 रुपये
4	598	श्री नम्बियार	जिन कर्मचारियों को रात्रि में काम करना पड़ता है उन सबको, इस बात का ध्यान न करते हुए कि उन्हें रात्रि में लगातार काम करना पड़ता है अथवा बीच-बीच में, रात की ड्यूटी का भत्ता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	599	श्री नम्बियार	कोटा (पश्चिम रेलवे) में डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय में कार्य की अस्त-व्यस्त दशा जिसके अनुसार उक्त डिवीजन में समय-समय पर असंतोष पैदा हो जाता है ।	100 रुपये
4	600	श्री नम्बियार	नागापट्टिनम (दक्षिण रेलवे) में रेलवे के सामान को अनुचित रूप से क्रमबद्ध प्रणाली से दूसरे स्थान पर ले जाना जिस से कि कर्मचारियों के लिये संचालन सम्बन्धी तथा अन्य कठिनाइयां पैदा होती हैं ।	100 रुपये
5	601	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	क्विलोन (दक्षिण रेलवे) में "लोको-शेड" में कर्मचारियों को शौचालयों, कैंटीन तथा हाथ आदि धोने सम्बन्धी उचित सुविधायें देने में भी असफलता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
5	603	श्री नम्बियार	वेतन लेने से पहले इंजीनियरी गैंगमैनों तथा दूसरे व्यक्तियों को वेतन-विवरणी पर हस्ताक्षर करने की अनुमति न देने तथा पढ़े लिखे व्यक्तियों के भी अंगूठे के निशान लेना जारी रखने की पुरानी प्रणाली को समाप्त करना ।	100 रुपये
5	604	श्री नम्बियार	इंजीनियरी विभाग के कार्मिकों को वेतन स्लिपें देने के आवश्यकता ताकि उन्हें यह पता लग सके कि उनके वेतन से वेतन विवरणी में वास्तव में कितनी कटौती दिखाई गई है ।	100 रुपये
5	605	श्री नम्बियार	रेलवे लाइन पर रात्रि को गश्त लगाने के लिए दो व्यक्तियों की मंजूरी देने की आवश्यकता ताकि रेल मार्ग की रक्षा की जा सके ।	100 रुपये
5	606	श्री नम्बियार	उन कार्मिकों को, जिन्होंने गोल्डन राक (दक्षिण रेलवे) कालोनी में पूर्व अनुमति से क्वार्टर खाली किये थे, मकान के किराये में बकाया राशि देने में अनुचित विलम्ब ।	100 रुपये
5	607	श्री नम्बियार	दक्षिण रेलवे के गोल्डन राक तथा पेरम्बूर वर्कशाप तथा लोको-शेडों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
5	608	श्री नी० कान्तन नायर	रेलवे कमर्शियल क्लर्कों के कार्य-भार पदोन्नति काम के घंटे निवास-स्थान तथा अंधाधुंध स्थानान्तरण के बारे में शिकायतें दूर करने की आवश्यकता ।	100 रूपये.

1	2	3	4	5.
5	609	श्री नी० कान्तननायर	दक्षिण रेलवे की डिवीजन सैक्शन में उन इंजीनियरी गैंगमैनों की सेवायें नियमित करने की आवश्यकता जिन्हें अनेक वर्षों से नैमत्तिक श्रमिक के रूप में रखा गया है ।	100 रुपये
5	610	श्री श्रीनिवास मिश्र	"सैक्शन कंट्रोलरों" के दो पदक्रमों को मिलाकर एक करने के बारे में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में असफलता ।	100 रुपये
5	611	श्री श्रीनिवास मिश्र	वेतन-मानों तथा पदक्रमों के बारे में नियंत्रण संगठन के कर्मचारियों के साथ किया गया भेद-भाव ।	100 रुपये
5	612	श्री श्रीनिवास मिश्र	नियन्त्रण संगठन के कर्मचारियों को समुचित प्रोत्साहन तथा पदोन्नति के उचित अवसर देने में भी असफलता ।	100 रुपये
5	613	श्री नम्बियार	दक्षिण रेलवे के कोचीन तेल शोधक कारखाने की रेलवे साइडिंग पर "वर्कर्स स्पेशल" पुनः चलाने तथा इरिम्पानम पर पीने के पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
5	614	श्री नम्बियार	दक्षिण रेलवे में थिरुवन्नामलई के रेलवे औषधालय को वहीं पर बनाये रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	617	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे बोर्ड को समाप्त करने की आवश्यकता ।	43,00,000 रुपये
1	618	श्री रामावतार शास्त्री	बजट का घाटा करने के लिए अधिकारियों का वेतन अधिक से अधिक एक हजार रुपये निश्चित करने की आवश्यकता ।	1,00,00,000 रुपये

1	2	3	4	5
1	619	श्री रामावतार शास्त्री	वातानुकूलित गाड़ियों को हटाने की आवश्यकता ।	1,00,00,000 रुपये
1	620	श्री रामावतार शास्त्री	सैलूनों की समाप्ति की आवश्यकता	1,00,00,000 रुपये
1	621	श्री रामावतार शास्त्री	अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति बन्द करने की आवश्यकता ।	1,00,00,000 रुपये
1	622	श्री रामावतार शास्त्री	उच्च अधिकारियों की संख्या कम करने की आवश्यकता ।	1,00,00,000 रुपये
1	623	श्री रामावतार शास्त्री	भारतीय रेलवे लोकोमैकेनिकल कर्मचारी संस्था की शिकायतें दूर करने में असफलता ।	100 रुपये
1	624	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे कार्यालय कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने में असफलता ।	100 रुपये
1	625	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे परिचालन कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने में असफलता ।	100 रुपये
1	626	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे टिकट निरीक्षकों को परिचालन कर्मचारी मानने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	627	श्री रामावतार शास्त्री	यात्री किराये में मनमाने ढंग से वृद्धि	100 रुपये
1	628	श्री रामावतार शास्त्री	तीसरे दर्जे के शयनयानों की यात्रा के लिए प्रति यात्री चार रुपये की वृद्धि ।	100 रुपये
1	629	श्री रामावतार शास्त्री	1966 में लक्खीसराय रेल दुर्घटना की जाँच करने के लिए नियुक्त की गई जाँच समिति की सिफारिशें लागू करने में असफलता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
1	638	श्री कंवर लाल गुप्त	यात्रियों की संख्या बढ़ जाने के परिणामस्वरूप तथा पुराने डिब्बों को बदलने के लिए नये डिब्बे बनाने में असफलता ।	100 रुपये
1	639	श्री कंवर लाल गुप्त	विदेशों से लिये गये ऋणों से इंजन बनाने में असफलता ।	100 रुपये
1	640	श्री कंवर लाल गुप्त	दिल्ली में रिंग रेलवे का निर्माण समय पर पूरा करने में असफलता ।	100 रुपये
1	641	श्री कंवर लाल गुप्त	दिल्ली में शीघ्रातिशीघ्र भूमिगत रेलवे बनाने में असफलता ।	100 रुपये
1	642	श्री कंवर लाल गुप्त	दिल्ली में सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को अधिक सुविधायें देने में असफलता ।	100 रुपये
1	643	श्री कंवर लाल गुप्त	शक्ति नगर सराय रोहिल्ला, पटेल नगर, और सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली के स्थानों पर ऊपरि पुल बनाने में असफलता।	100 रुपये
1	644	श्री कंवर लाल गुप्त	दिल्ली के आस पास विशेषकर शक्ति नगर में हाल्ट स्टेशन बनाने में असफलता ।	100 रुपये
1	645	श्री कंवर लाल गुप्त	अक्टूबर, 1968 तक दिल्ली से कलकत्ता तक तेज रफ्तार वाली गाड़ी चलाने मे असफलता ।	100 रुपये
2	649	श्री रामावतार शास्त्री	भागलपुर मन्दार रेलव लाइन को हानि के नाम पर बन्द करने की नीति का परित्याग करने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

1	2	3	4	5
2	650	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे में स्वचालित मशीनों की व्यवस्था समाप्त करने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।
4	657	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली से कलकत्ता तक मुख्य लाइन पर शीघ्रतम गति वाली रेल गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	658	श्री रामावतार शास्त्री	गुलजारबाग स्टेशन पर जनता गाड़ियों को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	659	श्री रामावतार शास्त्री	लोकोमैकेनिकल स्टाफ के कार्य-भार की जांच के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	660	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे के गैंगमैनों की संभावित छटनी से रक्षा की आवश्यकता ।	100 रुपये
5	661	श्री रामावतार शास्त्री	स्थानापन्न कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने में असफलता ।	100 रुपये
14	671	श्री जोगेश्वर यादव	करतल, नरेनी, अरत्रा, बवेरिया तथा राजापुर के लिये नई लाइन बनाने तथा उसे मध्य रेलवे के बरगढ़ स्टेशन से मिलाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	672	श्री जोगेश्वर यादव	मध्य रेलवे में झांसी, मनीपुर लाइन को हरपालपुर खजुराहो के रास्ते नई लाइन बना कर करतल नरेनी, अरतरा बवेरिया, कमासेन, राजापुर तथा बरगढ़ स्टेशन से मिलाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
14	673	श्री जोगेश्वर यादव	खजुराहो को रेल द्वारा मिलाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	674	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्व रेलवे के पटना-गया मार्ग को दोहरा बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	675	श्री रामावतार शास्त्री	बाहटा से बरास्ता विक्रम-पालीगंज अरवल तथा जहानाबाद, राजगृह तक नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	676	श्री रामावतार शास्त्री	उत्तर बिहार में बड़ी लाइन का विस्तार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	677	श्री रामावतार शास्त्री	राजगृह तथा गया के बीच नई लाइने बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	678	श्री रामावतार शास्त्री	फतुया-इसलामपुर लाइट रेलवे छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	679	श्री रामावतार शास्त्री	छोटा नागपुर में औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए वहाँ एक नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	689	श्री रामावतार शास्त्री	गुलजारबाग स्टेशन के विस्तार की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	690	श्री रामावतार शास्त्री	गुलजारबाग स्टेशन के दोनों ओर शैड बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	691	श्री रामावतार शास्त्री	पटना शहर स्टेशन (पूर्व रेलवे) के भूमिगत पुल को चौड़ा करने तथा उसका स्तर ऊंचा करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	692	श्री रामावतार शास्त्री	स्टेशनों पर शौचालयों तथा पीने के पानी के बारे में अच्छे प्रबन्ध किये जाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
15	693	श्री रामावतार शास्त्री	लक्खीसराय स्टेशन को पश्चिम की ओर ले जाने की आवश्यकता	100 रुपये
15	694	श्री रामावतार शास्त्री	लक्खीसराय स्टेशन पर उसके पश्चिम की ओर एक अतिरिक्त ऊपरि पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	695	श्री रामावतार शास्त्री	लक्खीसराय स्टेशन का पूर्ण-रूपेण स्टेशन के रूप में विकास किये जाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	696	श्री रामावतार शास्त्री	लक्खीसराय स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर नियुक्त किये जाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	697	श्री रामावतार शास्त्री	लक्खीसराय स्टेशन पर स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर का प्रबन्ध करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	698	श्री रामावतार शास्त्री	जमालपुर स्टेशन पर शौचालयों की सफाई की ओर ध्यान देने में असफलता ।	100 रुपये
15	699	श्री रामावतार शास्त्री	किऊल स्टेशन पर प्रतीक्षालयों के शौचालयों में पानी की पर्याप्त सप्लाई का प्रबन्ध करने में असफलता ।	100 रुपये
15	700	श्री रामावतार शास्त्री	दानापुर (पूर्व रेलवे) में कर्मचारियों के लिये अधिक क्वाटर बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	701	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्व रेलवे में वीहटा स्टेशन के प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षालय में कुर्सियों की कमी को दूर करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
15	702	श्री रामावतार शास्त्री	वीहटा स्टेशन के विस्तार की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	703	श्री रामावतार शास्त्री	वीहटा स्टेशन की गुमटी के पास ऊपरि पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	704	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्व रेलवे के शादीसोपुर स्टेशन पर शेड बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	705	श्री रामावतार शास्त्री	पटना शहर स्टेशन का नाम बदल कर पटना साहब स्टेशन रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	706	श्री रामावतार शास्त्री	पटना जंकशन का नाम बदल कर पाटलीपुत्र जंकशन रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	707	श्री रामावतार शास्त्री	दानापुर रेलवे स्टेशन पर पश्चिम की ओर एक और ऊपरि पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	708	श्री रामावतार शास्त्री	पटना—गया लाइन पर तरेगना स्टेशन पर शेड को बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	709	श्री रामावतार शास्त्री	तरेगना स्टेशन पर महिलाओं के लिये एक पृथक प्रतीक्षालय कक्ष की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	710	श्री रामावतार शास्त्री	तरेगना स्टेशन की टिकट घर के ऊपर वाले छज्जे को बढ़ाये जाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	711	श्री रामावतार शास्त्री	तरेगना स्टेशन के पूर्वी प्लेटफार्म पर पेय जल के लिये नल की व्यवस्था की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	712	श्री रामावतार शास्त्री	पटना में मीठापुर केबिन पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
15	713	श्री रामावतार शास्त्री	दानापुर रेलवे कालोनी को स्वच्छ रखने में असफलता ।	100 रुपये
15	714	श्री रामावतार शास्त्री	दानापुर रेलवे कालोनी के स्कूल की इमारत को बढ़ाया जाना ।	100 रुपये
15	715	श्री रामावतार शास्त्री	पेंशन की राशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	716	श्री रामावतार शास्त्री	पेंशनों के भुगतान में विलम्ब को दूर करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	717	श्री रामावतार शास्त्री	पेंशन पाने वालों के बच्चों के प्रवेश के लिये विशेष सुविधायें दिये जाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	718	श्री सी० मुत्तुस्वामी	करूर–डिण्डिगुल बड़ी लाइन को थाडीकोम्बू–बेडासंदूर, पाला-पट्टी और अर्वाकुरिचि के रास्ते मिलाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	719	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	1947 में किये गये सर्वेक्षण के पश्चात् तालचेर में हुए नये विकास-कार्य को ध्यान में रखते हुए तालचेर–विमलागढ़ रेल मार्ग का व्यवहार-एवं-लागत अध्ययन करने में असफलता ।	100 रुपये
7	720	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	ईंधन तथा अन्य प्रकार के सामान को संभाल कर रखने के लिये जोरदार प्रयत्न करने में असफलता ।	100 रुपये
8	721	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	माल की हो रही हानि और क्षति को कम करने के लिये जोर-दार प्रयत्न करने में असफलता ।	100 रुपये
9	722	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	रेलवे प्रशासन द्वारा संचालन व्यय में अधिकतम मितव्ययता बर-तने में असफलता ।	100 रुपये
9	723	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	रेल-फाटकों (लैवल–क्रासिंग) पर दुर्घटनाएं रोकने के लिये कार्य-वाही करने में असफलता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
11	724	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड तथा आसनसोल डिवीजनों में बिना टिकट यात्रा रोकने में असफलता ।	100 रुपये
11	725	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	रेलवे के लिये अधिक माल यातायात प्राप्त करने और परिवहन के अन्य साधनों की ओर माल यातायात को जाने से रोकने में असफलता ।	100 रुपये
12	726	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	समस्त देश में माल यातायात और राजस्व में वृद्धि रुक जाना ।	100 रुपये
14	727	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	उड़ीसा में दक्षिण पूर्व रेलवे की विद्यमान लाइनों को दुहरा बनाने और नई लाइनें बनाने में असफलता ।	100 रुपये
14	728	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	प्रदीप बन्दरगाह को उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के पृष्ठ प्रदेशों से जोड़ने में असफलता, जिससे कि बन्दरगाह की कार्यक्षमता तथा उसके महत्व पर प्रभाव पड़ रहा है ।	100 रुपये
14	729	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	दक्षिण रेलवे में बालासोर से खुर्दा रोड तक की लाइन पर और तालचेर से कटक तक की रेलवे लाइन पर बिजली लगाने में असफलता ।	100 रुपये
14	730	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	अकाल से बुरी तरह प्रभावित और खनिज बाहुल्य वाले पश्चिम उड़ीसा के क्षेत्र में दक्षिण-पूर्व रेलवे की मौजूदा कलकत्ता–मद्रास बड़ी लाइन से मिलाने वाले संचार साधनों में सुधार करने में असफलता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
14	731	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	दक्षिण-पूर्व रेलवे में उड़ीसा में कोरापुर, जिले के अम्बागुडा से कालाहाड़ी जिले के केसींगा तक रेलवे लाइन के निर्माण का उल्लेख न करना ।	100 रुपये
14	732	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	दक्षिण-पूर्व रेलवे में उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में तालचेर से सुन्दरगढ़ जिले में विमलागढ़ तक रेलवे लाइन बनाने का उल्लेख करने में असफलता ।	100 रुपये
14	733	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	दक्षिण-पूर्व रेलवे में उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में तालचेर से सम्बलपुर जिले में सम्बलपुर तक रेलवे लाइन बनाने का उल्लेख करने में असफलता ।	100 रुपये
15	734	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	दक्षिण-पूर्व रेलवे में केसिंगा, झारसुगुडा, सम्बलपुर, भेरामन्दोली तथा निर्गुन्डी स्टेशनों पर ऊपरी अथवा निचले पुलों की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
15	735	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	दक्षिण-पूर्व रेलवे में झारसूगुडा तथा सम्बलपुर रोड स्टेशनों के प्लैटफार्मों पर यात्रियों के लिये ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	736	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	डाउन पैसेंजर तथा एक्सप्रेस गाड़ियों को भिन्न भिन्न स्थानों पर रोकने की व्यवस्था करने में दक्षिण-पूर्व रेलवे की भेदभावपूर्ण उपेक्षा तथा यात्री डिब्बों की अपर्याप्तता जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण-पश्चिमी उड़ीसा की जनता को भारी असुविधा होती है ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
15	737	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	उड़ीसा क्षेत्र के अन्दर दक्षिण-पूर्व रेलवे में समेकित सेवा की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
15	738	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	उड़ीसा क्षेत्र के अन्दर दक्षिण-पूर्व रेलवे में सुपर एक्सप्रेस माल गाड़ियां चलाने में असफलता ।	100 रुपये
15	739	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	अलाभप्रद शाखा लाइनों को परीक्षण के आधार पर सचालन के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपे जाने में असफलता ।	100 रुपये
15	740	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	पर्यटकों के देखने योग्य स्थानों को जाने वाली शाखा लाइनों को बन्द करने का विचार जिसके परिणामस्वरूप पर्यटक यातायात में रुकावट पड़ेगी और देश में विदेशी मुद्रा की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ।	100 रुपये
15	741	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	यात्रियों के लिये पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था किये बिना यात्री-टिकटों पर अति-भार बढ़ाने का विचार ।	100 रुपये
15	742	श्री धीरेन्द्र नाथ देव	राउरकेला से खड़गपुर, कटक तथा भुवनेश्वर होते हुए पुरी तक एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने में असफलता ।	100 रुपये

श्री लोलाधर कटकी (नवगाँव) : हमारे लिये यह बड़ी चिन्ता की बात है कि वर्ष 1966–67 से लेकर रेलवे को प्रतिवर्ष लगभग 20 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। इस घाटे को पूरा करने के लिये मंत्री महोदय ने पहले की तरह अब भी किराये भाड़े में वृद्धि कर दी है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस कार्यवाही से रेलवे की अर्थ-व्यवस्था की त्रुटियाँ ठीक हो जायेंगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या रेलवे बजट और अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में योजना आयोग की परिवहन समिति की सिफ़ारिशों पर कोई कार्यवाही की गयी है? मेरे विचार में इस सारी समस्या की अच्छी प्रकार से छानबीन करने लिये विशेषज्ञों की एक उच्चशक्ति प्राप्त समिति बनायी जानी चाहिये।

इस घाटे के बावजूद मंत्री महोदय को अनिवार्य वस्तुओं के यातायात पर किराये भाड़े में वृद्धि के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करने चाहिये। रेलवे सार्वजनिक उपयोग की सेवा है और उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह जनता को किस प्रकार राहत दे सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि तीसरे दर्जे की स्लीपर बर्थ के बारे में क्या राहत दे रहे हैं।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान गोहाटी में भारतीय रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ के ग्यारहवें सम्मेलन में पास किये गये विभिन्न प्रस्तावों की ओर दिलाना चाहता हूं। इन प्रस्तावों में एक रेलवे के बजट और अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में था और दूसरा महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में था। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह अपने उत्तर में इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही पर प्रकाश डालें।

रेलवे के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनिवार्य सेवा निवृत्ति की योजना से रेलवे की कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। मंत्री महोदय को यह आश्वासन देना चाहिये कि वह अनिवार्य सेवा निवृत्ति के तरीके को नहीं अपनायेंगे विशेषकर जब अकुशल कर्मचारियों पर कार्यवाही करने के लिये अन्य साधन उपलब्ध हैं। मंत्री महोदय को रेलवे कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों के मामले की ओर भी ध्यान देना चाहिये जिससे अनजान व्यक्तियों को कोई नुक्सान न पहुंचाया जा सके। उत्तरपूर्व सीमा रेलवे सामरिक महत्व के क्षेत्र में स्थित है। वहाँ पर विद्रोहियों तथा अन्य राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा तोड़-फोड़ की कार्यवाही का ख़तरा बना हुआ है। इसलिये मैं यह अनुरोध करता हूं कि सिलिगुरी और अलीपुरद्वार सेक्शनों पर भी सुरक्षा के उपाय किये जाने चाहिये।

मालेगाँव, पाँडू और गोहाटी में रेलवे क्वाटरों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में कुछ ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

जोगीफोया से गोहाटी तक और फिर तिनसूकिया तक बड़ी लाईन का विस्तार किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। इन शब्दों के साथ रेलवे के अनुदानों की माँगों का मैं समर्थन करता हूं।

Shri Gunanand Thakur (Saharsa): It has been observed for the last three years that deficit budget is being presented. Government should try to give relief to the public.

I would like to say that Supaul-Pratapganj railway is very important line from strategic point of view. Saharsa is a backward area of Bihar State. Bihar State Government have also seen their recommendations for the construction of this railway line. I want to say that backward areas should not be ignored like this. We have demanded an overbridge at Saharsa but no action has been taken. Moreover development of rural areas are being ignored. There are lack of faciltlities of drinking water electricity and waiting rooms. Government should look into this matter. When taxes are imposed on the public and railway fare and freight charges are also increased, they should be provided with facilities also.

There is no security arrangement on narrow gauge and branch lines. The conditions of stations on these lines are deplorable. There should be halt stations at a distance of every five miles. It will provide the facilities to the public and revenues of Railways will also be increased. Security Police should be posted in these trains which will ensure safety of passengers as well as railway goods.

[Shri Gunanand Thakur]

At present there is no express train in our area. These should be atleast one express train which should go to Assam and Katihar *via* Saharsa. Moreover Darbhanga—Samastipur railway line should be converted into broadgauge line and in ca se the same is extended upto Sonpur, it will benefit the people of North Bihar.

Shri Mudrika Sinha (Aurangabad): I would like to say that even construction suggestions made by Members of Parliament are being rejected by the bureacracy of Railways. We get stereotype replies to our suggestions from the Railway Administration. It seems that members of Railway Board are all powerful and they do not listen to the hon'ble Minister.

In fact our suggestions should be considered on merits and if they are found to be correct and reasonable, the hon'ble Minister should get them implemented.

Deficit budget of Railways has become a recurring feature. In order to meet this deficit railway fare and freight charges are increased every year. Government should give serious thought to put an end to this recurring feature. In my opinion misman agement of Railway administrations, pilferage, confusion and complete anarchy are mainly responsible for this recurring deficit. The Railways have to give huge amount of compensation for the damage to the goods during the course of transit. On one hand there is overcrowding in the trains but on the other hand the revenues are not in conformity with the rush. There are certain honest officers in the Intelligence Branch of Railways but they have been degraded and removed from their present place of posting.

There has been a Patna—Gaya-Dehri line. This train used to steam off from Patna and reach Dehri *via* Gaya. This line was very useful for the inhabitants of these areas. I would suggest that either this railway line should be restored or I suggest that there is a train remaining from Dehri to Gaya and back. This train should be extended to Patna. At present there is no train from Patna to Gaya from 11·00 A.M. to 5 P.M. and if that train could be started from Patna at about 3 .00 it would be very convenient for the people of this area. Moreover the level of platform of Nabinagar Railway Station should be raised. We have already requested for it but Railways have not paid any attention towards our request.

I had also written to improve upon the approach road at Godaru Station but no action has been taken in that respect.

Shri Onkar Lal Berwa (Kota): Railways have increased fares but passengers have not been given the facilities corresponding to increase in the fares. Railway Board is all powerful. They do not pay any attention to petty matter. I want to give certain suggestion regarding deficit budget of Railways. For instance there are 2000 saloons of Railways. If half of them are kept reserved for Railways and rest of them are given on hire. It will add to the revenue of Railways. The second suggestion is that number of passes should be reduced from 6 to 3, it will also fetch additional income of Rs. 9 crores. It has also been observed that auction of old and broken bogies are not properly organised. These petty matters must be looked into if we want to increase the income of Railways. The catering staff of Railways is also notorious for corruption and this contributes to the losses of Railways.

A large amount of money was spent on the survey of Kotah—Chittorgarh line but it has not come up till now. A railway line from Kotah to Bundi should be constructed. It will provide sufficient revenues to Railways but no attention has been paid towards this.

It would be appreciated if narraw gauge line of swai Madhopure is converted into broad gauge line. It will also reduce the expenditure on staff.

The security arrangement is also very poor. The bogies which are disconnected from trains are pluced in the loco sheds for hours together. I want to say that proper seecurity arrangements should be made.

It has been observed that Guards and commercial clerks have to work in odd conditions. They should be given all the facilities to perform their duties efficiently. There is discrimination in the supply of liveries to Railway employees, which should be removed. This discriminations has resulted in heart burning unnecessarily. Moreover the uniform of ticket checkers is not proper as they just look to be post-men in their present khaki Uniforms. They should be supplied with a suitable Uniforms.

There is only one conductor Guard in Dehradun Express. Thsere should be more conductor Guards in this train.

No accommodation is reserved for Members of Parliament in the De-Luxe train which starts from Delhi. I want to suggest that seats should be reserved for the Members of Parliament during the course of Session as well. I would also suggest that Parcel Express should be extended to Delhi and a Conncection be provided for Jaipure.

The cases of corruption should be thoroughly investigated. some of the casual labourers and members of their families are suffering from T.B. and they seek the transfer but the concerned officers do not alow their transfer. Such cases should be looked into and officers should not harass them.

जम्मु तथा काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) विधेयक—जारी

Jammu and Kashmir Represantation of the People (Supplementary) Bill--Cont.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : संविधान के अनुच्छेद 327 के अन्तर्गत चुनावों के सम्बन्ध में कानून बनाने के अधिकार संसद् को दिये गये हैं परन्तु अनुच्छेद 370 के अधीन यह अनुच्छेद जम्मू तथा काश्मीर पर लागू नहीं होता। अब मंत्री महोदय ने संघ की सूची में प्रविष्टि 72 को सम्मिलित करने के लिये राष्ट्रपति का आदेश प्रस्तुत किया है। परन्तु जब तक राष्ट्रपति के आदेश में, जिसके द्वारा प्रविष्टि 72 की प्रयुक्ति का संशोधन किया गया है, अनुच्छेद 327 का उल्लेख है तब तक सभा को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को जम्मू तथा काश्मीर पर लागू करने का अधिकार नहीं है। यदि जम्मू तथा काश्मीर सम्बन्धी राष्ट्रपति के आदेश को लागू किया जाना है तो उसके लिये अनुच्छेद 327 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : श्री मिश्रा ने संविधान के अनुच्छेद 327 के आधार पर आपत्ति उठाई है। माननीय सदस्य यह समझते हैं कि कानून बनाने के लिये संसद को अनुच्छेद 327 के अन्तर्गत अधिकार दिये गये हैं। वास्तव में अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत यह शक्तियाँ दी गयी हैं। अतः अनुच्छेद 327 लागू नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय : मूल बात यह है कि अनुच्छेद 327 का हवाला दिये बिना क्या आप राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसमें संशोधन कर सकते हैं?

श्री मु० यूनस सलीम : मैं अभी इस बात को स्पष्ट करने जा रहा हूं।

अनुच्छेद 246 में कहा गया है कि "खण्ड (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी संसद् को सप्तम अनुसूची की सूची (1) में जो इस संविधान में "संघ सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है" तथा अनुच्छेद 327 में कहा गया है कि इस संविधान के अधीन रहते हुए संसद् समय समय पर विधि द्वारा . . . के बारे में उपबन्ध कर सकेगी। किन्हीं विषयों के बारे में विधि बनाने तथा किन्हीं विषयों के अधीन कुछ उपबन्ध करने के लिये विधि बनाने इन दोनों बातों में अन्तर है। अनुच्छेद 327 के अन्तर्गत राज्यों के विधान मंडलों के गठन सम्बन्धी कानून बनाने की शक्ति संसद् को दी गई है। अनुच्छेद 327 इस प्रकार है :

> "इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संसद् समय समय पर, विधि द्वारा संसद् के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निर्वाचनों से सम्बद्ध या संसक्त स. विषयों के सम्बन्ध में, जिनके अन्तर्गत निर्वाचक-नामावलियों का तैयार कराना तथा निर्वाचन-क्षेत्र का परिसीमक तथा ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन कराने के लिये अन्य सब आवश्यक विषय भी हैं, उपबन्ध कर सकेगा।"

अनुच्छेद 370 में जम्मू तथा काश्मीर राज्य का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद इस प्रकार है:

> "(ख) उक्त राज्य के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति—
>
> (1) संघ-सूची और समवर्ती सूची में के जिन विषयों को राज्य की सरकार परामर्श करके राष्ट्रपति उन विषयों का तत्स्थानी विषय घोषित कर दे जो भारत डोमिनियन में उस राज्य के प्रवेश के शासित करने वाली प्रवेश लिखत में उल्लिखित ऐसे विषय हैं, जिनके बारे में डोमिनियन विधान मंडल विधि बना सकता है, उन विषयों तक, तथा
>
> (2) उक्त सूचियों में जिन अन्य विषयों को उस राज्य की सरकार की सहमति से राष्ट्रपति आदेश द्वारा उल्लिखित करे उन विषयों तक सीमित होगी।"

संघ सूची की प्रविष्टि 72 तथा राज्य सूची की प्रविष्टि 37 एक समान हैं, जो इस प्रकार है। प्रविष्टि संख्या 72 में लिखा है :

> "संसद् और राज्यों के विधान मंडलों के लिये तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचन; निर्वाचन आयोग।

राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 37 इस प्रकार है : संसद्-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान मंडल के लिये निर्वाचन।

यह जो विधयक पेश किया गया है इसका उद्देश्य बहुत सीमित है। इसका उद्देश्य जम्मू तथा काश्मीर के चुनावों सम्बन्धी मामलों की अपीलें सुनने तथा उनका निपटारा करने के लिये उच्चतम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का विस्तार करना है। मेरा निवेदन है कि

इस विधेयक के पेश किये जाने से अनुच्छेद 327 का उल्लंघन नहीं होता है। अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सलाह से वह उच्चतम न्यायालय के अपीलों का निर्णय करने की कुछ सीमित शक्तियां दे सकता है। इसलिये अनुच्छेद 327 इस विधेयक के पेश किये जाने में बाधक नहीं हो सकता।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद 370 जानबूझ कर रखा गया है और जहां तक जम्मू तथा काश्मीर राज्य का सम्बन्ध है इस अनुच्छेद का क्षेत्राधिकार सीमित है। जब यह प्रबन्ध किया गया तो प्रविष्टि 72 पहले ही थी। अब इसे व्यापक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि अनुच्छेद 370 का संशोधन किये बिना ही माननीय मंत्री इस अनुच्छेद की शक्तियों का उल्लंघन करना चाहते हैं। यदि अनुच्छेद 370 को बदला न गया तो उच्चतम न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। माननीय मंत्री द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। मैं श्री श्रीनिवास मिश्र द्वारा उठाई गई आपत्ति का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अनुच्छेद 370 के संशोधन के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई है। उनकी आपत्ति मूलतः भिन्न है।

श्री विक्रम चन्द्र महाजन (चम्बा) : संविधान के चार अनुच्छेद यहां पर संगत हैं और वे हैं अनुच्छेद 327, 246, 370 तथा प्रविष्टि 72। उनकी आपत्ति यह है कि अनुच्छेद 327 उच्चतम न्यायालय से सम्बन्धित है और कोई दूसरा अनुच्छेद इस अनुच्छेद की शक्तियों को कम नहीं कर सकता। आप जरा अनुच्छेद 246 (1) को पढ़िये, जो इस प्रकार है :

> "खण्ड (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी संसद को सप्तम अनुसूची की सूची (1) में प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।"

अतः अनुच्छेद 246 से यह स्पष्ट है कि प्रविष्टि 72 अनुच्छेद 327 से उत्पन्न नहीं होती। अनुच्छेद 246 में अनुसूची 1 का उल्लेख है और अनुसूची 1 में प्रविष्टि 72 आती है। अनुच्छेद 327 में प्रविष्टि 72 का कोई उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत अनुच्छेद 327 और प्रविष्टि 72 दो स्वतंत्र शक्तियां हैं।

अब प्रश्न यह है कि यदि ये दो स्वतंत्र शक्तियां हैं तो कौन सी शक्ति सर्वोपरि है। सभी न्यायालयों में कानून का यह मान्य नियम है कि यदि संविधान के दो अनुच्छेदों में या किसी संविधि की दो धाराओं में परस्पर-विरोध है, तो बाद वाला उपबन्ध सर्वोपरि होता है। इसलिये प्रविष्टि 72 द्वारा अनुच्छेद 327 रद्द हो जाता है और प्रविष्टि 72 सर्वोपरि रह जाती है।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : कृपया अनुच्छेद 138 देखिये। अनुच्छेद 138 इस प्रकार है :

> (1) संघ सूची के विषयों में से किसी के बारे में उच्चतम न्यायालय को ऐसे और क्षेत्राधिकार और शक्तियां होंगी, जिसे संसद् विधि द्वारा प्रदान करे।

(2) यदि संसद् न्यायालय के लिये ऐसे क्षेत्राधिकार और शक्तियों के प्रयोग का विधि द्वारा उपबन्ध करे तो किसी विषय के बारे में उच्चतम न्यायालय को ऐसे और क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां होंगी, जिन्हें भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष करार द्वारा प्रदान करे।"

यदि आप अनुच्छेद 138 को अनुच्छेद 246 और प्रविष्टि 72 के साथ पढ़ें तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस संसद् में इस विधान को आरम्भ किया जाना सर्वथा उचित है और इसे राय जानने के लिये राष्ट्रपति अथवा उच्चतम न्यायालय को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई आपत्ति उचित नहीं है तथा मेरा निवेदन है कि हमें विधेयक पर आगे विचार करना चाहिये।

श्री क० कुण्डू (बालासोर) : हमारे सामने जो प्रश्न है वह केवल संविधियों को सुसंगत करने का है। यदि कोई माननीय सदस्य वास्तविक निर्वचन करता है तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अन्य अधिनियमों अथवा संविधान के अन्य उपबंधों से उसे ध्वनित नहीं किया जाना चाहिये, जो विशेष रूप से निषेध किया हुआ है। अनुच्छेद 370 बहुत स्पष्ट है। हमें खण्ड (2) के परन्तुक का आश्रय नहीं ले सकते हैं और न ही राष्ट्रपति के आदेश के जरिये प्रविष्टि 72 में कोई उपबन्ध जोड़ सकते हैं। यदि माननीय मंत्री अपने बहुमत के जोर से इस विधेयक को पास भी करवा लेते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अथवा किसी उच्च न्यायालय द्वारा इसे असंवैधानिक करार दिया जायेगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr)Mr. Diputy Speaker, Sir, the root cause of all this dispute is that the J. and K. Ligislative Assembly has enacted such an Act, which has encroached upon the power of this Parliament. In fact the power to enlarge the jurisdiction of SupremeCourt exclusively rests with the Parliament. I want to pointout that the jurisdiction of Entry 72 is more wide than Article 327. Article 327 deals with the appelate jurisdiction of the Supreme Cort and as such the jurisdiction of the Supreme Court cannot be enlarged under Entry 72 without making a reference of Article 327 in the Presidential order. I think it would be better to amend the Presidential order dated 9th Febiuary by making a reference of Article 327 in that order. It is obligatory to make a change in the Presidential order. So, if a reference is not made to Article 327 in the Bill, it will be declared void by the Supreme court, after it is passed. I want to tell the hon. Members that it is also our duty to see that a particular bill is according to the provision s of the Constitution before it is declared *ultravires* by the Supreme Court .

I want to congratulate the hon. Minister that he has enhanced the status of Lok Sabha in Comparison to the status of J.&K. Lagislative Assembly by bring forth this legislation .

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनस सलीम) : माननीय सदस्य श्री मधु लिमये ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति के आदेश में संविधान के अनुच्छेद 327 का उल्लेख किया जाना चाहिये था। संसद् को राष्ट्रपति के आदेश से पूर्व प्रविष्टि 72 में उल्लिखित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं था। राष्ट्रपति ने इस आदेश के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 138 के अधीन उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाने और अपील का उपबन्ध करने के सम्बन्ध में संसद् को कानून बनाने के कुछ सीमित अधिकार

दिये हैं। यदि राष्ट्रपति के आदेश में अनुच्छेद के 27 का उल्लेख किया जाता तो जम्मू तथा काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम निरर्थक हो जाता। यह आपत्ति संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन जारी किये गये राष्ट्रपति के उस आदेश से समाप्त हो जाती है, जिसके द्वारा प्रविष्टि 72 के उपबन्ध का विस्तार किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को याद होगा कि जब यह विधेयक पहले सभा के सामने लाया गया था तो श्री मधु लिमये द्वारा यह आपत्ति उठाई गई थी कि विधि बनाने की जो शक्ति केवल संसद् के पास है, उसका उपयोग राज्य विधान मंडल द्वारा किया गया है तथा अब यह विधेयक पेश करके माननीय मंत्री राज्य विधान मंडल की कार्यवाही को उचित ठहराना चाहते हैं। श्री मधु लिमये द्वारा उठाई गई आपत्ति का समाधान करने के लिये वर्तमान संशोधन पेश किया गया है। मैं स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। आज प्रातः श्री श्रीनिवास मिश्र ने अपनी आपति उठाते हुए कहा था कि यदि वर्तमान संशोधन पेश न किया गया होता, तो वह यह आपत्ति न उठाते। विधि मंत्री का कथन सुनने के बाद तथा उठाई गई सब आपत्तियों को सुनने के बाद म कहना चाहता हूं कि हमें एक मौलिक बात याद रखनी चाहिये और वह मौलिक बात यह है कि अनुच्छेद 370 काश्मीर के सम्बन्ध में प्राधिकार के प्रयोग के बारे में अपने आप लगाया गया एक प्रतिबन्ध है। यदि हम प्राधिकार का प्रयोग करना चाहें तो ऐसा राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा ही किया जा सकता है। आदेश में संघ सूची की प्रविष्टि 72 का उल्लेख किया गया है। विधेयक का उद्देश्य बहुत ही सीमित है और इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील करने के अधिकार का उपबन्ध किया गया है तथा इस के लिये विशेष अपील करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जैसा कि सामान्य न्यायालयों में होता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या अनुच्छेद 327 का उल्लेख किया जाना चाहिए था? मैंने इस प्रश्न पर बहुत गम्भीरता से विचार किया है। ऐसी स्थिति में यदि अनुच्छेद 327 का उल्लेख किया जाता तो और संवैधानिक आपत्तियां उठ सकती थीं। इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया गया। यह विधेयक संविधान के सामने है और सभा की क्षमता के भीतर है। अब माननीय मंत्री अपना संशोधन पेश करें।

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2, खण्ड 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

	[जम्मू तथा काश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की 116क, 116ख, और 116ग धाराओं का लागू होना।	2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, की 116क, 116ख और 116ग धाराओं के उपबन्ध निम्नलिखित रूपभेदों के अधीन, जम्मू तथा काश्मीर न्यायालय द्वारा दिये गये प्रत्येक आदेश पर लागू होंगे :—
1951 का 43वां		

(क) उक्त उपबन्धों में उच्च न्यायालयों को किये गये निदेशों में जम्मू तथा काश्मीर उच्च न्यायालय को किये गये निदेश शामिल समझे जायेंगे;

(ख) राज्य विधान मंडल अथवा उसके अध्यक्ष अथवा उसके सभापति को किये गये निदेशों में जम्मू तथा काश्मीर राज्य विधान मंडल अथवा उसके अध्यक्ष अथवा उसके सभापति को किये गये निदेश शामिल समझे जायेंगे; और

(ग) जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को किये गये निदेश जम्मू तथा काश्मीर लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 के उक्त प्रकार के उपबन्धों के बारे में किये गये निदेश समझे जायेंगे"

1951 का 43वां जम्मू तथा काश्मीर अधिनियम, 1957 का चौथा

["Application of sections 116 A, 116B and 116 C of the Representation of the People Act, 1951, to orders made by the the Jammu and Kashmir High Court.

2. The provisions of sections 116A, 116B and 116C of the Representation of the People Act, 1951, shall, so far as may be, apply to every order made by the high Court of Jammu and Kashmir subject to the following modifications. namely—

(a) references therein to the High Court shall be construed as including references to the High Court of Jammu and Kashmir,

(b) references therein to the State Legislature or to the Speaker or Chairman thereof shall be construed as including references to the Legislature of the State of Jammu and Kashmir and to the Speaker or Chairman thereof, and

(c) references therein to the provisions of the Representation of the People Act, 1951, shall, in relation to the State of Jammu and Kashmir, be construed as references to the corresponding provisions of the Jammu and Kashmir Representation of the people Act, 1957"]

43 of 1951

Jammu and Kashmir Act, No. IV of 1957.

[श्री मुहम्मद यूनस सलीम]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 as amended was added to the Bill

खण्ड 3, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 3, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री मुहम्मद यूनस सलीम : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir. so far as the principles and objects of this Bill are concerned I support them. But so far as the form in which the bill has been presented, despite the objection raised by Shri Mishra, it is objectionabe. The hon. Minister has brought this measure in the present form, which is illegal. It has been made clear that the Bill is illegal unless a reference is made to Atricle 327 of the Constitution in the Presidential order. I think the hon. Minister himself is fully aware of the fact and he has knowingly brought this Bill in the present form, because he wants that the ill gal Government of Mr. Sadiq should be kept in power as long as possible. He knows that this bill after becoming an Act will be declared void by the Supreme Court and this the illegal Government of Mr. Sadiq will be able to stay for a longer spell of time. I warn the Government if this Act was declared ultra vires by the Supreme Court, the entire responsibility of this would rest with the Government, because this bill is being brought in the present form despite very valid objections.

श्री धीरेन्द्र नाथ देव (अंगुल) : हमारा शुरू से यह अनुभव रहा है कि केन्द्रीय सरकार कश्मीर के मामले में सदा एक पक्ष तथा एक व्यक्ति पर विश्वास करती रही है। उसने पहले शेख अब्दुल्ला पर विश्वास किया, फिर बख्शी गुलाम मुहम्मद पर और फिर श्री सादिक पर। काश्मीर में विरोधी पक्षों को कभी पनपने नहीं दिया गया है। श्री सादिक ने इस बात का पर्याप्त प्रमाण पिछले आम चुनाव के दौरान दिया है, क्योंकि विरोधी पक्षों द्वारा समर्थित अधिकांश व्यक्तियों के नामांकन पत्रों को रद्द कर दिया गया, जबकि सत्ताधारी दल के किसी व्यक्ति के नामांकन पत्र को अस्वीकार नहीं किया गया। लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक विरोधी पक्षों को पनपने न दिया जाये।

जब जम्मू तथा काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है तो केन्द्रीय सरकार को यह निर्णय करने में इतना समय क्यों लगा कि जम्मू तथा काश्मीर उच्चन्यायालय की चुनाव याचिका सम्बन्धी अपीलें उच्चतम न्यायालय में सुनी जायेंगी। इस मामले को बहुत पहले निपटा लिया जाना चाहिये था।

अन्त में उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के मामले का समर्थन करते हैं, मैं पुनः अपने दल की इस मांग को दोहराता हूं कि जम्मू तथा काश्मीर में राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाना चाहिये और वहां मध्यावधि चुनाव करवाये जाने चाहिये।

श्री प० गोपालन (कोलचेरी) : इस विधेयक के द्वारा चुनावों के बारे में जम्मू तथा काश्मीर उच्चन्यायालय के निर्णयों की अपीलों को सुनने का अधिकार उच्चतम-न्यायालय को दिया जा रहा है। यह विधेयक पेश करके सरकार ऐसा प्रभाव डालना चाहती है कि काश्मीर में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि मुझ से पहले कई माननीय सदस्यों ने

[श्री प० गोपालन]

विस्तार से इस बात का उल्लेख किया है कि काश्मीर में पक्षपात के आधार पर चुनाव कराये जा रहे हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या जम्मू तथा काश्मीर के लोगों को चुनाव के दौरान अपना मत स्वतंत्रता के साथ व्यक्त करने का मौका दिया जाता है या नहीं। सच तो यह है कि जम्मू तथा काश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं। जब तक जनता को चुनाव में अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, तब तक इस विधेयक से भी कोई लाभ नहीं होगा। इस संदर्भ में मैं शेख अब्दुल्ला के वक्तव्य का उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है "हम कहते हैं कि भारत संसार में सब से बड़ा प्रजातंत्र है तथा इसी कारण से हमें भारत की ओर आकर्षित हुए थे। मैं काश्मीर का प्रधान मंत्री था। मुझे वहां के विधान मंडल का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। परन्तु एक दिन प्रातः जब मैं दौरे पर गया हुआ था तो मुझे सशस्त्र सेनाओं के सिपाहियों द्वारा घेर लिया गया। मेरे ही एक कनिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मुझे गिरफ्तारी के वारंट दिये और जब मैंने यह पूछा कि यह कार्यवाही किसके अधिकार पर की जा रही है तो उसने अपनी मशीनगन की ओर इशारा किया। तब मैंने राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री से प्रार्थना की कि मुझे विधान मंडल में अपना मामला रखने का अवसर दिया जाये तथा मुझे यह जानने का मौका दिया जाये कि मुझे विधान मंडल का विश्वास प्राप्त है या नहीं। परन्तु कुछ नहीं हुआ। क्या आप इसे प्रजातंत्र कहते हैं?"

गत 20 वर्षों में जम्मू तथा काश्मीर में इस प्रकार का प्रजातंत्र रहा है। मैं नहीं समझता कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के द्वारा भी काश्मीर समस्या को हल किया जा सकता है। परन्तु ऐसा करने से भारत के मामले को मेंनोवैज्ञानिक दृष्टि से काश्मीर की जनता के सामने रखा जा सकता है।

काश्मीर में 20 या 25 वयस्कों के पीछे एक सशस्त्र सैनिक है और सैनिक की बंदूक चुनाव परिणामों में निर्णायक होती है। राज्य में लोकतंत्र कायम किया जाना चाहिये और जनता को मूलभूत अधिकार दिये जाने चाहिये।

Shri Gulam Mohmmad Bakshi (Srinagar): Sir, while supporting this Bill, I want to say that I subscribe to the views expressed by Shri Madhu Limaye. So far as Article 370 is concerred. I agree with you Sir, that the powers of the Parliament are limited in respect of Jammu and Kashmir and no measure can be made applicable to that State by the President without the consent of that State. But I think that instead of extending the jurisdiction of the Supreme Court to hear appeals of the decisions of the High Court of Jammu and Kashmir in respect of election, it would be better to apply the entire People Representation Act to the State of Jammu and Kashmir. There are still four days more, when the present Ordinance will cease to operate and in the meantime the consent of the State Government can easily be obtained. If this is done the entire dispute will be settled once for all. The State Government should also have no objection in giving their consent, when they have given their consent in regard to this Bill. Though it is a good thing that the jurisdiction of the Supreme Court is being extended in respect of hearing appeals of the decisions of the High

Court, but I want to know as to why not the entire representation of the People Act of the Centre is being made applicable so that the present confusion which is prevailing there is removed.

Mr. Deputy Speaker: It is already 7 P.M. The hon. Member may continue his speach tomorrow.

इस के पश्चात लोक-सभा बुधवार, 20 मार्च 1968/30 फाल्गुन, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjorned till eleven of the clock on Wednesday, March 20, 1968/Phalguna 30, 1889 (Saka).

GMGIPND—LS III—863 (Ai) LS—24-10-68—600.